

RAPID REVISION SERIES

800 High Probable
Topics for
UPSC Prelims 2021
(Current Affairs + Static Portion)

हिंदी

Full Compilation

ECONOMY

Make the best use of this document by combining free explanation videos of these topics, Current Affairs Quiz, Static Quiz, CSAT Quiz, & 3 Full Mocks on rrs.iasbaba.Com (A Free Initiative targeting UPSC PRELIMS 2021)



IASBABA'S

**RAPID REVISION (RaRe)
SERIES - UPSC 2021**

RaRe Notes Hindi

DAY 10 - ECONOMY

#RaRebaba
www.rrs.iasbaba.com

विषय कवरेज:

71. अतिरिक्त बजटीय (ऑफ-बजट) उधारी (Off-Budget Borrowings)
 72. राजकोषीय घाटा और विभिन्न राजकोषीय संकेतक (Fiscal Deficit and Various Fiscal Indicators)
 73. वित्तीय घाटे का वित्तपोषण (Fiscal deficit financing)
 74. सरकारी प्रतिभूति (G-Sec) और इसके प्रकार (Government Security (G-Sec) and Its Types)
 75. गिल्ट खाता (Gilt Account)
 76. सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम (G-SAP)
 77. ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (Treasury Single Account)
 78. इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर (Inverted Duty Structure)
 79. करेंसी मैनिपुलेशन (Currency Manipulation)
 80. निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 (Export Preparedness Index 2020)
- *अतिरिक्त विषय: यील्ड कर्व्स (Yield curves)



विषय 71: अतिरिक्त बजटीय (ऑफ-बजट) उधारी (Off-Budget Borrowings)

ऑफ-बजट उधार या वित्तपोषण क्या है?

- अतिरिक्त बजटीय (ऑफ-बजट) उधार सरकारी संस्थाओं द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं को चलाने के लिए किए गए उधार हैं जो बजट में नहीं दिखाए जाते हैं।
- सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं द्वारा किए गए ये उधार जो प्रभावी रूप से सरकार के ऋण बन जाते हैं, अतिरिक्त बजट उधार या संसाधन के रूप में जाने जाते हैं।
- सरकारें अपने राजकोषीय घाटे को एक सम्मानजनक संख्या तक सीमित रखने के लिए "ऑफ-बजट उधार" का सहारा लेती हैं।
- इस तरह के वित्तपोषण के लिए सरकारी खर्च, उधार और ऋण की वास्तविक सीमा को छिपाने और ब्याज के बोझ को बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है।

Table 1: Fiscal Indicators (as percent of GDP)

		Revised Estimates 2020-21	Budget Estimates 2021-22
1.	Fiscal Deficit	9.5	6.8
2.	Revenue Deficit	7.5	5.1
3.	Primary Deficit	5.9	3.1
4.	Gross Tax Revenue	9.8	9.9
5.	Non-tax Revenue	1.1	1.1
6.	Central Government Debt		
	<i>Of which Liabilities on account of EBR</i>	3.1	2.9

*EBR = अतिरिक्त बजटीय संसाधन

विषय 72: राजकोषीय घाटा और विभिन्न वित्तीय संकेतक (Fiscal deficit and different Fiscal Indicators)

मुख्य बिंदु:

1. वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा (वित्त वर्ष 2020-21 के सरकारी बजट के अनुसार) सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% था।
2. हालांकि वित्त वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा बढ़कर जीडीपी का 9.5% हो गया।
3. हम कर अनुपालन में वृद्धि के साथ-साथ परिसंपत्ति मुद्रीकरण के माध्यम से कर राजस्व में उछाल बढ़ाकर वित्त वर्ष 26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% तक लाने का लक्ष्य बना रहे हैं।

कर प्लवनशीलता क्या है (What is tax buoyancy)?

- कर प्लवनशीलता सरकार की कर राजस्व आय में परिवर्तन और सकल घरेलू उत्पाद या आर्थिक विकास में परिवर्तन के बीच संबंध की व्याख्या करता है।
- जब कोई कर में प्लवनशीलता होती है, तो कर दर में वृद्धि किए बिना सरकार के कर राजस्व में वृद्धि होती है।

विभिन्न राजकोषीय संकेतक

राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit)	सरकार द्वारा राजकोषीय घाटे को 'एक वित्तीय वर्ष के दौरान भारत की समेकित निधि (Consolidated Fund of India) में कुल प्राप्तियों (ऋण प्राप्तियों को छोड़कर) की तुलना में कुल अदायगी (ऋण पुनर्भुगतान को छोड़कर) की अधिकता' के रूप में वर्णित किया गया है। सरल शब्दों में, यह सरकार के खर्च की तुलना में उसकी आय में कमी को दर्शाता है। जिस सरकार का राजकोषीय घाटा अधिक होता है, वह अपने साधनों से ज्यादा खर्च करती है। राजकोषीय घाटा = सरकार का कुल व्यय (पूंजी और राजस्व व्यय) - उधारी को छोड़कर सरकार की कुल आय (राजस्व प्राप्तियां + ऋण की वसूली + अन्य प्राप्तियां)
राजस्व घाटा (Revenue Deficit)	यह सरकार के राजस्व बजट में प्राप्तियों से अधिक व्यय को इंगित करता है।
प्रभावी राजस्व घाटा (Effective Revenue Deficit)	यह पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए राजस्व घाटे और अनुदानों के बीच का अंतर है। प्रभावी राजस्व घाटा यह दर्शाता है कि पूंजीगत प्राप्तियों की मात्रा का उपयोग वास्तविक उपभोग व्यय के लिए किया जा रहा है। राजस्व व्यय के रूप में सरकार कुछ धनराशि पूंजीगत परिसंपत्तियां (Capital Assets) सृजित करने के लिए अनुदान के रूप में खर्च करती है। जब इस राशि को राजस्व घाटे से घटा दिया जाता है तो उसे प्रभावी राजस्व घाटा कहते हैं।
प्राथमिक घाटा (Primary deficit)	यह ब्याज भुगतानों का एक शुद्ध राजकोषीय घाटा है। यह गैर-ब्याज घाटा है और सरकार के मौजूदा वित्तीय प्रयासों को दर्शाता है। प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
मुद्रिकृत राजकोषीय घाटा (Monetized Deficit)	राजकोषीय घाटे का वह हिस्सा जो भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेकर कवर किया जाता है।

Fiscal Deficit)	
------------------------	--

Table 1. Levels of Deficit

	2019-20	2020-21	2020-21	2021-22
	Actuals	Budget Estimates	Revised Estimates	Budget Estimates
Fiscal Deficit	933651	796337	1848655	1506812
	(4.6)	(3.5)	(9.5)	(6.8)
Revenue Deficit	666545	609219	1455989	1140576
	(3.3)	(2.7)	(7.5)	(5.1)
Effective Revenue Deficit	480904	402719	1225613	921464
	(2.4)	(1.8)	(6.3)	(4.1)
Primary Deficit	321581	88134	1155755	697111
	(1.6)	(0.4)	(5.9)	(3.1)

Source: Government of India (2021), Union Budget 2021-22 documents

विषय 73: वित्तीय घाटा वित्तपोषण (Financing Fiscal Deficit)

मुख्य बिंदु:

1. घाटे का वित्तपोषण बजटीय स्थिति है जहां व्यय राजस्व से अधिक होता है।
2. यह बाहरी संसाधनों के साथ अतिरिक्त व्यय के वित्तपोषण के लिए अपनाई गई एक प्रथा है।

नोट: व्यय राजस्व अंतर को मुद्रा की छपाई या उधार के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है।

Table 2. Sources of Financing Fiscal Deficit (Rs crore)

	2019-20		2020-21		2020-21		2021-22	
	Actual	% of Total	Budget Estimates	% of Total	Revised Estimates	% of Total	Budget Estimates	% of Total
Debt Deficit (Net)								
Market Borrowings (G-Sec + T Bills)	624089	66.84	535870	67.29	1273788	68.9	967708	64.22
Securities against Small Savings	240000	25.71	240000	30.14	480574	26	391927	26.01
State Provident Funds	11635	1.25	18000	2.26	18000	0.97	20000	1.33
Other Receipts (Internal Debt and Public Account)	44273	4.74	50848	6.39	39129	2.12	54280	3.6
External Debt	8682	0.93	4622	0.58	54522	2.95	1514	0.1
Draw Down of Cash Balance	4971	0.53	(-)53003	(-)6.66	(-)17358	(-)0.94	71383	4.74
Grand Total	933651	100	796337	100	1848655	100	1506812	100

Source: Government of India (2021), Union Budget 2021-22 documents

विषय 74: सरकारी प्रतिभूति (G-Sec) और इसके प्रकार

मुख्य बिंदु:

1. G-Sec केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा जारी एक व्यापार योग्य साधन है

- चूंकि ये ऋण साधन सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, इसलिए इनसे जुड़ा जोखिम बहुत कम होता है।
- सरकारी प्रतिभूतियों में व्यावहारिक रूप से डिफॉल्ट का कोई जोखिम नहीं होता है और इसलिए ये जोखिम मुक्त गिल्ट-एज्ड सिक्योरिटीज (Gilt-edged securities) कहलाते हैं।

सरकारी प्रतिभूतियों के प्रकार:

ट्रेजरी बिल या टी-बिल्स (Treasury Bills or T-Bills)	<ul style="list-style-type: none"> टी-बिल केवल केंद्र सरकार द्वारा जारी किये जा सकते हैं। वे एक वर्ष से कम की परिपक्वता अवधि के साथ अल्पकालिक मुद्रा बाजार के साधन हैं। ट्रेजरी बिल तीन अलग-अलग परिपक्वता अवधि के साथ जारी किए जाते हैं: 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन। ट्रेजरी बिल शून्य कूपन प्रतिभूतियां हैं।
नकद प्रबंधन बिल (Cash Management Bills)	<ul style="list-style-type: none"> ये बिल जीरो कूपन सिक्योरिटीज हैं। इन प्रतिभूतियों की परिपक्वता अवधि 91 दिनों से कम होती है। इन प्रतिभूतियों का उपयोग भारत सरकार द्वारा किसी भी अस्थायी नकदी प्रवाह आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है।
दिनांकित सरकारी प्रतिभूति (G-sec)	<ul style="list-style-type: none"> ये सरकारी प्रतिभूति (G-sec) लंबी अवधि के मुद्रा बाजार के साधन हैं जिनकी परिपक्वता अवधि 5 साल से शुरू होती है और 40 साल तक चलती है। ये उपकरण एक निश्चित और साथ ही एक अस्थायी ब्याज दर के साथ आते हैं। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए लगभग 9 विभिन्न प्रकार के दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियां हैं।
राज्य विकास ऋण (State Development Loan - SDL)	<ul style="list-style-type: none"> SDL भारत की राज्य सरकारों द्वारा उनकी गतिविधियों को वित्तपोषित करने और उनकी बजटीय जरूरतों को पूरा करने के लिए जारी किए जाते हैं। ये निवेश अवधि की विस्तृत श्रृंखला के साथ दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों के समान हैं।

विषय 75: गिल्ट खाता (Gilt Account)

मुख्य बिंदु:

- गिल्ट खाता एक ऐसा खाता है जो सरकारी प्रतिभूतियों को रखने के लिए खोला और अनुरक्षित किया जा सकता है।
- रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत "अभिरक्षक" के साथ यह खाता किसी संस्था या 'भारत के बाहर निवासी व्यक्ति' सहित किसी व्यक्ति द्वारा खोला और अनुरक्षित किया जा सकता है।

नोट: भारत के बाहर निवासी व्यक्ति के लिए, खाता विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 2000 में निर्दिष्ट नियमों और विनियमों द्वारा शासित होगा।

विषय 76: सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम (Government Securities Acquisition Programme G-SAP)

मुख्य बिंदु:

1. सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम (G-SAP) के माध्यम से, आरबीआई ने वित्त वर्ष 22 की पहली तिमाही में 1 लाख करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने की योजना बनाई है।
2. हम जानते हैं कि आरबीआई समय-समय पर खुले बाजार संचालन (OMO) के माध्यम से बाजार से सरकारी बांड खरीदता है।
3. G-SAP एक तरह से 'विशिष्ट चरित्र' वाला OMO है।

G-SAP के लाभ

1. इसका उद्देश्य बांड बाजार को अधिक सुविधा प्रदान करना है।
2. यह आरामदायक तरलता के बीच यील्ड वक्र के व्यवस्थित विकास को प्रदान करेगा।
3. यह बाजार सहभागियों द्वारा सामना की जाने वाली अनुचित अस्थिरता को नियंत्रित करता है।

खुला बाजार परिचालन (Open Market Operations) के बारे में:

- खुला बाजार परिचालन (Open Market Operations) बाजार में रुपये की तरलता की स्थिति को सतत आधार पर समायोजित करने के उद्देश्य से बाजार से सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री / खरीद के माध्यम से आरबीआई द्वारा किया जाने वाला बाजार संचालन है।
- OMO का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करना है।
- जब आरबीआई को लगता है कि बाजार में अतिरिक्त तरलता है, तो वह प्रतिभूतियों की बिक्री का सहारा लेता है जिससे रुपये की तरलता खत्म हो जाती है।
- इसी तरह, जब तरलता की स्थिति तंग होती है, आरबीआई बाजार से प्रतिभूतियां खरीद सकता है, जिससे बाजार में तरलता जारी हो सकती है।
- RBI वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से OMO करता है और जनता के साथ सीधे व्यवहार नहीं करता है।
- OMO उन उपकरणों में से एक है जिसका उपयोग RBI वर्ष के माध्यम से तरलता की स्थिति को सुचारू बनाने और ब्याज दर और मुद्रास्फीति दर के स्तर पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए करता है।

विषय 77: ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (Treasury Single Account)

मुख्य बिंदु:

1. ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (TSA) को वित्त वर्ष 2018-19 से शुरू होने वाले पायलट के रूप में लागू किया गया था और इसे 2021-22 में सार्वभौमिक बनाने के लिए प्रस्तुत किया गया था।

2. एक ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (TSA) मजबूत और सरकारों के नकदी संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक आवश्यक उपकरण है, इस प्रकार उधार लेने की लागत को कम करता है।
3. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार, एक TSA सरकारी बैंक खातों की एक एकीकृत संरचना है जो सरकारी नकद संसाधनों का एक समेकित दृष्टिकोण देता है। नकदी की एकता और खजाने की एकता के सिद्धांत के आधार पर, एक TSA एक बैंक खाता या लिंक किए गए खातों का एक समूह है जिसके माध्यम से सरकार अपनी सभी प्राप्तियों और भुगतानों का लेन-देन करती है।

TSA के लाभ:

1. TSA का प्राथमिक उद्देश्य सरकारी नकदी संतुलन पर प्रभावी समग्र नियंत्रण सुनिश्चित करना है।
2. उधार लेने की लागत को कम करता है।
3. धन का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करता है।
4. व्यय की गुणवत्ता में सुधार।
5. कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा धन के जमाव को कम करता है।

विषय 78: इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर (Inverted Duty Structure)

मुख्य बिंदु:

1. यह एक ऐसी स्थिति है जहां उपयोग किए गए इनपुट पर कर की दर तैयार माल पर कर की दर से अधिक होती है।
2. कपड़े बैग की एक काल्पनिक स्थिति लें; खरीदे गए गैर-बुने कपड़े (इनपुट) पर कर की दर 12% है जबकि तैयार फैब्रिक बैग पर कर की दर 5% है। यहां चूंकि इनपुट पर कर की दर तैयार माल पर कर की दर से अधिक है, इसलिए एक उलटी कर संरचना है।

Products		GST on	
Finished Goods (Output)	Raw Materials (Input)	Finished Goods	Raw Materials
Fabric Bag	Non-Woven Fabric	5%	12%

नोट- सामान्य स्थिति यह है कि इस्तेमाल किए गए आदानों पर कर तैयार माल की कर दर से कम होता है। उल्टी शुल्क संरचना आमतौर पर सीमा शुल्क (आयात शुल्क) के मामले में प्रचलित है।

विषय 79: करेंसी मैनिपुलेशन (Currency Manipulation)

करेंसी मैनिपुलेशन (Currency Manipulation) शब्द का क्या अर्थ है?

1. यह अमेरिकी सरकार द्वारा उन देशों को दिया गया एक लेबल है जो उन्हें लगता है कि डॉलर के मुकाबले जानबूझकर अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करके "अनुचित मुद्रा प्रथाओं" में शामिल हैं।
2. इस प्रथा का अर्थ यह होगा कि विचाराधीन देश दूसरों पर अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी मुद्रा के मूल्य को कृत्रिम रूप से कम कर रहा है।
3. ऐसा इसलिए है क्योंकि अवमूल्यन से निर्यातकों को लाभ होगा क्योंकि उनकी आय में वृद्धि होगी।

उपयोग किए जाने वाले मापदंड क्या हैं?

अमेरिकी खजाना मुद्रा हेरफेर को मापने के लिए तीन बेंचमार्क का उपयोग करता है:

1. अमेरिका के साथ 20 अरब डॉलर से अधिक का द्विपक्षीय व्यापार अधिशेष।
2. सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 3% का चालू खाता अधिशेष।
3. 12 महीने की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद के 2% की विदेशी मुद्रा की शुद्ध खरीद।

भारत ने पहले और तीसरे बेंचमार्क का उल्लंघन किया। दूसरी ओर, चार तिमाही के आधार पर देश का चालू खाता अधिशेष सीमा स्तर से नीचे रहा।

नोट: मुद्रा जोड़तोड़/ हेरफेर के रूप में किसी देश का पदनाम तुरंत किसी दंड को आकर्षित नहीं करता है, लेकिन वैश्विक वित्तीय बाजारों में किसी देश के बारे में विश्वास को कम करता है।

विषय 80: निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 (Export Preparedness Index 2020)

मुख्य बिंदु:

1. द्वारा जारी: नीति आयोग और प्रतिस्पर्धा संस्थान।
2. यह भारतीय राज्यों की निर्यात तैयारियों और प्रदर्शन की जांच करने वाली पहली रिपोर्ट है।
3. उद्देश्य: चुनौतियों और अवसरों की पहचान करना; सरकारी नीतियों की प्रभावशीलता में वृद्धि; और एक सुविधाजनक नियामक ढांचे को प्रोत्साहित करना।
4. EPI की संरचना में 4 स्तंभ शामिल हैं: नीति; व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र; निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र; निर्यात प्रदर्शन।

मुख्य टेकअवे (Key Takeaways)

भारतीय राज्यों ने निर्यात विविधीकरण, परिवहन कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के उप-स्तंभों में औसत 50% की वृद्धि की।

कुल मिलाकर, अधिकांश तटीय राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले हैं।

1. शीर्ष तटीय राज्य: गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु
2. शीर्ष लैंडलॉक राज्य: राजस्थान, तेलंगाना और हरियाणा।
3. शीर्ष हिमालयी राज्य: उत्तराखंड, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश।
4. शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश: दिल्ली, गोवा और चंडीगढ़।

विषय: यील्ड कर्व्स (Yield Curves)

खबरों में क्यों?

- भारत में 10 साल के बॉन्ड पर यील्ड हाल के निचले स्तर 5.76% से बढ़कर 6.20% हो गया है।

यील्ड कर्व क्या है?

1. एक यील्ड कर्व वह ग्राफ है जो आपको ब्याज दरों के अंकन से प्राप्त होता है, जिस पर एक उधारकर्ता बाजार से विभिन्न समय अवधियों के लिए ऋण ले सकता है।
2. एक यील्ड कर्व अलग-अलग समय क्षितिज पर बॉन्ड के लिए यील्ड का चित्रात्मक प्रतिनिधित्व है। उदाहरण के लिए, भारत सरकार समय-समय पर ट्रेजरी बिलों और सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी के माध्यम से बाजार से धन उधार लेती है।

उदाहरण के लिए, भारत सरकार समय-समय पर ट्रेजरी बिलों और सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी के माध्यम से बाजार से पैसा उधार लेती है। इसके यील्ड कर्व को अंकित करने के लिए, आप इसके 91-दिन, 182-दिन और 364-दिन के ट्रेजरी बिल और इसके 10-वर्ष, 20-वर्ष और 30-वर्ष के उधार पर वर्तमान बाजार ब्याज दरों के माध्यम से एक ग्राफ बनाते हैं।

नोट: अधिकांश बाजार पर नजर रखने वाले देश की यील्ड वक्र के आकार को मापने के लिए एक साल और 10 साल के उधार के बीच के फैलाव का उपयोग करते हैं।

यील्ड कर्व महत्वपूर्ण क्यों है?

- यील्ड कर्व और ब्याज दर का व्यवहार अर्थव्यवस्था के भविष्य के स्वास्थ्य के बारे में संकेत प्रदान करता है।
- दूसरे शब्दों में, बॉन्ड यील्ड में वृद्धि का मतलब है मौद्रिक प्रणाली में ब्याज दरों में गिरावट आई है, और निवेशकों के लिए रिटर्न (जो बांड और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं) में गिरावट आई है।

विभिन्न प्रकार के यील्ड कर्व (Yield Curves)

ऊपर की ओर झुका हुआ यील्ड वक्र (Upward sloping yield curve)	<ul style="list-style-type: none"> ● बॉन्ड निवेशकों को उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था सामान्य रूप से बढ़ेगी, फिर वे लंबी अवधि के लिए उधार देने पर अधिक पुरस्कृत होने की उम्मीद करेंगे। ● यह इस बात का संकेत है कि बाजार को भविष्य में ब्याज दरों में तेजी से बढ़ोतरी की उम्मीद है।
फ्लैट यील्ड वक्र (Flat yield curve)	<ul style="list-style-type: none"> ● उपज वक्र की स्थिरता यह निर्धारित करती है कि किसी अर्थव्यवस्था के कितनी तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। ● जब अर्थव्यवस्था में केवल मामूली वृद्धि की उम्मीद की जाती है, तो यील्ड वक्र "सपाट" होता है।
'इनवर्टेड यील्ड वक्र' (Inverted yield curve)	<ul style="list-style-type: none"> ● सैद्धांतिक रूप से, एक इनवर्टेड यील्ड वक्र (inverted yield curve), जिसमें दीर्घकालिक बॉण्डों पर प्राप्ति, अल्पकालिक बॉण्डों की तुलना में कम होती है, आर्थिक मंदी की ओर संकेत करता है। ● यील्ड विपरीतता (Yield Inversion) तब होता है जब लंबी अवधि के बॉन्ड पर वक्र छोटी अवधि के बॉन्ड के वक्र से कम हो जाती है। एक वक्र विपरीतता आम तौर पर मंदी का संकेत देती है।

- एक उलटा यील्ड वक्र दर्शाता है कि निवेशकों को भविष्य में विकास में तेजी से गिरावट की उम्मीद है।





IASBABA'S

**RAPID REVISION (RaRe)
SERIES - UPSC 2021**

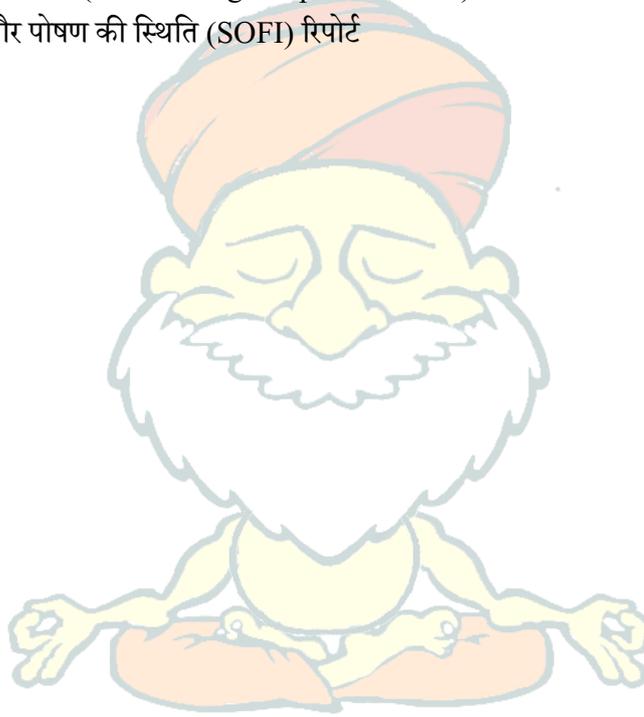
RaRe Notes Hindi

DAY II - ECONOMY

#RaRebaba
www.rrs.iasbaba.com

विषय कवरेज:

81. गरीबी (मूल बातें)
82. स्वतंत्रता के बाद गरीबी अनुमान (Post- Independence Poverty Estimation)
83. भारत में महामारी में प्रभावित गरीबी की प्रवृत्ति (Poverty trend in pandemic struck India)
84. वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (Global Multidimensional Poverty Index)
85. बहुआयामी गरीबी सूचकांक समन्वय समिति (Multidimensional Poverty Index Coordination Committee)
86. सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) भारत सूचकांक (Sustainable Development Goals (SDG) India Index 2020-21)
87. सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना सर्वेक्षण (SOCIO-ECONOMIC CASTE CENSUS SURVEY - SECC 2011)
88. ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट (Global Gender Gap Report)
89. वैश्विक वेतन रिपोर्ट 2020-21 (Global Wage Report 2020-21)
90. विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति (SOFI) रिपोर्ट



विषय 81: गरीबी (मूल बातें)**मुख्य बिंदु:**

1. गरीबी रेखा की गणना घरेलू व्यय के आधार पर की जाती है (जो गैर-खाद्य खर्चों के लिए एक छोटे से मार्जिन के साथ भोजन खरीदने की क्रय शक्ति का अनुमान लगाता है)
2. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) गरीबी रेखा को परिभाषित करने के लिए डेटा की आपूर्ति में एक अंतर्निहित कारक के रूप में उपभोग का उपयोग करता है।
3. वर्तमान गरीबी रेखा की गणना शहरी और ग्रामीण भारत में प्रति व्यक्ति क्रमशः 2,100 और 2,400 कैलोरी का उपभोग करने के लिए खर्च किए गए धन के आधार पर की जाती है।
4. विश्व बैंक की अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा (IPL) 1.90 अमेरिकी डॉलर (पीपीपी विनिमय दर) पर प्रतिदिन रहने वाले व्यक्ति के लिए है।

NSSO व्यय सर्वेक्षण के लिए डेटा संग्रहण विधि

समान संसाधन अवधि (Uniform Resource Duration - URP)	<ul style="list-style-type: none"> ● 1993-94 तक गरीबी रेखा URP के आंकड़ों पर आधारित थी। ● इसमें लोगों से 30-दिन की रिकॉल अवधि के दौरान उनके उपभोग व्यय के बारे में पूछना शामिल है।
मिश्रित संदर्भ अवधि (Mixed Reference Period -MRP)	<ul style="list-style-type: none"> ● 1999-2000 के बाद से, NSSO ने एक MRP विधि को अपनाया। ● यह पिछले वर्ष की तुलना में पांच निम्न आवृत्ति वाली वस्तुओं (कपड़े, जूते, टिकाऊ वस्तुओं, शिक्षा और संस्थागत स्वास्थ्य व्यय) और पिछले 30 दिनों में अन्य सभी मदों की खपत को मापता है।

NSSO निम्नलिखित दृष्टिकोणों पर भारत में बेरोजगारी को मापता है:

सामान्य स्थिति दृष्टिकोण (Usual Status Approach)	<ul style="list-style-type: none"> ● यह दृष्टिकोण केवल उन लोगों को बेरोजगार के रूप में अनुमान लगाता है जिनके पास सर्वेक्षण की तारीख से पहले के 365 दिनों के दौरान एक प्रमुख समय के लिए कोई लाभप्रद कार्य नहीं था।
साप्ताहिक स्थिति दृष्टिकोण (Weekly Status Approach)	<ul style="list-style-type: none"> ● यह दृष्टिकोण केवल उन लोगों को बेरोजगार के रूप में रिकॉर्ड करता है जिनके पास सर्वेक्षण की तारीख से पहले सप्ताह के किसी भी दिन एक घंटे के लिए लाभप्रद कार्य नहीं था।
दैनिक स्थिति दृष्टिकोण (Daily Status Approach)	<ul style="list-style-type: none"> ● यहां, किसी व्यक्ति की बेरोजगारी की स्थिति को एक संदर्भ सप्ताह में प्रत्येक दिन के लिए मापा जाता है। जिस व्यक्ति को दिन में 1 घंटा भी लाभकारी काम नहीं मिलता है, उसे उस दिन के लिए बेरोजगार कहा जाता है।

विषय 82: स्वतंत्रता के बाद गरीबी आकलन(Topic 82: Post- Independence Poverty Estimation)

गरीबी आकलन के लिए विभिन्न विशेषज्ञ समूहों का गठन (Various expert groups constituted for Poverty Estimation)

1. कार्य समूह (1962)
2. वी. एम. दांडेकर और एन. रथ द्वारा अध्ययन (1971)
3. डॉ. वाई. के. अलघ (1979) की अध्यक्षता में "न्यूनतम आवश्यकताओं और प्रभावी उपभोग मांग के अनुमान" पर कार्य दला
4. लकड़ावाला विशेषज्ञ समूह (1993)
5. तेंदुलकर विशेषज्ञ समूह (2009)
6. रंगराजन समिति (2014)

तेंदुलकर विशेषज्ञ समिति (2009)

- 2005 में, सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन गरीबी के आकलन के लिए कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए किया गया था।
- विशेषज्ञ समिति ने 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
- इसने नई गरीबी रेखा का निर्माण नहीं किया और 2004-05 (25.7%) की आधिकारिक रूप से मापी गई शहरी गरीबी रेखा को अपनाया। यह समिति लकड़ावाला समिति पर आधारित थी।
- लकड़ावाला समिति ने गरीबी रेखा को नए सिरे से परिभाषित किया और न्यूनतम पोषण आवश्यकताओं के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर अलग समिति द्वारा अनुशंसित अलग ग्रामीण और शहरी गरीबी रेखाओं को बनाए रखा।

तेंदुलकर विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें

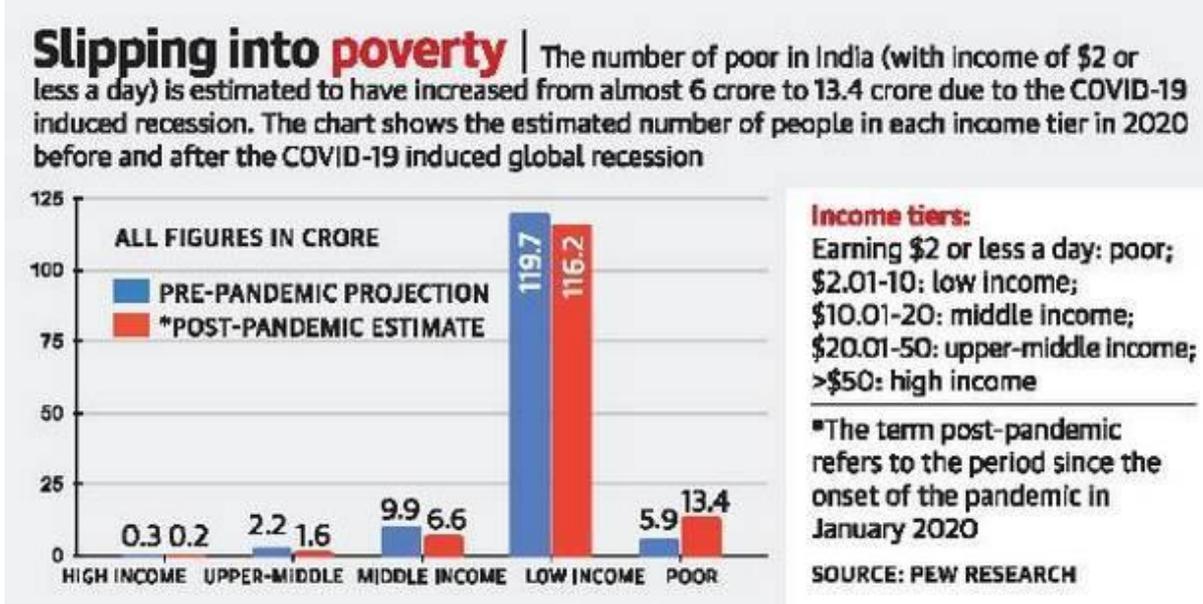
1. इसने 1979 के बाद से सभी गरीबी अनुमानों में उपयोग किए जाने वाले कैलोरी मानदंडों से गरीबी रेखा को दूर करने और इसके बजाय पोषण संबंधी परिणामों को लक्षित करने की सिफारिश की।
2. ग्रामीण और शहरी गरीबी रेखा के लिए दो अलग-अलग PLB के बजाय, इसने ग्रामीण और शहरी भारत में एक समान अखिल भारतीय शहरी PLB की सिफारिश की।
3. इसमें मिश्रित संदर्भ अवधि (Mixed Reference Period - MRP) आधारित अनुमानों का उपयोग करने की सिफारिश की गई थी, जबकि समान संदर्भ अवधि (Uniform Reference Period - URP) आधारित अनुमानों का उपयोग गरीबी के आकलन के लिए पहले के तरीकों में किया गया था।

	<ol style="list-style-type: none"> 4. इसमें गरीबी का आकलन करते हुए स्वास्थ्य और शिक्षा पर निजी खर्च को शामिल करने की सिफारिश की गई थी। 5. इसने भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य पर गरीबी रेखा के निकट प्रति व्यक्ति वास्तविक निजी उपभोग व्यय की पर्याप्तता की जाँच करके क्रमशः पोषण, शैक्षिक और स्वास्थ्य परिणामों के अनुरूप मानक व्यय के साथ तुलना करके गरीबी रेखा को मान्य किया। 6. मासिक घरेलू खपत के बजाय, उपभोग व्यय को प्रति व्यक्ति प्रति दिन की खपत में विभाजित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 32 रुपये और 26 रुपये प्रतिदिन का आंकड़ा था। 7. 2011-12 के लिए राष्ट्रीय गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 816 रुपये और शहरी क्षेत्रों के लिए 1,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह आंकी गई थी।
<p>रंगराजन समिति (2014)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● इसे 2012 में स्थापित किया गया था और इसने जून 2014 में रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग उपभोग बास्केट की सिफारिश की गयी थी, जिसमें खाद्य पदार्थ शामिल हैं जो अनुशंसित कैलोरी, प्रोटीन और वसा का सेवन और गैर-खाद्य पदार्थ जैसे कपड़े, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और परिवहन को सुनिश्चित करते हैं। ● इस समिति ने 2011-12 की कीमतों में दैनिक प्रति व्यक्ति व्यय को क्रमशः 32 रुपये और 26 रुपये से बढ़ाकर शहर के लिए 47 रुपये और ग्रामीण के लिए 32 रुपये कर दिया। ● मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रूपए और शहरी क्षेत्रों में 1407 रूपए अखिल भारतीय स्तर पर गरीबी रेखा के रूप में अनुशंसित है। ● सरकार ने रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट पर कोई फैसला नहीं लिया। ● रंगराजन समिति का अनुमान सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) द्वारा परिवारों के एक स्वतंत्र बड़े सर्वेक्षण पर आधारित है।

नोट:

- भारत ने 2011 के बाद से गरीबों की गणना नहीं की है।
- देश में गरीबों की संख्या 269.8 मिलियन या जनसंख्या का 21.9% आंकी गई थी। (2011 के अनुमान के अनुसार)
- लेकिन संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2019 में देश में गरीबों की संख्या 364 मिलियन या आबादी का 28 प्रतिशत होगी। (महामारी के कारण नए गरीबों को छोड़कर)

विषय 83: भारत में महामारी की प्रवृत्ति ने गरीबी को प्रभावित किया



मुख्य बिंदु:

1. मंदी के परिणामस्वरूप 2020 में भारत में मध्यम वर्ग के 3.2 करोड़ तक सिकुड़ने का अनुमान है।
2. मध्यम आय वर्ग वे लोग हैं जिनकी आय लगभग ₹700-1,500 या \$10-20 प्रति दिन है। भारत में गरीब लोगों की संख्या (2 डॉलर या उससे कम की आय के साथ) COVID-19 मंदी के कारण 7.5 करोड़ बढ़ने का अनुमान है।
3. भारत की अधिकांश आबादी निम्न आय वर्ग में आती है, जो प्रतिदिन लगभग ₹150 से 700 कमाते हैं। यह समूह 119.7 करोड़ से घटकर 116.2 करोड़ रह गया है। (लगभग 3.5 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे।)
4. एक दिन में ₹1,500 से अधिक कमाने वाली अमीर आबादी भी लगभग 30% गिरकर 1.8 करोड़ लोगों पर आ गई।

नोट:

विश्व बैंक के आंकड़ों का उपयोग करते हुए प्यू रिसर्च सेंटर (Pew Research Center) के अनुसार-

1. भारत में गरीबों की संख्या महज एक साल में 60 मिलियन से दोगुनी से अधिक 134 मिलियन हो गई है।
2. भारत 45 वर्षों के बाद "बड़े पैमाने पर गरीबी का देश" कहलाने की स्थिति में वापस आ गया है।

विषय 84: वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (Global Multidimensional Poverty Index)

मुख्य बिंदु:

1. यह ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल (OPHI) द्वारा जारी किया गया है।
2. इस सूचकांक के पीछे विचार विभिन्न संकेतकों का उपयोग करके विकासशील देशों में तीव्र बहुआयामी गरीबी को मापना है।
3. इसे 2010 में OPHI द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के साथ विकसित किया गया था।
4. यह UNDP की मानव विकास रिपोर्ट (HDR) का एक हिस्सा है और इसे सालाना जारी किया जाता है।

वैश्विक **MPI** के आयाम और संकेतक

तीन आयाम और 10 संकेतक हैं जिनका उपयोग करके देशों के प्रदर्शन को मापा जाता है। इनका उल्लेख नीचे किया गया है:

वैश्विक MPI के तीन आयाम	सूचक
1. स्वास्थ्य	<ul style="list-style-type: none"> ● पोषाहार ● बाल मृत्यु दर
2. शिक्षा	<ul style="list-style-type: none"> ● स्कूली शिक्षा के वर्ष ● स्कूल उपस्थिति
3. जीवन स्तर	<ul style="list-style-type: none"> ● खाना पकाने का तेल ● स्वच्छता ● पेय जल ● बिजली ● आवास ● संपत्ति

वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2020 - प्रमुख निष्कर्ष

1. MPI 2020 का विषय 'बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने के रास्ते: SDG को प्राप्त करना था।
2. ग्लोबल MPI 2020 107 देशों में भारत का 62वां स्थान रहा।
3. मूल्यांकन किए गए 107 विकासशील देशों में 5.9 बिलियन लोगों में से MPI 2020 ने 1.3 बिलियन लोगों (22% लोगों) को बहुआयामी रूप से गरीब बताया।
4. बच्चे बहुआयामी गरीबी की उच्च दर दिखाते हैं: उनमें से आधे 18 वर्ष से कम आयु के हैं।
5. बहुआयामी गरीबी वाले क्षेत्र हैं:
 - उप-सहारा अफ्रीका - 558 मिलियन MPI गरीब हैं।
 - दक्षिण एशिया - 530 मिलियन MPI गरीब हैं।
 - मध्यम आय वाले देशों में MPI गरीबों का 2/3 हिस्सा है।

यह पहली बार था कि OCHI और UNDP ने सामंजस्यपूर्ण MPI प्रवृत्तियों का पहला व्यापक अध्ययन किया, जिसे समय के साथ

परिवर्तन के रूप में भी जाना जाता है।

इस अध्ययन से पता चला कि 75 देशों में से 65 ने MPI को काफी कम कर दिया।

इस अध्ययन में गरीबी की प्रवृत्तियों में सामंजस्य के साथ 80 देशों को शामिल किया गया। भारत उनमें से एक था।

नोट:

MPI भारत के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) का उपयोग करके डेटा एकत्र करता है। भारत ने एमपीआई 2020 में 62वीं रैंक के साथ 0.123 स्कोर किया।

ग्लोबल एमपीआई 2020 में भारत का हेडकाउंट अनुपात 27.91% था।

2020 में भारत के पड़ोसियों की MPI रैंक थी:

1. श्रीलंका - 25
2. नेपाल - 65
3. बांग्लादेश - 58
4. चीन - 30
5. म्यांमार - 69
6. पाकिस्तान - 73

विषय 85: बहुआयामी गरीबी सूचकांक समन्वय समिति (Multidimensional Poverty Index Coordinating Committee - MPICC)

मुख्य बिंदु:

1. नीति आयोग ने बहुआयामी गरीबी सूचकांक समन्वय समिति (MPICC) का गठन किया है।
2. नीति आयोग ग्लोबल MPI के लिए नोडल एजेंसी है और उसे इसके लिए निगरानी तंत्र का लाभ उठाने और सुधारों को चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
3. MPICC की अध्यक्षता सुश्री संयुक्ता समदर, सलाहकार (SDG) करती हैं।
4. ग्लोबल MPI 29 चुनिंदा ग्लोबल इंडेक्स में देश के प्रदर्शन की निगरानी के लिए भारत सरकार के फैसले का हिस्सा है।

विषय 86: सतत विकास लक्ष्य (SDG) भारत सूचकांक 2020-21

मुख्य बिंदु:

1. नीति आयोग द्वारा 2018 में शुरू किया गया।
2. नीति आयोग ने 17 SDG (लक्ष्य 12, 13, 14 और 17 को छोड़कर) में से 13 SDG इंडिया इंडेक्स का निर्माण किया है।
3. SDG इंडिया इंडेक्स को भारत में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI), ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट और संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से विकसित किया गया था।
4. यह सूचकांक 62 राष्ट्रीय संकेतकों के एक सेट पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UT) की प्रगति को ट्रैक करता है।

5. SDG इंडिया इंडेक्स स्कोर 0-100 के बीच होता है, किसी राज्य/यूटी का स्कोर जितना अधिक होता है, लक्ष्य हासिल करने की उसकी दूरी उतनी ही अधिक होती है।

मुख्य निष्कर्ष:

1. भारत के समग्र SDG स्कोर में 6 अंकों का सुधार हुआ है - 2019 में 60 से 2020-21 में 66.
2. भारत ने पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 2020-21 में अपने गरीबी उन्मूलन, शून्य भूख और असमानता स्कोर में सुधार किया है।
3. केरल ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, जबकि बिहार को सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला स्थान दिया गया है।
4. दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन: हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु का रहा है।
5. बिहार के अलावा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य: झारखंड और असम हैं।
6. चंडीगढ़ ने 79 के स्कोर के साथ केंद्र शासित प्रदेशों में अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा, उसके बाद दिल्ली (68) का स्थान है।



GOAL-WISE TOP STATES/UTs

Goal 1: No Poverty
Tamil Nadu, Delhi



Goal 2: Zero Hunger
Kerala, Chandigarh

Goal 3: Good Health and Well-being
Gujarat, Delhi



Goal 4: Quality Education
Kerala, Chandigarh

Goal 5: Gender Equality
Chhattisgarh, Andaman and Nicobar Islands



Goal 6: Clean Water and Sanitation
Goa, Lakshadweep

Goal 7: Affordable and Clean Energy

Andhra Pradesh, Goa, Haryana, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Mizoram, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Telangana, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Delhi, Jammu and Kashmir, Ladakh



Goal 8: Decent Work and Economic Growth
Himachal Pradesh, Chandigarh

Goal 9: Industry, Innovation and Infrastructure
Gujarat, Delhi



Goal 10: Reduced Inequality
Meghalaya, Chandigarh

Goal 11: Sustainable Cities and Communities
Punjab, Chandigarh



Goal 12: Responsible Consumption and Production
Tripura, Jammu and Kashmir, Ladakh

Goal 13: Climate Action
Odisha, Andaman and Nicobar Islands



Goal 14: Life Below Water
Odisha

Goal 15: Life on Land
Arunachal Pradesh, Chandigarh



Goal 16: Peace, Justice and Strong Institutions
Uttarakhand, Puducherry



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

17 GOALS TO TRANSFORM OUR WORLD



विषय 87: सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना सर्वेक्षण (SECC) 2011

मुख्य बिंदु:

1. बीपीएल परिवारों की पहचान की एक नई पद्धति का प्रस्ताव देने के लिए डॉ. एन. सी. सक्सेना विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था।
2. समिति ने परिवारों के तीन गुना वर्गीकरण को "बहिष्कृत", "स्वचालित रूप से शामिल" और "अन्य" में प्रस्तावित किया।
3. सक्सेना समिति की सिफारिशों के आधार पर, 2011 में, MoRD ने सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) शुरू की।
4. सुमित बोस समिति (2017) ने केंद्र प्रायोजित, केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं के लिए लाभार्थियों की पहचान हेतु SECC 2011 के आंकड़ों का उपयोग करने की सिफारिश की।

नोट:

1. SECC का उद्देश्य गरीबी रेखा को प्रतिस्थापित करना नहीं था, बल्कि विभिन्न जातियों और जनसंख्या के वर्गों की सामाजिक आर्थिक स्थिति और शिक्षा की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करना और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान करने के लिए परिवारों को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में स्थान देने में सक्षम बनाना था।
2. SECC 2011 की जनगणना जून 2011 में शुरू हुई थी और मार्च 2016 में पूरी हुई।
3. SECC 2011 ने जनगणना-2011 के आंकड़ों को अपने मूल डेटा के रूप में इस्तेमाल किया।
4. SECC 2011 भारत में 640 जिलों में सरकार द्वारा हाथ से पकड़े गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर आयोजित पहली पेपरलेस जनगणना भी थी।

5. BPL जनगणनाओं के विपरीत, SECC-2011 पहली बार गरीबी की बहु-आयामीता पर ध्यान केंद्रित करते हुए परिवारों के अभाव को ट्रैक करने और अंतराल को प्रभावी ढंग से संबोधित करने की अनुमति देता है।

SECC 2011 तीन श्रेणियों में परिवारों को स्थान दिया:

1. स्वचालित रूप से बहिष्कृत: बहिष्करण मानदंडों को पूरा करने वाले परिवार - 13 संपत्ति और आय आधारित मापदंडों में से किसी को भी पूरा करने पर स्वचालित रूप से कल्याणकारी लाभों से बाहर हो जाते हैं;
2. स्वचालित रूप से शामिल: समावेशन मानदंडों को पूरा करने वाले परिवार - कल्याणकारी लाभों के लिए 5 तीव्र सामाजिक अभाव मानकों में से किसी में भी आने पर स्वचालित रूप से शामिल हो जाते हैं;
3. अन्य: "अन्य" को अभाव के 7 संकेतकों के आधार पर स्थान दिया गया है और संसाधनों की अनुमति, कल्याणकारी लाभों के लिए पात्र होंगे।

SECC 2011 में तीन जनगणना घटक हैं जो तीन अलग-अलग प्राधिकरणों द्वारा संचालित किए गए थे, लेकिन भारत सरकार में ग्रामीण विकास विभाग के समग्र समन्वय के तहत:

1. ग्रामीण क्षेत्रों में जनगणना ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयोजित की गई।
2. शहरी क्षेत्रों में जनगणना आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में है।
3. जाति जनगणना गृह मंत्रालय के प्रशासनिक: भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के नियंत्रण में है।

SECC 2011 में 17.97 करोड़ ग्रामीण परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर आंकड़ों को प्राप्त किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 7.07 करोड़ (39.36%) परिवार गरीब नहीं हैं, स्वचालित रूप से 0.16 करोड़ (0.91%) परिवारों को सबसे गरीब के रूप में शामिल किया गया है। और ग्रामीण परिवारों के 8.72 करोड़ (48.54%) वंचितों की श्रेणी को निर्धारित किया गया।

विषय 88: ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट (Global Gender Gap Report)

मुख्य बिंदु:

1. ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 हाल ही में जारी की गई थी।
2. इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया।



मुख्य निष्कर्ष (Key Takeaway)

1. भारत 28 स्थानों तक नीचे गिर गया है।
2. अब भारत दक्षिण एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में से एक है।
3. भारत पड़ोसी देशों - बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार से नीचे स्थान पर है।
4. भारत की रैंक: 156 देशों में 140 है।
5. दक्षिण एशिया संयोग से सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों में से एक है, जिसके बाद केवल मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका है।
6. कुल मिलाकर, कई देशों ने आर्थिक प्रदर्शन के कारण पिछले साल की तुलना में इस साल की रैंकिंग में खराब प्रदर्शन किया है।
7. अपने वर्तमान प्रक्षेपवक्र पर, दुनिया भर में लिंग अंतर को पाटने में अब इसे 135.6 वर्ष लगेंगे।

विषय 89: वैश्विक मजदूरी रिपोर्ट 2020-21

मुख्य बिंदु:

वैश्विक मजदूरी रिपोर्ट 2020-21: 'COVID-19 के समय में मजदूरी और न्यूनतम मजदूरी' हाल ही में जारी की गई। 2020-21 संस्करण न्यूनतम मजदूरी और असमानता के संबंधों के साथ-साथ COVID-19 संकट के मजदूरी प्रभावों का विश्लेषण करता है।

मुख्य निष्कर्ष (Key takeaway)

1. इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी किया जाता है।
2. रिपोर्ट में कम औसत वेतन, लंबे समय तक मजदूरी करने वाले भारतीय कामगारों सहित विभिन्न मुद्दों पर टिप्पणी की गई है।
3. इसमें यह भी बताया गया है कि एशिया और प्रशांत क्षेत्र में कामगारों ने 2006-19 की अवधि में सभी क्षेत्रों के बीच उच्चतम वास्तविक वेतन वृद्धि का आनंद लिया।
4. रिपोर्ट में राष्ट्रीय स्तर की न्यूनतम मजदूरी को ध्यान में रखा गया है जो 176 रुपये प्रतिदिन है। (हालांकि, वास्तविक मजदूरी कहीं अधिक है)
5. यदि विभिन्न राज्यों में न्यूनतम मजदूरी का औसत निकाला जाता है, तो यह भारत में 269 रुपये प्रतिदिन होगा।

6. रिपोर्ट से पता चलता है कि सभी श्रमिक इस संकट से समान रूप से प्रभावित नहीं हुए हैं। महिलाओं पर इसका प्रभाव पुरुषों की तुलना में अधिक खराब रहा है।

विषय 90: विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति (SOFI) रिपोर्ट

मुख्य बिंदु:

1. यह FAO, IFAD, UNICEF, WFP और WHO द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई एक वार्षिक प्रमुख रिपोर्ट है।
2. SOFI रिपोर्ट प्रमुख SDG लक्ष्यों और भूख को समाप्त करने, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने और पोषण में सुधार की दिशा में प्रगति पर गहन विश्लेषण प्रदान करती है।

नोट:

2017 के बाद से, SOFI खाद्य असुरक्षा के दो प्रमुख उपाय प्रस्तुत करता है:

1. अल्पपोषण की व्यापकता (PoU) नामक पारंपरिक उपाय और
2. मध्यम और गंभीर खाद्य असुरक्षा की व्यापकता (PMSFI) नामक एक नया उपाय

जबकि PoU कैलोरी की पुरानी कमी का सामना कर रही आबादी के अनुपात का अनुमान लगाने पर केंद्रित है, PMSFI पर्याप्त और पौष्टिक भोजन तक पहुंच की कमी का एक अधिक व्यापक उपाय है।

मुख्य निष्कर्ष:

- COVID-19 से उत्पन्न आर्थिक मंदी के कारण इस वर्ष विश्व स्तर पर 8.3 करोड़ से 13 करोड़ लोगों के भूखे रहने की संभावना है।
- 2014 के बाद से भूख में वृद्धि जारी है और कुपोषण का वैश्विक प्रसार, या भूखे लोगों का कुल प्रतिशत 8.9% है।
- एशिया सबसे अधिक कुपोषितों (38 करोड़) का घर बना हुआ है। अफ्रीका दूसरे (25 करोड़) स्थान पर है, उसके बाद लैटिन अमेरिका और कैरेबियन (4.8 करोड़) हैं।
- वर्तमान अनुमानों के अनुसार, 2019 में, 5 साल से कम उम्र के 21.3% (14.4 करोड़) बच्चे बौने, 6.9% (4.7 करोड़) वेस्टेड और 5.6% (3.8 मिलियन) अधिक वजन वाले थे।
- रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि एक स्वस्थ आहार की लागत ₹143 (या \$ 1.90/दिन) से अधिक है, जो अंतरराष्ट्रीय गरीबी की सीमा है।
- विश्व स्तर पर ऐसे लोगों की संख्या जो स्वस्थ आहार का खर्च नहीं उठा सकते हैं, उनकी संख्या 300 करोड़ है, या चीन और भारत की संयुक्त जनसंख्या से अधिक है।



IASBABA'S

**RAPID REVISION (RaRe)
SERIES - UPSC 2021**

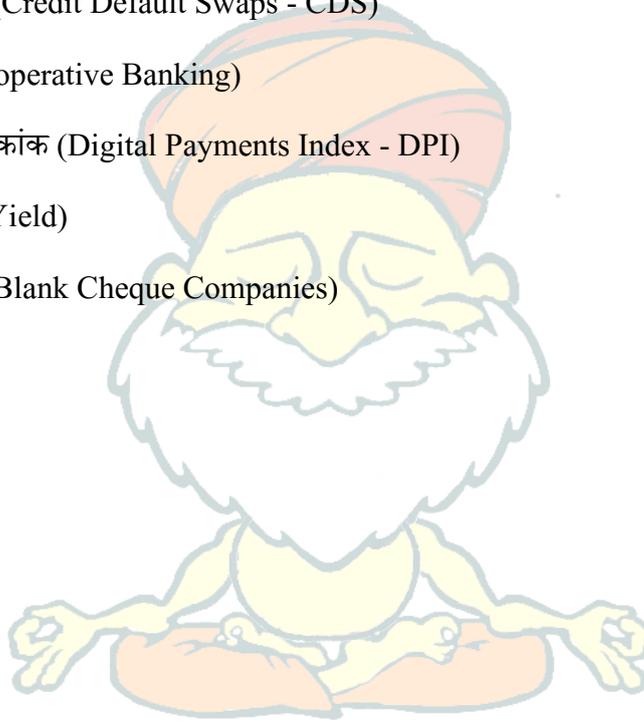
RaRe Notes Hindi

DAY 24 - ECONOMY

#RaRebaba
www.rrs.iasbaba.com

विषय

171. सुदर्शन सेन समिति (Sudarshan Sen Committee)
172. बैड बैंक (Bad Bank)
173. स्टेन्स ऑफ़ आरबीआई/ आरबीआई का रुख (Stances of RBI)
174. आरबीआई के संशोधित प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण दिशानिर्देश (RBI's revised priority sector lending guidelines)
175. लक्षित दीर्घकालिक रेपो संचालन (Targeted Long Term Repo Operations)
176. क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप (Credit Default Swaps - CDS)
177. सहकारी बैंकिंग (Co-operative Banking)
178. डिजिटल भुगतान सूचकांक (Digital Payments Index - DPI)
179. बॉन्ड यील्ड (Bond Yield)
180. ब्लैंक चेक कंपनियां (Blank Cheque Companies)



171. सुदर्शन सेन समिति (Sudarshan Sen Committee)



Sudarshan Sen Committee

In News: Reserve Bank of India recently set up a committee to study about the Asset Reconstruction Companies (ARC) in the country.

Terms of reference:

Legal and regulatory framework applicable to ARCs

Role of ARCs under the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC)

To review the business models of ARCs.

Issue:

The regulatory guidelines for ARC were given by SARFAESI Act the was enacted way back in 2002.

New provisions of IBC like – Insolvency Professionals, Insolvency professional Agency, etc. are incompatible.

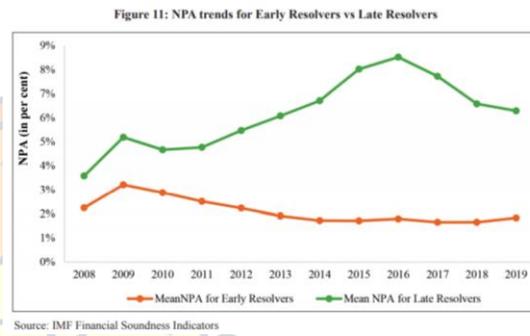
RBI has rejected several reconstructions proposals made by ARCs. Ex: UV ARC Limited's resolution plan for Aircel.

संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (ARC) के बारे में;

- यह एक विशेष वित्तीय संस्थान है जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों से गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) को खरीदता है ताकि वे अपनी बैलेंस शीट को साफ कर सकें।
- इससे बैंकों को सामान्य बैंकिंग गतिविधियों में ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है।
- बैंक अपना समय और प्रयास बर्बाद करके बकाएदारों के पीछे जाने के बजाय, खराब संपत्ति को पारस्परिक रूप से सहमत मूल्य पर ARC को बेच सकते हैं।

- प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित का प्रवर्तन (SARFAESI) अधिनियम, 2002 भारत में ARC की स्थापना के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है।
- SARFAESI अधिनियम अदालतों के हस्तक्षेप के बिना खराब संपत्तियों के पुनर्निर्माण में मदद करता है।
- SARFAESI अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, ARC के पास न्यूनतम शुद्ध स्वामित्व वाली रु. 100 करोड़ निधि और अपनी जोखिम भारित संपत्ति के 15% का पूंजी पर्याप्तता अनुपात होना चाहिए।

172. बैड बैंक (Bad Bank)



- एक बैड बैंक एक वित्तीय इकाई है जिसे बैंकों से गैर-निष्पादित संपत्ति (NPA), या बुरे ऋण खरीदने के लिए स्थापित किया गया है।
- एक बैड बैंक की स्थापना का उद्देश्य बैंकों की बैलेंस शीट से बैड लोन को हटाकर उनके बोझ को कम करने में मदद करना है और उन्हें बिना किसी बाधा के ग्राहकों को फिर से उधार उपलब्ध करना है।
- बैंक से बुरे ऋण की खरीद के बाद, बैड बैंक बाद में एनपीए को पुनर्गठित करने और उन निवेशकों को बेचने का प्रयास कर सकता है जो इसे खरीदने में रुचि रखते हैं।
- एक बैड बैंक अपने परिचालन में लाभ कमाता है यदि वह एक वाणिज्यिक बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए भुगतान की तुलना में अधिक कीमत पर ऋण बेचने का प्रबंधन करता है।
- हालांकि, मुनाफा कमाना आमतौर पर एक बैड बैंक का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है - इसका उद्देश्य बैंकों पर बोझ को कम करना है, जिसमें तनावग्रस्त संपत्तियों का एक बड़ा ढेर है, और उन्हें अधिक सक्रिय रूप से उधार देना है।

	On-balance-sheet guarantee	<ul style="list-style-type: none"> Here, the bank uses some mechanism (typically a government guarantee) to protect part of its portfolio against losses. While simple to implement, this situation is difficult for investors to assess.
	Internal restructuring	<ul style="list-style-type: none"> In this, the bank creates a separate unit to hold the bad assets. This solution is more transparent, but does not isolate the bank from risk.
	Special purpose entity (SPE)	<ul style="list-style-type: none"> Here, the bank transfers its bad assets to another organization, typically government backed. This solution requires significant government participation.
	Bad bank spinoff	<ul style="list-style-type: none"> The bank creates a new, independent bank to hold the bad assets. This completely isolates the original bank from the risky assets.

	बैड बैंक के लाभ	<ul style="list-style-type: none"> यह एक विशेष इकाई के तहत बैंकों के सभी बुरे ऋणों को समेकित करने में मदद कर सकता है। यह पूंजी मुक्त करके बैंकों के पूंजी बफर में सुधार कर सकता है। इससे बैंकों को फिर से ऋण देना शुरू करने में अधिक आत्मविश्वास महसूस हो सकता है। यह सरकार को उन बैंकों को पुनर्पूजीकरण करने की आवश्यकता को कम करता है जो उच्च एनपीए से पीड़ित हैं।
	बैड बैंड की चिंताएं	<ul style="list-style-type: none"> सरकार द्वारा समर्थित एक बैड बैंक तनावग्रस्त संपत्ति के लिए बहुत अधिक भुगतान करने की संभावना है। बैड बैंक के माध्यम से बैंकों को बाहर निकालने से वास्तव में बैड लोन संकट की मूल समस्या का समाधान नहीं होता है। एक बैड बैंक द्वारा प्रदान किया गया सुरक्षा जाल इन बैंकों को लापरवाही से उधार देने के लिए और अधिक कारण देता है, और इस प्रकार, खराब ऋण संकट को और बढ़ा देता है।

173. स्टैंस ऑफ आरबीआई/ आरबीआई का रुख (Stances of RBI)

	उदार रुख (Accommodative stance)	<ul style="list-style-type: none"> इसका मतलब है कि आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने के लिए नीतिगत दरों को कम कर सकता है।

	<ul style="list-style-type: none"> ● नीतिगत दरें सामान्य रूप से घटती हैं (वही भी रह सकती हैं)। ● अर्थव्यवस्था में मंदी आने पर यह नीति अपनाई जाती है।
तटस्थ रुख (Neutral stance)	<ul style="list-style-type: none"> ● इसका मतलब है कि आरबीआई के पास व्यापक आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए नीतिगत दरों को बढ़ाने या घटाने का लचीलापन होगा। ● नीतिगत दरें किसी भी दिशा में आगे बढ़ेंगी। ● मुद्रास्फीति की दर स्थिर होने पर यह नीति अपनाई जाती है।
कैलिब्रेटेड टाइटनिंग स्टेन्स/ जानबूझकर कठोर रुख (Calibrated Tightening stance)	<ul style="list-style-type: none"> ● इसका मतलब है कि आरबीआई या तो दरों को स्थिर रखेगा या दरों में वृद्धि करेगा। ● नीतिगत दरें या तो अपरिवर्तित रहती हैं या बढ़ जाती हैं। ● यह नीति मुद्रास्फीति की उच्च दर के दौरान अपनाई जाती है।
हॉकिश मौद्रिक नीति स्टेन्स (Hawkish Monetary Policy Stance)	<ul style="list-style-type: none"> ● मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए, हॉकिश (Hawkish) रुख उच्च ब्याज दरों का पक्षधर है। ● उच्च ब्याज दरों के कारण, उधार लेना (बैंकों से ऋण लेना) कम आकर्षक हो जाएगा।
तटस्थ मौद्रिक नीति स्टेन्स (Neutral Monetary Policy Stance)	<ul style="list-style-type: none"> ● इस मौद्रिक नीति रुख में कम ब्याज दरें शामिल हैं। ● कम ब्याज दरें उपभोक्ताओं को बैंकों और अन्य स्रोतों से ऋण (ऋण) लेने के लिए आकर्षित करेंगी।

174. आरबीआई के संशोधित प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण दिशानिर्देश (RBI's revised priority sector lending guidelines)

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के बारे में;

- आरबीआई बैंकों को अपने फंड का एक निश्चित हिस्सा निर्दिष्ट क्षेत्रों, जैसे कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई), निर्यात ऋण, शिक्षा, आवास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा को उधार देने के लिए अनिवार्य किया है।
- सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और विदेशी बैंकों (भारत में एक बड़ी उपस्थिति के साथ) को इन क्षेत्रों को उधार देने के लिए अपने समायोजित नेट बैंक क्रेडिट (ANDC) का 40% अलग रखना अनिवार्य है।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और लघु वित्त बैंकों को ANDC का 75% PSL को आवंटित करना है।
- इसके पीछे विचार यह सुनिश्चित करना है कि पर्याप्त संस्थागत ऋण अर्थव्यवस्था के कुछ कमजोर क्षेत्रों तक पहुंचे, जो अन्यथा लाभप्रदता के दृष्टिकोण से बैंकों के लिए आकर्षक नहीं हो सकते हैं।

संशोधित दिशानिर्देश

ताजा श्रेणियाँ	<p>निम्नलिखित श्रेणियां अब प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत वित्त के लिए पात्र हैं</p> <ul style="list-style-type: none"> ● स्टार्ट-अप को बैंक वित्त रु. 50 करोड़। ● ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सौरकरण के लिए सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए किसानों को ऋण। ● संपीडित बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए ऋण।
किसानों से संबंधित	<ul style="list-style-type: none"> ● किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के लिए उच्च ऋण सीमा निर्दिष्ट की गई है, लेकिन प्रति उधार लेने वाली इकाई 2 करोड़ रुपये की कुल सीमा के अधीन है। ● छोटे और सीमांत किसानों और कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित लक्ष्यों को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा। ● इसने एक हेक्टेयर तक की भूमि वाले किसानों को सीमांत किसानों के रूप में और 1 से 2 हेक्टेयर के बीच की भूमि वाले किसानों को छोटे किसानों के रूप में परिभाषित किया है।
नवीकरणीय ऊर्जा	<ul style="list-style-type: none"> ● सौर-आधारित और बायोमास-आधारित बिजली जनरेटर, पवन चक्कियों, गैर-पारंपरिक ऊर्जा-आधारित सार्वजनिक उपयोगिताओं आदि जैसे उद्देश्यों के लिए उधारकर्ताओं को 30 करोड़ रुपये की सीमा तक बैंक ऋण और व्यक्तिगत घरों के लिए, प्रति उधारकर्ता 10 लाख रुपये की ऋण सीमा होगी।
स्वास्थ्य देखभाल	<ul style="list-style-type: none"> ● टियर II से टियर VI केंद्रों में 'आयुष्मान भारत' के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रति उधारकर्ता 10 करोड़ रुपये की सीमा तक बैंक ऋण की अनुमति दी गई है।
असमानता को संबोधित करता है।	<ul style="list-style-type: none"> ● यह जिला स्तर पर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के प्रवाह में क्षेत्रीय असमानताओं से संबंधित मुद्दों को संबोधित करना चाहता है जिसमें शामिल हैं: <ul style="list-style-type: none"> ● प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में प्रति व्यक्ति ऋण प्रवाह के आधार पर जिलों की रैंकिंग। ● तुलनात्मक रूप से कम ऋण प्रवाह वाले जिलों के लिए प्रोत्साहन ढांचे का निर्माण करना और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के तुलनात्मक रूप से उच्च प्रवाह वाले जिलों के लिए एक प्रोत्साहन ढांचा तैयार करना। ● तुलनात्मक रूप से कम ऋण प्रवाह वाले जिलों के लिए प्रोत्साहन ढांचा तैयार करना और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के तुलनात्मक रूप से उच्च प्रवाह वाले जिलों के लिए एक विघटनकारी ढांचा तैयार करना। ● प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के ऋण को 'चिन्हित जिलों' में अधिक महत्व दिया गया है जहां प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र का ऋण प्रवाह तुलनात्मक रूप से कम है।

175. लक्षित दीर्घकालिक रेपो संचालन (Targeted Long Term Repo Operations)

- रेपो दर वह दर है जिस पर बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं। आम तौर पर, ये ऋण 3-28 दिनों से छोटी अवधि के लिए होते हैं।
 - उच्च परिपक्वता अवधि वाले ऋण (जैसे 1 वर्ष और 3 वर्ष) में अल्पावधि (रेपो) ऋणों की तुलना में अधिक ब्याज दर होगी।
- LTRO एक ऐसा उपकरण है जिसके तहत RBI, सरकारी प्रतिभूतियों को संपार्श्विक के रूप में स्वीकार करते हुए, प्रचलित रेपो दर पर बैंकों को एक साल से तीन साल का पैसा प्रदान करता है।
- इसे 'लक्षित' LTRO कहा जाता है यदि केंद्रीय बैंक चाहता है कि इस विकल्प के तहत धन का चयन करने वाले बैंक विशेष रूप से निवेश-ग्रेड कॉर्पोरेट ऋण में निवेश करें।

LTRO के संभावित प्रभाव

- LTRO संचालन का उद्देश्य बाजार में अल्पकालिक ब्याज दरों को नीति दर (यानी रेपो दर) से बहुत दूर जाने से रोकना है।
- LTRO/TLTRO बैंकिंग प्रणाली में तरलता को बढ़ाएगा।
- चूंकि ब्याज दर तुलनात्मक रूप से कम है, इसलिए अल्पावधि उधार दरों पर नीचे की ओर दबाव होगा।
- इसका परिणाम थोड़ा आसान मौद्रिक नीति होगा।
- LTRO बांड बाजार में छोटी अवधि की प्रतिभूतियों (1-3 साल की अवधि में) के प्रतिफल को कम करने में भी मदद करेगा।

क्या आप जानते हैं?

- LTRO को पहली बार यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) द्वारा 2008 में शुरू हुए अपने संप्रभु ऋण संकट के दौरान पेश किया गया था।
- LTRO शब्द ECB द्वारा गढ़ा गया था जो "दीर्घकालिक पुनर्वित्त संचालन"के लिए था।

Feature	LTRO	Term Repo
Interest rate	Fixed and at repo rate	Variable, depending upon auctions but higher than repo rate.
Term structure	1 year or 3 year	3 to 28 days
Individual bank's bid size	No restriction on the maximum amount of bidding by individual bidders.	0.75% of the banks' NDTL.
Disbursal	Auction (e-Kuber)	Auction (e-Kuber)
Applicants	Scheduled commercial banks	Scheduled commercial banks
Collateral	Same as under LAF	Same as under LAF
Total fund injections	Limit to be determined by the RBI	Limit to be determined by the RBI

176. क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप (Credit Default Swaps - CDS)

संदर्भ: आरबीआई ने ओवर-द-काउंटर (OTC) बाजारों में और देश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप (CDS) में डेरिवेटिव ट्रेडिंग (Derivatives trading) की अनुमति देने के लिए ड्राफ्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं।

- CDS क्रेडिट व्युत्पन्न अनुबंध को संदर्भित करता है जिसमें CDS विक्रेता खरीदार को एक क्रेडिट घटना (उधारकर्ताओं द्वारा ऋण पर डिफॉल्ट) के परिणामस्वरूप एक अंतर्निहित ऋण साधन (ऋण) के मूल्य में नुकसान की भरपाई करने के लिए प्रतिबद्ध करता है।
- बदले में, प्रतिभूति खरीदार अनुबंध की परिपक्वता या क्रेडिट इवेंट, जो भी पहले हो, तक CDS विक्रेता को आवधिक भुगतान (प्रीमियम) करता है।
- यह एक व्युत्पन्न या अनुबंध है जो निवेशक को किसी अन्य निवेशक के साथ अपने क्रेडिट जोखिम को स्वैप या ऑफसेट करने की अनुमति देता है।

CDS के संबंध में आरबीआई द्वारा प्रमुख दिशानिर्देश

- दिशानिर्देशों के अनुसार, गैर-खुदरा उपयोगकर्ताओं को हेजिंग के साथ-साथ अन्य उद्देश्यों के लिए क्रेडिट डेरिवेटिव में लेनदेन करने की अनुमति दी जाएगी।
- जो व्यक्ति भारत में निवासी है या अनिवासी है, वह बाजार में भाग ले सकता है।
- दिशानिर्देश के अनुसार, एक्सचेंज गारंटीकृत नकद निपटान को निर्दिष्ट करके मानकीकृत एकल-नाम सीडीएस अनुबंध प्रदान कर सकते हैं।
- वाणिज्यिक पत्र, सूचीबद्ध या असूचीबद्ध रेटेड रुपया कॉरपोरेट बॉन्ड, विशेष प्रयोजन वाहनों द्वारा जारी किए गए अनरेटेड बॉन्ड, जमा प्रमाणपत्र और 1 वर्ष तक की परिपक्वता के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर CDS अनुबंध में एक संदर्भ या वितरण योग्य दायित्व होने के पात्र हैं।

177. सहकारी बैंकिंग (Co-operative Banking)

समाचार: RBI विभिन्न शर्तों के अधीन जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) को राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) के साथ मिलाने पर विचार करेगा, जिसमें संबंधित राज्य सरकार द्वारा एक प्रस्ताव भी शामिल है।

भारत में ग्रामीण सहकारी ऋण प्रणाली मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है।

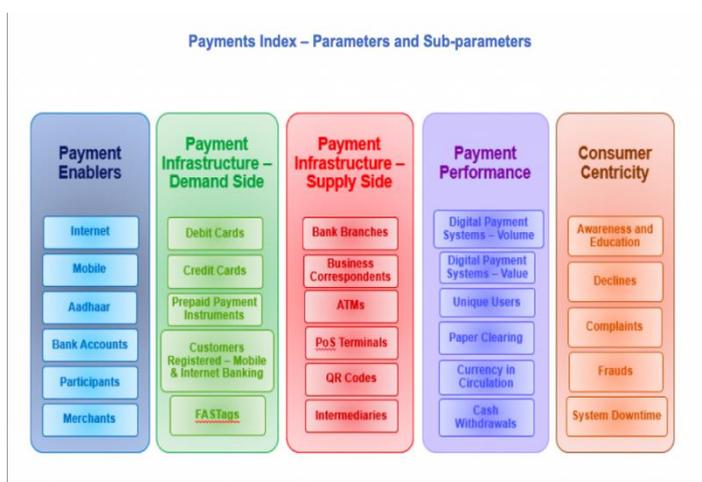
- इसमें अल्पकालिक और दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचनाएं शामिल हैं।
- अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना त्रि-स्तरीय प्रणाली के साथ संचालित होती है -
 - ग्राम स्तर पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS)
 - जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक (CCB)
 - राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक (STCB)
- PACS बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के दायरे से बाहर हैं और इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित नहीं हैं।

- StCBs/DCCBs संबंधित राज्य के राज्य सहकारी समिति अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजीकृत हैं और रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित हैं।
- राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंकों का निरीक्षण करने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम (सहकारी समितियों के लिए लागू) की धारा 35 ए के तहत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को अधिकार सौंपे गए हैं।

प्राथमिक सहकारी बैंक (PCBs), जिन्हें शहरी सहकारी बैंक (UCBs) भी कहा जाता है, शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में ग्राहकों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करते हैं।

- शहरी सहकारी बैंक मुख्य रूप से संबंधित राज्य के राज्य सहकारी समिति अधिनियम या बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत हैं यदि बैंक के संचालन का क्षेत्र एक राज्य की सीमाओं से बाहर है।
- यह क्षेत्र बैंकों के असमान भौगोलिक प्रसार के साथ चरित्र में विषम है। जबकि उनमें से कई बिना किसी शाखा नेटवर्क के इकाई बैंक हैं, उनमें से कुछ आकार में बड़े हैं और एक से अधिक राज्यों में काम करते हैं।
- हालांकि बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में लागू हुआ था, लेकिन बैंकिंग कानून केवल 1966 में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन के माध्यम से सहकारी समितियों पर लागू किए गए थे।
- तब से इन बैंकों पर नियंत्रण का द्वंद्व है जिसमें बैंकिंग संबंधी कार्य रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किए जाते हैं और प्रबंधन संबंधी कार्यों को संबंधित राज्य सरकारों/केंद्र सरकार द्वारा विनियमित किया जाता है।
 - रिजर्व बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 22 की धारा 23 और 1949 के प्रावधानों के तहत StCBs/DCCBs/शहरी सहकारी बैंकों के बैंकिंग कार्यों को नियंत्रित करता है (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू होता है)।
 - राज्यों का सहकारी बैंक विनियमन विभाग (DCBR) राज्य सहकारी बैंकों (StCBs), जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) और शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को नियंत्रित करता है।

178. डिजिटल भुगतान सूचकांक (Digital Payments Index - DPI)



- आरबीआई ने देश भर में भुगतानों के डिजिटलीकरण की सीमा को देखने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक (DPI) का निर्माण किया है।
- आरबीआई-डीपीआई में पांच व्यापक पैरामीटर शामिल हैं
 - भुगतान समर्थक (Payment Enablers) (भारत 25%),
 - भुगतान अवसंरचना-मांग-पक्ष कारक और (10%)
 - भुगतान अवसंरचना-आपूर्ति-पक्ष कारक (15%)
 - भुगतान प्रदर्शन (45%)
 - उपभोक्ता केंद्रीयता (5%)
- ये पैरामीटर विभिन्न समय अवधि में देश में डिजिटल भुगतान के गहन और विस्तार के माप को सक्षम करते हैं।
- आरबीआई-डीपीआई का निर्माण मार्च 2018 से आधार अवधि के रूप में किया गया है।
- आरबीआई-डीपीआई को मार्च 2021 से 4 महीने के अंतराल के साथ अर्ध-वार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाएगा।

179. बॉन्ड यील्ड (Bond Yield)



- बॉन्ड यील्ड वह रिटर्न है जो एक निवेशक को बॉन्ड पर मिलता है।
- यील्ड की गणना के लिए गणितीय सूत्र वार्षिक कूपन दर को बांड के मौजूदा बाजार मूल्य से विभाजित किया जाता है
 - बॉन्ड: पैसे उधार लेने का एक साधन है। एक बांड किसी देश की सरकार या किसी कंपनी द्वारा धन जुटाने के लिए जारी किया जा सकता है।
 - कूपन दर: यह बांड के अंकित मूल्य पर बांड जारीकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली ब्याज की दर है।
- प्रतिफल को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति, विशेष रूप से ब्याज दरों के प्रभाव, सरकार की वित्तीय स्थिति और उसके उधार कार्यक्रम, वैश्विक बाजार, अर्थव्यवस्था और मुद्रास्फीति हैं।
- ब्याज दरों में गिरावट से बॉन्ड की कीमतें बढ़ती हैं, और बॉन्ड यील्ड गिरती है - और बढ़ती ब्याज दरें बॉन्ड की कीमतों में गिरावट का कारण बनती हैं, और बॉन्ड यील्ड में वृद्धि होती है।

इक्विटी बाजारों के साथ संबंध	<ul style="list-style-type: none"> ● बॉन्ड यील्ड इक्विटी रिटर्न के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं; जब बॉन्ड यील्ड में गिरावट आती है, तो इक्विटी मार्केट का प्रदर्शन बेहतर होता है, और जब यील्ड बढ़ती है, तो इक्विटी मार्केट का रिटर्न लड़खड़ाने लगता है। ● परंपरागत रूप से, जब बॉन्ड यील्ड बढ़ जाती है, तो निवेशक इक्विटी से दूर और बॉन्ड में निवेश को फिर से शुरू करते हैं, क्योंकि वे अधिक सुरक्षित होते हैं। ● जैसे-जैसे बॉन्ड की यील्ड बढ़ती है, इक्विटी में निवेश की अवसर लागत बढ़ती जाती है, और इक्विटी कम आकर्षक हो जाती है।
पूंजी की लागत	<ul style="list-style-type: none"> ● बॉन्ड यील्ड में वृद्धि से कंपनियों के लिए पूंजी की लागत बढ़ जाती है, जो बदले में उनके शेयरों के मूल्यांकन को संकुचित करती है। ● यह कुछ ऐसा है जिसे निवेशक तब देखते हैं जब आरबीआई रेपो रेट में कटौती करता है या बढ़ाता है। रेपो दर में कटौती से कंपनियों के लिए उधार लेने की लागत कम हो जाती है, जिससे शेयर की कीमतों में वृद्धि होती है, और इसके विपरीत स्थिति में इसका विपरीत होता है।
विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) प्रवाह	<ul style="list-style-type: none"> ● बॉन्ड यील्ड FPI प्रवाह में बड़ी भूमिका निभाते हैं। ● परंपरागत रूप से, जब अमेरिका में बांड प्रतिफल बढ़ता है, एफपीआई भारतीय इक्विटी से बाहर चले जाते हैं। ● इसके अलावा, यह देखा गया है कि जब भारत में बॉन्ड यील्ड बढ़ जाती है, तो इसका परिणाम इक्विटी से और ऋण में पूंजी का बहिर्वाह होता है। ● विकसित बाजारों (जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका) में प्रतिफल में निरंतर वृद्धि भारतीय इक्विटी बाजारों पर अधिक दबाव डाल सकती है, जिससे धन का बहिर्वाह देखा जा सकता है। ● यहां तक कि घरेलू बॉन्ड प्रतिफल में वृद्धि से आवंटन को इक्विटी से ऋण में स्थानांतरित होते देखा जाएगा।

आरबीआई का रुख:

- आरबीआई का लक्ष्य **यील्ड** को कम रखना है क्योंकि इससे सरकार के लिए उधार लेने की लागत कम हो जाती है जबकि बाजार में उधार दरों में किसी भी तरह की बढ़ोतरी को रोका जा सकता है।
- बॉन्ड यील्ड में वृद्धि से बैंकिंग प्रणाली में ब्याज दरों पर दबाव पड़ेगा जिससे उधार दरों में बढ़ोतरी होगी। आरबीआई निवेश शुरू करने के लिए ब्याज दरों को स्थिर रखना चाहता है।

180. ब्लैंक चेक कंपनियां (Blank Cheque Companies)

- इसे विशेष प्रयोजन अधिग्रहण कंपनी (**special purpose acquisition company - SPAC**) के रूप में भी जाना जाता है।
- SPAC एक विशेष क्षेत्र में एक फर्म का अधिग्रहण करने के उद्देश्य से विशेष रूप से स्थापित एक इकाई है।
- इस SPAC का उद्देश्य आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) में धन जुटाना है, और इस समय, इसमें कोई संचालन या राजस्व नहीं होता है।
- एक बार जब जनता से पैसा जुटा लिया जाता है, तो इसे एस्करो खाते में रखा जाता है, जिस तक अधिग्रहण करते समय पहुँचा जा सकता है।
- यदि आईपीओ के दो साल के भीतर अधिग्रहण नहीं किया जाता है, तो SPAC को हटा दिया जाता है और पैसा निवेशकों को वापस कर दिया जाता है।





IASBABA'S

**RAPID REVISION (RaRe)
SERIES - UPSC 2021**

RaRe Notes Hindi

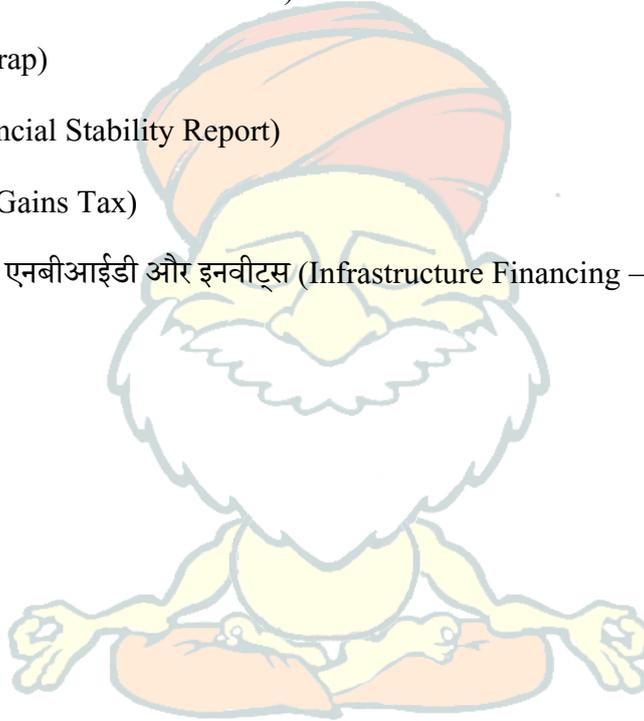
DAY 25 - ECONOMY

#RaRebaba

www.rrs.iasbaba.com

विषय

181. नेगेटिव आयल प्राइस (Negative Oil Prices)
182. कंसोल बांड (Consol Bonds)
183. डिजिटल मुद्रा (Digital Currency)
184. एफआरबीएम छूट (FRBM relaxations)
185. बड़े कॉर्पोरेट घरानों को बैंकिंग लाइसेंस (Banking Licence to Large Corporate Houses)
186. ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (Green Term Ahead Market)
187. तरलता जाल (Liquidity Trap)
188. वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (Financial Stability Report)
189. पूंजीगत लाभ कर (Capital Gains Tax)
190. अवसंरचनात्मक वित्तपोषण - एनबीआईडी और इन्वीट्स (Infrastructure Financing – NBFID & InvITs)



181. नेगेटिव आयल प्राइस (Negative Oil Prices)

समाचार में: अप्रैल 2020 में, दुनिया में कच्चे तेल की सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) की कीमतें न्यूयॉर्क (USA) में इंटरले व्यापार (Interlay Trade) में माइनस 40.32 डॉलर प्रति बैरल तक गिर गईं

इसका मतलब है कि कच्चे तेल का विक्रेता खरीदार को खरीदे गए प्रत्येक बैरल के लिए \$ 40 का भुगतान करेगा।

तेल मूल्य निर्धारण	<ul style="list-style-type: none"> ● किसी भी अन्य वस्तु की तरह ही कच्चे तेल की कीमतें वैश्विक आपूर्ति और मांग द्वारा निर्धारित होती हैं। ● बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं वे इंजन हैं जो तेल की मांग उत्पन्न करते हैं। ● दूसरी ओर, चयनित देशों या ओपेक जैसे समूहों द्वारा नियंत्रित कच्चे तेल की आपूर्ति प्रमुख रूप से तेल मूल्य को नियंत्रित करती है। ● ऐतिहासिक रूप से, ओपेक (सऊदी अरब के नेतृत्व में) एक कार्टेल के रूप में काम करता था और एक अनुकूल बैंड में कीमतें तय करता था। यह तेल उत्पादन बढ़ाकर कीमतों में कमी ला सकता है और उत्पादन में कटौती करके कीमतें बढ़ा सकता है। ● हाल के दिनों में, ओपेक वैश्विक कीमतों और आपूर्ति को ठीक करने के लिए ओपेक+ नामक 10 अन्य के साथ काम कर रहा है।
कीमतों में गिरावट के कारण	<ul style="list-style-type: none"> ● गिरती मांग: अधिक आपूर्ति और कम मांग के कारण वैश्विक लॉकडाउन से पहले ही कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आ रही थी। ● आपूर्ति कारक: मार्च 2020 में रूस और सऊदी अरब के बीच ओपेक + समझौते के टूटने का मतलब था कि तेल का उत्पादन अनियंत्रित रूप से बढ़ता रहा जिससे कीमतों में लगातार गिरावट आई। <ul style="list-style-type: none"> ○ 2020 की शुरुआत में कच्चा तेल 60 डॉलर प्रति बैरल के करीब था और मार्च के अंत तक यह 20 डॉलर प्रति बैरल के करीब था। ● महामारी का झटका: कोविड -19 के कारण यात्रा मार्गों के बंद होने और वैश्विक लॉकडाउन से तेल की मांग में भारी कमी आई है, जिसने समस्या को और बढ़ा दिया है। <p>परिणाम - भंडारण मुद्दा</p> <ul style="list-style-type: none"> ● भारी मांग में गिरावट के साथ तेल की निरंतर आपूर्ति ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जहां तेल के लिए भंडारण स्थान की दुनिया भर में कमी है।

	<ul style="list-style-type: none"> ● ट्रेन और जहाज, जो आमतौर पर तेल परिवहन के लिए उपयोग किए जाते थे, का उपयोग केवल तेल भंडारण के लिए किया जा रहा है।
<p>WTI क्रूड के लिए तेल की कीमतें शून्य से नीचे (Oil Prices Below Zero for WTI Crude)</p>	<p>उपरोक्त पृष्ठभूमि में, ऐतिहासिक घटना निम्नलिखित तरीके से सामने आई:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● कीमतों में गिरावट यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड के लिए मई वायदा अनुबंध की समाप्ति से शुरू हुई थी। वायदा अनुबंध भविष्य में एक निश्चित तिथि पर मानकीकृत गुणवत्ता की एक विशिष्ट वस्तु खरीदने या बेचने के लिए एक मानक अनुबंध है। ● प्रत्येक अनुबंध एक महीने के लिए व्यापार करता है और मई अनुबंध 23 अप्रैल 2020 को समाप्त होने वाला था। ● मई अनुबंध रखने वाले निवेशक तेल की डिलीवरी नहीं लेना चाहते थे और ना ही भंडारण लागत (जो भंडारण स्थान की कमी के कारण बढ़ गई थी) को वहन करना चाहते थे। ● दूसरी ओर तेल उत्पादक अविश्वसनीय रूप से कम कीमतों पर भी अपने तेल से छुटकारा पाना चाहते थे। यदि नहीं, तो उन्हें उत्पादन में कटौती या यहां तक कि बंद करना पड़ा जो एक कठिन निर्णय है, क्योंकि इसे फिर से शुरू करना कम (यहां तक कि नकारात्मक) कीमतों के साथ होने वाले नुकसान की तुलना में जटिल और अधिक महंगा है। ● इसके अलावा, यदि कोई देश उत्पादन में कटौती करता है, तो अन्य देशों द्वारा सूट का पालन नहीं करने पर बाजार हिस्सेदारी खोने का जोखिम होता है। ● अंततः, दोनों के लिए - डिलीवरी अनुबंध के धारक और तेल उत्पादक - \$ 40 प्रति बैरल का भुगतान करना और इसे (खरीदारों) या उत्पादन (उत्पादकों) को रोकने के बजाय तेल से छुटकारा पाना कम खर्चीला था।

पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (Organization of Petroleum Exporting Countries - OPEC)

- यह एक अंतर सरकारी संगठन है, जिसे 1960 में बगदाद सम्मेलन में बनाया गया था।
- ओपेक में सऊदी अरब के नेतृत्व में 13 सदस्य हैं और इसमें ईरान, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, वेनेजुएला शामिल हैं।
- ओपेक के सदस्य विश्व के कुल प्रमाणित तेल भंडार का लगभग 82% नियंत्रित करते हैं।

- 2018 में, ओपेक के सदस्यों का कुल विश्व कच्चे तेल उत्पादन में 41% हिस्सा था। ओपेक प्लस देशों में ओपेक + अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिण सूडान और सूडान शामिल हैं।
- इस समूह को अनौपचारिक रूप से 'वियना समूह' के रूप में भी जाना जाता है।
- ओपेक प्लस ने 2016 में कीमतों के स्थिरीकरण के लिए संयुक्त रूप से उत्पादन में कटौती करने के लिए एक समझौते को औपचारिक रूप दिया था जिसे मार्च 2020 में नवीनीकृत नहीं किया गया था, जिससे तेल की कीमत में गिरावट आई।

भारत में क्रूड मूल्य निर्धारण तंत्र

- कच्चे तेल के मूल्य निर्धारण के लिए APM (प्रशासित मूल्य निर्धारण तंत्र) की स्थापना की गई थी।
- APM ने एक संयुक्त मूल्य निर्धारण तंत्र का पालन किया जिसके तहत अंतरराष्ट्रीय कीमतों का भारत औसत और उत्पादन की घरेलू लागत का उपयोग प्रशासित मूल्य पर पहुंचने के लिए किया गया था।
- 2002 से शुरू, APM को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया गया।
- APM के विघटन के साथ, स्वदेशी कच्चे तेल की कीमत को अंतरराष्ट्रीय कीमतों से जोड़ा गया है, जिसका अर्थ है कि घरेलू कच्चे तेल उत्पादकों द्वारा प्राप्त मूल्य अंतरराष्ट्रीय कीमतों से जुड़ा हुआ है।
- APM की समाप्ति के बाद, पेट्रोल और डीजल की कीमतों को अंततः भारत सरकार द्वारा क्रमशः 2010 और 2014 में अविनियमित कर दिया गया था।
- खुदरा स्टेशन पर ईंधन की कीमत में केंद्र सरकार के उत्पाद शुल्क और कर, राज्य सरकार के कर और परिचालन लागत, तेल कंपनियों के मार्जिन और खुदरा विक्रेता के मुनाफे जैसी अतिरिक्त लागतें शामिल हैं।

182. कंसोल बांड (Consol Bonds)

- कंसोल बॉन्ड (जिसे परपेचुअल बॉन्ड के रूप में भी जाना जाता है) एक निश्चित आय सुरक्षा है जिसमें कोई परिपक्वता तिथि नहीं होती है।
- इसे अक्सर ऋण के बजाय एक प्रकार की इक्विटी माना जाता है।
- इन बांडों का प्रमुख लाभ यह है कि वे हमेशा के लिए ब्याज भुगतान की एक सतत प्रवाह का भुगतान करते हैं। हालांकि, इन बांडों को जारीकर्ता के विवेकाधिकार पर भुनाया जा सकता है।

कंसोल बांड की उत्पत्ति

- 5% के ब्याज का भुगतान करने वाले बांड, 1917 में ब्रिटेन सरकार द्वारा युद्ध की चल रही लागत (प्रथम विश्व युद्ध) के वित्तपोषण के लिए अधिक धन जुटाने के लिए जारी किए गए थे।

- नागरिकों को इन बांडों में एक संदेश के साथ निवेश करने के लिए कहा गया था कि उनका निवेश देश से लड़ने में मदद करेगा, एक सैनिक की लड़ाई के समान लेकिन उनके जीवन के लिए कोई जोखिम नहीं है।
- नतीजतन, यूके में अधिकांश कंसोल बॉन्ड छोटे निवेशकों के स्वामित्व में थे, जिनमें 70% से अधिक की हिस्सेदारी £1,000 से कम थी।
- 2014 में, ब्रिटिश सरकार ने, WWI की शुरुआत के एक सदी बाद, कुल बकाया कंसोल बांड ऋण का 10% भुगतान किया।

COVID-19 महामारी से प्रेरित आर्थिक झटके की पृष्ठभूमि में भारत सरकार के लिए कंसोल बॉन्ड को एक बेहतर समाधान के रूप में सुझाया गया था।

- पारस्परिक रूप से लाभप्रद: बांड या कर छूट के लिए एक आकर्षक कूपन दर भी निवेशकों के लिए एक प्रोत्साहन हो सकता है, जो निवेश के रास्ते तलाश रहे हैं। जिस सरकार के राजस्व में गिरावट आई है, वह भी इस विकल्प के माध्यम से जनता से संसाधन जुटा सकती है।
- निवेशकों के लिए कम जोखिम: अचल संपत्ति के पतन के साथ और लाभदायक विकल्पों की कमी को देखते हुए, बॉन्ड खुदरा निवेशकों के लिए जोखिम मुक्त निवेश के रूप में दोहरा लाभ प्रदान करेगा।
- सरकार के लिए लचीलापन: यह केंद्र सरकार द्वारा स्थायी आधार पर जारी किया जाएगा, जब यह उचित लगे तो इसे वापस लेने का अधिकार होगा। अर्थव्यवस्था को उच्च विकास के रास्ते पर वापस लाने के बाद सरकार इन बांडों को चरणबद्ध तरीके से भुनाने पर विचार कर सकती है।
- कल्याण उन्मुख: पीएम-केयर्स के विपरीत, बॉन्ड की आय का उपयोग डॉक्टरों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण से लेकर MSMEs के लिए प्रोत्साहन तक हर चीज के लिए किया जा सकता है।
- सहभागी: यह नागरिकों को महामारी के कारण होने वाली मंदी के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय भागीदार बनाता है।

183. डिजिटल मुद्रा (Digital Currency)

संदर्भ: जापान बैंक ने डिजिटल मुद्रा का एक वर्षीय परीक्षण शुरू किया है।

CBDC: सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्राएं	क्रिप्टो मुद्राएं
केंद्रीय बैंक द्वारा निर्मित।	सर्वसम्मति एल्गोरिथ्म के माध्यम से किसी एक द्वारा निर्मित।
कम कर चोरी	टैक्स चोरी की अपार संभावनाएं
सरकार द्वारा नियंत्रित	अत्यधिक अस्थिर
पारदर्शी	अपारदर्शी

ख) डिजिटल मुद्रा के अभिशासन के लिए वैश्विक संघ

- जनवरी 2020 में, विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने दावोस में अपनी वार्षिक बैठक में, डिजिटल मुद्रा शासन के लिए एक वैश्विक संघ का शुभारंभ किया।
- यह डिजिटल मुद्राओं के शासन के लिए एक रूपरेखा तैयार करने पर केंद्रित है।
 - सुशासन की कमी के कारण डिजिटल मुद्राएं बड़े पैमाने पर अपनाने के दायरे से बाहर रही हैं।
 - उचित रूप से विनियमित डिजिटल मुद्रा का उपयोग सस्ती और तेज सीमा पार भुगतान, वित्तीय समावेशन और अवैध वित्त को जड़ से खत्म करने के लिए किया जा सकता है।
- बिटकॉइन से लेकर फेसबुक के लिब्रा और केंद्रीय बैंक द्वारा जारी विकल्पों तक के विभिन्न रूपों में डिजिटल मुद्राओं के उद्भव ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को एक उपयुक्त एकीकृत नियामक प्रणाली बनाने के लिए मजबूर कर दिया है।
- इस पहल का उद्देश्य अग्रणी कंपनियों, वित्तीय संस्थानों, सरकारी प्रतिनिधियों, तकनीकी विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और मंच के समुदायों के सदस्यों को वैश्विक स्तर पर एक साथ लाना है।
 - इसका उद्देश्य समावेशी और अंतःक्रियात्मक अभिनव नीति समाधानों के माध्यम से वित्तीय प्रणाली तक पहुंच बढ़ाना है।

विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum)

- WEF 1971 में स्थापित एक स्विस गैर-लाभकारी फाउंडेशन है, जो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है।
- इसे स्विस अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक-निजी सहयोग के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- WEF वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग एजेंडा को आकार देने के लिए व्यवसाय, राजनीतिक, शैक्षणिक और समाज के अन्य नेताओं को शामिल करके दुनिया की स्थिति में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- WEF द्वारा प्रकाशित कुछ प्रमुख रिपोर्टें हैं:

- ✓ ऊर्जा संक्रमण सूचकांक
- ✓ वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट
- ✓ वैश्विक आईटी रिपोर्ट

WEF ने INSEAD और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इन रिपोर्ट को प्रकाशित करती है।

- ✓ ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट
- ✓ वैश्विक जोखिम रिपोर्ट
- ✓ वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट

184. राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (Fiscal responsibility and Budget Management - FRBM) अधिनियम में छूट

संदर्भ: कई राज्यों ने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम के तहत लचीलेपन की मांग की थी। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि COVID-19 के मद्देनजर राजकोषीय प्रोत्साहन FRBM विचारों से बाधित न हो।

- FRBM अधिनियम अगस्त 2003 में अधिनियमित किया गया था।
- पृष्ठभूमि: सरकार द्वारा अपने कार्यक्रमों को वित्तपोषित करने के लिए असंतुलित रूप से ऋण लेने ने उच्च राजकोषीय घाटा, उच्च राजस्व घाटा और उच्च ऋण-से-जीडीपी अनुपात का नेतृत्व किया था।
- **FRBM** का उद्देश्य: राजकोषीय प्रबंधन और दीर्घकालिक वृहद आर्थिक स्थिरता में अंतर-पीढ़ीगत इक्विटी सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार को उत्तरदायी बनाना है।
- इस अधिनियम में केंद्र सरकार के कर्ज और घाटे पर सीमा तय करने की परिकल्पना की गई है।
 - अधिनियम ने राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3% तक कम करना अनिवार्य कर दिया - प्रारंभिक लक्ष्य 31 मार्च, 2009 था, लेकिन इसे 2008 के बाद से मार्च 2023 के लिए 3.1% के सबसे हालिया लक्ष्य के लिए स्थगित कर दिया गया है।
- राजकोषीय परिचालनों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, बजट के साथ प्रतिवर्ष संसद में निम्नलिखित दस्तावेज रखे जाने चाहिए थे:
 - व्यापक आर्थिक ढांचा वक्तव्य
 - राजकोषीय नीति रणनीति वक्तव्य
 - मध्यम अवधि राजकोषीय नीति वक्तव्य
 - मध्यम अवधि व्यय रूपरेखा विवरण
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य भी आर्थिक रूप से विवेकपूर्ण हैं, 12 वें वित्त आयोग की सिफारिशों ने 2004 में समान कानूनों के अधिनियमन के साथ राज्यों को ऋण राहत से जोड़ा।
 - राज्यों ने तब से अपने स्वयं के संबंधित वित्तीय उत्तरदायित्व विधान को अधिनियमित किया है, जो उनके वार्षिक बजट घाटे पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की 3% सीमा निर्धारित करता है।

एनके सिंह समिति (2016 में स्थापित) ने सिफारिश की थी कि सरकार को 31 मार्च, 2020 तक जीडीपी के 3% के राजकोषीय घाटे को लक्षित करना चाहिए, इसे 2020-21 में 2.8% और 2023 तक 2.5% तक घटाना चाहिए।

FRBM में छूट यानी एस्केप क्लॉज

- अधिनियम की धारा 4(2) के तहत, केंद्र कुछ आधारों का हवाला देते हुए वार्षिक राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पार कर सकता है।
 - इसमें आधार शामिल हैं -

- राष्ट्रीय सुरक्षा, युद्ध
- राष्ट्रीय आपदा
- कृषि का पतन
- संरचनात्मक सुधार
- एक तिमाही की वास्तविक उत्पादन वृद्धि में पिछली चार तिमाहियों के औसत से कम से कम 3% की गिरावट

अतीत में **FRBM** मानदंडों में छूट के उदाहरण

- **2008-09** में - वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान, जब केंद्र ने राजकोषीय प्रोत्साहन का सहारा लिया - राजकोषीय घाटा 2.7% के बजट लक्ष्य से बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 6.2% हो गया।
 - इसके साथ ही, राज्यों के लिए घाटे के लक्ष्यों को भी 2008-09 के लिए GSDP के 3.5% और वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए GSDP के 4% तक शिथिल कर दिया गया था।
- **2020-21** के लिए हाल के केंद्रीय बजट में - कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती को संरचनात्मक सुधारों के रूप में माना गया था ताकि एस्केप क्लॉज को सक्रिय किया जा सके - 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य पहले के 3.3% से 3.8% तक पुनः अंशांकित किया गया था।

185. बड़े कॉर्पोरेट घरानों को बैंकिंग लाइसेंस (Banking Licence to Large Corporate Houses)

संदर्भ: नवंबर 2020 में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आंतरिक कार्य समूह (IWG) ने सुझाव दिया कि बड़े कॉर्पोरेट और औद्योगिक घरानों को बैंकों के प्रमोटर के रूप में अनुमति दी जा सकती है।

- लंबे समय में प्रमोटरों की हिस्सेदारी की सीमा को बैंक की पेड-अप वोटिंग इक्विटी (**Paid-up Voting Equity**) शेयर पूंजी के मौजूदा 15% से बढ़ाकर 26% तक की जा सकती है।
- इसने एक नया सार्वभौमिक बैंक स्थापित करने के लिए आवश्यक प्रारंभिक भुगतान पूंजी या निवल मूल्य को बढ़ाकर ₹1,000 करोड़ करने का सुझाव दिया; लघु वित्त बैंकों के लिए ₹300 करोड़ और और SFB को स्थानांतरित करने वाले शहरी सहकारी बैंक के लिए, यह पाँच वर्षों में ₹300 करोड़ है।
- रिपोर्ट औद्योगिक घरानों को दो विकल्प प्रदान करती है - या तो लाइसेंस के लिए एक सीधा आवेदन करें, या जिनके पास पहले से ही ऋण देने का संचालन है, वे अपने मौजूदा व्यवसायों को बैंक में बदल सकते हैं।

क्या आप जानते हैं?

- ✓ बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुसार, भारत में कोई भी कंपनी तब तक बैंकिंग व्यवसाय नहीं करेगी, जब तक कि उसके पास भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी लाइसेंस न हो और ऐसा कोई भी लाइसेंस ऐसी शर्तों के अधीन जारी किया जा सकता है जो रिजर्व बैंक लगाना उचित समझते हैं।
- ✓ 1969 में 14 बड़े निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद से, RBI ने बड़े कॉर्पोरेट और औद्योगिक घरानों को बैंक स्थापित करने के लिए लाइसेंस नहीं दिया है। वर्तमान में, 12 पुराने और नौ नए निजी बैंक (1991 के बाद की अवधि में स्थापित) हैं, जिनमें अधिकांश स्वामित्व व्यक्तियों और वित्तीय संस्थाओं के पास है।

- ✓ आरबीआई बैंकिंग लाइसेंस के मामले में बहुत उदार नहीं रहा है। पिछले दो लाइसेंस सात साल पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और बंधन बैंक को वित्तीय समावेशन हासिल करने के विशिष्ट उद्देश्य से दिए गए थे। इनसे पहले आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक और यस बैंक को दो लाइसेंस दिए थे।

बड़े कॉर्पोरेट घरानों के बैंकिंग लाइसेंस का विश्लेषण

इसकी सिफारिश क्यों	<ul style="list-style-type: none"> ● भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित होने के लिए धन (ऋण) की आवश्यकता है। ● सरकारी वित्त पहले से ही तनावपूर्ण था। ● सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एनपीए से पीड़ित हैं। ● बड़े कॉर्पोरेट्स के डेड फंड का सबसे अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है।
लाभ	<ul style="list-style-type: none"> ● पूंजी की आवश्यकता पूरी हो सकती है। ● अधिक शाखाएं खोलना और शामिल करना। ● सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर प्रतिस्पर्धी बनने के लिए दबाव डाला जाएगा।
चिंताएं	<ul style="list-style-type: none"> ● आर्थिक शक्ति का एकाग्रता, ● कॉर्पोरेट्स को बैंकों को अनुमति देने में वित्तीय स्थिरता संभावित जोखिम हैं। ● अंतःसमूह ऋण और धन का फैलावा ● कॉर्पोरेट डिफॉल्ट्स फाइनेंशियल सेक्टर (Defaults Financial Sector) में फैल रहे हैं।

186. ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (Green Term Ahead Market -GTAM)

संदर्भ: सितंबर 2020 में, विद्युत और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने बिजली में अखिल भारतीय ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (GTAM) लॉन्च किया।

जून 2020 में पावर एक्सचेंजों में रियल टाइम मार्केट (RTM) ट्रेडिंग को मंजूरी मिलने के बाद यह कदम उठाया गया है।

भारतीय ऊर्जा विनिमय (IEX) वर्तमान में निम्नलिखित मॉडलों के माध्यम से व्यापार करता है:

1	डे अहेड मार्केट (Day Ahead Market - DAM)	<ul style="list-style-type: none"> ● यहां एक दिन पहले बिजली के लेन-देन की अनुमति है।
---	------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2	टर्म अहेड मार्केट (Term-Ahead-Market - TAM)	● यहां बिजली का कारोबार उसी दिन से लेकर 11 दिन पहले तक किया जाता है।
3	नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (Renewable Energy Certificate - REC)	● यहां बिजली की हरित ऊर्जा विशेषताओं का कारोबार किया जाता है।
4	रीयल टाइम मार्केट (Real time Market - RTM)	● यहां नीलामी सत्र घंटे पर सम (Even) समय ब्लॉक पर आयोजित किए जाते हैं, और व्यापार सत्र बंद होने के एक घंटे बाद डिलीवरी शुरू होती है।

GTAM के लिए पृष्ठभूमि

- ✓ यद्यपि देश में अक्षय ऊर्जा की पहुंच बढ़ रही है, मौजूदा DAM और TAM खंड में अक्षय ऊर्जा की भागीदारी नगण्य (1% से कम) रही है क्योंकि प्रणाली द्वारा पारंपरिक बिजली और हरित ऊर्जा के बीच कोई अलगाव नहीं हुआ है।
- ✓ इस मुद्दे को दूर करने के लिए, एक वैकल्पिक नया मॉडल, अर्थात् GTAM पेश किया गया था।

GTAM के बारे में -

- GTAM को विशेष रूप से लंबे समय तक बिजली खरीद समझौतों (PPA) में शामिल किए बिना खुले बाजार में अक्षय विकासक द्वारा बिजली बेचने के लिए पेश किया गया है।
- GTAM अक्षय ऊर्जा के अल्पकालिक व्यापार के लिए एक विशेष मंच प्रदान करेगा।

GTAM की प्रमुख विशेषताएं हैं:

- ✓ एकीकृत अक्षय खरीद दायित्व (RPO): GTAM अनुबंध के माध्यम से निर्धारित ऊर्जा को खरीदार के RPO अनुपालन के रूप में माना जाएगा। इससे पहले, पवन या सौर कंपनी से बिजली के खरीदार यह दावा नहीं कर सकता थे कि वे RPO से मिले हैं।
- ✓ द्विपक्षीय लेनदेन: साथ ही, GTAM के माध्यम से लेन-देन द्विपक्षीय प्रकृति का होगा, जिसमें संबंधित खरीदारों और विक्रेताओं की स्पष्ट पहचान होगी, अक्षय खरीद दायित्वों (आरपीओ) के लिए लेखांकन में कोई कठिनाई नहीं होगी।
- ✓ सौर और गैर-सौर: सौर और गैर-सौर RPO पूर्ति की सुविधा के लिए सौर और गैर-सौर ऊर्जा दोनों के लिए अलग-अलग अनुबंध होंगे।
- ✓ एक से अधिक उपकरण: जिनमें शामिल हैं
 - ग्रीन इंट्राडे (Green Intraday) (उसी दिन के लिए दस घंटे का अनुबंध)
 - डे अहेड कंटेजेंसी (Day Ahead Contingency) (अगले दिन के लिए प्रति घंटा अनुबंध)
 - दैनिक (सभी या एक ही दिन में घंटे के एक ब्लॉक)

- साप्ताहिक अनुबंध (सोमवार से रविवार)



मूल्य की खोज निरंतर आधार पर होगी अर्थात मूल्य समय प्राथमिकता के आधार पर

GTAM ने अपने लॉन्च के बाद से उत्साहजनक प्रतिक्रिया देखी और पहले 11 दिनों में 30 लाख यूनिट (एमयू) का व्यापार पंजीकृत किया है।

नवीकरणीय खरीद दायित्व (About Renewable purchase obligation - RPO)

इसके बारे में -

- RPO एक ऐसा तंत्र है जिसके द्वारा बाध्य संस्थाएं बिजली की कुल खपत के प्रतिशत के रूप में अक्षय ऊर्जा स्रोतों से कुछ प्रतिशत बिजली खरीदने के लिए बाध्य हैं।
- बाध्य संस्थाओं में डिस्कॉम, ओपन एक्सेस उपभोक्ता और कैप्टिव बिजली उत्पादक शामिल हैं।
- RPO को सोलर और नॉन सोलर RPO के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- बिजली अधिनियम 2003 और राष्ट्रीय टैरिफ नीति 2006 के तहत RPO प्रदान किए जाते हैं।

GTAM पहल का महत्व और लाभ:

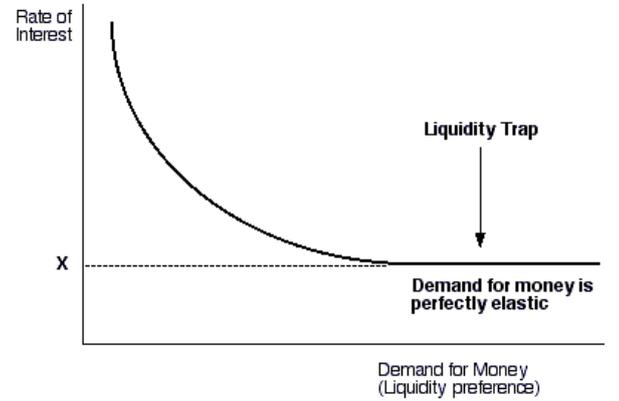
- उत्पादक को लाभ: GTAM मंच अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को अखिल भारतीय बाजार तक पहुंच प्रदान करके लाभान्वित करेगा। हरित बाजार अंततः हरित उत्पादकों को बिक्री और व्यापार के कई मॉडल अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
- खरीदार को लाभ: यह प्रतिस्पर्धी कीमतों और पारदर्शी और लचीली खरीद के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा के खरीदारों को लाभान्वित करेगा।
- राज्य सरकारों को प्रोत्साहन: यह अक्षय ऊर्जा संपन्न राज्यों पर बोझ को कम करेगा और उन्हें अपने स्वयं के RPO से परे RE क्षमता विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
- RE बाजार को मजबूत करता है: पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धी कीमतों, लचीलेपन और भुगतान सुरक्षा और वित्तीय बचत जैसे मजबूत मूल्य प्रस्तावों के साथ, जो विनिमय बाजार प्रदान करता है, एक अखिल भारतीय हरित बाजार में क्षेत्र में प्रतिभागियों की संख्या में वृद्धि करके अक्षय ऊर्जा बाजार को मजबूत बनाने की क्षमता है।
- राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है: पारदर्शी मंच देश के RE क्षमता वृद्धि लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। सरकार का लक्ष्य 2022 तक 175 GW RE क्षमता प्राप्त करना है।

187. तरलता जाल (Liquidity Trap)

संदर्भ: नवंबर 2020 में, IMF अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था एक तरलता जाल की ओर बढ़ रही है।

- एक तरलता जाल एक विरोधाभासी आर्थिक स्थिति है जिसमें ब्याज दरें बहुत कम होती हैं और बचत दरें अधिक होती हैं।

- आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बैंक के प्रयासों में बाधा आ रही है क्योंकि वे निवेशकों और उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज दरों को और कम करने में असमर्थ हैं, जिससे मौद्रिक नीति अप्रभावी हो गई है।
- यह एक ऐसे परिदृश्य की ओर ले जाता है जहां अर्थव्यवस्था में उत्पन्न कोई भी अतिरिक्त धन आपूर्ति निवेश के बजाय बचत की ओर प्रवाहित हो जाती है, जिससे अर्थव्यवस्था समान तरलता स्तर पर बनी रहती है।
- जबकि एक तरलता जाल आर्थिक स्थितियों का एक कार्य है, यह मनोवैज्ञानिक भी है क्योंकि उपभोक्ता नकारात्मक आर्थिक दृष्टिकोण के कारण उच्च-भुगतान वाले निवेशों को चुनने के बजाय नकदी जमा करने का विकल्प अपना रहे हैं।
- तरलता जाल के दौरान, उपभोक्ता बॉन्ड से बचने और अपने फंड को नकद बचत में रखने का विकल्प चुनते हैं क्योंकि प्रचलित धारणा है कि ब्याज दरें जल्द ही बढ़ सकती हैं (जो बॉन्ड की कीमतों को कम कर देगी)
 - इसके अतिरिक्त, क्योंकि बांडों का ब्याज दरों से विपरीत संबंध होता है, कई उपभोक्ता ऐसी कीमत के साथ संपत्ति नहीं रखना चाहते हैं जिसके घटने की उम्मीद है।
- एक तरलता जाल बांड तक सीमित नहीं है। यह अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित करता है, क्योंकि उपभोक्ता उत्पादों पर कम खर्च कर रहे हैं, जिसका अर्थ है कि व्यवसायों को किराए पर लेने की संभावना कम है।



तरलता जाल के लक्षण	<ul style="list-style-type: none"> ● कम ब्याज दर। ● कीमतों का कम रहना। ● व्यवसाय द्वारा अतिरिक्त नकदी का खर्च न करना। ● स्थिर वेतन। ● कम ब्याज दरों का बड़ी हुए ऋण में परिवर्तित न होना।
समाधान	<ul style="list-style-type: none"> ● ब्याज दरों में वृद्धि। ● कीमत में पर्याप्त गिरावट। ● विस्तारक राजकोषीय नीति। ● वित्तीय नवाचार। ● वैश्विक पुनर्संतुलन।



गीता गोपीनाथ ने किस आधार पर यह कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था एक तरलता जाल की ओर बढ़ रही है?

- कम ब्याज दरें एक वैश्विक घटना है: वैश्विक अर्थव्यवस्था का 60 प्रतिशत - जिसमें 97 प्रतिशत उन्नत अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं - केंद्रीय बैंकों ने नीतिगत ब्याज दरों को 1% से नीचे धकेल दिया है। दुनिया के एक-पांचवें हिस्से में, वे नकारात्मक हैं। यह केंद्रीय बैंकों के लिए एक और झटका लगने पर ब्याज दरों में और कटौती करने के लिए बहुत कम जगह छोड़ता है।
- कमजोर वैश्विक मांग: बेहद कम ब्याज दरों के बावजूद, COVID-19 महामारी के प्रभाव के कारण वैश्विक मांग अभी भी सुस्त है।
- संभावित मुद्रा युद्ध का खतरा: ब्याज दरों में कमी के कारण, दुनिया भर में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी जो संभावित रूप से व्यापारिक क्षेत्र में विनिमय दरों में गिरावट के कारण मुद्रा युद्ध को सक्रिय कर सकती है।
- विकासशील देशों तक पहुंचने वाले प्रभाव: आमतौर पर, उच्च औसत ब्याज दरों के कारण विकासशील देशों में इस समस्या के विकसित होने की संभावना नहीं है। लेकिन हाल ही में, पेरू और चिली जैसे विकासशील देशों ने अपनी दुर्घटनाग्रस्त अर्थव्यवस्थाओं के कारण उधार लेने की लागत को लगभग शून्य कर दिया है, इस प्रकार एक तरलता जाल का संकेत मिलता है।

188. वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (Financial Stability Report)

संदर्भ: जनवरी 2021 में आरबीआई द्वारा FSR जारी हुई

- FSR वित्तीय स्थिरता के जोखिमों और वित्तीय क्षेत्र के विकास और विनियमन से संबंधित समकालीन मुद्दों के संदर्भ में वित्तीय प्रणाली की लचीलापन को दर्शाता है।
- FSR भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है।

मापदंड		एफएसआर जनवरी 2021 खोज (FSR Jan 2021 Finding)	
1	पूंजी से जोखिम-भारित संपत्ति अनुपात (Capital to risk-weighted assets ratio - CRAR):	<ul style="list-style-type: none"> ● CRAR को पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) के रूप में भी जाना जाता है, यह अपनी जोखिम भारित परिसंपत्तियों और वर्तमान देनदारियों के संबंध में बैंक की पूंजी का अनुपात है। ● बेसल III मानदंड CRAR 8% निर्धारित किया गया। 	<p>अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCB) का CRAR सितंबर 2020 में बढ़कर 15.8% हो गया, जो मार्च 2020 में 14.7% था।</p>
2	सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (Gross non-performing)	<ul style="list-style-type: none"> ● एक गैर निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) एक ऋण या अग्रिम है जिसके लिए मूलधन या ब्याज भुगतान 90 दिनों की अवधि के लिए अतिदेय है। 	<ul style="list-style-type: none"> ● SCB का GNPA अनुपात 8.4% से घटकर 7.5% हो गया है।

<p>asset - GNPA) अनुपात:</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● आधारभूत परिदृश्य के तहत सितंबर 2021 तक सभी अनुसूचित सहकारी बैंकों का GNPA अनुपात 13.5% और गंभीर तनाव परिदृश्य में 14.8% तक बढ़ सकता है।
<p>3 प्रावधान कवरेज अनुपात (Provision Coverage Ratio - PCR)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● बैंकों को अपने मुनाफे का एक हिस्सा खराब ऋणों के प्रावधान के रूप में अलग रखना होगा। इसे PCR कहते हैं। ● एक उच्च PCR अनुपात (आदर्श रूप से 70% से ऊपर) का मतलब है कि अधिकांश परिसंपत्ति गुणवत्ता के मुद्दों का ध्यान रखा गया है और बैंक कमजोर नहीं है। 	<ul style="list-style-type: none"> ● PCR 66.2% से बढ़कर 72.4% हो गया है।
<p>4 संप्रभु ऋण (Sovereign debt)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● संप्रभु ऋण एक संप्रभु राष्ट्र की सरकार की वित्तीय देयता को अपने विदेशी और घरेलू लेनदारों को संदर्भित करता है। ● क्राउड आउट: सरकार के प्रभुत्व के कारण निजी क्षेत्र के लिए (बैंकों से) उधार लेने का अवसर कम हो जाता है, 	<ul style="list-style-type: none"> ● राजस्व की कमी के कारण सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम में विस्तार ने बैंकों पर अतिरिक्त दबाव डाला है। ● इसके अलावा यह संप्रभु ऋण को उन स्तरों तक बढ़ा रहा है जिन्होंने भीड़ के साथ स्थिरता से संबंधित चिंताओं को तेज किया है।

189. पूंजीगत लाभ कर (Capital Gains Tax)

संदर्भ: वित्त विधेयक, 2021 ने पूंजीगत लाभ कर (CGT) से संबंधित नियमों में संशोधन का प्रस्ताव रखा।

- संशोधन किसी कंपनी के साझेदार द्वारा सेवानिवृत्त होने पर प्राप्त किसी भी संपत्ति या शेयरों पर CGT लगाता है।
- दिशानिर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जहां किसी भागीदार को फर्म/एसोसिएशन के विघटन या पुनर्गठन के समय कोई पैसा या अन्य संपत्ति प्राप्त होती है, वहां होने वाले लाभ पर 'पूंजीगत लाभ' के तहत शुल्क लगेगा।
- इसके अलावा, कर काल्पनिक लाभ पर लगाया जाएगा अर्थात्, संपत्ति हस्तांतरण के मामले में उचित बाजार मूल्य और वास्तविक लागत के बीच अंतर से प्राप्त लाभ।

पूंजीगत लाभ कर के बारे में -

- पूंजीगत लाभ कर व्यक्तियों और निगमों द्वारा उन निवेशों को बेचने पर किए गए निवेशों के मूल्य में वृद्धि पर लगने वाला कर है।
- पूंजीगत लाभ उपचार केवल "पूंजीगत संपत्ति" जैसे स्टॉक, बांड, गहने, सिक्का संग्रह और अचल संपत्ति पर लागू होता है। दूसरे शब्दों में, यह केवल उन लेन-देन पर लागू होता है जो प्रकृति में पूंजी हैं यानी, संपत्ति या देनदारियों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप है।
- पूंजीगत लाभ विरासत में मिली संपत्ति पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि कोई बिक्री नहीं होती है, केवल स्वामित्व का हस्तांतरण होता है। आयकर अधिनियम ने विशेष रूप से विरासत या वसीयत के माध्यम से उपहार के रूप में प्राप्त संपत्ति को छूट दी है। हालांकि, अगर विरासत में मिली संपत्ति को व्यक्ति बेचने का फैसला करता है, तो पूंजीगत लाभ कर लागू होगा।

निम्नलिखित पूंजीगत संपत्ति की श्रेणी में नहीं आते हैं:

- व्यवसाय या पेशे के उद्देश्य के लिए रखे गए किसी भी स्टॉक, उपभोग्य या कच्चे माल।
- व्यक्तिगत उपयोग के लिए रखे गए कपड़े और फर्नीचर जैसे व्यक्तिगत सामान
- ग्रामीण भारत में कृषि भूमि।
- 6½% स्वर्ण बांड (1977) या 7% स्वर्ण बांड (1980) या केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांड (1980)
- विशेष वाहक बांड (1991)
- स्वर्ण जमा योजना (1999) के तहत जारी स्वर्ण जमा बांड या स्वर्ण मुद्राकरण योजना, 2015 के तहत जारी जमा प्रमाण पत्र।

CGT ढांचा उस समय के आधार पर कर को दो प्रकारों में विभाजित करता है जिसके लिए उन्हें आयोजित किया जाता है-

<p>शॉर्ट-टर्म कैपिटल एसेट पर शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स (Short-Term Capital Gains Tax - STCG)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● जब किसी परिसंपत्ति को 36 महीने या उससे कम की अवधि के लिए रखा जाता है, तो उसे अल्पकालिक पूंजी परिसंपत्ति कहा जाता है। ● भूमि, भवन और गृह संपत्ति जैसी अचल संपत्तियों के लिए 36 महीने के मानदंड को घटाकर 24 महीने कर दिया गया है। ● उदाहरण के लिए, यदि आप घर की संपत्ति को 24 महीने से कम अवधि के लिए रखने के बाद बेचते हैं, तो उत्पन्न होने वाली किसी भी आय को अल्पकालिक पूंजीगत लाभ माना जाएगा।
<p>लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (Long-term Capital Gains Tax - LTCG)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● एक संपत्ति जो 36 महीने से अधिक समय तक आयोजित की जाती है, एक दीर्घकालिक पूंजी संपत्ति होती है।

190. अवसंरचनात्मक वित्तपोषण - एनबीआईडी और इनवीट्स (Infrastructure Financing – NaBFID & InvITs)

A) बुनियादी ढांचे और विकास के वित्तपोषण के लिए नेशनल बैंक (NaBFID)

संदर्भ: संसद ने NaBFID विधेयक, 2021 को पारित किया है।

- विधेयक दीर्घकालिक गैर-आश्रय अवसंरचना वित्तपोषण के विकास के लिए एक विकास वित्तीय संस्थान (DFI) NaBFID की स्थापना का समर्थन करता है।

NaBFID के कार्य	<ul style="list-style-type: none"> बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए ऋण और अग्रिमों का विस्तार या पुनर्वित्त करना। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए निजी क्षेत्र और संस्थागत निवेशकों से निवेश आकर्षित करना। बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण में परामर्श सेवाएं प्रदान करना। बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के क्षेत्र में विवाद समाधान के लिए सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत को सुविधाजनक बनाना। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में विदेशी भागीदारी को व्यवस्थित और सुविधाजनक बनाना।
NaBFID की शेरधारिता:	<ul style="list-style-type: none"> केंद्र सरकार, बहुपक्षीय संस्थानों, सॉवरेन वेल्थ फंड, पेंशन फंड, बीमा कंपनियों, वित्तीय संस्थानों, आदि के पास 1 लाख करोड़ रुपये की अधिकृत शेर पूंजी के साथ NaBFID की स्थापना एक कॉर्पोरेट निकाय के रूप में की जाएगी। प्रारंभ में, केंद्र सरकार के पास संस्था के 100% शेर होंगे जो बाद में संस्था द्वारा स्थिरता और पैमाने हासिल करने के बाद 26% तक कम हो सकते हैं।
धन स्रोत:	<ul style="list-style-type: none"> NaBFID ऋण के रूप में या अन्यथा भारतीय रुपये और विदेशी मुद्रा दोनों में, या बांड और डिबेंचर सहित विभिन्न वित्तीय साधनों के निर्गम और बिक्री के रूप में धन जुटा सकता है।
प्रबंधन	<ul style="list-style-type: none"> NaBFID का संचालन निदेशक मंडल और आरबीआई के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा गठित निकाय प्रबंध निदेशक और उप प्रबंध निदेशक के पद के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश करेगा।

		<ul style="list-style-type: none"> ● बोर्ड एक आंतरिक समिति की सिफारिश के आधार पर स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करेगा।
जांच अभियोजन	और	<ul style="list-style-type: none"> ● NaBFID के कर्मचारियों से जुड़े मामलों में अपराधों का संज्ञान लेने के लिए न्यायालयों को भी पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी। ● NaBFID के कर्मचारियों के खिलाफ बिना पूर्वानुमति के कोई जांच शुरू नहीं की जा सकती है। <ul style="list-style-type: none"> ○ अध्यक्ष या अन्य निदेशकों के मामले में केंद्र सरकार ○ अन्य कर्मचारियों के मामले में प्रबंध निदेशक।

विकास वित्तीय संस्थान (DFIs) के बारे में

- DFI को विकास बैंक या विकास वित्त कंपनी के रूप में जाना जाता है।
- संस्थान जो विभिन्न क्षेत्रों को दीर्घकालिक विकास वित्त प्रदान करते हैं, जैसे उद्योग, कृषि, आवास और बुनियादी ढांचा।
- DFI विशेष रूप से विकासशील देशों में ऋण देने और अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- DFI या तो पूर्ण या आंशिक रूप से सरकार के स्वामित्व में हो सकते हैं और कुछ के पास बहुसंख्यक निजी स्वामित्व होता है, जो वित्तपोषित गतिविधियों की प्रकृति और उनके संबंधित जोखिम-रिटर्न प्रोफाइल द्वारा निर्धारित किया जाता है।
- आरबीआई अधिनियम, 1934 या कंपनी अधिनियम, 1956 या DFI स्थापित करने वाले विभिन्न विधियों में 'DFI' शब्द का कोई विशिष्ट उपयोग नहीं है, जबकि आरबीआई अधिनियम और कंपनी अधिनियम के तहत कुछ वित्तीय संस्थान व्यापक अर्थों में DFI की भूमिका निभाते हैं।

	वाणिज्यिक बैंक	वित्तीय विकास संस्थान
परिभाषा	बैंक जो व्यक्तियों और उद्योगों को सेवाएं प्रदान करते हैं।	● एक व्यापक विकास एजेंडा के साथ बहुउद्देश्यीय वित्तीय संस्थानों के रूप में कार्य करने वाले बैंक।
कानूनी आधार	कंपनी अधिनियम के तहत बैंकिंग कंपनियों के रूप में स्थापित।	● विशेष अधिनियम के तहत स्थापित उदा-औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम।
उद्देश्य	उच्च ब्याज दर पर पैसा उधार देकर लाभ कमाना।	● उच्च ब्याज दर पर पैसा उधार देकर लाभ कमाना।
स्रोत निधि	जमाकर्ताओं द्वारा किए गए निवेश और जमा के माध्यम से धन जुटाया जाता है।	● निधियां उधार ली जाती हैं और अनुदानों द्वारा अर्जित, प्रतिभूतियों की बिक्री की जाती हैं।
ऋण की अवधि	लघु और मध्यम अवधि के ऋण ग्राहकों में व्यक्ति और व्यावसायिक संस्थाएं शामिल हैं।	मध्यम और दीर्घकालिक ऋण <ul style="list-style-type: none"> ● ग्राहकों में सरकार और कॉर्पोरेट शामिल हैं।

B) इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (Infrastructure Investment Trust - InvITs)

संदर्भ:

- दिसंबर 2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NHA को InvIT स्थापित करने के लिए अधिकृत किया।
- अप्रैल 2021 में, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (PGCIL) ने पावरग्रिड इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (PGInvIT) नामक अपने InvIT को लॉन्च किया। जिसे पावरग्रिड इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (PGInvIT) कहा जाता है।

InvITs के बारे में

- InvIT एक म्यूचुअल फंड के समान एक सामूहिक निवेश योजना है, जो आय के एक छोटे हिस्से को रिटर्न के रूप में अर्जित करने के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में व्यक्तिगत और संस्थागत निवेशकों से सीधे पैसे का निवेश करने में सक्षम बनाता है।
- यह आय-सृजन और परिचालन बुनियादी ढांचे की संपत्ति जैसे सड़कों, बिजली पारेषण लाइनों, गैस पाइपलाइनों आदि को रखने के लिए बनाया गया है।
 - इन परिसंपत्तियों में मजबूत प्रतिपक्षों के साथ दीर्घकालिक अनुबंध होते हैं जो लंबी अवधि में एक स्थिर नकदी प्रवाह प्रदान करते हैं - आमतौर पर 15-20 साल।
- InvITs को सेबी (इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स) विनियम, 2014 द्वारा विनियमित किया जाता है।

एक InvITs में चार तत्व होते हैं:

- ट्रस्टी के पास एक InvITs के प्रदर्शन का निरीक्षण करने की जिम्मेदारी होती है।
- प्रायोजक उस कंपनी के प्रवर्तक हैं जो InvIT की स्थापना करते हैं।
- निवेश प्रबंधक को InvIT की संपत्ति और निवेश की निगरानी का काम सौंपा गया है।
- परियोजना प्रबंधक परियोजना के निष्पादन के लिए उत्तरदायी होते हैं।
- InvITs की इकाइयों को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध और व्यापार किया जा सकता है, जिससे उन्हें तरलता प्रदान की जा सकती है। या वे निजी और गैर-सूचीबद्ध हो सकते हैं, इस मामले में उनका सार्वजनिक रूप से कारोबार नहीं होता है और बड़े पैमाने पर संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश किया जाता है।

InvITs के गुण

- ✓ प्रायोजकों (इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स) के लिए, InvITs राजस्व उत्पन्न करने वाली संपत्तियों का मुद्रीकरण करने, इक्विटी लाभ अनलॉक करने और उनकी बैलेंस शीट (यानी ऋण कम करने के लिए) को कम करने के लिए एक सुविधाजनक मार्ग प्रदान करते हैं।
- ✓ InvIT से विदेशी निवेशकों विशेष रूप से पेंशन फंड, सॉवरेन वेल्थ फंड और बीमा कंपनियों के हित को आकर्षित करने की अत्यधिक संभावना है।
- ✓ InvITs के इर्द-गिर्द निर्मित नियामक ढांचा कॉर्पोरेट प्रशासन, अनिवार्य वितरण नियमों के कारण स्थिर दीर्घकालिक रिटर्न, कम जोखिम, उच्च गुणवत्ता वाली संपत्ति और आय वितरण पर कर लाभ प्रदान करता है।

- ✓ एक ट्रस्ट होने के नाते, InvIT द्वारा अंतर्निहित परिसंपत्तियों से प्राप्त सभी आय को पास-श्रू उपचार प्राप्त होता है और इनविट स्तर पर कर योग्य नहीं होता है। नतीजतन, InvITs एक अधिक कर-अनुकूल संरचना भी प्रस्तुत करते हैं।
- ✓ InvITs बैंकों, वित्तीय संस्थानों, पेंशन फंड, बीमा कंपनियों और यहां तक कि खुदरा निवेशकों जैसे निवेशकों के लिए एक अच्छा कम जोखिम वाला निवेश अवसर प्रदान करते हैं।

InvITs के नुकसान:

- ✓ InvITs नियामक और कर कानून में बदलाव के प्रति संवेदनशील हैं।
- ✓ भारत में बुनियादी ढांचा परिसंपत्तियां मुद्रास्फीति से जुड़ी नहीं हैं। मुद्रास्फीति की उच्च दर का InvITs के प्रदर्शन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।





IASBABA'S

**RAPID REVISION (RaRe)
SERIES - UPSC 2021**

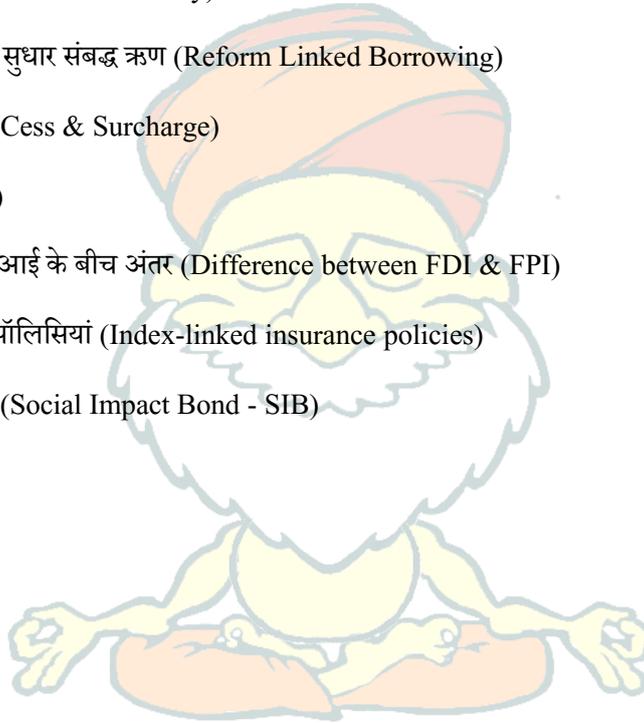
RaRe Notes Hindi

DAY 38 - ECONOMY

#RaRebaba
www.rrs.iasbaba.com

विषय

271. नीर और रीर (NEER & REER)
272. आरबीआई का ऑपरेशन ट्विस्ट (Operation Twist of RBI)
273. मात्रात्मक सहजता और फेड टेपरिंग (Quantitative Easing & Fed Tapering)
274. चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy)
275. रिफॉर्म लिंक्ड बॉरोइंग/ सुधार संबद्ध ऋण (Reform Linked Borrowing)
276. उपकर और अधिभार (Cess & Surcharge)
277. प्रेषण (Remittances)
278. एफडीआई और एफपीआई के बीच अंतर (Difference between FDI & FPI)
279. सूचकांक संबद्ध बीमा पॉलिसियां (Index-linked insurance policies)
280. सामाजिक प्रभाव बांड (Social Impact Bond - SIB)



271. नीर और रीर (NEER & REER)

- भारत कई अन्य देशों के साथ मुद्रा के कई अन्य रूपों में व्यापार करता है।
- इसलिए, यदि हम रुपये की सामर्थ्य/अस्थिरता को निष्पक्ष रूप से मापना चाहते हैं, तो हमें इसकी कीमत में उतार-चढ़ाव की तुलना न सिर्फ अमेरिकी डॉलर के खिलाफ बल्कि कई मुद्राओं (यूरो, येन, पाउंड आदि) से करनी होगी। इस प्रकार, नीर और रीर की उत्पत्ति हुई है।

नाममात्र प्रभावी विनिमय दर (Nominal Effective Exchange Rate - NEER)

- नाममात्र प्रभावी विनिमय दर (NEER) घरेलू मुद्रा की द्विपक्षीय नाममात्र विनिमय दरों के भारित औसत का एक सूचकांक है, जो व्यापारिक भागीदारों की मुद्राओं की तुलना में घरेलू मुद्रा की व्यापार टोकरी में उनके शेयरों से प्राप्त भार के साथ है।
 - नाममात्र विनिमय दर विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए आवश्यक घरेलू मुद्रा की मात्रा है।
- यह एक भारित सूचकांक है-अर्थात्, जिन देशों के साथ भारत अधिक व्यापार करता है, उन्हें सूचकांक में अधिक भार दिया जाता है।
 - इस सूचकांक में कमी रुपये के मूल्य में मूल्यहास को दर्शाती है जबकि वृद्धि अधिमूल्यन को दर्शाती है।
- NEER की गणना व्यापारिक साझेदार मुद्राओं के संदर्भ में घरेलू मुद्रा की द्विपक्षीय विनिमय दरों के ज्यामितीय भारित औसत के रूप में की जाती है। विशेष रूप से, नीर की गणना निम्नानुसार की जा सकती है:

$$NEER = \prod_{i=1}^n \left(\frac{e}{e_i} \right)^{w_i}$$

- 'e' सूचकांक के रूप में IMF के विशेष आहरण अधिकार (SDR) के सापेक्ष रुपये की विनिमय दर का प्रतिनिधित्व करता है।
- 'e_i' विदेशी मुद्रा 'i' की विनिमय दर है जो सूचकांक के रूप में अंकीय (IMF के SDR) के सापेक्ष है।
- 'w_i' विदेशी मुद्रा/व्यापारिक भागीदार 'i' को सौंपे गए व्यापार-/निर्यात-आधारित भार को दर्शाता है,
- 'n' REER बास्केट में शामिल मुद्राओं (घरेलू मुद्रा के अलावा) की संख्या है।
- 'e' or 'e/e_i' में वृद्धि मुद्रा 'i' और इसके विपरीत रुपये के मूल्य में वृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है।

वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (Real effective exchange rate - REER)

- REER सापेक्ष कीमतों या लागतों द्वारा समायोजित NEER है, जिसे आमतौर पर घरेलू अर्थव्यवस्था और व्यापारिक भागीदारों के बीच मुद्रास्फीति के अंतर में कैप्चर किया जाता है।
- REER, जो घरेलू कीमतों के विदेशी कीमतों के अनुपात के भारित औसत द्वारा समायोजित NEER है, की गणना इस प्रकार की जाती है:

$$REER = \prod_{i=1}^n \left[\left(\frac{e}{e_i} \right) \left(\frac{P}{P_i} \right) \right]^{w_i}$$

- P और 'P_i' क्रमशः घरेलू अर्थव्यवस्था और व्यापारिक भागीदार 'i' के मूल्य सूचकांकों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

- 'w_i' विदेशी मुद्रा/व्यापारिक भागीदार 'i' को सौंपे गए व्यापार-/निर्यात-आधारित भार को दर्शाता है,
- 'n' REER बास्केट में शामिल मुद्राओं (घरेलू मुद्रा के अलावा) की संख्या है।

Country/Area	2015-16	
	Trade-based Weight	Export-based Weight
1. Euro Area	11.4	14.0
2. China	10.0	5.0
3. UAE	9.4	12.4
4. US	9.1	14.7
5. Saudi Arabia	6.4	4.1
6. Switzerland	3.7	0.5
7. Hong Kong	2.9	4.8
8. Indonesia	2.9	1.8
9. Singapore	2.8	4.4
10. Iraq	2.7	0.4
11. Korea	2.5	1.6
12. Kuwait	2.5	0.4
13. Japan	2.5	2.3
14. Qatar	2.4	0.3
15. Nigeria	2.3	1.0
16. UK	2.2	3.5

तालिका: 40-मुद्रा NEER/REER टोकरी – सामान्यीकृत भार का नमूना

क्या आप जानते हैं?

- वैचारिक रूप से, ईईआर की स्थापना क्रय शक्ति समता (**Purchasing power parity - PPP**) परिकल्पना पर की जाती है।
- 2015-16 को NEER/REER सूचकांकों के लिए नए आधार वर्ष के रूप में चुना गया है।
- NEER/REER बास्केट का दायरा 36 से **40** मुद्राओं तक विस्तारित किया गया है।
- व्यापार-आधारित मुद्रा भार प्राप्त करने के लिए, पिछले तीन वर्षों के दौरान व्यापारिक भागीदारों के साथ भारत के व्यापार (निर्यात प्लस आयात) के ज्यामितीय साधनों की गणना की जाती है और फिर इसे 100 तक सामान्यीकृत किया जाता है।
- नई व्यापार-भारित टोकरी EMDE की मुद्राओं पर हावी है। जबकि यूरो क्षेत्र ने व्यापार टोकरी में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, 2015-16 में अमेरिका को निर्यात टोकरी में सबसे अधिक भार सौंपा गया है (तालिका प्रविष्टि 1 और 4 के ऊपर की जाँच करें)
- प्रभावी विनिमय दर (Effective Exchange Rate - EER) निम्न के रूप में कार्य करते हैं
 - मुद्रा के उचित मूल्य का आकलन करने के लिए पैमाना
 - एक अर्थव्यवस्था की बाहरी प्रतिस्पर्धा के लिए पैमाना
 - मौद्रिक और वित्तीय स्थितियों को स्थापित करने के लिए दिशानिर्देश

272. आरबीआई का ऑपरेशन ट्विस्ट (Operation Twist of RBI)

- ऑपरेशन ट्विस्ट आरबीआई की अल्पकालिक प्रतिभूतियों की एक साथ बिक्री और खुले बाजार परिचालन (Market Operations - OMO) के माध्यम से दीर्घकालिक प्रतिभूतियों की खरीद है।

- यह दीर्घकालिक ब्याज दरों को कम करने और अल्पकालिक दरों को बढ़ाने के लिए किया जाता है।
 - ऑपरेशन ट्विस्ट का उपयोग पहली बार 1961 में अमेरिकी फेडरल रिजर्व (सेंट्रल बैंक) द्वारा अमेरिकी डॉलर को मजबूत करने और अर्थव्यवस्था में नकदी प्रवाह को प्रोत्साहित करने के तरीके के रूप में किया गया था।

यह कैसे कार्य करता है?

- जैसा ही केंद्रीय बैंक दीर्घकालिक प्रतिभूतियों (बॉन्ड) को खरीदता है, उनकी मांग बढ़ जाती है जो बदले में उनकी कीमतों को बढ़ाती है।
- हालांकि, बॉन्ड यील्ड कीमतों में वृद्धि के साथ नीचे आता है (उलटा संबंध)
 - यील्ड वह रिटर्न है जो एक निवेशक को उसके (बॉन्ड) होल्डिंग/निवेश पर मिलता है।
- एक अर्थव्यवस्था में ब्याज दर उपज द्वारा निर्धारित की जाती है। यदि उपज कम है, तो ब्याज दरें घट जाती हैं।
- इस प्रकार, कम लंबी अवधि की ब्याज दरों का मतलब है कि लोग कम दरों पर लंबी अवधि के ऋण (जैसे घर खरीदना, कार या वित्तपोषण परियोजनाएं) प्राप्त कर सकते हैं।
- इससे अर्थव्यवस्था में खपत और खर्च में वृद्धि होगी जो बदले में विकास को पुनर्जीवित करेगा।

बॉन्ड

- एक बांड एक ऋण साधन है जिसमें एक निवेशक एक इकाई (आमतौर पर कॉर्पोरेट या सरकार) को पैसा उधार देता है जो एक चर या निश्चित ब्याज दर पर निर्धारित अवधि के लिए धन उधार लेता है।
- विभिन्न परियोजनाओं और गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए धन जुटाने के लिए कंपनियों, नगर पालिकाओं, राज्यों और संप्रभु सरकारों द्वारा बांड का उपयोग किया जाता है।
- बांड के मालिक जारीकर्ता के ऋण धारक या लेनदार होते हैं।

गवर्नमेंट सिक्योरिटीज/ सरकारी प्रतिभूतियाँ (G-Sec)

- एक G-Sec केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा जारी एक व्यापार योग्य साधन है। यह सरकार के ऋण दायित्व को स्वीकार करता है।
- लघु अवधि की प्रतिभूतियां: उन्हें आमतौर पर ट्रेजरी बिल कहा जाता है, जिसमें एक वर्ष से कम की मूल परिपक्वता होती है - वर्तमान में तीन अवधि में जारी की जाती है, अर्थात् 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन।
- दीर्घकालिक प्रतिभूतियां: इन्हें आमतौर पर एक वर्ष या उससे अधिक की मूल परिपक्वता के साथ सरकारी बांड या दिनांकित प्रतिभूतियां कहा जाता है।
- भारत में, केंद्र सरकार ट्रेजरी बिल और बांड या दिनांकित प्रतिभूतियां दोनों जारी करती है जबकि राज्य सरकारें केवल बांड या दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करती हैं, जिन्हें राज्य विकास ऋण (SDL) कहा जाता है।
- सरकारी प्रतिभूतियों में व्यावहारिक रूप से डिफॉल्ट का कोई जोखिम नहीं होता है और इसलिए, जोखिम मुक्त गिल्ट-धारित उपकरण कहलाते हैं।

ओपन मार्केट ऑपरेशंस (Open Market Operations - OMO) के बारे में -

- RBI द्वारा मुद्रा आपूर्ति की शर्तों को समायोजित करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों (G-Sec) की बिक्री या खरीद के माध्यम से OMO का संचालन किया जाता है।
- RBI वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से OMO का संचालन करता है और जनता के साथ सीधे व्यवहार नहीं करता है।

- केंद्रीय बैंक प्रणाली से तरलता को दूर करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियां बेचता है और प्रणाली में तरलता डालने के लिए सरकारी प्रतिभूतियां वापस खरीदता है।

273. मात्रात्मक सहजता और फेड टेपरिंग (Quantitative Easing & Fed Tapering)

- मात्रात्मक सहजता (Quantitative easing - QE) मौद्रिक नीति का एक रूप है जिसका उपयोग केंद्रीय बैंकों द्वारा घरेलू मुद्रा आपूर्ति को तेजी से बढ़ाने और आर्थिक गतिविधियों को गति देने के तरीके के रूप में किया जाता है।
- मात्रात्मक सहजता में आमतौर पर एक देश का केंद्रीय बैंक शामिल होता है जो ऐसे बांडों की उपज कम करने के लिए लंबी अवधि के सरकारी बांड खरीदता है (इस प्रकार ब्याज दर कम करता है)।
- केंद्रीय बैंक भी वाणिज्यिक बैंकों और अन्य निजी संस्थानों से निर्दिष्ट मात्रा में वित्तीय संपत्ति खरीदता है, इस प्रकार मौद्रिक आधार में वृद्धि और उन वित्तीय परिसंपत्तियों पर यील्ड को कम करता है।
- मात्रात्मक सहजता आमतौर पर तब लागू की जाती है जब ब्याज दरें पहले से ही शून्य के करीब होती हैं, क्योंकि इस बिंदु पर, केंद्रीय बैंकों के पास आर्थिक विकास को प्रभावित करने के लिए कम उपकरण होते हैं।
- अमेरिका ने तीन बार मात्रात्मक सुगमता के उपाय किए हैं - 2008, 2010 और 2012 में।
- यदि मात्रात्मक सहजता स्वयं प्रभावशीलता खो देती है, तो सरकार की राजकोषीय नीति का उपयोग मुद्रा आपूर्ति को और विस्तारित करने के लिए भी किया जा सकता है।

मात्रात्मक सहजता के संभावित प्रभाव

- यदि केंद्रीय बैंक मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि करते हैं, तो यह मुद्रास्फीति पैदा कर सकता है।
 - एक केंद्रीय बैंक के लिए सबसे खराब संभव परिदृश्य यह है कि इसकी मात्रात्मक सहजता रणनीति इच्छित आर्थिक विकास के बिना मुद्रास्फीति का कारण बन सकती है।
 - एक आर्थिक स्थिति जहां मुद्रास्फीति होती है, लेकिन कोई आर्थिक विकास नहीं होता है, उसे मुद्रास्फीतिजनित मंदी कहा जाता है।
- मात्रात्मक सहजता का एक और संभावित नकारात्मक परिणाम यह है कि यह घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन कर सकता है।
 - अवमूल्यन मुद्रा घरेलू निर्माताओं की मदद कर सकती है क्योंकि निर्यात किया गया सामान वैश्विक बाजार में सस्ता हो जाता है और इससे निर्यात को प्रोत्साहित करने में मदद मिलती है।
 - हालांकि, एक गिरती मुद्रा मूल्य आयात को अधिक महंगा बना देती है।
- इसके अलावा, बैंक उन फंडों को व्यक्तियों और व्यवसायों (QE के उद्देश्य को विफल करने) को उधार देने के बजाय रिजर्व में मात्रात्मक सहजता से उत्पन्न धन रखने का निर्णय ले सकते हैं।

फेडरल टेपरिंग (Federal Tapering)

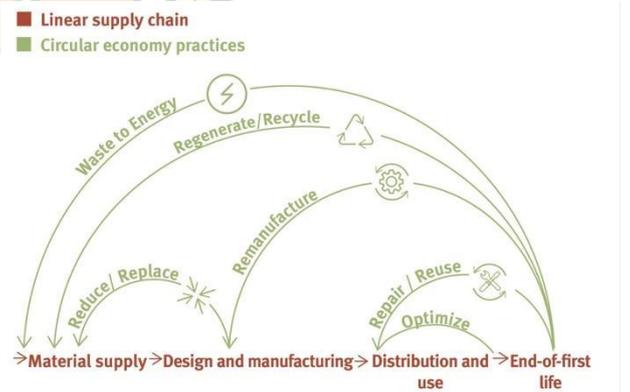
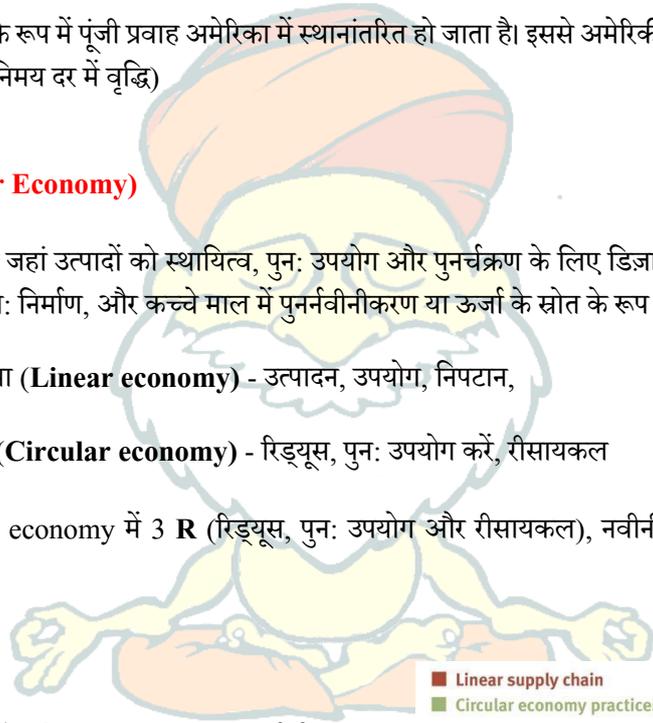
- टेपरिंग का तात्पर्य संयुक्त राज्य अमेरिका के फेडरल रिजर्व द्वारा परिसंपत्तियों की मासिक खरीद में क्रमिक कमी से है। दूसरे शब्दों में, यह उस दर को धीमा करने की प्रक्रिया है जिस पर मात्रात्मक सहजता की जाती है।
 - उदाहरण के लिए: \$85 बिलियन की संपत्ति हर महीने फेड की बैलेंस शीट में जोड़ी जा रही थी- ट्रेजरी में \$45 बिलियन और बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों (MBS) में \$40 बिलियन। फेड के निकास ढांचे में पहला कदम हर महीने परिसंपत्ति खरीद के स्तर को कम करना, या उन्हें टेपर करना था।
- भारत जैसे उभरते बाजारों को फेड टैपिंग का डर क्यों है?
 - मात्रात्मक सहजता ने अमेरिकी बैंकों और निवेशकों के साथ मुद्रा प्रवाह में वृद्धि की, जिसने भारत जैसे उभरते बाजारों में FDI/FPI के रूप में अपना रास्ता खोज लिया।
 - एक बार फेडरल टेपरिंग होने के बाद, बैंकों के पास ऋण देने के लिए उनके पास केवल कम मुक्त मुद्रा होगी। यह भारत में FDI और FPI प्रवाह को प्रभावित कर सकता है।
 - अमेरिका में वृद्धि के रूप में पूंजी प्रवाह अमेरिका में स्थानांतरित हो जाता है। इससे अमेरिकी डॉलर मजबूत होगा और भारतीय रुपया कमजोर होगा (विनिमय दर में वृद्धि)

274. चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy)

- यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादों को स्थायित्व, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण के लिए डिज़ाइन किया गया है और इस प्रकार लगभग हर चीज का पुनः उपयोग, पुनः निर्माण, और कच्चे माल में पुनर्नवीनीकरण या ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है।
 - रैखिक अर्थव्यवस्था (Linear economy) - उत्पादन, उपयोग, निपटान,
 - सर्कुलर इकोनॉमी (Circular economy) - रिड्यूस, पुनः उपयोग करें, रीसायकल
- सर्कुलर इकोनॉमी Circular economy में 3 R (रिड्यूस, पुनः उपयोग और रीसायकल), नवीनीकरण, पुनर्प्राप्त और सामग्री की मरम्मत शामिल है।

चक्रीय अर्थव्यवस्था का उद्देश्य

- सीमित संसाधनों के उपयोग में अधिकतम दक्षता तक पहुंचने के लिए,
- अक्षय संसाधनों के लिए क्रमिक संक्रमण
- उनके उपयोगी जीवन के अंत में सामग्री और उत्पादों की पुनः प्राप्ति
- अनिवार्य रूप से, एक चक्रीय अर्थव्यवस्था एक पुनर्योजी आर्थिक प्रणाली का वर्णन करती है।



275. रिफॉर्म लिंकड बॉरोइंग (Reform Linked Borrowing)

संदर्भ: भारतीय रिफॉर्म लिंकड बॉरोइंग विंडो (Reform Linked Borrowing Window) के कारण 2020-21 (FY21) में 1.06 लाख करोड़ अतिरिक्त रुपये उधार लेने में सक्षम थे।

रिफॉर्म लिंकड बॉरोइंग के बारे में

- अक्टूबर 2020 में, केंद्र सरकार ने अपने GSDP (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) के 1% अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति को चार महत्वपूर्ण सुधारों के कार्यान्वयन से जोड़ा था, जो हैं:
 1. एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली का कार्यान्वयन: सभी राशन कार्डों की आधार सीडिंग, लाभार्थियों का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, राज्य में सभी उचित मूल्य की दुकानों का स्वचालन)
 2. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार: पंजीकरण प्रमाणपत्र/अनुमोदन/लाइसेंस, कम्प्यूटरीकृत केंद्रीय यादृच्छिक निरीक्षण प्रणाली और 'जिला स्तरीय व्यवसाय सुधार कार्य योजना' की नवीनीकरण आवश्यकताओं का उन्मूलन।
 3. शहरी स्थानीय निकाय / उपयोगिता सुधार: संपत्ति कर और पानी और सीवरेज शुल्क की न्यूनतम दरों को अधिसूचित करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों और राज्यों का वित्तीय सुदृढीकरण।
 4. बिजली क्षेत्र में सुधार: AT और घाटे में कमी, आपूर्ति की औसत लागत और औसत राजस्व प्राप्ति अंतर में लक्षित कमी, और किसानों को बिजली सब्सिडी का DBT.
- यह एक बढ़ावा था, जो राज्यों को अतिरिक्त धन प्राप्त करने के लिए प्रगतिशील नीतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- इन सुधारों से जुड़ी उधार खिड़की के तहत राज्यों को इन चारों सुधारों को पूरा करने पर 2.14 लाख करोड़ रुपये तक की धनराशि प्राप्त करनी थी।
- वित्त वर्ष 2021-22 के लिए, पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों के लिए शुद्ध उधार सीमा अनुमानित GSDP के 4% (लगभग 8.46 लाख करोड़ रुपये) पर तय की गई है।
- अनुच्छेद 292 में केंद्र सरकार द्वारा उधार लेना शामिल है।
- अनुच्छेद 293 में राज्य सरकारों द्वारा उधार लेना शामिल है।
 - अनुच्छेद 293 (3) के अनुसार केंद्र सरकार की ऋणी राज्य सरकारों को उधार लेने से पहले केंद्र सरकार की सहमति लेने की आवश्यक है।

276. उपकर और अधिभार (Cess & Surcharge)

संदर्भ: संसद में पेश किए गए केंद्र सरकार के खातों के नवीनतम ऑडिट से पता चला है कि 2018-19 में सभी उपकर संग्रह का लगभग 40% भारत के समेकित कोष (CFI) में रखा गया है।

- उपकर एक करदाता की आधार कर देयता के ऊपर लगाए गए कर का एक रूप है।
 - उदाहरण के लिए, 30 प्रतिशत व्यक्तिगत आयकर पर 3% शिक्षा उपकर मौजूदा 30 प्रतिशत पर कर के रूप में लगाया जाता है। परिणामस्वरूप, समग्र कर दर बढ़कर 30.9 प्रतिशत (30 प्रतिशत मूल दर + 30 प्रतिशत कर दर का 3% (उपकर)) हो जाती है।
- एक उपकर आमतौर पर अतिरिक्त रूप से तब लगाया जाता है जब राज्य या केंद्र सरकार विशिष्ट उद्देश्यों के लिए धन जुटाना चाहती है।
 - उदाहरण के लिए, सरकार प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के वित्तपोषण के लिए अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने के लिए शिक्षा उपकर लगाती है।
- उपकर सरकार के लिए राजस्व का एक स्थायी स्रोत नहीं है, और इसे लगाने का उद्देश्य पूरा होने पर इसे बंद कर दिया जाता है।
- यह अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों प्रकार के करों पर लगाया जा सकता है।

- उपकर से कर राजस्व को पहले भारत के समेकित कोष (CFI) में जमा किया जाता है और केंद्र सरकार संसद द्वारा किए गए उचित विनियोग के बाद, निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए धन का उपयोग कर सकती है।
- संविधान का अनुच्छेद 270 उपकर को करों के विभाज्य पूल के दायरे से बाहर रखने की अनुमति देता है जिसे केंद्र सरकार को राज्यों के साथ साझा करना चाहिए।
- स्वतंत्रता के बाद, उपकर करों को शुरू में एक विशेष उद्योग के विकास से जोड़ा गया था, जिसमें 1953 में नमक उपकर और एक चाय उपकर शामिल था।
- 2017 में वस्तु एवं सेवा कर (GST) की शुरुआत के कारण अधिकांश उपकर समाप्त हो गए। अभी मौजूद कुछ उपकर इस प्रकार हैं:
 - कृषि कल्याण सेस
 - स्वच्छ भारत उपकर:
 - स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर
 - सड़क और अवसंरचना उपकर,
 - अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर,
 - राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कर्तव्य
 - तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर शुल्क
 - जीएसटी मुआवजा उपकर

सरचार्ज/ अधिभार (Surcharge)

- सरचार्ज एक अतिरिक्त शुल्क या मौजूदा कर पर लगाया जाने वाला कर है।
- एक उपकर के विपरीत, जो अस्थायी आवश्यकता के लिए राजस्व जुटाने के लिए होता है, अधिभार आमतौर पर प्रकृति में स्थायी होता है।
- अधिभार के माध्यम से अर्जित राजस्व पूरी तरह से केंद्र द्वारा बनाए रखा जाता है और अन्य कर राजस्व के विपरीत, राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता है।
- अधिभार भारत के समेकित कोष (CFI) में जाता है और इसे किसी भी उद्देश्य के लिए खर्च किया जा सकता है। उपकर भी CFI में जाता है लेकिन इसे केवल विशिष्ट उद्देश्यों के लिए ही खर्च किया जा सकता है।
- भारत में अधिभार का उपयोग कराधान प्रणाली को अधिक 'प्रगतिशील' बनाने के लिए किया जाता है।

277. प्रेषण (Remittances)

संदर्भ: विश्व बैंक के प्रवासन और विकास संक्षिप्त के नवीनतम संस्करण के अनुसार, कोविड -19 के बावजूद, प्रेषण प्रवाह 2020 में लचीला बना रहा, जिसमें पहले की तुलना में कम गिरावट दर्ज की गई।

प्रेषण के बारे में

- प्रेषण प्रवासियों से उनके गृह देश में स्थानांतरित किया जाने वाला धन है।
- कई विकासशील देशों के लिए, विदेशों में काम कर रहे नागरिकों से प्रेषण बहुत आवश्यक धन का एक आयात स्रोत प्रदान करता है। प्रेषण गृह देश में परिवारों को भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और बुनियादी जरूरतों को वहन करने में मदद करते हैं।
- प्रेषण कम आय वाले और विकासशील देशों के लोगों के लिए आय के सबसे बड़े स्रोतों में से एक का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह अक्सर प्रत्यक्ष निवेश और आधिकारिक विकास सहायता की राशि से अधिक होता है।

- पूंजी प्रवाह की तुलना में प्रेषण प्रवाह अधिक स्थिर होते हैं, और वे प्रतिचक्रिय होते हैं - आर्थिक मंदी के दौरान या प्राकृतिक आपदा के बाद जब निजी पूंजी प्रवाह में कमी आती है।
- भारत प्रेषण का विश्व का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है। प्रेषण भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करता है और इसके चालू खाते के घाटे को पूरा करने में मदद करता है।

प्रेषण से जुड़ी संभावित लागतें हैं।

- प्रवासियों से प्रेषण प्राप्त करने वाले देश लागत वहन करते हैं यदि उत्प्रवास करने वाले श्रमिक अत्यधिक कुशल हैं या यदि उनके प्रस्थान से श्रम की कमी होती है।
- इसके अलावा, यदि प्रेषण बढ़े हैं, तो प्राप्तकर्ता देश को 'रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट' (**Real Effective Exchange Rate-REER**) का सामना करना पड़ सकता है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी अर्थव्यवस्था को कम प्रतिस्पर्धी बना सकता है।
- कुछ लोगों का तर्क है कि प्रेषण, प्राप्तकर्ताओं के काम करने के प्रोत्साहन को कम कर सकता है और इस प्रकार आर्थिक विकास धीमा कर सकता है।
-
- प्रेषण में मानवीय लागत भी होती है। प्रवासी कभी-कभी महत्वपूर्ण बलिदान करते हैं - जिसमें परिवार से अलग होना भी शामिल है - और दूसरे देश में काम खोजने के लिए जोखिम उठाते हैं।

प्रमुख बिंदु

- विश्व अर्थव्यवस्था को तबाह करने वाली महामारी के बावजूद, भारत शीर्ष पर है, भारत को 2020 में प्रेषण में 83 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक प्राप्त हुआ, जो पिछले वर्ष की तुलना में केवल 0.2 प्रतिशत कम है।
- 2020 में वैश्विक प्रेषण के मामले में चीन दूसरे स्थान पर है, जिसने 2020 में प्रेषण में 59.5 बिलियन अमरीकी डालर प्राप्त किए।
- भारत और चीन के बाद मैक्सिको, फिलीपींस, मिस्र, पाकिस्तान, फ्रांस और बांग्लादेश का स्थान है।
- प्रेषण बहिर्वाह संयुक्त राज्य अमेरिका (68 बिलियन अमरीकी डालर) से अधिकतम था, इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और चीन का स्थान था।

प्रेषण के सतत प्रवाह का कारण:

- राजकोषीय प्रोत्साहन जिसके परिणामस्वरूप मेजबान देशों में अपेक्षित आर्थिक स्थिति बेहतर हुई।
- नकदी से डिजिटल और अनौपचारिक से औपचारिक चैनलों की ओर प्रवाह में बदलाव।
- तेल की कीमतों और मुद्रा विनिमय दरों में चक्रीय उतार-चढ़ाव।

278. एफडीआई और एफपीआई के बीच अंतर (Difference between FDI & FPI)

संदर्भ: वित्त वर्ष 2020-21 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में 10% (82 अरब डॉलर) की वृद्धि देखी गई है। FDI इक्विटी निवेश 19% बढ़कर 60 अरब डॉलर हो गया।

- 2019-20 में भारत को FDI में 74.39 बिलियन डॉलर प्राप्त हुए, जिसमें लगभग 50 बिलियन डॉलर इक्विटी निवेश के रूप में आए थे।

प्रमुख बिंदु

- सिंगापुर सभी निवेशों के लगभग एक तिहाई के साथ शीर्ष निवेशक के रूप में उभरा, इसके बाद अमेरिका का 23% एफडीआई और मॉरीशस का हिस्सा था जहां से 9% विदेशी पूंजी प्रवाह उत्पन्न हुआ।
- 2020-21 में गुजरात शीर्ष एफडीआई गंतव्य था, जिसमें विदेशी इक्विटी प्रवाह का 37% हिस्सा था, इसके बाद महाराष्ट्र (दूसरा) था, जिसे 27% इक्विटी प्रवाह मिला।
- कर्नाटक (तीसरा) ने इक्विटी निवेश का अन्य 13% हिस्सा लिया।
-
- कुल FDI इक्विटी प्रवाह का लगभग 44% हिस्सा 2020-21 के दौरान कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर शीर्ष क्षेत्र के रूप में उभरा है। इसके बाद क्रमशः निर्माण (बुनियादी ढांचे) गतिविधियाँ (13%) और सेवा क्षेत्र (8%) का स्थान है।

	FDI	FII
1	FDI is when foreign company brings capital into a country or an economy to set up a production or some other facility. FDI gives the foreign company some control in the operations of the company	FII is when a foreign company buys equity in a company through the stock markets. Therefore, in this case, FII would not give the foreign company any control in the company
2	FDI involves in the direct production activity & also of medium to long term nature	FII is a short term investment mostly in the financial markets & it consist of FII
3	It enables a degree of control in the company	It does not involve obtaining a degree of control in a company
4	FDI brings-long term capital	FII brings short-term capital
5	Any investment above 10% treated as FDI	Allowed to invest up to 10% of the paid-up capital
6	More stable	less stable
7	Only targets specific enterprise	It increases capital availability in general
8	Difficult entry and exit	Easy entry-exit
9	Investment inflows in the primary market	Investment inflows in the secondary market
10	Critical driver of economic growth	Gives impetus to the equity market of the country

279. सूचकांक संबद्ध बीमा पॉलिसियां (Index Linked Insurance Policies - ILIP)

संदर्भ: भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा गठित एक समिति ने इंडेक्स-लिंकड बीमा पॉलिसियों (ILIP) को शुरू करने की सिफारिश की है।

सूचकांक लिंकड बीमा पॉलिसियों के बारे में

- ILIP से मिलने वाले रिटर्न को बेंचमार्क इंडेक्स से जोड़ा जाएगा।
- ILIP बेंचमार्क सूचकांकों से जुड़े बीमा उत्पाद हैं। इसमें 10 साल का सॉबरेन बॉन्ड इंडेक्स, सेसेक्स या निफ्टी आदि शामिल हैं।
 - सरकारी बॉन्ड से जुड़े ILIP कम जोखिम वाले होते हैं जबकि इक्विटी आधारित सूचकांकों से जुड़े लोग शेयर बाजार के प्रदर्शन के अनुसार रिटर्न में उतार-चढ़ाव से गुजरेंगे।
- ILIP वर्तमान पारंपरिक गारंटीशुदा उत्पादों (वार्षिकियां और बचत उत्पादों सहित) और यूनिट-लिंक्ड बीमा योजनाओं (ULIP) के लिए एक वैकल्पिक या पूरक विकल्प हो सकता है।
- ILIP को उत्पादों के एक सूट के रूप में देखा जा सकता है जिसमें ग्राहकों को उत्पाद संरचना और लाभों के संबंध में अधिक पारदर्शिता की सुविधा दी जा सकती है और जहां जोखिम ग्राहकों द्वारा किए गए विकल्प के अनुरूप हैं।
- ILIP को धारा 10(10डी) और बीमा पॉलिसी अधिनियम की कर योग्यता के तहत जीवन बीमा पॉलिसी के रूप में माना जा सकता है।

भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI)

- यह एक स्वायत्त, सांविधिक निकाय है जिसे भारत में बीमा और पुनः बीमा उद्योगों और बीमा एजेंसी को विनियमित और बढ़ावा देने का कार्य दिया गया है।
- भारत सरकार द्वारा 1999 में संसद का एक अधिनियम पारित किया गया जिसे बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के रूप में जाना जाता है, जिसके कारण इसका निर्माण हुआ।
- मुख्यालय: हैदराबाद, तेलंगाना।
- यह 10 सदस्यीय निकाय है जिसमें अध्यक्ष, भारत सरकार द्वारा नियुक्त पांच पूर्णकालिक और चार अंशकालिक सदस्य शामिल हैं।

कार्य

- बीमा और पुनः व्यवसाय से जुड़े पेशेवर संगठनों को बढ़ावा देना और विनियमित करना; बीमा कंपनियों द्वारा धन के निवेश को विनियमित करना।
- बीमा पॉलिसी धारकों के अधिकारों की रक्षा करना।
- जीवन बीमा कंपनियों को पंजीकरण प्रमाणन प्रदान करना।
- बीमाकर्ताओं और बिचौलियों या बीमा बिचौलियों के बीच विवादों का निर्णय करना।

280. सामाजिक प्रभाव बांड (Social Impact Bond - SIB)

संदर्भ: दिसंबर 2020 में, पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम (PCMC) ने भारत के पहले सामाजिक प्रभाव बांड (SIB) के सह-निर्माण के लिए UNDP इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

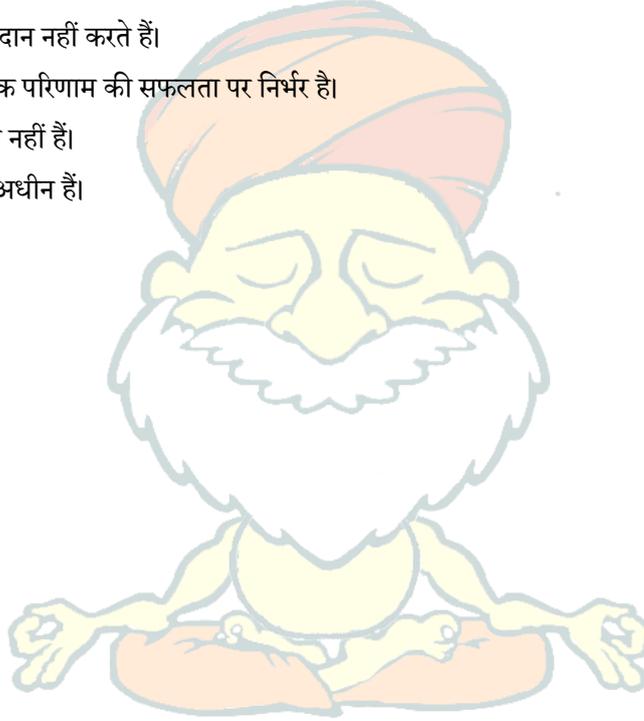
सामाजिक प्रभाव बांड के बारे में (SIB)

- SIB सार्वजनिक क्षेत्र या शासी प्राधिकरण के साथ एक अनुबंध है, जिसके तहत यह कुछ क्षेत्रों में बेहतर सामाजिक परिणामों के लिए भुगतान करता है और निवेशकों को प्राप्त बचत के हिस्से को देता है।

- यह अनुबंध की शुरुआत में प्राप्त किए जाने वाले परिणाम-आधारित लक्ष्यों को निर्धारित करता है।
- यह परिणामों की प्रगति पर नजर रखने की अनुमति देता है, इस प्रकार निवेशकों के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।
- यह SIB अपने नागरिकों के लिए विशेष रूप से महामारी के संबंध में न्यूनतम निवेश जोखिम उठाते हुए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने में PCMC का समर्थन करेगा।
- SIB की शुरुआत सार्वजनिक कल्याण परियोजनाओं को निधि देने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के अधिक निवेशकों को आकर्षित करेगी और इस प्रकार निवेश घाटे को पूरा करने में मदद करेगी।
- यह पहली बार है कि एक सरकारी निकाय एक बांड में 'परिणाम निधि' के रूप में कार्य करेगा, जबकि परंपरागत रूप से अधिकांश सरकारी वित्त पोषित सार्वजनिक परियोजनाओं को सरकार द्वारा परिणामों की पर्याप्त अवधि के साथ बड़े और शुरुआती निवेश की आवश्यकता होती है और इसमें विभिन्न प्रकार के जोखिम शामिल होते हैं।

सामाजिक प्रभाव बांड की मुख्य विशेषताएं

- वे एक निश्चित अवधि में काम करते हैं।
- वे लाभ की एक निश्चित दर प्रदान नहीं करते हैं।
- परिणाम पूरी तरह से सामाजिक परिणाम की सफलता पर निर्भर है।
- वे बाजार जोखिम से प्रभावित नहीं हैं।
- वे मुद्रास्फीति के जोखिम के अधीन हैं।





IASBABA'S

**RAPID REVISION (RaRe)
SERIES - UPSC 2021**

RaRe Notes Hindi

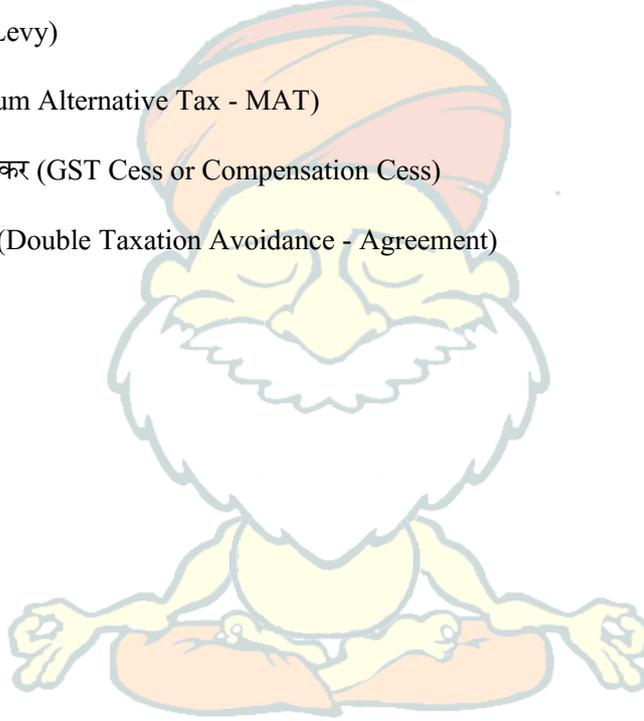
DAY 39 - ECONOMY

#RaRebaba

www.rrs.iasbaba.com

विषय

281. नैशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (NATIONAL FINANCIAL REPORTING AUTHORITY - NFRA)
282. ई-वे बिल (E-Way Bill)
283. मुद्रा स्वैप सुविधा (Currency Swap Facility)
284. विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves)
285. उदारीकृत प्रेषण योजना (Liberalized Remittance Scheme - LRS)
286. एंटी डंपिंग ड्यूटी (Anti – Dumping Duty)
287. समतुल्य लेवी (Equalisation Levy)
288. न्यूनतम वैकल्पिक कर (Minimum Alternative Tax - MAT)
289. जीएसटी उपकर या मुआवजा उपकर (GST Cess or Compensation Cess)
290. दोहरा कराधान परिहार समझौता (Double Taxation Avoidance - Agreement)



281. नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (NATIONAL FINANCIAL REPORTING AUTHORITY - NFRA)

समाचार में: राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (NFRA) उन कंपनियों (सार्वजनिक हित संस्थाओं) और लेखा परीक्षकों का एक सत्यापित और सटीक डेटाबेस बनाने की प्रक्रिया में है जो इसके नियामक दायरे में आते हैं।

- इस संबंध में, NFRA कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) के कॉर्पोरेट डेटा प्रबंधन (CDM) डिवीजन और भारत में तीन मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के साथ जुड़ा हुआ है।

NFRA के बारे में -

- यह एक ऑडिट रेगुलेटर है।
- NFRA का गठन 2018 में भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 (1) के तहत किया गया था।
- NFRA के गठन का फैसला लेखापरीक्षकों और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की भूमिका के बाद लिया गया था, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक सहित विभिन्न कॉर्पोरेट घोटालों में कथित खामियों को उजागर किया गया था।

	NFRA की मुख्य विशेषताएं
संगठन	<ul style="list-style-type: none"> ● इसमें एक अध्यक्ष होता है, जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त लेखा, लेखा परीक्षा, वित्त या कानून में श्रेष्ठता और विशेषज्ञता वाला व्यक्ति होगा। ● और ऐसे अन्य सदस्य जिनकी संख्या 15 से अधिक न हों।
कार्य और कर्तव्य	<ul style="list-style-type: none"> ● केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन के लिए कंपनियों द्वारा अपनाई जाने वाली लेखांकन और लेखा परीक्षा नीतियों और मानकों की सिफारिश करना। ● लेखा मानकों और लेखा परीक्षा मानकों के अनुपालन की निगरानी और प्रवर्तना। ● ऐसे मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने से जुड़े व्यवसायों की सेवा की गुणवत्ता की निगरानी करना और सेवा की गुणवत्ता में सुधार के उपाय सुझाना। ● सार्वजनिक हित की रक्षा करना।
शक्तियां	<p>यह निम्नलिखित श्रेणी की कंपनियों और कारपोरेट निकायों से संबंधित जांच कर सकता है जिसे जनहित संस्थाएं कहा जाता है:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ऐसी कंपनियाँ जिनकी प्रतिभूतियाँ भारत में या भारत के बाहर किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं। ● गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियाँ जिनकी चुकता पूंजी रु. 500 करोड़ या 1,000 करोड़ रुपये से कम का वार्षिक कारोबार नहीं है, या तत्काल वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक कुल बकाया ऋण, डिबेंचर और जमा राशि 500 करोड़ से कम है। ● बीमा कंपनियाँ, बैंकिंग कंपनियाँ, बिजली उत्पादन या आपूर्ति में लगी कंपनियाँ, <p>कोई अन्य संस्थान कदाचार के ऐसे मामलों में कोई कार्यवाही शुरू नहीं करेगा जहां NFRA ने जांच शुरू की है।</p>

	<p>इसे या तो स्वप्रेरणा से या केंद्र सरकार द्वारा इसे दिए गए किसी संदर्भ पर जांच करने की शक्ति होगी, इसके पास वही शक्तियाँ होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत एक दीवानी अदालत में निहित हैं,</p> <p>प्रक्रिया, 1908, के मामलों में एक मुकदमे की कोशिश करते हुए:</p> <p>खाते की पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों की खोज और उत्पादन; व्यक्तियों को बुलाना और उन्हें उपस्थिति सुनिश्चित कराना और शपथ पर उनकी परीक्षा करना; किसी भी पुस्तक, रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण।</p> <p>जहां पेशेवर या अन्य कदाचार साबित होता है, वहां जुर्माना लगाने और सीए या फर्म को 10 साल तक के लिए प्रतिबंधित करने का आदेश देने की शक्ति है।</p>
मुख्यालय	नई दिल्ली
जवाबदेही	<ul style="list-style-type: none"> • इसके खाते की निगरानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। • NFRA वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी गतिविधियों का पूरा लेखा-जोखा देते हुए अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और इसकी एक प्रति केंद्र सरकार को अग्रेषित करेगा और केंद्र सरकार वार्षिक रिपोर्ट संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेगी।

- ICAI (इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया) निजी लिमिटेड कंपनियों और सार्वजनिक गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में अपनी भूमिका जारी रखेगा, जो नियमों में अधिसूचित की जाने वाली सीमा से नीचे हैं।
- ICAI, NFRA की सिफारिशों के माध्यम से सलाहकार की भूमिका निभाना जारी रखेगा।
- गैर सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निर्धारित सीमा से नीचे अन्य की गुणवत्ता लेखा परीक्षा की निगरानी गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड (QRB) द्वारा की जाएगी।

282. ई-वे बिल (E-Way Bill)

समाचार में: राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान, ट्रांसपोर्टर्स ने समाप्त हो चुके इलेक्ट्रॉनिक वे (ई-वे) बिलों से उत्पन्न होने वाले संभावित दंड पर चिंता व्यक्त की थी।

इलेक्ट्रॉनिक वे बिल

- GST के तहत इलेक्ट्रॉनिक रोड परमिट द्वारा वस्तुओं का एक राज्य से दूसरे राज्य के भीतर या बाहर आवागमन ई-वे बिल के जरिए होता है।
- 50,000 से अधिक राशि के वस्तुओं के आवागमन के लिए विक्रेता और खरीददाता को ई-वे बिल की आवश्यकता होती है।
- ई-वे बिल सभी प्रकार की सामग्री जैसे स्टॉक की बिक्री या ट्रांसफर, कैपिटल गुड्स, नौकरी के काम के लिए भेजे गए सामान या बिजनेस के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रकम के लिए जरूरी होता है।
- जब एक ई-वे बिल जनरेट होता है, तो एक अद्वितीय ई-वे बिल नंबर (EBN) आवंटित किया जाता है जो आपूर्तिकर्ता, प्राप्तकर्ता और ट्रांसपोर्टर को उपलब्ध होता है।
- ट्रांसपोर्टर को माल की आवाजाही के लिए समर्थन दस्तावेजों के रूप में चालान और ई-वे बिल की प्रति ले जानी होती है।

- हालांकि जीएसटी के तहत चेक-पोस्ट को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन माल के सभी राज्य के भीतर और राज्य के बाहर गतिविधि के लिए ई-वे बिल के सत्यापन के लिए किसी भी बिंदु पर एक खेप को रोका जा सकता है।
- यदि ई-वे बिल के बिना कोई खेप पाई जाती है, तो 10,000 रूपए का जुर्माना या कर चोरी की रकम, जो भी अधिक हो, लगाया जा सकता है।
- एक ई-वे बिल को समाप्ति से पहले ट्रांसपोर्टर द्वारा पुनः जनरेट किया जा सकता है, लेकिन, यदि ई-वे बिल की समय सीमा समाप्त हो गई है, तो सिस्टम उसी चालान से जुड़े पुनर्जनन की अनुमति नहीं देगा।

ई-वे बिल का लाभ

- अंतर्राज्यीय जांच बिंदुओं पर लगने वाले समय को समाप्त करना। पहले भारत में एक सामान्य ट्रक अपना 20% समय अंतर-राज्यीय चौकियों में व्यतीत करता था।
- ई-वे बिल कर-चोरी को कम करने में मदद करता है क्योंकि प्रेषक और खरीदार दोनों द्वारा उत्पन्न प्रत्येक ई-वे बिल को जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के लिए अद्यतन किया जाता है।
- पिछली कर व्यवस्था में, कर अधिकारियों को बिल को मैन्युअल रूप से क्रॉस-चेक करना पड़ता था।
- देश भर में माल की आवाजाही के लिए सिंगल इलेक्ट्रॉनिक वे बिल से काफी कागजी कार्रवाई की बचत होगी।
- **LPI** में सुधार परफॉर्म (लॉजिस्टिक्सस इंडेक्स Logistics Performance Index)
- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार।
- इससे सरकार के राजस्व में 20% की वृद्धि हो सकती है।

283. मुद्रा स्वैप सुविधा (Currency Swap Facility)

समाचार में: बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक ने श्रीलंका को \$200 बिलियन की मुद्रा स्वैप सुविधा को मंजूरी दी है।

- आरबीआई ने नवंबर 2022 तक श्रीलंका के लिए 40 करोड़ डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा के लिए सहमति व्यक्त की है।

इसके बारे में

- स्वैप शब्द का अर्थ है विनिमय।
- दो देशों के बीच एक मुद्रा स्वैप पूर्व निर्धारित नियमों और शर्तों के साथ मुद्राओं का आदान-प्रदान करने के लिए एक समझौता या अनुबंध है।
- केंद्रीय बैंक और सरकारें अल्पकालिक विदेशी मुद्रा तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या लंबी व्यवस्था किए जाने तक भुगतान संतुलन (BoP) संकट से बचने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा सुनिश्चित करने के लिए विदेशी समकक्षों के साथ मुद्रा स्वैप में संलग्न हैं।
- इन स्वैप परिचालनों में कोई विनिमय दर या अन्य बाजार जोखिम नहीं होते हैं क्योंकि लेनदेन की शर्तें अग्रिम रूप से निर्धारित की जाती हैं।
 - विनिमय दर जोखिम, जिसे मुद्रा जोखिम के रूप में भी जाना जाता है, एक विदेशी मुद्रा के खिलाफ आधार मुद्रा के मूल्य में उतार-चढ़ाव से उत्पन्न होने वाला वित्तीय जोखिम है जिसमें किसी कंपनी या व्यक्ति की संपत्ति या दायित्व होते हैं।

बांग्लादेश-श्रीलंका समझौता

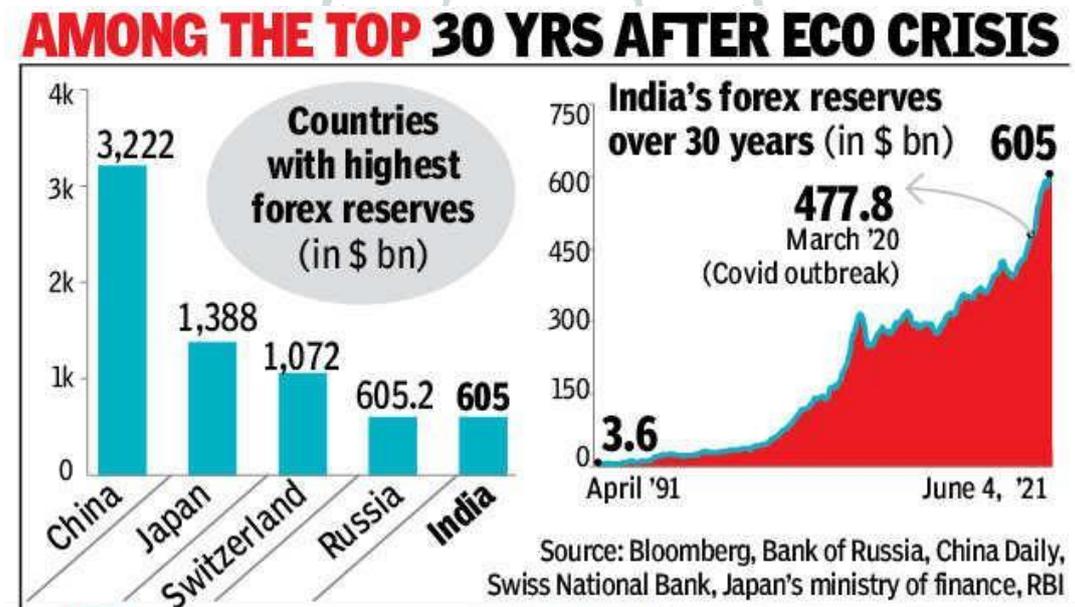
- वर्तमान संदर्भ में, एक मुद्रा स्वैप प्रभावी रूप से एक ऋण है जो बांग्लादेश श्रीलंका को डॉलर में देगा, इस समझौते के साथ कि ऋण श्रीलंकाई रुपये में ब्याज के साथ चुकाया जाएगा।
- श्रीलंका के लिए, यह बाजार से उधार लेने की तुलना में सस्ता है, और एक जीवन रेखा है क्योंकि यह अपने बाहरी ऋणों के पुनर्भुगतान के रूप में पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है।

सार्क के लिए स्वैप सुविधाओं के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की रूपरेखा:

- सार्क मुद्रा स्वैप सुविधा 15 नवंबर, 2012 को लागू हुई।
- आरबीआई 2 बिलियन अमरीकी डालर के समग्र कोष के भीतर स्वैप व्यवस्था की पेशकश कर सकता है।
- स्वैप निकासी अमेरिकी डॉलर, यूरो या भारतीय रुपये में की जा सकती है। यह ढांचा भारतीय रुपये में स्वैप निकासी के लिए कुछ रियायतें प्रदान करता है।
- यह सुविधा सभी सार्क सदस्य देशों को उपलब्ध होगी, जो द्विपक्षीय स्वैप समझौतों पर हस्ताक्षर करने के अधीन होंगे।

284. विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves)

समाचार में: भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, 25 जून, 2021 को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा (विदेशी मुद्रा) भंडार \$ 5 बिलियन बढ़कर \$ 609 बिलियन हो गया।



विदेशी मुद्रा के बारे में

- विदेशी मुद्रा भंडार एक केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्राओं में आरक्षित संपत्ति है, जिसमें बांड, ट्रेजरी बिल और अन्य सरकारी प्रतिभूतियां शामिल हो सकती हैं।
- भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल हैं:

- विदेशी मुद्रा संपत्ति
- स्वर्ण भंडार
- विशेष आहरण अधिकार
- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के साथ रिजर्व स्थिति
- इन भंडार का उपयोग देनदारियों को वापस करने, आरबीआई बाजार के हस्तक्षेप के माध्यम से विनिमय दर को प्रभावित करने और मौद्रिक नीति को प्रभावित करने के लिए किया जाता है।

बढ़ते विदेशी मुद्रा भंडार का महत्व:

- सरकार के लिए आरामदायक स्थिति: भारत के बाहरी और आंतरिक वित्तीय मुद्दों के प्रबंधन में।
- संकट का प्रबंधन: यह आर्थिक मोर्चे पर भुगतान संतुलन (BoP) संकट की स्थिति में एक कुशन के रूप में कार्य करता है।
- रूपए का मूल्यहास: बढ़ते भंडार ने भी डॉलर के मुकाबले रुपये को मजबूत करने में मदद की है।
- बाजार में विश्वास: भंडार बाजारों और निवेशकों को विश्वास का स्तर प्रदान करेगा कि एक देश अपने बाहरी दायित्वों को पूरा कर सकता है।

विशेष आहरण अधिकार (Special Drawing Rights - SDR)

- SDR एक अंतरराष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है, जिसे IMF ने 1969 में अपने सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार के पूरक के लिए बनाया था।
- SDR न तो मुद्रा है और न ही IMF पर दावा। बल्कि, यह IMF सदस्यों की स्वतंत्र रूप से उपयोग करने योग्य मुद्राओं पर एक संभावित दावा है। इन मुद्राओं के लिए SDR का आदान-प्रदान किया जा सकता है।
- SDR के मूल्य की गणना अमेरिकी डॉलर, यूरो, जापानी येन, चीनी युआन और ब्रिटिश पाउंड सहित प्रमुख मुद्राओं की भारित टोकरी से की जाती है।
- SDR या (SDRI) पर ब्याज दर सदस्यों को उनके SDR स्वामित्व पर दिया जाने वाला ब्याज है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में आरक्षित स्थिति

- एक आरक्षित किश्त की स्थिति का तात्पर्य मुद्रा के आवश्यक कोटे के एक हिस्से से है जिसे प्रत्येक सदस्य देश को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) को प्रदान करना चाहिए जिसका उपयोग अपने उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।
- आरक्षित किश्त मूल रूप से एक आपातकालीन खाता है जिसे IMF सदस्य किसी भी समय शर्तों से सहमत हुए या सेवा शुल्क का भुगतान किए बिना अभिगम कर सकते हैं।

285. उदारकृत प्रेषण योजना (Liberalized Remittance Scheme - LRS)

- यह भारतीय रिजर्व बैंक की योजना है, जिसे वर्ष 2004 में शुरू किया गया था।
- इस योजना के तहत, नाबालिगों सहित सभी निवासी व्यक्तियों को किसी भी अनुमेय चालू या पूंजी खाता लेनदेन या दोनों के संयोजन के लिए प्रति वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) में 2,50,000 अमेरिकी डॉलर तक मुक्त रूप से विप्रेषित करने की अनुमति है।

- यह योजना निगमों, साझेदारी फर्मों, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF), ट्रस्ट आदि के लिए उपलब्ध नहीं है।
- हालांकि LRS के तहत प्रेषण की आवृत्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है, एक बार वित्तीय वर्ष के दौरान 2,50,000 अमरीकी डालर तक की राशि के लिए प्रेषण किए जाने के बाद, एक निवासी व्यक्ति इस योजना के तहत कोई और प्रेषण करने के लिए पात्र नहीं होगा।
- निवासी व्यक्ति के लिए अधिकृत व्यक्तियों के माध्यम से किए गए LRS के तहत सभी लेनदेन के लिए अपना स्थायी खाता संख्या (पैन) प्रदान करना अनिवार्य है।

प्रेषित धन का उपयोग इसके लिए किया जा सकता है:

- यात्रा (निजी या व्यवसाय के लिए), चिकित्सा उपचार, अध्ययन, उपहार और दान, करीबी रिश्तेदारों के रखरखाव आदि से संबंधित खर्च।
- शेयरों, ऋण लिखतों में निवेश और विदेशी बाजार में अचल संपत्तियों की खरीद।
- व्यक्ति योजना के तहत अनुमत लेनदेन करने के लिए भारत के बाहर के बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा खाते खोल सकते हैं, बनाए रख सकते हैं।

प्रेषित धन का उपयोग इसके लिए नहीं किया जा सकता है:

- अनुसूची-I (जैसे लॉटरी टिकटों, प्रतिबंधित पत्रिकाओं, आदि की खरीद) के तहत विशेष रूप से निषिद्ध कोई भी उद्देश्य या विदेशी मुद्रा प्रबंधन (चालू खाता लेनदेन) नियम, 2000 की अनुसूची II के तहत प्रतिबंधित कोई भी वस्तु।
- विदेश में विदेशी मुद्रा में व्यापार।
- वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) द्वारा समय-समय पर "गैर-सहकारी देशों और क्षेत्रों" के रूप में पहचाने जाने वाले देशों को पूंजी खाता प्रेषण, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से।
- उन व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रेषण, जिनकी पहचान रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को अलग से सूचित आतंकवाद के कृत्यों के एक महत्वपूर्ण जोखिम के रूप में की गई है।

286. एंटी डंपिंग ड्यूटी (Anti – Dumping Duty)

- डंपिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक कंपनी किसी उत्पाद को उस कीमत पर निर्यात करती है जो उस कीमत से काफी कम है जो वह आमतौर पर अपने घरेलू (या अपने घरेलू) बाजार में वसूलती है।
- एक डंपिंग रोधी शुल्क एक संरक्षणवादी शुल्क है जो एक घरेलू सरकार विदेशी आयात पर लगाती है जिसे वह मानता है कि डंप किया गया है।
 - यह इस तर्क के साथ किया जाता है कि इन उत्पादों में स्थानीय व्यवसायों और स्थानीय अर्थव्यवस्था को कम करने की क्षमता है।
- माल की डंपिंग और उसके व्यापार विकृत प्रभाव से उत्पन्न स्थिति को सुधारने के लिए एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है।
- विश्व व्यापार संगठन (WTO) शासन सहित वैश्विक व्यापार मानदंडों के अनुसार, किसी देश को घरेलू निर्माताओं को एक स्तर का खेल मैदान प्रदान करने के लिए ऐसे उत्पादों पर शुल्क लगाने की अनुमति है।

- यह शुल्क भारत में व्यापार उपचार महानिदेशालय (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) जैसे अर्ध-न्यायिक निकाय द्वारा गहन जांच के बाद ही लगाया जाता है।

- जबकि एंटी-डॉपिंग शुल्क का उद्देश्य घरेलू नौकरियों को बचाने के लिए है, इन शुल्कों से घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कीमतें भी बढ़ सकती हैं।
- लंबी अवधि में, एंटी-डॉपिंग शुल्क समान वस्तुओं का उत्पादन करने वाली घरेलू कंपनियों की अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को कम कर सकता है।

काउंटरवेलिंग ड्यूटी (CVD) से अलग:

- घरेलू उत्पादकों की सुरक्षा के लिए आयात सब्सिडी के नकारात्मक प्रभाव का मुकाबला करने के लिए CVD लगाया जाता है।
- काउंटरवेलिंग ड्यूटी (CVD) निर्यातक देश में इन वस्तुओं के उत्पादकों को दी जाने वाली सब्सिडी को ऑफसेट करने के लिए आयातित वस्तुओं पर लगाए गए शुल्क हैं।
- CVD का उद्देश्य किसी उत्पाद के घरेलू उत्पादकों और उसी उत्पाद के विदेशी उत्पादकों के बीच खेल के मैदान को समतल करना है जो अपनी सरकार से मिलने वाली सब्सिडी के कारण इसे कम कीमत पर बेचने का जोखिम उठा सकते हैं।

287. समतुल्य लेवी (Equalisation Levy)

समाचार में: जुलाई 2020 में, केंद्र सरकार ने कहा है कि वह अनिवासी ई-कॉमर्स अभिकर्ताओं द्वारा समान लेवी के भुगतान की समय सीमा नहीं बढ़ाएगी, भले ही उनमें से अधिकांश को कर की पहली किस्त जमा करना बाकी है।

इसके बारे में

- समतुल्य लेवी (Equalisation Levy) का उद्देश्य उन विदेशी कंपनियों पर कर लगाना है, जिनके पास भारत में एक महत्वपूर्ण स्थानीय ग्राहक आधार है, लेकिन वे देश की कर प्रणाली से प्रभावी रूप से बचकर अपनी अपतटीय इकाइयों के माध्यम से बिलिंग कर रही हैं।
- ऑनलाइन विज्ञापनों के लिए एक अनिवासी सेवा प्रदाता को प्रति वर्ष 1 लाख रुपये से अधिक के भुगतान पर 6% की दर से समतुल्य लेवी 2016 से लागू है।
 - उदाहरण: आईएसबाबा अपनी वेबसाइटों पर विज्ञापन रखने के लिए गूगल (अनिवासी सेवा प्रदाता) को 1,50,000 रुपये का भुगतान करता है। फिर, 6% (1.5 लाख का) स्रोत पर कटौती की जाती है और गूगल पर लगाए गए समतुल्य लेवी के रूप में भारतीय कर अधिकारियों को भुगतान किया जाता है।
- वित्त अधिनियम, 2020 में संशोधन ने 2% प्रभावी लेवी के साथ वस्तुओं की ऑनलाइन बिक्री और सेवाओं के प्रावधान सहित सेवाओं की आपूर्ति में शामिल अनिवासी ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए समतुल्य लेवी के दायरे का विस्तार किया था, जो 1 अप्रैल 2020 से लागू है।

शामिल दंड:

- भुगतान न करने पर ब्याज के साथ समतुल्य लेवी की राशि के बराबर जुर्माना लगाया जा सकता है।
- देर से भुगतान 1% प्रति माह या महीने के हिस्से की दर से ब्याज को आकर्षित करेगा।

288. न्यूनतम वैकल्पिक कर (Minimum Alternative Tax - MAT)

- कई बार ऐसा हो सकता है कि करदाता कंपनी होने के नाते कंपनी ने वर्ष के दौरान आय अर्जित की हो, लेकिन आयकर कानून के विभिन्न प्रावधानों (जैसे छूट, कटौती, मूल्यहास, आदि) का लाभ उठाकर, इसने अपनी कर देयता या किसी भी कर का भुगतान नहीं किया हो।

- MAT की अवधारणा उन कंपनियों को लक्षित करने के लिए पेश की गई थी जो भारी मुनाफा कमाती हैं और अपने शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान करती हैं, लेकिन आयकर अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत कोई/न्यूनतम कर का भुगतान नहीं करती हैं।
- न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) वित्त अधिनियम, 1987 द्वारा मूल्यांकन वर्ष 1988-89 से लागू किया गया था। बाद में, इसे वित्त अधिनियम, 1990 द्वारा वापस ले लिया गया और फिर वित्त अधिनियम, 1996 द्वारा पुनः प्रस्तुत किया गया।
- न्यूनतम वैकल्पिक कर आयकर अधिनियम के तहत देय है। यहां, कंपनियों को अपने मुनाफे का एक निश्चित प्रतिशत न्यूनतम वैकल्पिक कर के रूप में देना होता है।
- MAT की गणना बुक प्रॉफिट (लाभ और हानि खाते में दिखाया गया लाभ) या सामान्य कॉर्पोरेट दरों पर 15% (प्लस अधिभार और उपकर लागू) पर की जाती है, और जो भी अधिक हो, कर के रूप में देय है।
 - अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की एक इकाई होने और केवल परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में अपनी आय प्राप्त करने वाली कंपनी के मामले में MAT 9% (लागू अधिभार और उपकर) की दर से लगाया जाता है।
- भारत में सभी कंपनियां, चाहे घरेलू हों या विदेशी, इस प्रावधान के अंतर्गत आती हैं। MAT को बाद में गैर-कॉर्पोरेट संस्थाओं को भी कवर करने के लिए बढ़ा दिया गया था।
- MAT एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिससे कर बचाव को रोका जा सकता है।
- MAT के प्रावधान केवल कॉर्पोरेट करदाता पर लागू होते हैं, जबकि वैकल्पिक न्यूनतम कर (AMT) कंपनी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति पर लागू होता है (समान अवधारणा)।
 - MAT किसी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार या व्यक्तियों के संघ या व्यक्तियों के निकाय पर लागू होगा।
 - समायोजित कुल आय का 18.5% @ MAT लगाया जाता है।

289. जीएसटी उपकर या मुआवजा उपकर (GST Cess or Compensation Cess)

- जीएसटी मुआवजा उपकर माल और सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम 2017 द्वारा लगाया जाता है।
- इस उपकर को लगाने का उद्देश्य 1 जुलाई 2017 को GST के कार्यान्वयन के कारण होने वाले राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को पांच साल की अवधि या जीएसटी परिषद द्वारा अनुशंसित अवधि के लिए क्षतिपूर्ति करना है।
 - GST, खपत आधारित कर होने के कारण, विनिर्माण-भारी राज्यों के लिए राजस्व का नुकसान होगा।
- अधिसूचित वस्तुओं पर नियमित GST के अलावा GST मुआवजा उपकर लगाया जाता है, जो ज्यादातर लकजरी और अवगुण श्रेणियों से संबंधित होता है। पूर्व तंबाकू, पान मसाला, कोयला, ऑटोमोबाइल, वातित जल।
- GST अधिनियम में कहा गया है कि GST परिषद की सिफारिश पर एकत्र उपकर को उपकर क्षतिपूर्ति निधि में जमा किया जाएगा।
- मुआवजे के रूप में निर्धारित फार्मूले के आधार पर नुकसान उठाने वाले राज्यों को आय का वितरण किया जाएगा।

GST क्षतिपूर्ति उपकर की गणना कैसे की जाती है?

- GST उपकर की गणना GST से पहले अधिसूचित वस्तुओं की कीमत पर की जाती है।
- उदाहरण के लिए, कोयले पर मुआवजा उपकर 400 रुपये प्रति टन है।
- यदि आप एक टन कोयला बेचते हैं जिसका मूल्य 5,000 रु है तो 400 का भुगतान रुपये के जीएसटी उपकर के रूप में करना होगा। इसके अतिरिक्त, उसी के लिए 5% की दर से जीएसटी 250 रु।
- इसलिए, कोयले की आपूर्ति के लिए कुल जीएसटी देयता 750 रु है।

- हालांकि, जब मुआवजा उपकर 1 जुलाई, 2022 को समाप्त होता है, तो कुल जीएसटी देयता केवल 250 रु होगा।

राज्यों को मुआवजा उपकर कैसे वितरित किया जाएगा?

प्रत्येक राज्य को वितरित किए जाने वाले मुआवजे की राशि की गणना निम्नानुसार की जाती है:

चरण 1: आधार राजस्व = वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य का कर राजस्व।

चरण 2: विकास दर को 14% मान लें और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित राजस्व की गणना करें।

अनुमानित राजस्व का निहितार्थ यह है कि यदि जीएसटी लागू नहीं किया गया तो यह वह राजस्व होगा जो एक राज्य अर्जित कर सकता था। यह गणना पांच साल की अवधि के लिए की जाती है क्योंकि मुआवजा उपकर पांच साल की संक्रमण अवधि के लिए प्रभावी हो सकता है।

चरण 3: प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए देय मुआवजे की गणना निम्नानुसार करें

	उस विशेष वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित राजस्व	xxx
(-)	राज्य द्वारा अर्जित वास्तविक राजस्व	yyy
=	राज्य को देय मुआवजा	(xxx-yyy)

290. दोहरा कराधान परिहार समझौता (Double Taxation Avoidance - Agreement)

- DTAA दो या दो से अधिक देशों के बीच हस्ताक्षरित एक कर संधि है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि इन देशों में करदाता एक ही आय के लिए दो बार कर लगाने से बच सकें।
- DTAA उन मामलों में लागू होता है जहां करदाता एक देश में रहता है और दूसरे देश में आय अर्जित करता है।
- यदि कोई व्यक्ति किसी विदेशी देश में व्यापार करना चाहता है, तो वह दोनों ही मामलों में आयकर का भुगतान कर सकता है, अर्थात् वह देश जहां आय अर्जित की जाती है और वह देश जहां व्यक्ति की नागरिकता या निवास है।
- DTAA या तो आय के सभी स्रोतों को कवर करने के लिए व्यापक हो सकता है या कुछ क्षेत्रों तक सीमित हो सकता है जैसे शिपिंग, हवाई परिवहन, विरासत आदि से आय पर कर लगाना।
- भारत ने 80 से अधिक देशों के साथ DTAA पर हस्ताक्षर किए हैं।

DTAA का महत्व

- DTAA का उद्देश्य दोहरे कराधान पर राहत प्रदान करके देश को एक आकर्षक निवेश गंतव्य बनाना है। इस तरह की राहत विदेश में अर्जित आय को निवासी देश में कर से छूट देकर या उस सीमा तक क्रेडिट प्रदान करके प्रदान की जाती है जिस सीमा तक करों का भुगतान विदेश में किया जा चुका है।
- DTAA कुछ मामलों में कर की रियायती दरों का भी प्रावधान करते हैं।

DTAA का दुरुपयोग

- भारत ने मॉरीशस, सिंगापुर, केमैन आइलैंड्स आदि जैसे टैक्स हेवन के साथ DTAA पर हस्ताक्षर किए हैं।
- इन DTAA का भारत में अपनी कर देयता को कम करने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा दुरुपयोग किया गया है।
- उदाहरण के लिए, यदि कंपनी (शेल कंपनी) टैक्स हेवन में पंजीकृत है और भारत में स्थित अपनी सहायक कंपनी के माध्यम से संचालन करती है।
- DTAA के प्रावधानों के तहत, कंपनी केवल टैक्स हेवन देश में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी, यहां तक कि भारत में होने वाले मुनाफे के लिए भी।
- इससे भारत को राजस्व का काफी नुकसान होता है।





IASBABA'S

**RAPID REVISION (RaRe)
SERIES - UPSC 2021**

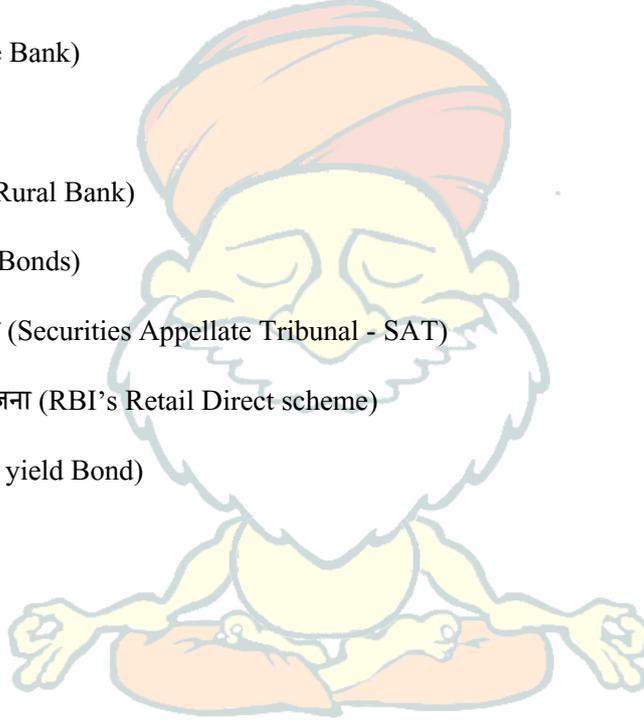
RaRe Notes Hindi

DAY 52 - ECONOMY

#RaRebaba
www.rrs.iasbaba.com

विषय

371. म्युचुअल फंड (Mutual Funds)
372. एक्सचेंज ट्रेडेड फंड - भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (Exchange Traded Fund - Bharat Bond Exchange Traded Fund - ETF)
373. डेरिवेटिव (Derivatives)
374. लघु वित्त बैंक (Small Finance Bank)
375. भुगतान बैंक (Payment Bank)
376. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (Regional Rural Bank)
377. म्युनिसिपल बॉन्ड (Municipal Bonds)
378. प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (Securities Appellate Tribunal - SAT)
379. आरबीआई की खुदरा प्रत्यक्ष योजना (RBI's Retail Direct scheme)
380. नेगेटिव यील्ड बॉण्ड (Negative yield Bond)



371. म्यूचुअल फंड (Mutual Funds)

- म्यूचुअल फंड एक प्रकार का वित्तीय वाहन है जो कई निवेशकों से कई शेयरों, बांडों, मुद्रा बाजार उपकरणों और अन्य परिसंपत्तियों जैसी प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए एकत्र किए गए धन के पूल से बना होता है।
 - म्यूचुअल फंड का एक हिस्सा सिर्फ एक होल्डिंग के बजाय कई अलग-अलग शेयरों (या अन्य प्रतिभूतियों) में निवेश का प्रतिनिधित्व करता है।
 - औसत म्यूचुअल फंड में सौ से अधिक विभिन्न प्रतिभूतियां होती हैं, जिसका अर्थ है कि म्यूचुअल फंड शेयरधारकों को कम कीमत पर महत्वपूर्ण विविधीकरण प्राप्त होता है।
- म्यूचुअल फंड पेशेवर धन प्रबंधकों द्वारा संचालित होते हैं, जो फंड की संपत्ति आवंटित करते हैं और फंड के निवेशकों के लिए पूंजीगत लाभ या आय का उत्पादन करने का प्रयास करते हैं।
- म्यूचुअल फंड छोटे या व्यक्तिगत निवेशकों को इक्विटी, बॉन्ड और अन्य प्रतिभूतियों के पेशेवर रूप से प्रबंधित पोर्टफोलियो तक पहुंच प्रदान करते हैं। इसलिए, प्रत्येक शेयरधारक फंड के लाभ या हानि में आनुपातिक रूप से भाग लेता है।
- म्यूचुअल फंड वार्षिक शुल्क (जिसे व्यय अनुपात कहा जाता है) और, कुछ मामलों में, कमीशन लेते हैं, जो उनके समग्र रिटर्न को प्रभावित कर सकते हैं।
- म्यूचुअल फंड शेयर की कीमत को प्रति शेयर शुद्ध संपत्ति मूल्य (NAV) के रूप में जाना जाता है। एक फंड का NAV पोर्टफोलियो में प्रतिभूतियों के कुल मूल्य को बकाया शेयरों की कुल राशि से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है।
- म्यूचुअल फंड के शेयर में निवेश करना स्टॉक के शेयरों में निवेश करने से अलग है। स्टॉक के विपरीत, म्यूचुअल फंड शेयर अपने धारकों को कोई वोटिंग अधिकार नहीं देते हैं।
- सेबी भारत में प्रतिभूति बाजार और म्यूचुअल फंड उद्योग को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए नियामक निकाय है।

म्यूचुअल फंड की प्रकृति

- एक म्यूचुअल फंड एक निवेश और एक वास्तविक कंपनी दोनों है। यह दोहरी प्रकृति अजीब लग सकती है, लेकिन यह इससे अलग नहीं है कि कैसे AAPL का हिस्सा Apple Inc. का प्रतिनिधित्व करता है।
- जब कोई निवेशक एपल स्टॉक खरीदता है, तो वह कंपनी और उसकी संपत्ति का आंशिक स्वामित्व खरीद रहा होता है। इसी तरह, एक म्यूचुअल फंड निवेशक म्यूचुअल फंड कंपनी और उसकी संपत्ति का आंशिक स्वामित्व खरीद रहा है।
- अंतर यह है कि एपल इनोवेटिव डिवाइस और टैबलेट बनाने के कारोबार में है, जबकि एक म्यूचुअल फंड कंपनी निवेश करने के कारोबार में है।
- यदि एक म्यूचुअल फंड को एक आभासी कंपनी के रूप में माना जाता है, तो इसका सीईओ फंड मैनेजर होता है, जिसे कभी-कभी इसका निवेश सलाहकार भी कहा जाता है।
 - निवेश सलाहकार या फंड मैनेजर कुछ विश्लेषकों को निवेश चुनने या बाजार अनुसंधान करने में मदद करने के लिए नियुक्त कर सकता है।
- अधिकांश म्यूचुअल फंड एक बहुत बड़ी निवेश कंपनी का हिस्सा हैं; सबसे बड़े के पास सैकड़ों अलग-अलग म्यूचुअल फंड हैं।

ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड:

- यहां निवेशक NAV-आधारित मूल्य पर जब चाहें खरीद या बेच सकते हैं।
- जैसे ही निवेशक इकाइयाँ खरीदते और बेचते हैं, जारी की गई इकाइयों की संख्या भी हर दिन बदलती रहती है।
- इसलिए योजना के पोर्टफोलियो का मूल्य और इसलिए, NAV भी दैनिक आधार पर बदलता है।

क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड:

- एक क्लोज-एंडेड फंड आमतौर पर केवल एक बार निवेशकों को इकाइयाँ जारी करता है।
- जब वे एक प्रस्ताव शुरू करते हैं, जिसे भारत में न्यू फंड ऑफर (NFO) कहा जाता है।
- इनका प्रबंधन फंड हाउस द्वारा सीमित वर्षों के लिए किया जाता है।
- और अवधि के अंत में या तो निवेशकों को पैसा वापस कर दिया जाता है या योजना को ओपन एंडेड बना दिया जाता है।
- कोई भी निवेशक एक्सचेंज के माध्यम से इन इकाइयों को खरीद और बेच सकता है।
- इसलिए, इन्हें स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया जाना है।

372. एक्सचेंज ट्रेडेड फंड - भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (Exchange Traded Fund - Bharat Bond Exchange Traded Fund - ETF)

- ETF प्रतिभूतियों की एक टोकरी है जो एक नियमित स्टॉक की तरह एक एक्सचेंज पर व्यापार करती है।
- इसका व्यापारिक मूल्य अंतर्निहित शेयरों (जैसे शेयर) के शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (Net Asset Value - NAV) पर आधारित होता है, जिसका यह प्रतिनिधित्व करता है।
- ETF शेयर की कीमतों में पूरे दिन उतार-चढ़ाव होता है क्योंकि इसे खरीदा और बेचा जाता है। यह म्यूचुअल फंड से अलग है जो बाजार बंद होने के बाद दिन में केवल एक बार व्यापार करता है।
- एक ETF विभिन्न उद्योगों में सैकड़ों या हजारों शेयरों का मालिक हो सकता है, या इसे एक विशेष उद्योग या क्षेत्र में अलग किया जा सकता है।
- ETF निवेशकों को एक विविध निवेश पोर्टफोलियो प्रदान करते हैं, कम व्यय अनुपात, म्यूचुअल फंड की तुलना में व्यक्तिगत रूप से स्टॉक खरीदने से कम ब्रोकर कमीशन और अधिक तरलता की पेशकश करते हैं।
- ETF में स्टॉक, कमोडिटी या बॉन्ड सहित सभी प्रकार के निवेश शामिल हो सकते हैं;
 - बॉन्ड ETF एक प्रकार का ETF है जिसमें सरकारी बॉन्ड, कॉरपोरेट बॉन्ड, और राज्य और स्थानीय बॉन्ड शामिल हो सकते हैं - जिन्हें म्युनिसिपल बॉन्ड कहा जाता है।
 - उद्योग ETF एक विशेष उद्योग जैसे प्रौद्योगिकी, बैंकिंग, या तेल और गैस क्षेत्र को ट्रैक करते हैं।
 - कमोडिटी ETF कच्चे तेल या सोने सहित वस्तुओं में निवेश करते हैं।
 - मुद्रा ETF यूरो या कनाडाई डॉलर जैसी विदेशी मुद्राओं में निवेश करते हैं।

- व्युत्क्रम **ETF** शेयरों को छोटा करके स्टॉक में गिरावट से लाभ अर्जित करने का प्रयास करते हैं। शॉर्टिंग एक स्टॉक बेच रहा है, मूल्य में गिरावट की उम्मीद कर रहा है, और इसे कम कीमत पर पुनर्खरीद कर रहा है।

भारत 22 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF)

- भारत 22 एक ETF है जो 22 शेयरों के प्रदर्शन को ट्रैक करेगा, जिन्हें सरकार विनिवेश करने की योजना बना रही है।
- इसे सरकार द्वारा विभिन्न सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों को शामिल करके लॉन्च किया गया है।
- जारी की गई इकाइयाँ किसी को भी उद्धृत मूल्य पर खरीदने या बेचने के लिए एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध होती हैं।
- B22 बुनियादी सामग्री, ऊर्जा, वित्त, FMCG, उद्योग और उपयोगिताओं जैसे छह क्षेत्रों में फैला होगा।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, खनिकों, निर्माण कंपनियों और ऊर्जा की बड़ी कंपनियों के अलावा, ETF में SUUTI (भारतीय यूनिट ट्रस्ट का निर्दिष्ट उपक्रम) में सरकार की कुछ हिस्सेदारी भी शामिल होगी।
- भारत 22 ETF का प्रबंधन **ICICI** प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड द्वारा किया जाता है।
- भारत 22 ETF की नींव सरकार ने केंद्रीय बजट 2017 में रखी थी।

भारत 22 ETF के लाभ

- सरकार के लिए अपने विनिवेश लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करने के लिए ETF तंत्र एक स्मार्ट, प्रभावी तरीका साबित हुआ है।
- राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कारक है।
- ETF मार्ग सरकार को एक बड़े बास्केट में छोटी हिस्सेदारी (2-3 प्रतिशत) की छूट देकर एक साफ-सुथरा समाधान प्रदान करता है।

373. डेरिवेटिव (Derivatives)

- डेरिवेटिव ऐसे उत्पाद हैं जिनका मूल्य एक या अधिक बुनियादी चर (basic variables) के मूल्य से प्राप्त होता है, जिन्हें अंतर्निहित संपत्ति (Underlying Assets) कहा जाता है।
- अंतर्निहित परिसंपत्ति इक्विटी, सूचकांक, विदेशी मुद्रा (विदेशी मुद्रा), कमोडिटी या कोई अन्य संपत्ति हो सकती है।
- डेरिवेटिव स्वयं दो या दो से अधिक पार्टियों के बीच एक अनुबंध है, और डेरिवेटिव इसकी कीमत अंतर्निहित परिसंपत्ति में उतार-चढ़ाव से प्राप्त करता है।
- डेरिवेटिव के लिए सबसे आम अंतर्निहित संपत्ति स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटीज, मुद्राएं, ब्याज दरें और बाजार सूचकांक हैं। इन परिसंपत्तियों को आमतौर पर ब्रोकरेज के माध्यम से खरीदा जाता है।
- कमोडिटी से जुड़े डेरिवेटिव लगभग तीन सौ वर्षों तक एकमात्र डेरिवेटिव बने रहे। लेकिन 1970 के दशक के बाद, वित्तीय डेरिवेटिव सुर्खियों में आए।

POWER OF 22

The new ETF is another tool to raise ₹72,500 crore budgeted through disinvestment

BLUE CHIPS UNDER ONE ROOF

ENERGY ONGC, IOC, BPCL and Coal India	FMCG ITC
BASIC MATERIALS National Aluminum	INDUSTRIALS L&T, Bharat Electronics, Engineers India, NBCC
FINANCIALS SBI, Axis Bank, Bank of Baroda, Indian Bank, PFC and REC	UTILITIES Power Grid, NTPC, GAIL, NHPC, NLC, SJVNL

ANOTHER WAY OF INVESTING

ETFs are akin to mutual funds but with a defined asset basket like shares of an index

They are more liquid than mutual funds as they can be traded on stock exchanges

Value of units of ETF depends on the value of assets held by the fund

- अधिकांश डेरिवेटिव का एक्सचेंजों पर कारोबार नहीं किया जाता है और संस्थानों द्वारा (ओवर-द - काउंटर एक्सचेंज) जोखिम से बचाव या अंतर्निहित परिसंपत्ति में मूल्य परिवर्तन पर अनुमान लगाने के लिए उपयोग किया जाता है।
- वायदा या स्टॉक विकल्प जैसे एक्सचेंज-ट्रेडेड डेरिवेटिव मानकीकृत हैं और ओवर-द-काउंटर डेरिवेटिव के कई जोखिमों को समाप्त या कम करते हैं।

वायदा

- वे भविष्य की तारीख में एक सहमत कीमत पर एक परिसंपत्ति की खरीद और वितरण के लिए दो पक्षों के बीच एक समझौता हैं।
- व्यापारी अपने जोखिम से बचने या अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमत पर अनुमान लगाने के लिए वायदा अनुबंध का उपयोग करेंगे।
- वायदा लेनदेन में शामिल पक्ष अंतर्निहित परिसंपत्ति को खरीदने या बेचने की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए बाध्य हैं।
- उदाहरण के लिए, मान लें कि 1 जनवरी, 2021, कंपनी-A \$62 प्रति बैरल की कीमत पर तेल के लिए एक वायदा अनुबंध खरीदता है जो 14 फरवरी 2021 को समाप्त होता है।
 - कंपनी ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसे फरवरी में तेल की जरूरत है और उसे चिंता है कि कंपनी को खरीदने की जरूरत से पहले कीमत बढ़ जाएगी।
 - एक तेल वायदा अनुबंध खरीदना कंपनी के जोखिम की रक्षा करता है क्योंकि अनुबंध के दूसरी तरफ विक्रेता अनुबंध समाप्त होने तक कंपनी-A को 62 डॉलर प्रति बैरल के लिए तेल देने के लिए बाध्य है।
 - मान लें कि 14 फरवरी, 2021 तक तेल की कीमतें बढ़कर 80 डॉलर प्रति बैरल हो जाती हैं, कंपनी-A वायदा अनुबंध के विक्रेता से 62 डॉलर प्रति बैरल पर तेल की डिलीवरी स्वीकार कर सकती है।
 - हालांकि, अगर कंपनी-A को अब तेल की आवश्यकता नहीं है, तो यह समाप्ति से पहले भी अनुबंध बेच सकती है और मुनाफा रख सकती है।

विकल्प

- एक विकल्प अनुबंध एक वायदा अनुबंध के समान है कि यह एक विशिष्ट मूल्य के लिए पूर्व निर्धारित भविष्य की तारीख में एक परिसंपत्ति खरीदने या बेचने के लिए दो पक्षों के बीच एक समझौता है।
- विकल्प और वायदा के बीच महत्वपूर्ण अंतर यह है कि, एक विकल्प के साथ, खरीदार खरीदने या बेचने के लिए अपने समझौते का उपयोग करने के लिए बाध्य नहीं है।

मुद्रा डेरिवेटिव का उदाहरण

एक यूरोपीय निवेशक की कल्पना करें, जिसके सभी निवेश खाते यूरो (EUR) में मूल्यवर्ग के हैं। यह निवेशक यू.एस. कंपनी के शेयरों को यू.एस. एक्सचेंज के माध्यम से यू.एस. डॉलर (USD) का उपयोग करके खरीदता है। अब निवेशक उस स्टॉक को धारण करते समय विनिमय-दर जोखिम के संपर्क में है। विनिमय दर जोखिम का खतरा है कि यूरो के मूल्य में अमरीकी डॉलर के संबंध में वृद्धि होगी। यदि यूरो का मूल्य बढ़ता है, तो स्टॉक को बेचने पर निवेशक को जो भी लाभ होता है, वह यूरो में परिवर्तित होने पर कम मूल्यवान हो जाता है।

इस जोखिम से बचाव के लिए, निवेशक एक विशिष्ट विनिमय दर में लॉक करने के लिए एक मुद्रा डेरिवेटिव खरीद सकता है।

374. लघु वित्त बैंक (Small Finance Bank)

- लघु वित्त बैंक वित्तीय संस्थान हैं जो देश के असेवित, दुर्गम और असंबद्ध क्षेत्र को वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं।
- वे कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत हैं।
- लघु वित्त बैंकों की स्थापना के उद्देश्य इस प्रकार हैं:
 - आम जनता के लिए बचत का एक अवसर प्रदान करके वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को आगे बढ़ाना।
 - लघु व्यवसाय इकाइयों, लघु और सीमांत किसानों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों और अन्य असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं के लिए ऋण की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बनाए रखा जाता है।
 - ग्रामीण और अर्ध-शहरी बचत को बढ़ावा देने और स्थानीय क्षेत्रों में व्यवहार्य आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान करने के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करना।
- वे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और अन्य प्रासंगिक विधियों के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं।
- बैंक किसी भी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेंगे।

पात्रता मापदंड:

- निवासी व्यक्ति/पेशेवर, अकेले या संयुक्त रूप से, प्रत्येक के पास बैंकिंग और वित्त में कम से कम 10 साल का अनुभव हो और कम से कम पांच साल की अवधि के लिए अपने व्यवसाय चलाने का सफल ट्रैक रिकॉर्ड हो, लघु वित्त बैंक स्थापित करने के लिए प्रवर्तक के रूप में पात्र होंगे।
- निजी क्षेत्र में मौजूदा गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (NBFC), सूक्ष्म वित्त संस्थान (MFI), और स्थानीय क्षेत्र के बैंक (LAB), प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (UCB) भी छोटे वित्त बैंकों में रूपांतरण का विकल्प चुन सकते हैं।
- ऐसे लघु वित्त बैंकों का न्यूनतम निवल मूल्य रु. व्यवसाय शुरू होने की तारीख से 100 करोड़। हालांकि, उन्हें अपनी न्यूनतम निवल संपत्ति रुपये तक बढ़ानी होगी। कारोबार शुरू होने की तारीख से पांच साल के भीतर 200 करोड़ रुपये।
- प्रमोटर को न्यूनतम 40% इक्विटी पूंजी का योगदान करना चाहिए और इसे 10 वर्षों में 30% तक लाया जाना चाहिए।

गतिविधियों का दायरा

- छोटी जमा राशि लेना और ऋण वितरित करना।
- म्यूचुअल फंड, बीमा उत्पाद और अन्य साधारण तृतीय-पक्ष वित्तीय उत्पादों का वितरण।
 - भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के साथ और ऐसे उत्पादों के लिए क्षेत्रीय नियामक की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के बाद।
- अपने कुल समायोजित निवल बैंक ऋण का 75% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार दें।
- एकल उधारकर्ता के लिए अधिकतम ऋण आकार पूंजीगत निधि का 10%, समूह के लिए 15% होगा।
- इसके ऋण पोर्टफोलियो का कम से कम 50% कम से कम 25 लाख रुपये तक के ऋण और अग्रिम का गठन करना चाहिए।

- लघु वित्त बैंक अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं के लिए विदेशी मुद्रा व्यापार में एक अधिकृत डीलर भी बन सकता है।
- SFB को नकद आरक्षित अनुपात (CRR) और वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) बनाए रखने की आवश्यकता है।
- लघु वित्त बैंक के अंतर्निहित जोखिम को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किसी भी उच्च प्रतिशत के अधीन, निरंतर आधार पर अपनी जोखिम भारत परिसंपत्तियों (आरडब्ल्यूए) के 15% का न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखना आवश्यक होगा।

ऐसी गतिविधियाँ जिनकी अनुमति नहीं है-

- बड़े कॉरपोरेट्स और समूहों को उधार।
- पहले पांच वर्षों के लिए पूर्व आरबीआई अनुमोदन के साथ शाखाएं नहीं खोल सकते।
- प्रमोटर की अन्य वित्तीय गतिविधियों को बैंक के साथ नहीं मिलाना चाहिए।
- यह गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवाओं की गतिविधियों को शुरू करने के लिए सहायक कंपनियों की स्थापना नहीं कर सकता है।
- वे किसी अन्य बैंक के लिए एक व्यापार सम्पर्की (Business Correspondent - BC) नहीं हो सकते। हालांकि, उनके पास अपना BC नेटवर्क हो सकता है।

विदेशी शेयरधारिता

- FDI की सीमा निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति के अनुसार है। वर्तमान में, सभी स्रोतों से एक निजी क्षेत्र के बैंक में कुल FDI को बैंक की पेड-अप पूंजी के अधिकतम 74% तक की अनुमति होगी।
- विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII)/विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) के मामले में, व्यक्तिगत एफआईआई/एफपीआई होल्डिंग कुल भुगतान पूंजी के 10% से कम तक सीमित है।
- सभी FII/FPI/योग्य विदेशी निवेशकों (QFI) की कुल सीमा कुल भुगतान की गई पूंजी के 24% से अधिक नहीं हो सकती है। इसके निदेशक मंडल द्वारा संकल्प के माध्यम से सीमा को 49% तक बढ़ाया जा सकता है, जिसके बाद इसके सामान्य निकाय द्वारा इस आशय का एक विशेष संकल्प किया जा सकता है।

375. भुगतान बैंक (Payment Bank)

- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दो प्रकार के बैंकिंग लाइसेंस दिए जाते हैं - यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस और विभेदित बैंक लाइसेंस।
- पेमेंट्स बैंक एक अलग बैंक लाइसेंस के अंतर्गत आता है क्योंकि यह उन सभी सेवाओं की पेशकश नहीं कर सकता है जो एक वाणिज्यिक बैंक प्रदान करता है।
- वह बैंकिंग प्रणाली जहाँ जनसंख्या के एक निश्चित जनसांख्यिकीय वर्ग की आवश्यकता पूरी होती है, विभेदित बैंकिंग कहलाती है (उदाहरण लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक)

गतिविधियों का दायरा

- इस बैंक के माध्यम से भुगतान और प्रेषण सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं।

- मांग जमा की स्वीकृति, शुरू में प्रति व्यक्तिगत ग्राहक रु. 100,000 की अधिकतम शेष राशि रखने तक सीमित थी।
- एक भुगतान बैंक उधार नहीं दे सकता।
- यह डेबिट कार्ड जारी कर सकता है लेकिन क्रेडिट कार्ड नहीं।
- गैर-जोखिम साझा करने वाले सरल वित्तीय उत्पादों जैसे म्यूचुअल फंड इकाइयों और बीमा उत्पादों आदि का वितरण।
- उन्हें केवल ग्राहकों की जमा राशि से प्राप्त धन को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति है।
- वे एनआरआई जमा स्वीकार नहीं कर सकते।
- पेमेंट बैंक खाताधारक किसी भी एटीएम या अन्य सेवा प्रदाताओं के माध्यम से पैसे जमा और निकालने में सक्षम होगा।
- इसे कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जाएगा।
- व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को पूरा करने के लिए मोबाइल फर्मों, सुपरमार्केट श्रृंखलाओं और अन्य को भुगतान लाइसेंसधारियों को प्रदान किया जाएगा।

विनियमन

- यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949; भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934; विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007, अन्य प्रासंगिक विधियों और निर्देशों के प्रावधानों द्वारा शासित है।
- उन्हें नकद आरक्षित अनुपात (CRR) बनाए रखने की आवश्यकता है।
- पात्र सरकारी प्रतिभूतियों में सांविधिक तरलता अनुपात (SLR) में अपनी "मांग जमा शेष राशि" का न्यूनतम 75% निवेश करना आवश्यक है।
- परिचालन उद्देश्यों और तरलता प्रबंधन के लिए अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ वर्तमान और समय/सावधि जमा में अधिकतम 25% रखने की आवश्यकता है।
- भुगतान बैंक के लिए न्यूनतम चुकता पूंजी 100 करोड़ रुपये है। चुकता इक्विटी पूंजी में न्यूनतम प्रारंभिक योगदान इसके व्यवसाय के प्रारंभ से पहले पांच वर्षों के लिए कम से कम 40% होना चाहिए।

376. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (Regional Rural Bank - RRB)

पृष्ठभूमि

- 1970 के दशक की शुरुआत में, यह महसूस किया गया था कि 1969 में बैंक के राष्ट्रीयकरण के बाद भी, कुछ ऐसे मुद्दे थे, जिसने वाणिज्यिक बैंकों के लिए, यहां तक कि सरकारी स्वामित्व के तहत, किसानों को उधार देना मुश्किल बना दिया था।
- इस मुद्दे को सरकार ने उठाया और इसने 1975 में नरसिंहम वर्किंग ग्रुप की स्थापना की।
- इस समिति की सिफारिशों के आधार पर, RRB अध्यादेश सितंबर 1975 में प्रख्यापित किया गया था, जिसे RRB अधिनियम 1976 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

- 1975 में गांधी जयंती पर प्रथम ग्रामीण बैंक के गठन के साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अस्तित्व में आए।

RRB के बारे में

- RRB वित्तीय संस्थान हैं जो कृषि और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करते हैं। उनकी कल्पना ग्रामीण लोकाचार, स्थानीय अनुभव और गरीब ध्यान केंद्रित करने वाले कम लागत वाले संस्थानों के रूप में की गई थी।
- प्रत्येक RRB को "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक" द्वारा प्रायोजित किया जाना था, हालांकि, उन्हें आत्मनिर्भर क्रेडिट संस्थान के रूप में नियोजित किया गया था जो अपने आंतरिक संसाधनों को स्वयं में पुनर्वित्त करने में सक्षम थे और सांविधिक पूर्व-उत्सर्जन से अलग थे।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्वामित्व तीन संस्थाओं के पास उनके संबंधित शेरों के साथ निम्नानुसार था:
 - केंद्र सरकार 50%
 - राज्य सरकार 15%
 - प्रायोजक बैंक 35%
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण समस्याओं के परिचितता के संदर्भ में एक सहकारी की विशेषताओं और एक वाणिज्यिक बैंक की अपनी व्यावसायिकता और वित्तीय संसाधनों को जुटाने की क्षमता के संदर्भ में जोड़ते हैं।
- प्रत्येक RRB सरकार द्वारा अधिसूचित स्थानीय सीमा के भीतर संचालित होता है।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मुख्य उद्देश्य हैं -
 - ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे और सीमांत किसानों, कृषि मजदूरों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करना।
 - शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण जमाओं के बहिर्वाह की जांच करना और क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना और ग्रामीण रोजगार उत्पादन में वृद्धि करना।
 - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपने कुल ऋण का 75% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण के रूप में प्रदान करना आवश्यक है।
- प्रायोजक बैंक के पास क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रबंधकीय और परिचालन पर्यवेक्षण की शक्ति है।
- जबकि, प्रदर्शन निगरानी और नियामक पर्यवेक्षण नाबार्ड द्वारा किया जाता है।
- 1975 में, कुल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या केवल 6 थी। 1990 में इसे बढ़ाकर 196 बैंकों के साथ अधिकतम किया गया था।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा वित्तीय संकट और खराब प्रदर्शन के कारण, कुछ बैंकों को कुछ अन्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ विलय कर दिया गया था। अंततः अब RRB की संख्या 56 है।
- RRB की पुनर्पूजीकरण प्रक्रिया को के सी चक्रवर्ती की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर 2011 में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था।
 - नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पहचान करता है, जिन्हें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की CRAR स्थिति के आधार पर 9% की अनिवार्य CRAR बनाए रखने के लिए पुनर्पूजीकरण सहायता की आवश्यकता होती है, जैसा कि हर साल 31 मार्च को होता है।
 - RRB के पुनर्पूजीकरण की योजना को 2011 के बाद चरणबद्ध तरीके से 2019-20 तक बढ़ा दिया गया था।

- CRAR या पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) एक बैंक की पूंजी का उसकी जोखिम भारित संपत्ति और वर्तमान देनदारियों के संबंध में अनुपात है।

377. म्यूनिसिपल बॉन्ड (Municipal Bonds)

संदर्भ: हाल ही में लखनऊ नगर निगम (LMC) के 200 करोड़ रुपये के बांड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में सूचीबद्ध किए गए हैं।

म्यूनिसिपल बॉन्ड के बारे में:

- एक म्यूनिसिपल बॉन्ड (**muni**) एक ऋण सुरक्षा है जो किसी राज्य, नगरपालिका या काउंटी द्वारा राजमार्गों, पुलों या स्कूलों के निर्माण सहित अपने पूंजीगत व्यय को वित्त करने के लिए जारी किया जाता है।
 - म्यूनिसिपल बॉन्ड के माध्यम से, एक नगर निगम व्यक्तियों या संस्थानों से धन जुटाता है और एक निर्दिष्ट राशि का भुगतान करने का वादा करता है और एक विशिष्ट परिपक्वता तिथि पर मूल राशि वापस करता है।
- ये ज्यादातर संघीय करों से और अधिकांश राज्य और स्थानीय करों से मुक्त होते हैं, जो उन्हें उच्च आयकर कोष्ठक में लोगों के लिए विशेष रूप से आकर्षक बनाते हैं।
- म्यूनिसिपल बॉन्ड शहरी स्थानीय निकायों (**ULB**) को बजटीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राजस्व जुटाने में मदद कर सकते हैं क्योंकि संपत्ति कर नगरपालिका राजस्व का एकमात्र प्रमुख स्रोत है।
- जनता को जारी किए जाने वाले म्यूनिसिपल बॉन्ड को क्रिसिल जैसी प्रसिद्ध एजेंसियों द्वारा रेट किया जाता है, जो निवेशकों को निवेश विकल्प की विश्वसनीयता के बारे में पारदर्शिता की अनुमति देता है।
- म्यूनिसिपल बॉन्ड जैसे सरकारी बॉन्ड को आमतौर पर कम जोखिम वाले निवेश के रूप में देखा जाता है, क्योंकि सरकार द्वारा अपने ऋण भुगतान में चूक की संभावना कम होती है।
- बंगलौर नगर निगम 1997 में भारत में म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला पहला शहरी स्थानीय निकाय (ULB) था।

म्यूनिसिपल बांड दो प्रकार के होते हैं

- पानी, स्वच्छता, कचरा निपटान आदि जैसी नागरिक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सामान्य दायित्व बांड जारी किए जाते हैं। वे आम तौर पर एक विशिष्ट परियोजना से राजस्व द्वारा समर्थित नहीं होते हैं।
- राजस्व बांड एक विशिष्ट उद्देश्य जैसे टोल रोड या टोल ब्रिज के निर्माण के लिए जारी किए जाते हैं।

सेबी विनियम, 2015 के अनुसार, नगरपालिका या कॉर्पोरेट नगर निकाय (CME) को म्यूनिसिपल बांड जारी करने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना चाहिए:

- ULB के पास पिछले वित्तीय वर्षों में से किसी भी तीन में नकारात्मक निवल मूल्य नहीं होना चाहिए।
- नगरपालिका द्वारा पिछले 365 दिनों के दौरान ऋण प्रतिभूतियों या बैंकों या वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋणों के पुनर्भुगतान में चूक नहीं होनी चाहिए।
- नगरपालिकाओं को परियोजना लागत का कम से कम **20%** योगदान करने की आवश्यकता है।

- कॉरपोरेट म्युनिसिपल इकाई, उसके प्रमोटर, समूह कंपनी या डायरेक्टर का नाम **RBI** द्वारा प्रकाशित विलफुल डिफॉल्टर्स की सूची में नहीं होना चाहिए था।
- जनता को जारी किए गए ऋण लिखतों के संबंध में ब्याज के भुगतान या मूल राशि के पुनर्भुगतान में चूक नहीं होनी चाहिए, यदि कोई हो।
- पब्लिक इश्यू के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड में निवेश ग्रेड से ऊपर अनिवार्य रेटिंग होनी चाहिए।

378. प्रतिभूति अपीलिय न्यायाधिकरण (Securities Appellate Tribunal - SAT)

- SAT सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 15K के प्रावधानों के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है।
- SAT के कार्य:
 - सेबी अधिनियम, 1992 के तहत **SEBI** या न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपीलों को सुनना और उनका निपटान करना।
 - पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (**PFRDA**) द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई एवं निराकरण करना।
 - भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (**IRDAI**) द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई और निपटान करना।
- SAT के पास वही शक्तियां हैं जो एक दीवानी अदालत में निहित होती हैं। इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति SAT के निर्णय या आदेश से व्यथित महसूस करता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।
- SAT में एक पीठासीन अधिकारी और दो अन्य सदस्य होते हैं।
 - SAT के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी।
- SAT मुख्यालय: मुंबई

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(Securities and Exchange Board of India - SEBI)

- प्रारंभ में, सेबी एक गैर-वैधानिक निकाय था। अप्रैल, 1988 में भारत सरकार के एक संकल्प के तहत भारत में पूंजी बाजार के नियामक के रूप में SEBI का गठन किया गया था।
- **SEBI** अधिनियम, 1992 को लागू करके इसे वैधानिक दर्जा दिया गया था।
- इसका मुख्यालय मुंबई में है और क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में स्थित हैं।
- SEBI एक अर्ध-विधायी, अर्ध-न्यायिक और अर्ध-कार्यकारी निकाय है। यह नियमों का मसौदा तैयार कर सकता है, पूछताछ कर सकता है, निर्णय को पारित कर सकता है और जुर्माना लगा सकता है।
- सेबी के कार्य:

- प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना और प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देना और विनियमित करना।
- मुख्य रूप से तीन प्रकार की प्रतिभूतियां हैं: इक्विटी- जो धारकों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करती है; ऋण-अनिवार्य रूप से आवधिक भुगतान के साथ चुकाया गया ऋण; और संकर-जो ऋण और इक्विटी के पहलुओं को जोड़ते हैं।
- स्टॉक ब्रोकरों, मर्चेन्ट बैंकरों, हामीदारों, पोर्टफोलियो प्रबंधकों, निवेश सलाहकारों और ऐसे अन्य मध्यस्थों के कामकाज को पंजीकृत और विनियमित करना जो किसी भी तरह से प्रतिभूति बाजार से जुड़े हो सकते हैं।

379. आरबीआई की खुदरा प्रत्यक्ष योजना (RBI's Retail Direct scheme)

समाचार में आरबीआई ने एक योजना की घोषणा की है जिसके तहत खुदरा निवेशकों को सीधे केंद्रीय बैंक के साथ खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ट खाते (RDG) खोलने की अनुमति दी जाएगी।

- एक "गिल्ट खाता" का अर्थ किसी संस्था या व्यक्ति द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को रखने के लिए खोला और बनाए रखा गया खाता है।
- यह पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) के प्राथमिक निर्गमन और NDS-OM (निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम - ऑर्डर मैचिंग सेगमेंट) तक पहुंच प्रदान करेगा।
 - NDS-OM का अर्थ है द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार के लिए आरबीआई की स्क्रीन आधारित, अनाम इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर मिलान प्रणाली।
- यह व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सुविधा के लिए वन-स्टॉप समाधान प्रदान करेगा।
- आरबीआई के साथ खाता खोलने और बनाए रखने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए पात्र अनिवासी खुदरा निवेशक भी योजना के तहत पात्र हैं।

सरकारी प्रतिभूतियां (G-Sec)

- सरकारी प्रतिभूतियां (G-Sec) सरकार द्वारा पैसा उधार लेने के लिए जारी किए गए ऋण साधन हैं।
- बैंक सावधि जमा की तरह, सरकारी प्रतिभूतियां कर-मुक्त नहीं हैं।
- उन्हें आम तौर पर निवेश का सबसे सुरक्षित रूप माना जाता है क्योंकि वे सरकार द्वारा समर्थित हैं। तो, डिफॉल्ट का जोखिम लगभग शून्य है।
- हालांकि, वे ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के अधीन हैं। इसलिए, वे पूरी तरह से जोखिम मुक्त नहीं हैं।
- ऐसी प्रतिभूतियां अल्पावधि (91 दिन, 182 दिन और 364 दिन की परिपक्वता अवधि वाले ट्रेजरी बिल) या लंबी अवधि (एक वर्ष या उससे अधिक की परिपक्वता वाले सरकारी बांड) हैं।
- भारत में, केंद्र सरकार ट्रेजरी बिल और बांड या दिनांकित प्रतिभूतियां दोनों जारी करती है जबकि राज्य सरकारें केवल बांड या दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करती हैं, जिन्हें राज्य विकास ऋण (SDL) कहा जाता है।
- जब सरकार अपनी प्रतिभूतियों को पहली बार (प्राथमिक बाजार) जारी करती है तो अधिकृत संस्थानों को सरकारी प्रतिभूतियां खरीदने की अनुमति होती है। इन संस्थानों को प्राथमिक डीलर कहा जाता है जिसमें बैंक और वित्त संबंधी कंपनियां शामिल होती हैं।

- एक बार जब ये सरकारी प्रतिभूति खरीद लेते हैं, तो आरबीआई, बैंक, एनबीएफसी जैसे अन्य संस्थान इन प्रतिभूतियों को द्वितीयक बाजार में खरीद सकते हैं।
- कुछ साल पहले, आरबीआई ने व्यक्तियों (खुदरा निवेशकों) को प्राथमिक बाजार के साथ-साथ द्वितीयक बाजार में भाग लेने की अनुमति दी थी, लेकिन सीधे तौर पर अन्य संस्थानों के माध्यम से नहीं। लेकिन अब खुदरा निवेशक आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम के तहत सीधे खरीद सकेंगे।

380. नेगेटिव यील्ड बॉण्ड (Negative yield Bond)

संदर्भ: चीन ने पहली बार ऋणात्मक-यील्ड ऋण बेचा। 5 साल के बांड की कीमत -0.152% की यील्ड के साथ, और 10 साल और 15 साल की प्रतिभूतियों की 0.318% और 0.664% की सकारात्मक यील्ड के साथ थी।

- बांड पैसा उधार लेने का एक साधन है। किसी देश की सरकार या किसी कंपनी द्वारा धन जुटाने के लिए बांड जारी किया जा सकता है।
- एक बॉण्ड की यील्ड रिटर्न की प्रभावी दर है जो इसे कमाती है।
 - आम तौर पर, निवेशक अपने अंकित मूल्य पर बांड खरीदते हैं, जो निवेश की गई मूल राशि है। बदले में, निवेशक आमतौर पर एक बांड की यील्ड अर्जित करते हैं।
 - प्रत्येक बॉण्ड की परिपक्वता तिथि होती है, जो तब होती है जब निवेशक को मूल राशि का भुगतान किया जाता है।
- ऋणात्मक- यील्ड बांड ऋण उपकरण हैं जो निवेशक को बांड की खरीद मूल्य से कम परिपक्वता राशि का भुगतान करने की पेशकश करते हैं।
 - आमतौर पर, उदाहरण के लिए एक निवेशक 100 रुपये में एक बांड खरीदेगा और परिपक्वता अवधि पर 110 अंकित मूल्य प्राप्त करेगा। ऋणात्मक- यील्ड बांड के मामले में एक निवेशक ऐसे बांड को 110 रुपये में खरीदेगा और परिपक्वता पर 100 रुपये वापस प्राप्त करेगा।
- इसलिए, निवेशक अपने पैसे (बॉण्ड जारीकर्ता) के साथ रखने के लिए उधारकर्ता को ब्याज का भुगतान करते हैं।

निवेशक ऐसे बॉण्ड क्यों खरीदते हैं?

- ऐसे उपकरण आमतौर पर तनाव और अनिश्चितता के समय मांग में होते हैं। यह उनकी पूंजी को महत्वपूर्ण क्षरण से बचाने के लिए है।
- मुद्रा में उतार-चढ़ाव से लेकर अपस्फीति तक, ऐसे परिदृश्य हैं जिनमें नकारात्मक- यील्ड बांड के खरीदार आगे आ सकते हैं।
- कई निवेशक इक्विटी में अपने जोखिम पोर्टफोलियो को हेजिंग (**Hedging**) के उद्देश्य से नकारात्मक- यील्ड वाले सरकारी ऋण में अस्थायी रूप से पैसा लगा सकते हैं।



IASBABA'S

**RAPID REVISION (RaRe)
SERIES - UPSC 2021**

RaRe Notes Hindi

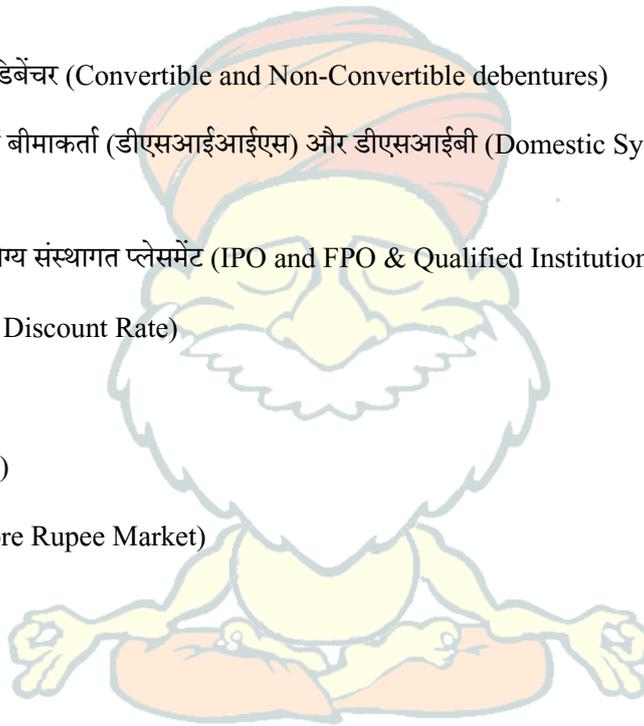
DAY 53 - ECONOMY

#RaRebaba

www.rrs.iasbaba.com

विषय

381. लघु और मध्यम उद्योग (Small & Medium Industry)
382. लघु बिक्री - और लघु निचोड़ (Short Sell — and Short Squeeze)
383. माइक्रो एटीएम (Micro ATM)
384. परिवर्तनीय और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (Convertible and Non-Convertible debentures)
385. घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता (डीएसआईआईएस) और डीएसआईबी (Domestic Systematically Important Insurers (DSIIS) and DSIBs)
386. आईपीओ और एफपीओ और योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (IPO and FPO & Qualified Institutional Placements)
387. मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट (Merchant Discount Rate)
388. LIBOR और SONIA
389. सर्किट ब्रेकर (Circuit Breaker)
390. अपतटीय रुपया बाजार (Offshore Rupee Market)



381. लघु और मध्यम उद्योग (Small & Medium Industry)

पूर्ववर्ती MSME वर्गीकरण			
मानदंड: संयंत्र और मशीनरी/उपकरण में निवेश			
वर्गीकरण	सूक्ष्म	लघु	मध्यम
विनिर्माण उद्यम	25 लाख रुपये से अधिक का निवेश नहीं	5 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश नहीं	10 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश नहीं
सेवाएं प्रदान करने वाले उद्यम	10 लाख रुपये से अधिक का निवेश नहीं	2 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश नहीं	5 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश नहीं

संशोधित MSME वर्गीकरण (1 जुलाई, 2020 से प्रभावी)			
समग्र मानदंड: संयंत्र और मशीनरी/उपकरण और वार्षिक कारोबार में निवेश			
वर्गीकरण	सूक्ष्म	लघु	मध्यम
विनिर्माण उद्यम और उद्यम सेवाएं प्रदान करना।	P&M / उपकरण में निवेश 1 करोड़ रुपये से अधिक नहीं और वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं	P&M / उपकरण में निवेश 10 करोड़ रुपये से अधिक नहीं और वार्षिक कारोबार 50 करोड़ रुपये से अधिक नहीं	P&M / उपकरण में निवेश 50 करोड़ रुपये से अधिक नहीं & वार्षिक कारोबार 250 करोड़ रुपये से अधिक नहीं

समाचार में MSME

- कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने लघु और मध्यम आकार की कंपनियों (SMCs) के लिए कारोबार और उधार सीमा का विस्तार किया है, जिससे बड़ी संख्या में फर्मों को लेखांकन मानदंडों के तहत रिपोर्टिंग छूट का लाभ मिल सकता है।

परिवर्तन क्या है?

- MCA ने SMCs के लिए टर्नओवर सीमा 50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 250 करोड़ रुपये और उधार सीमा को 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये कर दिया है।
- छोटी फर्मों के लिए नियामक फाइलिंग की जटिलता को कम करने के लिए SMC को कंपनी (लेखा मानक) नियम 2021 के तहत कई छूटों का लाभ उठाने की अनुमति है।
- बैंकों, वित्तीय संस्थानों, बीमा कंपनियों और सूचीबद्ध कंपनियों को SMC के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।
- इसके अलावा, कोई भी कंपनी जो या तो होल्डिंग कंपनी है या किसी कंपनी की सहायक कंपनी जो SMC नहीं है उसे SMC के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।

SMCs को कौन सी छूट उपलब्ध हैं जो अन्य फर्मों के लिए उपलब्ध नहीं हैं?

- SMCs को नकदी प्रवाह विवरण दर्ज करने और अनिवार्य फाइलिंग में अपने वित्तीय प्रदर्शन का एक खंडीय विवरण प्रदान करने से पूरी तरह से छूट दी गई है।
- SMCs को कर्मचारियों को लाभ दायित्वों का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करने से छूट दी गई है, लेकिन अभी भी कर्मचारियों के लिए कंपनी के दायित्वों के मूल्यांकन में उपयोग किए जाने वाले बीमांकिक अनुमान प्रदान करने की आवश्यकता है।
- SMC को अपनी फाइलिंग में प्रति शेयर डायल्यूटेड (**Diluted**) आय की रिपोर्ट करने से भी छूट दी गई है।
 - प्रति शेयर डायल्यूटेड आय एक कंपनी की प्रति शेयर आय को दर्शाती है, यह मानते हुए कि अन्य प्रतिभूतियों को शेयरों में बदलने के सभी विकल्पों का प्रयोग किया जाता है।

यह इन फर्मों को कैसे प्रभावित करता है?

- इस कदम से उन फर्मों के लिए व्यापार करने में आसानी होगी जिन्हें अब SMC की परिभाषा के तहत शामिल किया जाएगा।
- SMC के लिए लेखांकन मानक, जिन्हें दिसंबर 2006 में अधिसूचित किया गया था और समय-समय पर संशोधित किया गया था, भारतीय लेखा मानकों (Ind AS) की तुलना में बहुत सरल हैं। इन लेखांकन मानकों में इसके आवेदन में कम जटिलता शामिल है, जिसमें आवश्यक प्रकटीकरण की संख्या कम महत्वपूर्ण है।
 - **Ind AS** मानक बड़ी फर्मों पर लागू होते हैं, और अधिकांश विकसित क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (IFRS) के समान होते हैं।

382. लघु बिक्री - और लघु निचोड़ (Short Sell — and Short Squeeze)

- शॉर्ट सेलिंग एक काफी सरल अवधारणा है—एक निवेशक एक स्टॉक उधार लेता है, स्टॉक बेचता है, और फिर इसे ऋणदाता को वापस करने के लिए स्टॉक खरीदता है।
- लघु विक्रेता शर्त लगा रहे हैं कि वे जो स्टॉक बेचते हैं वह कीमत में गिर जाएगा। यदि स्टॉक बेचने के बाद गिरता है, तो लघु विक्रेता इसे कम कीमत पर वापस खरीदता है और इसे ऋणदाता को लौटाता है। बिक्री मूल्य और खरीद मूल्य के बीच का अंतर लाभ है।
- लघु-विक्रेता प्रतिभूति की कीमत में गिरावट पर दांव लगाते हैं, और उससे लाभ प्राप्त करते हैं। इसकी तुलना लंबे निवेशकों के साथ की जा सकती है जो चाहते हैं कि कीमत बढ़े।
- शॉर्ट सेलिंग, जब यह सफल होता है, तो निवेशक को अल्पावधि में अच्छा लाभ मिल सकता है क्योंकि स्टॉक तेजी से मूल्य खो देते हैं।

उदाहरण के लिए, यदि कोई निवेशक सोचता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) के शेयर का मूल्य ₹ 2100 प्रति शेयर से अधिक है, और कीमत में गिरावट जा रही है, तो निवेशक अपने ब्रोकर से RIL के 10 शेयर "उधार" ले सकता है, जो इसे वर्तमान बाजार मूल्य ₹2100 प्रति शेयर में बेचता है। यदि स्टॉक ₹1900 तक नीचे चला जाता है, तो निवेशक इस कीमत पर 10 शेयर वापस खरीद सकता है और अपने ब्रोकर को शेयर वापस कर सकता है, और ₹2000 (₹21,000- ₹19,000) का शुद्ध लाभ प्राप्त कर सकता है। हालांकि, अगर RIL की कीमत ₹2200 तक बढ़ जाती है, तो निवेशक को ₹1000 (₹21,000- ₹22,000) का नुकसान होगा।

उधार लिए जा सकने वाले शेयरों का पता लगाने और व्यापार के अंत में उन्हें वापस करने की प्रक्रिया को ब्रोकर द्वारा पर्दे के पीछे से संभाला जाता है।

स्क्वीज़ (Squeeze) क्या है:

- यह तब होता है जब बड़ी संख्या में व्यापारियों को उनके खिलाफ मूल्य बढ़ने के कारण बाजार से बाहर कर दिया जाता है।
- एक निचोड़ के लिए सक्रिय घटना अप्रत्याशित समाचार या कोई अन्य हो सकती है।
- स्क्वीज़ नाम इस तथ्य से आता है कि कई व्यापारी एक ही समय में एक ही निकास से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं।

शॉर्ट स्क्वीज़ (Short Squeeze)

- लघु निचोड़ बाजार सहभागियों द्वारा एक घटना को संदर्भित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है जहां एक स्टॉक में छोटे विक्रेता जिन्होंने स्टॉक के पतन पर अपना दांव लगाया है, अपने शेयर को बचाने के लिए भागते हैं या प्रतिकूल मूल्य की स्थिति में स्टॉक खरीदते हैं, ताकि उनके नुकसान को कवर किया जा सके।
- इससे शेयर की मांग में तेज वृद्धि होती है, और शेयर की कीमतों में भारी उछाल होता है।

लॉन्ग स्क्वीज़ (long Squeeze)

- लॉन्ग स्क्वीज़ एक ऐसी स्थिति है जिसमें बड़े शेयर वाले निवेशक अपने घाटे को कम करने के लिए गिरते बाजार में बेचने की जरूरत महसूस करते हैं।
- बेचने का यह दबाव आमतौर पर बाजार की कीमतों में और गिरावट की ओर जाता है।

383. माइक्रो एटीएम (Micro ATM)

- माइक्रो एटीएम एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग बुनियादी बैंकिंग सेवाओं को वितरित करने के लिए लाखों बिजनेस कॉरिस्पोंडेंट (Business Correspondents - BCs) द्वारा किया जाता है।
- यह प्लेटफॉर्म बिजनेस कॉरिस्पोंडेंट (जो स्थानीय किराना दुकान का मालिक हो सकता है और 'माइक्रो एटीएम' के रूप में कार्य करेगा) को तत्काल लेनदेन करने में सक्षम बनाएगा।
- माइक्रो प्लेटफॉर्म कम लागत वाले उपकरणों के माध्यम से कार्य करने में सक्षम होगा जो देश भर के बैंकों से जुड़े होंगे।

- यह किसी विशेष BC से जुड़े बैंक की परवाह किए बिना किसी व्यक्ति को तुरंत धनराशि जमा करने या निकालने में सक्षम बनाता है।
- यह उपकरण मोबाइल फोन कनेक्शन पर आधारित होगा और प्रत्येक BC पर उपलब्ध कराया जाएगा। ग्राहकों को बस अपनी पहचान प्रमाणित (फिंगर प्रिंट) करवानी होगी और अपने बैंक खातों में पैसे निकालने या डालने होंगे।
- यह पैसा BC के कैश दराज से आएगा। अनिवार्य रूप से, BC ग्राहकों के लिए बैंक के रूप में कार्य करेंगे और उन्हें केवल ग्राहकों के UID (उदा: आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से फिंगर प्रिंट) का उपयोग करके ग्राहक की प्रामाणिकता को सत्यापित करना होगा।
- माइक्रो एटीएम द्वारा समर्थित मूल लेनदेन प्रकार, जमा, निकासी, फंड ट्रांसफर और बैलेंस पूछताछ हैं।
- माइक्रो एटीएम भी कार्ड स्वाइप मशीन के जरिए मर्चेन्ट लेनदेन हो सकते हैं। यह मशीन इसके साथ संलग्न एक फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आती है।



384. परिवर्तनीय और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (Convertible and Non-Convertible debentures)

- डिबेंचर को एक प्रकार के दीर्घकालिक ऋण साधन के रूप में संदर्भित किया जाता है जो किसी भी संपार्श्विक द्वारा समर्थित नहीं होता है। दूसरे शब्दों में, डिबेंचर सुरक्षित नहीं हैं या उनमें किसी प्रकार की सुरक्षा का अभाव है।
- बांड के साथ, डिबेंचर सबसे लोकप्रिय ऋण साधनों में से एक है।
- संपत्तियों के आधार पर डिबेंचर की विभिन्न श्रेणियां हैं जैसे परिवर्तनीयता, प्रतिदेयता, हस्तांतरणीयता, आदि।
- परिवर्तनीयता के आधार पर, दो प्रकार के डिबेंचर हैं जो परिवर्तनीय और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर हैं।

	परिवर्तनीय डिबेंचर	गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर
परिभाषा	वे डिबेंचर हैं जिन्हें कंपनी के इक्विटी शेयरों में परिवर्तित किया जा सकता है।	यह वे डिबेंचर हैं जिन्हें कंपनी के इक्विटी शेयरों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।
ब्याज की दर	आमतौर पर कम ब्याज दर	उच्च ब्याज दर
परिपक्वता पर मूल्य	परिवर्तनीय डिबेंचरों की परिपक्वता का मूल्य उस समय कंपनी के स्टॉक मूल्य पर निर्भर होता है, जिसका अर्थ है कि उच्च स्टॉक मूल्य उच्च रिटर्न देगा जबकि कम स्टॉक मूल्य कम रिटर्न देगा।	गैर-परिवर्तनीय डिबेंचरों का मूल्य निश्चित है और इसलिए उन्हें परिपक्वता पर निश्चित रिटर्न प्राप्त होगा।
बाजार की स्थितियों का प्रभाव	खराब बाजार स्थितियों के दौरान, परिवर्तनीय डिबेंचर के धारकों के पास इक्विटी शेयरों में बदलने का विकल्प होता है।	खराब बाजार स्थितियों के दौरान, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है और केवल परिपक्वता पर ही भुनाया जा सकता है।
स्थिति	परिवर्तनीय डिबेंचर के धारक दोहरी स्थिति का आनंद	गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर के धारक केवल कंपनी के लेनदार हैं।

	लेते हैं क्योंकि वे लेनदार के साथ-साथ कंपनी के मालिक भी हो सकते हैं।	
जोखिम कारक	कम जोखिम भरा	परिवर्तनीय डिबेंचर की तुलना में जोखिम भरा।

385. घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता (डीएसआईआईएस) और डीएसआईबी (Domestic Systematically Important Insurers (DSIIs) and DSIBs)

- भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC), भारतीय सामान्य बीमा निगम और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को बीमा नियामक, IRDAI द्वारा 2020-21 के लिए घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता (D-SII) के रूप में पहचाना गया है।
- IRDAI वार्षिक आधार पर D-SII की पहचान करेगा और सार्वजनिक जानकारी के लिए ऐसे बीमाकर्ताओं के नामों का खुलासा करेगा।

घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता (DSII):

- D-SIIs ऐसे आकार, बाजार महत्व और घरेलू और वैश्विक अंतर्संबंध के बीमाकर्ताओं को संदर्भित करता है जिनके संकट या विफलता घरेलू वित्तीय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण अव्यवस्था का कारण बनेगी।
- D-SII को ऐसे बीमाकर्ता के रूप में माना जाता है जो 'बहुत बड़े या विफल होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण' (TBTF) हैं।
- इस प्रकार, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए बीमा सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता के लिए D-SII का निरंतर कामकाज महत्वपूर्ण है।
- D-SII को प्रणालीगत जोखिमों और नैतिक खतरे के मुद्दों से निपटने के लिए अतिरिक्त नियामक उपायों के अधीन किया जाता है।
 - प्रणालीगत जोखिम यह संभावना है कि कंपनी स्तर पर एक घटना गंभीर अस्थिरता को सक्रिय कर सकती है या पूरे उद्योग या अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर सकती है।
 - नैतिक खतरा एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक पक्ष यह जानते हुए जोखिम भरी घटना में शामिल हो जाता है कि वह जोखिम से सुरक्षित है और दूसरा पक्ष लागत वहन करेगा। यह तब उत्पन्न होता है जब दोनों पक्षों के पास एक दूसरे के बारे में अधूरी जानकारी होती है।

घरेलू प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण बैंक (D-SIBs)

- D-SIB का मतलब है कि बैंक विफल होने के लिए बहुत बड़ा है।
- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुसार, कुछ बैंक अपने आकार, क्रॉस-क्षेत्राधिकार गतिविधियों, जटिलता और विकल्प और अंतर्संबंध की कमी के कारण व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जिन बैंकों की संपत्ति जीडीपी के 2% से अधिक है, उन्हें इस समूह का हिस्सा माना जाता है।
- वर्तमान में, भारतीय स्टेट बैंक(एसबीआई), आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक की पहचान भारत में DSIBs के रूप में की गई है।
- महत्व:
 - यदि ऐसा बैंक विफल हो जाता है, तो बैंकिंग प्रणाली और समग्र अर्थव्यवस्था को प्रदान की जाने वाली आवश्यक सेवाओं में महत्वपूर्ण व्यवधान होगा।
 - टू-बिग-टू-फेल यह भी संकेत देता है कि संकट की स्थिति में, सरकार से इन बैंकों का समर्थन करने की अपेक्षा की जाती है।
 - इस धारणा के कारण, इन बैंकों को वित्त पोषण में कुछ लाभ प्राप्त होते हैं। इसका मतलब यह भी है कि इन बैंकों के पास प्रणालीगत जोखिमों और नैतिक जोखिम के मुद्दों के संबंध में नीतिगत उपायों का एक अलग सेट है।

386. आईपीओ और एफपीओ और योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (IPO and FPO & Qualified Institutional Placements)

- आरंभिक सार्वजनिक निर्गम या आईपीओ पहली बार होते हैं जब कोई कंपनी सार्वजनिक होती है। जब हम कहते हैं कि कोई कंपनी सार्वजनिक हो गई है, तो इसका मतलब है कि उसने अपने शेयरों को बड़े पैमाने पर जनता के लिए पेश किया है और देश के स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने के लिए तैयार है।
- हमारे पास दो एक्सचेंज हैं: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (Bombay Stock Exchange - (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (National Stock Exchange - NSE)। पहली बार जब कोई कंपनी बीएसई, एनएसई या दोनों में सूचीबद्ध होती है और अपने शेयरों को सार्वजनिक रूप से कारोबार करने की पेशकश करती है तो उसे IPO कहा जाता है।

FPO

- एक अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश (FPO) एक कंपनी द्वारा निवेशकों को शेयर जारी करना है जो पहले से ही स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है।
- एक अनुवर्ती पेशकश एक प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) के बाद एक कंपनी द्वारा किए गए अतिरिक्त शेयरों को जारी करना है।
- अनुवर्ती प्रस्ताव को द्वितीयक प्रस्ताव के रूप में भी जाना जाता है।
- कंपनियां आमतौर पर इक्विटी बढ़ाने या कर्ज कम करने के लिए FPO की घोषणा करती हैं।
- FPO के दो मुख्य प्रकार हैं:
 - डाइल्यूटिव एफपीओ (**Dilutive FPO**): डाइल्यूटिव एफपीओ में, कंपनी जनता के लिए बाजार में अतिरिक्त संख्या में शेयर जारी करती है, हालांकि कंपनी का मूल्य वही रहता है। इससे शेयरों की कीमत कम हो जाती है और प्रति शेयर आय स्वतः कम हो जाती है।
 - नॉन-डिल्यूटिव एफपीओ (**Non-dilutive FPO**): यहां कंपनी के बड़े शेयरधारक जैसे निदेशक मंडल या संस्थापक अपने निजी तौर पर रखे गए शेयरों को बाजार में बेचते हैं। यह तकनीक कंपनी के लिए शेयरों की संख्या में वृद्धि नहीं करती है, बस जनता के लिए उपलब्ध शेयरों की संख्या बढ़ जाती है।
 - एट-द-मार्केट ऑफर (**At-the-market offer - ATM**) एक प्रकार का एफपीओ है जिसके द्वारा कोई कंपनी किसी भी दिन, आमतौर पर प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर, पूंजी जुटाने के लिए द्वितीयक सार्वजनिक शेयरों की पेशकश कर सकती है।

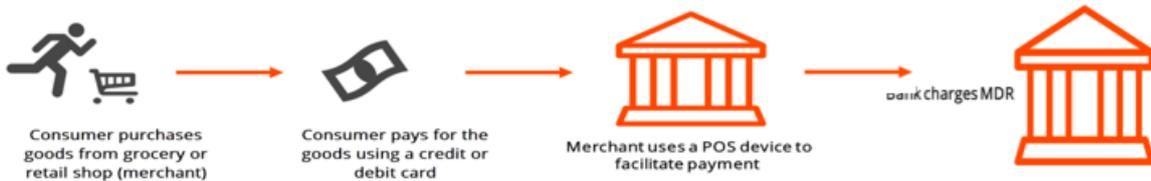
	IPO	FPO
अर्थ	किसी कंपनी द्वारा शेयरों का पहला अंक	आईपीओ के बाद अतिरिक्त पूंजी जुटाने के लिए कंपनी द्वारा शेयर जारी करना
कीमत	निश्चित या परिवर्तनशील मूल्य सीमा	मूल्य बाजार संचालित है और शेयरों की संख्या बढ़ने या घटने पर निर्भर है
शेयर पूंजी	बढ़ जाती है क्योंकि कंपनी लिस्टिंग के लिए जनता के लिए ताजा पूंजी जारी करती है।	डाइल्यूटिव एफपीओ में शेयरों की संख्या बढ़ जाती है और नॉन-डिल्यूटिव एफपीओ में समान रहता है

मूल्य	महंगा	ज्यादातर मामलों में सस्ता क्योंकि कंपनी का मूल्य और कमजोर होता जा रहा है।
जोखिम	जोखिम भरा	तुलनात्मक रूप से कम जोखिम भरा
कंपनी की स्थिति	एक असूचीबद्ध कंपनी एक आईपीओ जारी करती है	पहले से सूचीबद्ध कंपनी एक एफपीओ जारी करती है

योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (Qualified Institutional Placement - QIP)

- QIP एक पूंजी जुटाने का उपकरण है जिसमें एक सूचीबद्ध कंपनी इक्विटी शेयर, पूर्ण और आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर, या कोई भी प्रतिभूति (वारंट के अलावा) जारी कर सकती है जो इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय है।
- यह निजी प्लेसमेंट की एक विधि है जिसके तहत एक सूचीबद्ध कंपनी निवेशकों के एक चुनिंदा समूह को शेयर या परिवर्तनीय प्रतिभूतियां जारी कर सकती है।
- QIP खरीदने के लिए योग्य एकमात्र पक्ष योग्य संस्थागत खरीदार (QIB) हैं, जो मान्यता प्राप्त निवेशक हैं, जैसा कि सेबी द्वारा परिभाषित किया गया है।
 - यह सीमा इस धारणा के कारण है कि QIB विशेषज्ञता और वित्तीय शक्ति वाले संस्थान हैं जो उन्हें एफपीओ के कानूनी आश्वासन के बिना, उस स्तर पर पूंजी बाजार में मूल्यांकन और भाग लेने की अनुमति देते हैं।
 - QIB में म्यूचुअल फंड, घरेलू वित्तीय संस्थान जैसे बैंक और बीमा कंपनियां, उद्यम पूंजी फंड, विदेशी संस्थागत निवेशक और अन्य शामिल हैं।
- QIP, इसके मूल में, सूचीबद्ध कंपनियों के लिए बाजार नियामकों को कानूनी कागजी कार्रवाई प्रस्तुत किए बिना पूंजी जुटाने का एक तरीका है
 - QIP नियमों के एक शिथिल सेट का पालन करता है लेकिन यहां आवंटियों (QIBs) को अधिक विनियमित किया जाता है।
- QIP विकसित करने का प्राथमिक कारण भारत को अपने आर्थिक विकास के लिए विदेशी पूंजी पर बहुत अधिक निर्भर होने से रोकना था।
 - QIP से पहले, भारतीय नियामकों की ओर से यह चिंता बढ़ रही थी कि इसकी घरेलू कंपनियां भारतीय-आधारित पूंजी स्रोतों के बजाय अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीदों (ADR), विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (FCCB) और वैश्विक डिपॉजिटरी रसीदों (GDR) के माध्यम से बहुत आसानी से अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण तक पहुंच रही थीं।
- QIP कुछ कारणों से सहायक होते हैं। उनका उपयोग QIP जारी करने के रूप में समय बचाता है और पूंजी तक पहुंच एक अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव(FPO) के माध्यम से बहुत तेज है।

387. मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट (Merchant Discount Rate)



- MDR एक व्यापारी द्वारा अपने ग्राहकों से डिजिटल माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के लिए एक बैंक को भुगतान की जाने वाली लागत है। व्यापारी छूट दर आमतौर पर लेनदेन राशि के प्रतिशत में व्यक्त की जाती है।

- वर्तमान में, यह ऑनलाइन लेनदेन और क्यूआर-आधारित लेनदेन के लिए लागू है।
- प्रत्येक लेन-देन के लिए व्यापारी द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि तीन हितधारकों के बीच वितरित की जाती है-
 - बैंक जो लेनदेन को सक्षम बनाता है,
 - प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन लगाने वाले विक्रेता
 - कार्ड नेटवर्क प्रदाता जैसे वीजा, मास्टरकार्ड, रुपये
- मर्चेन्ट डिस्काउंट दर को वैकल्पिक रूप से लेनदेन छूट दर के रूप में भी जाना जाता है।
- जून 2020 में, सरकार ने अनिवार्य किया है कि न तो ग्राहकों और न ही व्यापारियों को **BHIM UPI, UPI QR** कोड, आधार पे, डेबिट कार्ड, **NEFT, RTGS**, अन्य का उपयोग करके डिजिटल भुगतान करते समय MDR का भुगतान करना होगा।
 - जनता की धारणा के विपरीत MDR को जीरो नहीं किया गया है। FM के इस फैसले से सिर्फ आरबीआई और बैंकों पर ही असर पड़ा है।

388. LIBOR और SONIA

- समाचार: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों और अन्य विनियमित संस्थाओं को एक सलाह जारी की, जिसमें उन्होंने लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट (LIBOR) को बेंचमार्क के रूप में संदर्भित करने वाले नए वित्तीय अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने से रोकने की आवश्यकता पर बल दिया है।

LIBOR के बारे में

- लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट (LIBOR) एक बेंचमार्क ब्याज दर है जिस पर प्रमुख वैश्विक बैंक अल्पकालिक ऋण के लिए अंतरराष्ट्रीय इंटरबैंक बाजार में एक दूसरे को उधार देते हैं।
- यह ब्रिटेन के प्रमुख बैंकों द्वारा प्रस्तुत ब्याज दर औसत है।
- यह बैंकों के बीच उधार लेने की लागत को इंगित करता है।
- दर की गणना की जाती है और इंटरकांटीनेंटल एक्सचेंज (ICE) द्वारा प्रत्येक दिन प्रकाशित किया जाना जारी रहेगा, लेकिन हाल के घोटालों और बेंचमार्क दर के रूप में इसकी वैधता के आसपास के सवालों के कारण, इसे चरणबद्ध किया जा रहा है।
- फेडरल रिजर्व और यूके में नियामकों के अनुसार, **LIBOR** को **30 जून, 2023** तक चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा, और इसे सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट (SOFR) से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट (Secured overnight financing rate - SOFR)

- यह डॉलर-मूल्यवर्गीय डेरिवेटिव और ऋणों के लिए एक बेंचमार्क ब्याज दर है जो लंदन इंटरबैंक पेशकश दर (LIBOR) का स्थान ले रहा है।
- SOFR ट्रेजरी पुनर्खरीद बाजार में लेनदेन पर आधारित है और इसे लिबोर से बेहतर माना जाता है क्योंकि यह अनुमानित उधार दरों के बजाय अवलोकन योग्य लेनदेन के आंकड़ों पर आधारित है।
- जबकि SOFR डॉलर-मूल्यवर्गीय डेरिवेटिव और ऋण के लिए बेंचमार्क दर बन रहा है, अन्य देशों ने अपनी वैकल्पिक दरों की मांग की है, जैसे SONIA

SONIA के बारे में

- **SONIA** 'स्टर्लिंग ओवरनाइट इंटरबैंक एवरेज रेट (Sterling Overnight Interbank Average Rate)' का संक्षिप्त है।
- यह ब्रिटिश स्टर्लिंग बाजार में असुरक्षित लेनदेन के लिए बैंकों द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रभावी ओवरनाइट ब्याज दर है।
- इसका उपयोग उन ट्रेडों के लिए ओवरनाइट फंडिंग के लिए किया जाता है जो ऑफ-ऑवर्स में होते हैं और बाजार में ओवरनाइट कारोबार की गहराई का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- SONIA दर सक्रिय और तरल थोक नकद बाजारों में वास्तविक ओवरनाइट ब्याज दरों पर आधारित है। यह बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा प्रशासित है।
- LIBOR सर्वेक्षण किए गए वैश्विक बैंकों के अनुमानों पर आधारित है, वास्तविक लेनदेन पर नहीं, जबकि SONIA वास्तविक लेनदेन पर आधारित है और बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा इसकी जांच की जाती है, जिससे इसे अधिक विश्वसनीयता मिलती है।
- SONIA भी (वस्तुतः) जोखिम मुक्त है क्योंकि इसमें कोई क्रेडिट जोखिम/तरलता प्रीमियम शामिल नहीं है जो कि LIBOR की गणना में निहित है क्योंकि LIBOR लंबी अवधि में एक-दूसरे को उधार देने वाले बैंकों पर आधारित है।

389. सर्किट ब्रेकर (Circuit Breaker)

- सर्किट ब्रेकर बाजारों को दुर्घटनाग्रस्त होने से रोकने के लिए तंत्र हैं, जो तब होता है जब बाजार प्रतिभागी अपने शेयरों को बेचने से घबराने लगते हैं।
- इंडेक्स आधारित मार्केट-वाइड सर्किट ब्रेकर सिस्टम को सेबी (सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) द्वारा 2001 में पेश किया गया था।
- सर्किट ब्रेकर इक्विटी और इक्विटी व्युत्पन्न बाजारों के व्यापार में एक समन्वित पड़ाव लाता है। सिस्टम को इंडेक्स मूवमेंट के 3 चरणों में अलग तरह से लागू किया जाता है:
 - जब सूचकांक गिरता है >10% 1 बजे से पहले: 45 मिनट के लिए व्यापार रोक दिया जाता है।
 - जब सूचकांक गिरता है >15% दोपहर 2 बजे या उसके बाद: शेष दिन के लिए व्यापार रोक दिया जाता है।
 - जब सूचकांक गिरता है >दिन के किसी भी समय 20%: शेष दिन के लिए व्यापार रोक दिया जाता है।

390. अपतटीय रुपया बाजार (Offshore Rupee Market)

समाचार: भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा बाजारों में अस्थिरता को कम करने के लिए भारतीय बैंकों की अपतटीय इकाइयों को अपतटीय रुपया व्युत्पन्न बाजार में भाग लेने की अनुमति दी है।

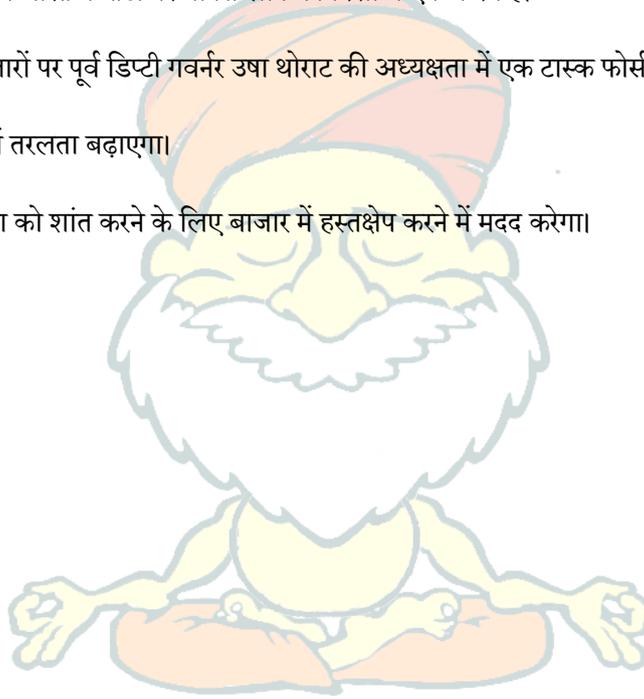
अपतटीय रुपया बाजार (Offshore Rupee Market) के बारे में -

- घरेलू बाजार में करेंसी ट्रेडिंग काफी सीधी है। आप NSE या BSE एक्सचेंजों में मुद्रा डेरिवेटिव में व्यापार कर सकते हैं। जब मुद्राएं स्थानीय बाजार में बेची जाती हैं, तो इसे तटवर्ती बाजार कहा जाता है।
- तटवर्ती बाजार को आरबीआई और सेबी जैसे बाजार नियामकों द्वारा विनियमित और मॉनिटर किया जाता है।

- लेकिन जब विदेशी मुद्रा या भारतीय रुपया आधारित डेरिवेटिव का विदेशी बाजार में आदान-प्रदान किया जाता है, तो इसे अपतटीय बाजार कहा जाता है।
- विदेशी स्थान पर व्यापार करना आरबीआई और सेबी जैसे नियामकों के लिए निगरानी करना विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण बनाता है, यही वजह है कि नियामक अपतटीय मुद्रा व्यापार से सावधान हैं।

RBI द्वारा घोषित प्रमुख परिवर्तन हैं:

- बैंकों को अब अपतटीय रुपया व्युत्पन्न बाजार में भाग लेने की अनुमति होगी। अब तक यह मुख्य रूप से भारतीय विदेशी मुद्रा बाजार में अपतटीय व्यापारियों का वर्चस्व रहा है।
- अपतटीय रुपया बाजार में प्रतिभागी भारतीय नियामकों द्वारा निर्धारित कड़े दस्तावेजीकरण और नियामक आवश्यकताओं के बिना भारतीय मुद्रा की दिशा पर दांव लगा सकते हैं।
- यह रुपया डेरिवेटिव बाजार को भारत के तटों पर वापस लाने की दिशा में एक कदम है।
- ये कदम अपतटीय रुपया बाजारों पर पूर्व डिप्टी गवर्नर उषा थोराट की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स की सिफारिशों पर आधारित थे।
- यह अपतटीय रुपया बाजार में तरलता बढ़ाएगा।
- यह आरबीआई को अस्थिरता को शांत करने के लिए बाजार में हस्तक्षेप करने में मदद करेगा।





IASBABA'S

**RAPID REVISION (RaRe)
SERIES - UPSC 2021**

RaRe Notes Hindi

DAY 66 - ECONOMY

#RaRebaba

www.rrs.iasbaba.com

विषय

471. ओईसीडी/G-20 दो स्तंभ योजना (OECD/G-20 Two Pillar Plan)
472. द्विपक्षीय निवेश संधि - बीआईटी (Bilateral Investment Treaty - BIT)
473. जीएसटी में एडवांस रूलिंग मैकेनिज्म (Advance Ruling Mechanism in GST)
474. परिवर्तनीय पूंजी कंपनी (Variable Capital Company)
475. दिवाला और दिवालियापन संहिता (Insolvency & Bankruptcy Code)
476. डेटा स्थानीयकरण (Data Localization)
477. इतात ई-द्वार (Itat e-dwar)
478. स्वतंत्र निदेशक (Independent Directors)
479. सॉवरेन गोल्ड बांड (Sovereign Gold Bonds)
480. कॉर्पोरेट प्रशासन पर उदय कोटक समिति (Uday Kotak Committee on Corporate governance)



471. ओईसीडी/G-20 दो स्तंभ योजना (OECD/G-20 Two Pillar Plan)

समाचार में: भारत और OECD -G 20 समावेशी ढांचे पर आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण (BEPS) के अधिकांश सदस्य अंतर्राष्ट्रीय कराधान नियमों में सुधार के लिए एक नई दो-स्तंभ योजना में शामिल हो गए हैं।

मुख्य बिंदु

- यह योजना 130 देशों की थी जो वैश्विक जीडीपी के 90% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- नया ढांचा अर्थव्यवस्थाओं के डिजिटलीकरण से उत्पन्न होने वाली कर चुनौतियों का समाधान करना चाहता है।
- यह संधि खरीदारी को रोकने के लिए सीमा पार लाभ स्थानांतरण पर चिंताओं को दूर करने का भी प्रयास करता है।

स्तंभ एक:

- यह अपने घरेलू देशों से MNEs पर कुछ कर लगाने के अधिकारों को उन बाजारों में फिर से आवंटित करेगा जहां उनके पास व्यावसायिक गतिविधियां हैं और लाभ कमाते हैं।
- OECD के अनुसार, प्रत्येक वर्ष बाजार अधिकार-क्षेत्र में 100 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक के लाभ होने की उम्मीद है।

स्तंभ दो:

- यह वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर दर के माध्यम से देशों के बीच न्यूनतम मानक कर दर रखना चाहता है, जो वर्तमान में 15% प्रस्तावित है।
- इससे कर राजस्व में अतिरिक्त 150 बिलियन अमरीकी डालर उत्पन्न होने की उम्मीद है।

आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण (BEPS)

- BEPS एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग कर नियोजन रणनीतियों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो विभिन्न क्षेत्राधिकारों के कर नियमों के बीच मौजूद असंतुलन और अंतराल का फायदा उठाते हैं।
- यह निगम कर को कम करने के लिए किया जाता है जो कुल मिलाकर देय होता है, या तो कर लाभ को 'गायब' कर देता है या मुनाफे को कम कर क्षेत्राधिकारों में स्थानांतरित कर देता है जहां यह बहुत कम या कोई वास्तविक गतिविधि नहीं है।
- सामान्य तौर पर BEPS रणनीतियाँ अवैध नहीं होती हैं; बल्कि वे विभिन्न क्षेत्राधिकारों में संचालित विभिन्न कर नियमों का लाभ उठाते हैं।
- BEPS विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से बहुराष्ट्रीय उद्यमों (MNE) से कॉर्पोरेट आयकर पर भारी निर्भरता के कारण प्रमुख महत्व का है।
- BEPS पहल एक OECD पहल है, जिसे G20 द्वारा अनुमोदित किया गया है, ताकि विश्व स्तर पर अधिक मानकीकृत कर नियम प्रदान करने के तरीकों की पहचान करता है।

472. द्विपक्षीय निवेश संधि - बीआईटी (Bilateral Investment Treaty - BIT)

- BIT एक देश के दूसरे देश में निजी निवेश के लिए नियम और शर्तें स्थापित करने वाला एक समझौता है।
- BIT में निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यवहार, स्वामित्व से सुरक्षा, साधनों का मुफ्त हस्तांतरण और निवेश के लिए पूर्ण सुरक्षा और संरक्षा शामिल है।
- संधि द्विपक्षीय निवेश प्रवाह को बढ़ाने के उद्देश्य से किसी भी देश में निवेश को बढ़ावा देने और संरक्षित करने का प्रयास करती है।
- यह प्रत्येक देश को अपने क्षेत्र में निवेश करने के लिए दूसरे देश के निवेशकों के लिए अनुकूल परिस्थितियों (जलवायु) बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता है।
- BIT व्यक्तिगत निवेशकों को मेजबान राज्यों के खिलाफ मामले लाने की अनुमति देते हैं यदि मौद्रिक क्षतिपूर्ति के लिए बाद के संप्रभु नियामक उपाय बिट के अनुरूप नहीं हैं।
 - निवेशक जिनका BIT के तहत अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, वे अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का सहारा ले सकते हैं। यह ICSID (निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र) के माध्यम से है, न कि मेजबान राज्य पर अपनी अदालतों में मुकदमा करने के बजाया। इस प्रक्रिया को निवेशक-राज्य विवाद निपटान कहा जाता है।
 - यह मोटे तौर पर समानता के अधिकार और मनमानी राज्य कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षा के समान है।

भारत और BIT

- यूके के साथ 1994 में पहली BIT पर हस्ताक्षर करने के बाद से, भारत ने 86 ऐसी द्विपक्षीय संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो 2020 में ब्राजील के साथ नवीनतम है।
- BIT भारत में FDI अंतर्वाह के प्रमुख संचालकों में से एक रहे हैं।
- 2016 के एक अध्ययन से पता चलता है कि विदेशी निवेशकों को पर्याप्त सुरक्षा और प्रतिबद्धता प्रदान करके, BIT ने वास्तव में 2001-2012 की अवधि में बढ़ते एफडीआई में योगदान दिया।
- हालाँकि, भारत के खिलाफ एक अंतरराष्ट्रीय विवाद निपटान (ISDS) न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए दंड के कई मामले सामने आए हैं।
- उदाहरण के लिए पूर्वव्यापी कर लगाने, स्पेक्ट्रम और दूरसंचार लाइसेंसों को रद्द करने और रद्द करने जैसे नियामक उपायों से जुड़े मामलों में।
- इससे BIT की समीक्षा हुई और 2016 में भारत ने मॉडल BIT लॉन्च किया। इसका उद्देश्य अन्य राज्यों के साथ नए BIT पर बातचीत करने के साथ-साथ मौजूदा लोगों की फिर से बातचीत के लिए एक आधार के रूप में कार्य करना है। नए मॉडल बिट की कुछ प्रमुख विशेषताएं :
 - नया मॉडल स्पष्ट करता है कि यह केवल उन निवेशों को कवर करता है जिनकी मेजबान राज्य के क्षेत्र में भौतिक उपस्थिति और पर्याप्त व्यावसायिक गतिविधियां हैं।
 - निवेशकों को ISDS का महत्वपूर्ण लाभ मिलता है - लेकिन घरेलू अदालतों के समक्ष पूर्व उपचार करने से पहले नहीं।
 - भारत का नया मॉडल BIT स्पष्ट करता है कि उसका लक्ष्य केवल निवेशक संरक्षण से अधिक हासिल करना है।
- 2016 में मॉडल BIT के अनुसार, भारत विदेशी निवेश से संबंधित कुछ हद तक संरक्षणवादी दृष्टिकोण के लिए अत्यधिक निवेशक-अनुकूल दृष्टिकोण से दूर चला गया।

- इसके अपनाने के बाद से, भारत ने 2016 से 2019 के बीच 66-विषम BIT को एकतरफा समाप्त कर दिया है, जिससे वैश्विक निवेशक समुदाय को नकारात्मक संकेत मिल रहे हैं।
- यह स्पष्ट है क्योंकि किसी भी देश ने मॉडल BIT के आधार पर फिर से बातचीत करने के लिए कोई झुकाव नहीं दिखाया है।
- 2016 के बाद से, भारत ने केवल तीन संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें से कोई भी अभी तक लागू नहीं है।

473. जीएसटी में एडवांस रूलिंग मैकेनिज्म (Advance Ruling Mechanism in GST)

- कोई भी अग्रिम कर निर्णय कर कानूनों की लिखित व्याख्या है।
- यह कर अधिकारियों द्वारा निगमों और व्यक्तियों को जारी किया जाता है जो कुछ कर मामलों के स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध करते हैं।
- एक अग्रिम निर्णय का अक्सर अनुरोध किया जाता है जब करदाता कुछ प्रावधानों के बारे में भ्रमित और अनिश्चित होता है। अग्रिम कर सत्तारूढ़ के लिए प्रस्तावित गतिविधि शुरू करने से पहले लागू किया जाता है।
- उदाहरण के लिए, आयकर के तहत, अंतरराष्ट्रीय कराधान में अग्रिम निर्णय उपलब्ध है। यह गैर-निवासियों को आयकर देयता का पता लगाने, अग्रिम रूप से अपने आयकर की योजना बनाने और लंबे समय से खींचे गए और महंगे कानूनी विवादों से बचने में मदद करने के लिए है।
- GST के अनुसार, अग्रिम निर्णय कर अधिकारियों द्वारा एक आवेदक को माल/सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित प्रश्नों पर दिया गया एक लिखित निर्णय है।

GST के तहत एडवांस रूलिंग की परिभाषा

- "अग्रिम निर्णय" का अर्थ है प्राधिकरण या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा एक आवेदक को माल या सेवाओं की आपूर्ति के मामलों पर प्रदान किया गया निर्णय।
- एक अग्रिम सत्तारूढ़ पहले अग्रिम सत्तारूढ़ (प्राधिकरण) के लिए प्राधिकरण को भेजा जाता है। अग्रिम निर्णय से नाखुश कोई भी व्यक्ति अग्रिम फैसले (अपीलीय प्राधिकरण) के लिए अपीलीय प्राधिकरण में अपील कर सकता है।

जीएसटी के तहत अग्रिम फैसले के उद्देश्य

- अग्रिम में कर देयता में निश्चितता प्रदान करें
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करना
- मुकदमेबाजी कम करें
- समय पर, पारदर्शी और सस्ते तरीके से निर्णय लें।

सवाल जिस पर GST के तहत अग्रिम निर्णय मांगा जा सकता है:

- किसी भी सामान या सेवाओं या दोनों का वर्गीकरण; माल या सेवाओं की आपूर्ति का समय और मूल्य; भुगतान किए गए या भुगतान किए गए समझे गए कर के इनपुट टैक्स क्रेडिट की स्वीकार्यता; कर का भुगतान करने के दायित्व का निर्धारण।

उन्नत शासन का अधिकार

- CGST अधिनियम, 2017 की धारा 96 अग्रिम निर्णय के लिए प्राधिकरण को निम्नानुसार परिभाषित करती है:
- अग्रिम निर्णय के लिए प्राधिकरण (AAR) और 'अग्रिम निर्णय के लिए अपीलीय प्राधिकरण' (AAR) का गठन राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या केंद्र शासित प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम के प्रावधानों के तहत किया जाता है।
- सरकार अग्रिम निर्णय के लिए प्राधिकरण के सदस्य के रूप में संयुक्त आयुक्त के पद से नीचे के अधिकारियों को नियुक्त नहीं करेगी।

प्रयोज्यता

- AAR या AAAR द्वारा घोषित एक अग्रिम निर्णय केवल आवेदक पर बाध्यकारी होगा।
- इसका स्पष्ट अर्थ है कि राज्य में अन्य कर योग्य व्यक्तियों के लिए एक अग्रिम निर्णय लागू नहीं है।
- यदि कानून, मूल अग्रिम सत्तारूढ़ के तथ्य बदलते हैं तो अग्रिम निर्णय लागू नहीं होगा।

474. परिवर्तनीय पूंजी कंपनी (Variable Capital Company)

समाचार में: केपी कृष्णन की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में परिवर्तनीय पूंजी कंपनियों की व्यवहार्यता पर अपनी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) को प्रस्तुत की है।

VCC के बारे में:

- यह एक कॉर्पोरेट संरचना है जिसे सामूहिक निवेश योजनाओं के लिए तैयार किया गया है।
- इसके तहत कई सामूहिक निवेश योजनाएं एक ही कॉर्पोरेट इकाई की छत्रछाया में एकत्रित की जा सकती हैं और फिर भी एक-दूसरे से घिरी रह सकती हैं।
- यह फंड यूनिट ट्रस्ट, सीमित भागीदारी, सीमित देयता भागीदारी और कंपनियों के लिए एक विकल्प देता है।
- यह उप-निधि को निदेशक मंडल को साझा करने की अनुमति देता है और समान सेवा प्रदाता हैं, जैसे कि एक ही फंड मैनेजर, कस्टोडियन, ऑडिटर और प्रशासनिक एजेंट।
- कुछ प्रशासनिक कार्यों जैसे, सामान्य बैठकें आयोजित करना और प्रॉस्पेक्टस तैयार करना, को भी समेकित किया जा सकता है।
- जहां एक VCC को कई उप-निधि के साथ एक छत्र निधि के रूप में स्थापित किया जाता है, सदस्य ऐसे शेयर रख सकते हैं जिन्हें वीसीसी द्वारा रखे गए एक विशेष उप-निधि में संदर्भित किया जाता है।

कृष्णन समिति की सिफारिशें

- समिति ने IFSCs में फंड प्रबंधन गतिविधि के संचालन के उद्देश्य से VCC जैसी कानूनी संरचना को अपनाने की सिफारिश की।
- समिति ने माना कि फंड प्रबंधन करने वाली संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे को निम्नलिखित के लिए प्रदान करना चाहिए:
 - निवेशकों के लिए निश्चितता और स्पष्टता।
 - संपत्ति के विभिन्न पूर्णों का प्रभावी पृथक्करण और रिंग-फेंसिंग।

- शेयरों के विभिन्न वर्गों को जारी करने की क्षमता।
- विनियामक अनुमोदन के बिना निधियों की पूंजी संरचना में परिवर्तन।
- विभिन्न विशेषताओं वाली निधियों पर लागू उपयुक्त लेखांकन मानकों को चुनने की स्वतंत्रता।
- त्वरित घुमाव की क्षमता।

475. दिवाला और दिवालियापन संहिता (Insolvency & Bankruptcy Code)

दिवाला और दिवालियापन के बारे में

- दिवाला वह स्थिति है जहां देनदार लेनदार को वापस भुगतान करने की स्थिति में नहीं होता है।
- एक कॉर्पोरेट फर्म के लिए, इसके संकेत बिक्री में मंदी, भुगतान की समय सीमा का गायब होना आदि हो सकते हैं।
- दिवालियापन दिवाला होने की कानूनी घोषणा है।

दिवाला और दिवालियापन संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code - IBC) की आवश्यकता

- एक एकीकृत कोड आवश्यक है क्योंकि पहले इस मुद्दे को कम से कम 13 विभिन्न कानूनों के तहत नियंत्रित किया जाता था।
- इससे पहले, यदि कोई कंपनी चूक करती है, तो देनदारों और लेनदारों के लिए कम से कम चार अलग-अलग कानूनी मार्ग उपलब्ध थे - उच्च न्यायालय, कंपनी लॉ बोर्ड, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (BIFR), और ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT)
- इससे देनदार के लिए कई बातचीत, कई दंड आदि हो सकते हैं, जिससे उसकी दुर्दशा बढ़ सकती है।
- कानूनों का वर्तमान दलदल मुसीबत से ग्रस्त संस्थाओं के बाहर निकलने में आसानी में मदद नहीं करता है, जिसने चक्रव्यूह की स्थिति की तुलना करने के लिए भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार को बनाया (जहां कंपनियां आसानी से प्रवेश कर सकती हैं लेकिन बाहर निकलना मुश्किल है)
- बढ़ते NPA की पृष्ठभूमि में, परिसमापन प्रक्रिया में आसानी से बैंकों को बहुत सारे बुरे ऋणों की वसूली में मदद मिल सकती है।

दिवाला और दिवालियापन संहिता की मुख्य विशेषताएं:

- इस प्रकार IBC को 2016 में कॉर्पोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के पुनर्गठन और दिवाला समाधान के लिए एक समयबद्ध तरीके से ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
- आईबीसी कोड 2016 में सभी व्यक्तियों, कंपनियों, सीमित देयता भागीदारी (LLP) और साझेदारी फर्म शामिल हैं।
- निर्णायक प्राधिकरण कंपनियों और एलएलपी के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) और व्यक्तियों और साझेदारी फर्मों के लिए डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल (DRT) है।
- इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स (Insolvency Professionals): लाइसेंसशुदा पेशेवरों का एक विशेष संवर्ग सृजित करने का प्रस्ताव है। ये पेशेवर समाधान प्रक्रिया का प्रबंधन करेंगे, देनदार की संपत्ति का प्रबंधन करेंगे, और लेनदारों को निर्णय लेने में उनकी सहायता करने के लिए जानकारी प्रदान करेंगे।

- सूचना उपयोगिताएँ: यह एक सूचना नेटवर्क है जो वित्तीय डेटा जैसे उधार, डिफॉल्ट और सुरक्षा हितों को फर्मों के अन्य लोगों के बीच संग्रहीत करेगा।
- दिवाला और दिवालियापन बोर्ड: बोर्ड संहिता के तहत स्थापित इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स दिवाला पेशेवर एजेंसियों और सूचना उपयोगिताओं को विनियमित करेगा। बोर्ड में भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त, कॉर्पोरेट मामलों और कानून मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

हाल ही में, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम 2016 में संशोधन किया है।

प्रमुख संशोधन

- समाधान पेशेवरों (RP) को एक कॉर्पोरेट देनदार (CD) के परिहार लेनदेन के बारे में न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को सूचित करना होगा।
- इसके लिए आरपी को दिवाला शुरू होने की तारीख के 140वें दिन या उससे पहले इस तरह के विवरण की सूचना देनी होती है।
- कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) के दौरान अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए RP को पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं सहित किसी भी पेशेवर को नियुक्त करने की अनुमति देता है।
- इसके लिए सभी पूर्व नामों और पंजीकृत कार्यालय के पते (ईएस) का खुलासा करने के लिए एक इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल (IP) की आवश्यकता होती है, इसलिए दो वर्षों में CD के वर्तमान नाम और पंजीकृत कार्यालय के पते के साथ-साथ उसके सभी संचारों और रिकॉर्डों में इन्सॉल्वेंसी की शुरुआत से पहले बदल दिया गया है।

476. डेटा स्थानीयकरण (Data Localization)

समाचार में: हाल ही में, RBI ने भारत में डेटा के भंडारण के लिए दिशानिर्देशों का पालन न करने का हवाला देते हुए, भारत में नए घरेलू ग्राहकों (डेबिट, क्रेडिट या प्रीपेड) कार्ड जारी करने से मास्टरकार्ड एशिया पर प्रतिबंध लगा दिया है।

भारतीय रिजर्व बैंक की डेटा स्थानीयकरण नीति:

- भुगतान प्रणाली डेटा के भंडारण पर आरबीआई के परिपत्र दिनांक 6 अप्रैल, 2018 ने सभी सिस्टम प्रदाताओं (भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत भारत में एक कार्ड नेटवर्क का संचालन) को अपने भारतीय परिचालन से संबंधित सभी एंड-टू-एंड लेनदेन डेटा को देश में स्थित प्रणाली में संग्रहीत करने के लिए कहा था।
- कंपनियों को छह महीने के भीतर इन नियमों का पालन करना था।
- इसका कारण भारतीय उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता की रक्षा करना और राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को दूर करना था।
- सरकारों का यह भी मानना है कि विदेशी कंपनियों को स्थानीय बुनियादी ढांचे को स्थापित करने के लिए अनिवार्य करना उनकी स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा दे सकता है।
- केंद्रीय बैंक चाहता था कि डिजिटल लेनदेन और धोखाधड़ी बढ़ने के मद्देनजर एक प्रभावी डेटा भंडारण प्रणाली हो।
- ऐसी सभी कार्ड कंपनियों को एक अनुपालन रिपोर्ट और एक ऑडिट अनुपालन रिपोर्ट दर्ज करनी थी।

477. इतत ई-द्वार (Itat e-dwar)

समाचार में: केंद्रीय कानून और न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री ने हाल ही में इतत ई-द्वार का शुभारंभ किया

प्रमुख बिंदु:

- Itat e-dwar आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) का ई-फाइलिंग पोर्टल है।
- यह पार्टियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपनी अपील, विविध आवेदन, दस्तावेज, पेपर बुक इत्यादि दर्ज करने में सक्षम बनाता है।
- यह डिजिटल कोर्ट रूम, वर्चुअल सुनवाई और न्यायिक जानकारी प्रदान करने वाला मोबाइल एप्लिकेशन प्रदान करता है।
- पोर्टल ITAT के दिन-प्रतिदिन के कामकाज में पहुंच को बढ़ाएगा।
- इसके परिणामस्वरूप न केवल कागज के उपयोग का अर्थशास्त्र, लागत में बचत होगी, बल्कि मामलों के निर्धारण का युक्तिकरण भी होगा, जिससे मामलों का त्वरित निपटान होगा।

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (Income Tax Appellate Tribunal - ITAT) के बारे में:

- ITAT जनवरी 1941 में स्थापित एक अर्ध न्यायिक संस्थान है।
- यह प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के तहत अपीलों से निपटने में विशिष्ट है।
- इसका गठन आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 5A के तहत किया गया था।
- इसका आदर्श वाक्य 'निष्पक्ष सुलभ सतवर न्याय' है।
- यह देश का सबसे पुराना ट्रिब्यूनल है।
- ITAT द्वारा पारित आदेश अंतिम हैं, उच्च न्यायालय में अपील तभी की जा सकती है जब निर्धारण के लिए कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है।
- 1941 में शुरू हुए छह सदस्यों के साथ तीन बेंच - दिल्ली, कोलकाता (कलकत्ता) और मुंबई (बॉम्बे) में एक-एक बेंच का गठन किया गया, बेंचों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है और वर्तमान में ITAT में 63 बेंच हैं जो 27 विभिन्न स्टेशनों पर हैं, जिनमें लगभग सभी शहर शामिल हैं।

478. स्वतंत्र निदेशक (Independent Directors)

समाचार में: भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित सख्त मानदंडों को मंजूरी दी है।

- सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार स्थापित एक सांविधिक निकाय है। सेबी का मूल कार्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना और प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देना और विनियमित करना है।

स्वतंत्र निदेशकों के बारे में:

- एक स्वतंत्र निदेशक (जिसे कभी-कभी बाहरी निदेशक के रूप में भी जाना जाता है) एक गैर-कार्यकारी निदेशक होता है।

- उसका कंपनी के साथ किसी भी प्रकार का संबंध, सामग्री या वित्तीय संबंध नहीं है।
- उनकी भूमिका स्पष्ट रूप से और स्वतंत्र रूप से एक स्टैंड लेने के लिए है ताकि बहुसंख्यक शेयरधारकों की सनक पर नियंत्रण और संतुलन हो, जो कंपनी को अनुचित जोखिमों के लिए उजागर कर सकता है। इसका मतलब है कि वे आम तौर पर अल्पसंख्यक हितधारकों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- कंपनी अधिनियम, 2013 ने सभी सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों को कुल निदेशकों का कम से कम एक तिहाई स्वतंत्र होना अनिवार्य किया है।
- उनकी भूमिका के लिए उन्हें नैदानिक होने की आवश्यकता होती है जबकि व्यवसाय उनसे व्यावहारिक होने की उम्मीद करते हैं, यही वह तंग रस्सी है जिस पर वे चलते हैं।
- स्वतंत्र निदेशकों के लिए एक बड़ा कहना धोखाधड़ी, कुप्रबंधन और गलत शासन को रोक सकता है।

सेबी के हालिया मानदंडों के प्रमुख बिंदु

- शेयरधारकों द्वारा पारित एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से ही स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जा सकती है। एक विशेष प्रस्ताव को पारित होने के पक्ष में 75% मतों की आवश्यकता होती है।
- नियामक ने स्वतंत्र निदेशक बनने के लिए आवश्यक कौशल के लिए प्रकटीकरण आवश्यकताओं को भी विस्तृत और मजबूत किया है।
- निदेशक मंडल की नामांकन और पारिश्रमिक समिति, जो नियुक्तियों और मुआवजे का फैसला करती है, और लेखा परीक्षा समिति में अब साधारण बहुमत की तुलना में दो-तिहाई स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए।
- साथ ही, एक सूचीबद्ध कंपनी को एक स्वतंत्र निदेशक के त्याग पत्र का खुलासा करना आवश्यक होगा।
- इसके अलावा, एक ही कंपनी/होल्डिंग/सहायक/सहयोगी कंपनी या प्रमोटर समूह से संबंधित किसी भी कंपनी में पूर्णकालिक निदेशक के लिए एक स्वतंत्र निदेशक के लिए एक वर्ष की कूलिंग अवधि होगी।

नए मानदंडों का महत्व:

- परिवर्तन कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं को मजबूत करने के साथ-साथ अधिक निवेशकों को आकर्षित करना चाहते हैं।
- यह कॉर्पोरेट बोर्डरूम में अल्पसंख्यक शेयरधारकों के हित को बनाए रखने में मदद करेगा जहां उनका प्रतिनिधित्व न्यूनतम है।
- उम्मीद है कि इसका परिणाम वास्तव में 'स्वतंत्र' स्वतंत्र निदेशकों के रूप में होना चाहिए, न कि केवल स्वतंत्रता की झलक के साथ।

479. सॉवरेन गोल्ड बांड (Sovereign Gold Bonds)

समाचार में: भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के परामर्श से मई 2021 से सितंबर 2021 तक छह चरणों में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने का निर्णय लिया है।

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में:

- सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सरकार की ओर से आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं।

- वे सरकारी प्रतिभूतियां हैं जिन्हें ग्राम सोने में मूल्यांकित किया जाता है जो भौतिक सोना रखने के विकल्प हैं।
- 2015 में, भौतिक सोने की मांग को कम करने के उद्देश्य से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना शुरू की गई थी।
- गोल्ड बॉन्ड में प्रारंभिक निवेश की राशि पर **2.50%** प्रति वर्ष की निश्चित दर से ब्याज होता है जिसे अर्ध-वार्षिक रूप से जमा किया जाएगा।
- यदि सोने की कीमतों में वृद्धि होती है, तो निवेशक को अधिक कीमत और **2.5%** ब्याज और इसके विपरीत मिलेगा।
- न्यूनतम निवेश **1** ग्राम होगा, जिसमें व्यक्तियों के लिए सदस्यता की अधिकतम सीमा 4 किलोग्राम, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के लिए 4 किलोग्राम और ट्रस्टों के लिए 20 किलोग्राम होगी।
- अवधि: स्वर्ण बांड आठ साल की परिपक्वता अवधि के साथ आते हैं, जिसमें पहले पांच वर्षों के बाद निवेश से बाहर निकलने का विकल्प होता है।
- निर्गम मूल्य: गोल्ड बॉन्ड की कीमतें इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA), मुंबई द्वारा प्रकाशित 999 शुद्धता (24 कैरेट) के सोने की कीमत से जुड़ी हुई हैं।
- बांड वाणिज्यिक बैंकों, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SHCIL), नामित डाकघरों और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से सीधे या एजेंटों के माध्यम से बेचे जाते हैं।
- पात्रता: बांड निवासी व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF), ट्रस्टों, विश्वविद्यालयों और धर्मार्थ संस्थानों को बिक्री के लिए प्रतिबंधित हैं।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य:

- उनका उपयोग बैंकों, वित्तीय संस्थानों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) से ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप में किया जा सकता है।
- बांड पर ब्याज आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के प्रावधानों के अनुसार कर योग्य होगा।
- लेकिन किसी व्यक्ति को SGB के मोचन पर होने वाले पूंजीगत लाभ कर में छूट दी गई है।
- बांड के हस्तांतरण पर किसी भी व्यक्ति को होने वाले दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के लिए इंडेक्सेशन लाभ प्रदान किया जाएगा।
- हालांकि TDS बांड पर लागू नहीं होता है, लेकिन यह धारक की जिम्मेदारी है कि वह कर कानूनों का पालन करे।
- बॉन्ड एक्सचेंजों पर व्यापार योग्य होगा, यदि डीमैट रूप में आयोजित किया जाता है और इसे किसी अन्य पात्र निवेशक को भी हस्तांतरित किया जा सकता है।

480. कॉर्पोरेट प्रशासन पर उदय कोटक समिति (Uday Kotak Committee on Corporate governance)

समाचार में: COVID 19 के मद्देनजर उदय कोटक ने 1991 जैसे सुधारों की सिफारिश की है।

कोटक समिति के बारे में

- इसका गठन 2017 में उदय कोटक की अध्यक्षता में किया गया था।

- भारत में सूचीबद्ध कंपनियों के कॉर्पोरेट प्रशासन से संबंधित मानकों में सुधार के लिए

समिति की प्रमुख सिफारिशें

- सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशकों की अधिकतम संख्या को 10 से घटाकर 8 कर दिया गया है।
- स्वतंत्र निदेशकों के लिए पात्रता मानदंड का विस्तार करना।
- लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और जोखिम प्रबंधन समिति की बड़ी भूमिका।
- QIP/अधिमानी निर्गम से निधियों के उपयोग का प्रकटीकरण।
- लेखा परीक्षक क्रेडेंशियल्स, लेखा परीक्षा शुल्क, लेखा परीक्षकों के इस्तीफे के कारणों का खुलासा।
- निदेशकों की विशेषज्ञता / कौशल का प्रकटीकरण।
- संबंधित पार्टी लेनदेन (RPT) का उन्नत प्रकटीकरण।
- वित्तीय वर्ष 20 से प्रभावी समेकित तिमाही परिणामों का अनिवार्य प्रकटीकरण।
- सहायक कंपनियों के संबंध में सूचीबद्ध संस्थाओं पर बढ़ी हुई बाध्यताएं।
- सूचीबद्ध संस्थाओं और उनकी सामग्री असूचीबद्ध सहायक कंपनियों के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा अनिवार्य होगी।
- बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष 1,000 सूचीबद्ध संस्थाओं में न्यूनतम छह निदेशक।
- बाजार पूंजीकरण द्वारा शीर्ष 500 सूचीबद्ध संस्थाओं में कम से कम एक महिला स्वतंत्र निदेशक।
- CEO/MD और अध्यक्ष का पृथक्करण शुरू में बाजार पूंजीकरण द्वारा शीर्ष 500 सूचीबद्ध संस्थाओं पर लागू किया जाएगा।
- वित्त वर्ष 2018-19 की समाप्ति के बाद यानी 31 अगस्त, 2019 तक 5 महीनों के भीतर AGM आयोजित करने वाली शीर्ष 100 संस्थाएं।
- बाजार पूंजीकरण द्वारा शीर्ष 100 संस्थाओं के लिए FY-19, AGM का वेबकास्ट अनिवार्य होगा।
- संबंधित पक्ष को रॉयल्टी/ब्रांड भुगतान के लिए शेयरधारक की मंजूरी समेकित कारोबार के 2% से अधिक (प्रस्तावित 5% के बजाय)



IASBABA'S

**RAPID REVISION (RaRe)
SERIES - UPSC 2021**

RaRe Notes Hindi

DAY 67 - ECONOMY

#RaRebaba
www.rrs.iasbaba.com

विषय

481. अग्रणी बैंक योजना (Lead Bank Scheme)
482. चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स (Chandler Good Government Index - CGGI)
483. FICN समन्वय समूह (FICN Coordination Group - FCORD)
484. NPCI द्वारा UPI ऐप्स के लिए बाजार हिस्सेदारी सीमा तय (NPCI caps market share for UPI apps)
485. पोंजी योजना (Ponzi Scheme)
486. असमानता को कम करने के लिए ऑक्सफैम प्रतिबद्धता (सीआरआई) सूचकांक 2020 (Oxfam Commitment to Reducing Inequality - CRI Index 2020)
487. विश्व व्यापार संगठन के घरेलू समर्थन और सब्सिडी बॉक्स (Domestic support and subsidy boxes of WTO)
488. व्यापार उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट (Business Responsibility and Sustainability Report - BRSR)
489. गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (Serious Fraud Investigation Office - SFIO)
490. संयुक्त राष्ट्र कर समिति (UN TAX Committee)

481. अग्रणी बैंक योजना (Lead Bank Scheme)

इसके बारे में

- अग्रणी बैंक योजना (LBS) की उत्पत्ति का पता सामाजिक उद्देश्यों के कार्यान्वयन के लिए संगठनात्मक ढांचे पर प्रो. डी. आर. गाडगिल (गाडगिल अध्ययन समूह) की अध्यक्षता वाले अध्ययन समूह से लगाया जा सकता है, जिसने अक्टूबर 1969 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
- 1969 के अंत में शुरू की गई लीड बैंक योजना में आवंटित जिलों के लिए अलग-अलग बैंकों (सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों) को प्रमुख भूमिकाएं सौंपने की परिकल्पना की गई है।
- किसी दिए गए जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं का अपेक्षाकृत बड़ा नेटवर्क रखने वाले और पर्याप्त वित्तीय और जनशक्ति संसाधनों से संपन्न बैंक को आमतौर पर उस जिले की प्रमुख जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तदनुसार, देश के सभी जिलों को विभिन्न बैंकों को आवंटित किया गया है।
- लीड बैंक आवंटित जिलों में सभी ऋण संस्थानों के प्रयासों के समन्वय के लिए एक नेता के रूप में कार्य करता है ताकि ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र में शामिल कृषि, लघु उद्योगों और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण का प्रवाह बढ़ाया जा सके।

लीड बैंक योजना के उद्देश्य

- उन क्षेत्रों की पहचान करना जो जिलों में बैंक रहित और कम बैंकिंग वाले हैं और आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से उनकी शारीरिक, कृषि जलवायु अंत सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का मूल्यांकन करना है।
- उचित ऋण परिनियोजन के माध्यम से क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने में मदद करना।
- बैंक रहित क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करना।

क्षेत्र दृष्टिकोण

- मूल विचार लक्षित और केंद्रित बैंकिंग के लिए "क्षेत्रीय दृष्टिकोण" रखना था।
- एस. नरीमन की अध्यक्षता वाली बैंकर समिति ने निष्कर्ष निकाला कि जिले क्षेत्र दृष्टिकोण के लिए इकाइयाँ होंगे और प्रत्येक जिले को एक विशेष बैंक को आवंटित किया जा सकता है जो एक अग्रणी बैंक की भूमिका निभाएगा।

उषा थोराट समिति की सिफारिशें

- RBI की डिप्टी गवर्नर श्रीमती उषा थोराट की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी ने LBS में सुधारों का सुझाव दिया।
- समिति ने योजना का दायरा बढ़ाने की सिफारिश की और सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं की समीक्षा के बजाय वित्तीय समावेशन की सुविधा पर अधिक ध्यान देने का सुझाव दिया।

482. चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स (Chandler Good Government Index - CGGI)

- समाचार में: चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स (CGGI) में, भारत हाल ही में 49 वें स्थान पर था।
- चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस (CIG) एक अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन है, जिसका मुख्यालय सिंगापुर में है।
- सूचकांक सरकारी क्षमताओं और परिणामों के संदर्भ में 104 देशों को वर्गीकृत करता है।
- प्रत्येक देश को 50 से अधिक खुले डेटा बिंदुओं में मापा जाता है।
- सूचकांक सात स्तंभों पर केंद्रित है
 - 1) नेतृत्व और दूरदर्शिता
 - 2) मजबूत कानून और नीतियां।
 - 3) मजबूत संस्थान।
 - 4) वित्तीय प्रबंधन।
 - 5) आकर्षक बाजार।
 - 6) वैश्विक प्रभाव और प्रतिष्ठा।
 - 7) लोगों को ऊपर उठाने में मदद करना।
- चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स (CGGI) दर्शाता है कि सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए लोगों और कंपनियों के लिए मजबूत सरकारी क्षमताओं में निवेश क्यों महत्वपूर्ण है।

2021 इंडेक्स की मुख्य बातें

- शीर्ष दस देशों में से सात यूरोप में हैं, लेकिन शीर्ष दस में प्रतिनिधित्व करने वाले चार महाद्वीप हैं, जिसमें सिंगापुर एशिया में पहला, न्यूजीलैंड अग्रणी ओशिनिया और कनाडा अमेरिका में सबसे आगे है।
- विश्व बैंक द्वारा परिभाषित सभी शीर्ष दस देश उच्च आय वाले हैं।
- भारत 0.516 के स्कोर के साथ 49वें स्थान पर है।

2021 इंडेक्स की मुख्य बातें

- शीर्ष दस देशों में से सात यूरोप में हैं, लेकिन शीर्ष दस में प्रतिनिधित्व करने वाले चार महाद्वीप हैं, जिसमें सिंगापुर एशिया में पहला, न्यूजीलैंड अग्रणी ओशिनिया और कनाडा अमेरिका में सबसे आगे है।
- विश्व बैंक द्वारा परिभाषित सभी शीर्ष दस देश उच्च आय वाले हैं।
- भारत 0.516 के स्कोर के साथ 49वें स्थान पर है।
- ब्रिक्स देशों की रैंकिंग इस प्रकार है
 - चीन (40 वां)
 - रूस (48 वां)
 - भारत (49वां)
 - ब्राजील (67वां)
 - दक्षिण अफ्रीका (70वां)
- दक्षिण एशियाई देशों में रैंकिंग इस प्रकार है:

- भारत (49वां)
- नेपाल (92वां)
- पाकिस्तान (90वां)
- श्रीलंका (74वां)

483. FICN समन्वय समूह (FICN Coordination Group - FCORD)

- नकली भारतीय मुद्रा नोट्स (FICN) नेटवर्क भारत में आतंक वित्त पोषण के चैनलों में से एक है।
- गृह मंत्रालय में FICN समन्वय समूह (FCORD) का गठन किया गया है।
- देश के भीतर नकली मुद्रा के प्रचलन के खतरे का मुकाबला करने के लिए राज्य/केंद्र की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच खुफिया/सूचना साझा करना।
- वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्र और राज्यों की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ सहयोग।

आतंक निधि और नकली मुद्रा सेल (TFFC)

- यह आतंकवादी वित्त पोषण और नकली मुद्रा मामलों की जांच के उद्देश्य से राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के तहत गठित किया गया है।
 - 2008 के मुंबई हमलों के चलते 2009 में एनआईए की स्थापना हुई थी। NIA अधिनियम एजेंसी को UAPA समेत आठ विशेष कानूनों के तहत अपराधों की जांच करने की शक्ति प्रदान करता है।

484. NPCI द्वारा UPI ऐप्स के लिए बाजार हिस्सेदारी सीमा तय (NPCI caps market share for UPI apps)

खबरों में: मार्च 2021 में, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने यूपीआई ऐप्स के लिए कुल भुगतान संस्करणों के 30 प्रतिशत पर बाजार हिस्सेदारी को निर्धारित किया है।

- भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिक तंत्र में समानता लाने और किसी भी एकल अभिकर्ता द्वारा बाजार प्रभुत्व को रोकने के लिए, NPCI ने विस्तृत दिशानिर्देशों को स्वीकार्य वॉल्यूम जारी किया है कि कोई भी एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यीई) ऐप कुल बाजार के 30% पर संसाधित कर सकता है।
- तेजी से बढ़ते डिजिटल भुगतान क्षेत्र में बाजार की एकाधिकार से बड़ी तकनीकी फर्मों को रोकने के लिए भारत में एक नियामक एजेंसी द्वारा पहली बार यह कदम उठाया गया है।
- नए नियम, जनवरी 2021 से शुरू होने वाली तिमाही से प्रभावी होंगे, ग्राहकों के घर्षण को कम करने के लिए मौजूदा अभिकर्ताओं को अनुपालन के लिए दो साल की खिड़की के साथ प्रमुख बाजार हिस्सेदारी प्रदान करते हैं।
 - वॉलमार्ट का फोन पेज और Google Pay - 2020 के अंत में लगभग 40% की बाजार हिस्सेदारी के साथ - अब नए ग्राहक अधिग्रहण को "मध्यम" करना होगा और 2022 के अंत तक निर्धारित सीमाओं के भीतर लेनदेन की मात्रा को कम करना होगा।
 - पेट्टीएम, अमेज़न पे और फेसबुक के व्हाट्सएप पे जैसे अन्य यूपीआई ऐप्स के लिए, संशोधित दिशानिर्देश चल रही तिमाही से ही लागू होंगे।

- नए नियमों के तहत, सभी UPI भुगतान ऐप NPCI द्वारा तीन-स्तरीय सीमा निगरानी के अधीन होंगे।
 - 25% बाजार हिस्सेदारी का उल्लंघन करने वाले ऐप को NPCI से "अलर्ट" प्राप्त होगा, जिसे इसे "स्वीकार" करना होगा।
 - 27% मार्केट कैप से अधिक होने पर, ऐप को वॉल्यूम कम करने की अपनी योजनाओं के बारे में NPCI को "सबूत" प्रदान करना होगा।
 - अंत में, अगर यह अनुमत 30% कैप का उल्लंघन करता है, तो ऐप को नए ऑनबोर्डिंग को रोकना होगा और NPCI को एक उपक्रम प्रदान करना होगा।
- इसके अलावा अधिकतम सीमा तक पहुंचने पर "मामला-दर-मामला" आधार पर छह महीने तक खिलाड़ियों को छूट देने का एक प्रावधान होगा, ताकि यह बाजार में अचानक व्यवधान न पैदा करे।
 - इस तरह की छूट के बाद भी उल्लेखित UPI ऐप को उल्लंघन अधिसूचना के पांच दिनों के भीतर वॉल्यूम कम करने के लिए अपनी कार्रवाई पर NPCI को एक योजना प्रदान करनी होगी।
- ऐप्स जब निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन करता है तो इसे नए ग्राहकों के ऑनबोर्डिंग को रोकने के कारणों के बारे में सूचित करने के लिए कहा गया है।
- भुगतान सेवा प्रदाता (PSP) या बैंक जो बहु-बैंक मॉडल के माध्यम से ऐप्स की ओर से UPI लेनदेन की सुविधा प्रदान करते हैं, को अनुपालन सुनिश्चित करने का शुल्क लिया जाएगा।
- भारतीय कानून UPI ऐप या TPAP जैसे गूगल पे, फोनपे, अमेज़न पे और अन्य को लाइसेंस प्राप्त भुगतान प्रणाली प्रदाताओं के बजाय तीसरे पक्ष के मध्यस्थ के रूप में मानता है।
- इन ऐप्स में नियामक बाधाएं हैं जो उन्हें ग्राहक निधि के प्रबंधन से रोकती हैं क्योंकि उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीधे नियंत्रित नहीं किया जाता है। उनकी भूमिका UPI पर लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए अधिक है।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (National Payments Corporation of India - NPCI)

- यह भारत में सभी खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए एक विस्तृत संगठन है।
- इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारतीय बैंक संघ (IBA) के मार्गदर्शन और समर्थन के साथ की गई थी।
- उद्देश्य:
 - सभी खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए एक राष्ट्रव्यापी वर्दी और मानक व्यापार प्रक्रिया में मौजूदा एकाधिक प्रणालियों को समेकित और एकीकृत करना।
 - देश भर में आम आदमी को लाभ पहुंचाने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक किरफायती भुगतान तंत्र की सुविधा प्रदान करना।

485. पॉजी योजना (Ponzi Scheme)

- पॉजी स्कीम एक धोखाधड़ी वाला निवेश घोटाला है जो बाद के निवेशकों से लिए गए पैसे के साथ पहले के निवेशकों के लिए रिटर्न उत्पन्न करता है।
- इस योजना से पीड़ितों को यह विश्वास होता है कि लाभ उत्पाद की बिक्री या अन्य साधनों से आ रहा है, और वे इस बात से अनजान रहते हैं कि बाद के निवेशक उनके रिटर्न का स्रोत हैं।
- यह योजना चार्ल्स पॉजी नाम के एक व्यक्ति द्वारा निर्मित की गयी, जो 1920 के दशक में तकनीक का उपयोग करने के लिए कुख्यात हो गया था।

पॉजी योजनाओं को समझना

- एक पॉजी योजना एक निवेश धोखाधड़ी है जिसमें ग्राहकों को बिना किसी जोखिम में बड़े लाभ का वादा किया जाता है।
- एक पॉजी योजना में संलग्न कंपनियां निवेश करने के लिए नए ग्राहकों को आकर्षित करने में अपनी सभी ऊर्जा को केंद्रित करती हैं।
- इस नई आय का उपयोग मूल निवेशकों को उनके रिटर्न का भुगतान करने के लिए किया जाता है, जिसे वैध लेनदेन से लाभ के रूप में चिह्नित किया जाता है।
- पॉजी योजनाएं पुराने निवेशकों को रिटर्न प्रदान करने के लिए नए निवेश के निरंतर प्रवाह पर भरोसा करती हैं।
- जब यह प्रवाह समाप्त हो जाता है, तो योजना अलग हो जाती है।
- पॉजी योजना की कुछ विशेषताएं हैं
 - कम या बिना किसी जोखिम के साथ उच्च निवेश रिटर्न
 - अत्यधिक लगातार रिटर्न
 - अपंजीकृत निवेश
 - असीमित विक्रेता
 - गुप्त या जटिल रणनीतियां
 - भुगतान प्राप्त करने में कठिनाई

भारत में जमा योजनाओं का विनियमन

- जमा योजनाओं के प्रकारों के आधार पर कई प्राधिकरणों द्वारा जमा योजनाओं का निरीक्षण और विनियमन किया जाता है।
 - वर्तमान में नियामकों में आरबीआई, SEBI, नेशनल हाउसिंग बैंक, EPFO, IRDAI, पीएफआरडीएआई, केंद्रीय रजिस्ट्रार, बहु-राज्य सहकारी समितियां, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारें शामिल हैं।
- प्रत्येक प्राधिकरण विभिन्न प्रकार की जमा लेने वाली योजनाओं की देखरेख करता है, जिसमें आरबीआई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) द्वारा ली गई जमाओं की देखरेख करता है, और सेबी म्यूचुअल फंड की देखरेख करता है।

- किसी भी जमा-लेने की योजना को संबंधित प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होना चाहिए, जो उस श्रेणी के आधार पर है, और उसके बाद ही इसका संचालन कानूनी है।

486. असमानता को कम करने के लिए ऑक्सफैम प्रतिबद्धता (सीआरआई) सूचकांक 2020 (Oxfam Commitment to Reducing Inequality - CRI Index 2020)

- समाचार में: हाल ही में, भारत सरकार ने आरोप लगाया कि भारत को सौंपी गई रैंक और CRI सूचकांक में अपनाई गई कार्यप्रणाली स्पष्ट नहीं है क्योंकि इसने चार नए श्रम संहिताओं के प्रावधानों को ध्यान में नहीं रखा है।

असमानता (CRI) सूचकांक 2020 को कम करने के लिए ऑक्सफैम प्रतिबद्धता के बारे में

- यह CRI इंडेक्स का तीसरा संस्करण है, जो दुनिया भर में 158 सरकारों को असमानता को कम करने की प्रतिबद्धता पर रैंक करता है।
- सूचकांक विकास वित्त इंटरनेशनल और ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा एक संयुक्त परियोजना है जो असमानता के खिलाफ लड़ाई में इस शक्तिशाली उपकरण को शुरू करने के लिए एक साथ आए हैं।
- सूचकांक रैंकिंग देशों ने तीन क्षेत्रों में अपनी नीतियों और कार्यों को मापने वाले देशों को लिखा है कि यह असमानता को कम करने से सीधे संबंधित साबित हुआ है।
 - स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा सहित सार्वजनिक सेवाएं
 - कराधान और
 - श्रमिक अधिकार।
- प्रत्येक स्तंभ में अब संकेतक के तीन स्तर होते हैं:
 - नीति प्रतिबद्धता संकेतक: ये अपनी नीतियों के माध्यम से सरकारों की प्रतिबद्धता को मापते हैं (जिसे हमेशा व्यवहार में लागू नहीं किया जा सकता है)
 - कवरेज या कार्यान्वयन संकेतक: ये देखते हैं कि नीतिगत कार्यों के परिणामस्वरूप कौन कवर किया गया है (या नहीं), या सरकार कितनी अच्छी तरह से कागज पर नीतियों को व्यवहार में लाती है।
 - प्रभाव संकेतक: ये असमानता के स्तर पर नीति कार्यों के प्रभाव को मापते हैं।

COUNTRY	PUBLIC SERVICES RANKING	TAX RANKING	LABOUR RANKING	CRI RANKING
Norway	14	21	1	1
Denmark	8	28	2	2
Germany	5	17	11	3
Belgium	7	37	8	4
Finland	2	61	4	5

COUNTRY	PUBLIC SERVICES RANKING	TAX RANKING	LABOUR RANKING	CRI RANKING
South Sudan	158	155	154	158
Nigeria	156	127	158	157
Bahrain	102	158	131	156
Chad	157	113	145	155
Liberia	129	150	132	154

भारत का प्रदर्शन

- कुल मिलाकर, भारत ने सीआरआई सूचकांक में 158 देशों में से सरकारी नीतियों, और शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, कराधान और श्रमिकों के अधिकारों की सार्वजनिक सेवाओं के क्षेत्रों में कार्रवाई पर 129 वां स्थान प्राप्त किया है।
- सूचकांक के अनुसार, भारत ने अपने बजट का सिर्फ 4 प्रतिशत स्वास्थ्य पर खर्च किया जो महामारी में खर्च हो रहा है —यह दुनिया में चौथा सबसे कम है।
- भारत ने श्रम अधिकारों की रक्षा में खराब प्रदर्शन किया है और 158 देशों में 151 रैंक पर फिसल गया है।
- पुरुषों के लिए अनौपचारिक क्षेत्र की उच्चतम उपस्थिति उत्तर प्रदेश में 86.9 प्रतिशत थी और महिलाओं के लिए आंध्र प्रदेश में 73.6 प्रतिशत पर थी।
- अपनी सार्वजनिक सेवाओं के संदर्भ में, यह 141 वें स्थान पर है।
- CRI इंडेक्स ने ट्रेड यूनियनों, महिला श्रमिकों के लिए कानूनी सुरक्षा और न्यूनतम मजदूरी के उपायों के संबंध में शीर्ष 10 सबसे कम प्राप्तांकों में से भारत को आठवां स्थान दिया है।
- सूचकांक में कहा गया है कि भारत की आधी आबादी के पास ही सबसे जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच है, जबकि स्वास्थ्य खर्च का 70 प्रतिशत से अधिक हिस्सा खुद लोगों द्वारा पूरा किया जा रहा है।

ऑक्सफैम इंटरनेशनल के बारे में

- ऑक्सफैम इंटरनेशनल का गठन 1995 में स्वतंत्र गैर-सरकारी संगठनों के एक समूह द्वारा किया गया था।
- वे दक्षता को अधिकतम करने और वैश्विक गरीबी और अन्याय को कम करने के लिए अधिक प्रभाव प्राप्त करने के लिए एक संघ के रूप में शामिल हुए।
- "ऑक्सफैम" नाम 1942 में ब्रिटेन में स्थापित अकाल राहत के लिए ऑक्सफोर्ड कमेटी से आता है।
- समूह ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दुश्मन के कब्जे वाले ग्रीस में महिलाओं और बच्चों को भूखा रखने के लिए मित्र देशों की नौसेना नाकाबंदी के माध्यम से भेजे जाने वाले खाद्य आपूर्ति के लिए अभियान चलाया।
- युद्ध के बाद, ऑक्सफैम ने अपने काम को जारी रखा, पूरे यूरोप में गरीब लोगों की सहायता करने वाले समूहों को सामग्री और वित्तीय सहायता भेजा। चूंकि यूरोप की स्थिति में सुधार हुआ, ऑक्सफैम का ध्यान विकासशील देशों में लोगों की जरूरतों में स्थानांतरित हो गया।

सदस्य संगठन

ऑक्सफैम इंटरनेशनल कन्फेडरेशन के 19 सदस्य संगठन हैं। वे ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, हांगकांग, आयरलैंड, भारत, इटली, मेक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, क्यूबेक, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं।

487. विश्व व्यापार संगठन के घरेलू समर्थन और सब्सिडी बॉक्स (Domestic support and subsidy boxes of WTO)

- घरेलू समर्थन सरकारी सब्सिडी को संदर्भित करता है जो न्यूनतम मूल्य (या इनपुट सब्सिडी) की गारंटी देता है जो घरेलू स्तर पर सीधे या उत्पाद-विशिष्ट या दोनों पर प्रदान किए जाते हैं।

घरेलू सब्सिडी को आम तौर पर 3 बॉक्स में वर्गीकृत किया जाता है

ग्रीन बॉक्स सब्सिडी

- ग्रीन बॉक्स सब्सिडी मुक्त व्यापार को विकृत नहीं करती हैं या मुक्त व्यापार को बहुत कम या नगण्य स्तर पर विकृत करती हैं।
- इस सब्सिडी का उदाहरण सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित सरकारी कार्यक्रम हैं जिनमें कृषि अनुसंधान और विकास, कृषि प्रशिक्षण, पर्यावरण कार्यक्रमों के तहत सब्सिडी आदि शामिल हैं।
- ग्रीन बॉक्स सब्सिडी गैर-मूल्य सहायक हैं इस प्रकार कुल बाजार समर्थन (AMS) की गणना से छूट दी गई हैं।

ब्लू बॉक्स सब्सिडी

- ब्लू बॉक्स सब्सिडी उत्पादन सीमित कार्यक्रमों के तहत प्रत्यक्ष भुगतान हैं। डब्ल्यूटीओ के अनुसार, ब्लू बॉक्स "अम्बर बॉक्स सब्सिडी के साथ" संलग्न है।
- ब्लू बॉक्स सब्सिडी का उद्देश्य उत्पादन को सीमित करना है, उत्पादन कोटा लगाकर या किसानों को अपनी भूमि के हिस्से को अलग करने की आवश्यकता होती है।
- ब्लू बॉक्स सब्सिडी को AMS की गणना से भी छूट दी जाती है।

एम्बर बॉक्स सब्सिडी

- ये सब्सिडी हैं जो प्रकृति में व्यापार-विकृत हैं और किसी भी कीमत पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है।
- एम्बर बॉक्स में घरेलू सब्सिडी की श्रेणी शामिल है जिसे "समेकित माप के समर्थन" (Aggregate Measure of Support - AMS) नामक सूत्र के आधार पर कम करने के लिए निर्धारित किया जाता है।
- AMS ब्लू बॉक्स, हरे रंग के बॉक्स और 'डी मिनिमिस' स्तर में खर्च किए गए पैसे को छोड़कर कृषि उत्पादन पर सरकारों द्वारा खर्च किए गए धन की राशि है।
- बत्तीस विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के पास एम्बर बॉक्स में अपने व्यापार-विकृत घरेलू समर्थन को कम करने के लिए प्रतिबद्धताएं हैं (यानी "समर्थन के कुल कुल माप" या AMS को कम करने के लिए)।

AMS= (कृषि उत्पादन में खर्च की गई कुल राशि) - (नीली, हरी बॉक्स सब्सिडी की कुल राशि) - (AOA में निर्धारित डी मिनिमिस स्तर)

AOA= डब्ल्यूटीओ द्वारा कृषि पर समझौते का उद्देश्य व्यापार बाधाओं को दूर करना और पारदर्शी बाजार पहुंच और वैश्विक बाजारों के एकीकरण को बढ़ावा देना है।

डी मिनिमिस का स्तर: उत्पाद विशिष्ट और गैर-उत्पाद विशिष्ट (एम्बर बॉक्स) सब्सिडी की ओर AOA में निर्धारित न्यूनतम स्तर है, विकसित देशों के लिए डी मिनिमिस स्तर 5% है और विकासशील देशों के लिए यह 10% है।

विशेष और अंतर बॉक्स सब्सिडी

- यह एक विशेष और अंतर बॉक्स है जो विकसित देशों पर लागू नहीं होता है लेकिन विकासशील और कम से कम विकसित देशों पर लागू होता है।
- ये देश में कृषि और ग्रामीण विकास गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी हैं।

कृषि पर समझौता तीन स्तंभ पर खड़ा है:

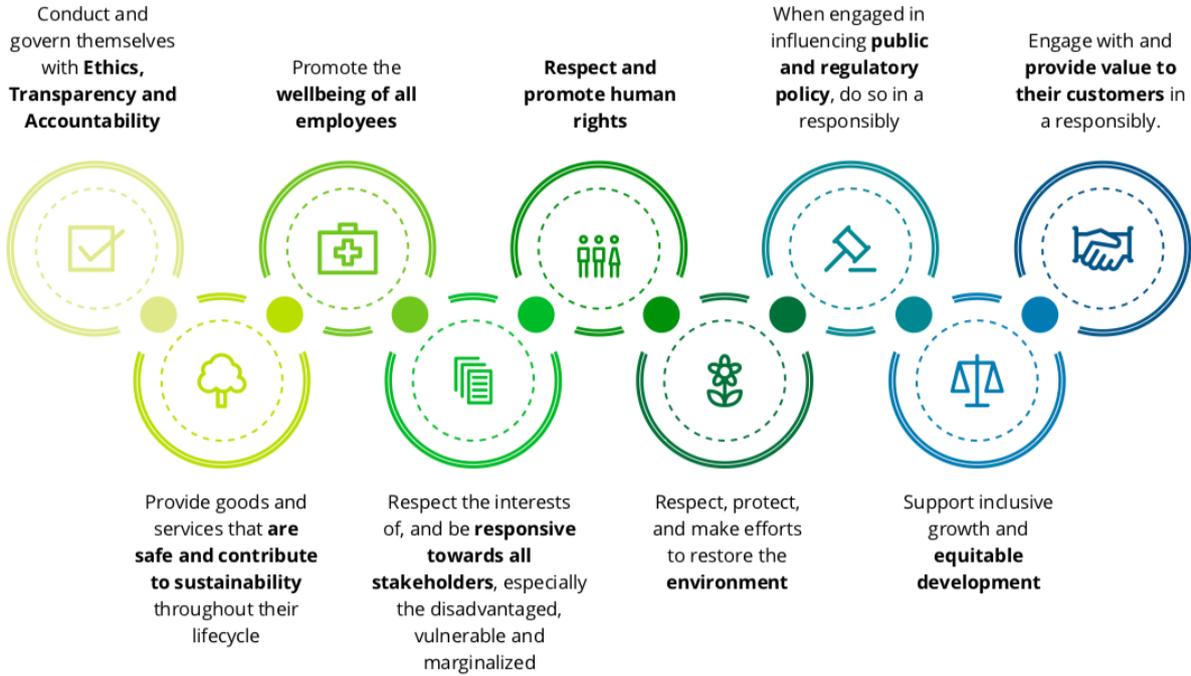
- घरेलू समर्थन: यह घरेलू सब्सिडी में कमी की मांग करता है जो मुक्त व्यापार और उचित मूल्य को विकृत करता है। इस प्रावधान के तहत, विकासशील देशों द्वारा 6 वर्षों की अवधि में 20% की तुलना में समर्थन (AMS) का कुल माप 20% और विकासशील देशों द्वारा 10 वर्षों की अवधि में 13% कम किया जाना है।
- बाजार पहुंच: विश्व व्यापार संगठन में माल के लिए बाजार पहुंच का अर्थ है शर्तों, टैरिफ और गैर-टैरिफ उपाय, जो सदस्यों द्वारा अपने बाजारों में विशिष्ट वस्तुओं के प्रवेश के लिए सहमत हैं। बाजार पहुंच के लिए आवश्यक है कि मुक्त व्यापार की अनुमति देने के लिए अलग-अलग देशों द्वारा तय किए गए टैरिफ (जैसे कस्टम ड्यूटी) को उत्तरोत्तर काट दिया जाए। इसके लिए देशों को गैर-टैरिफ बाधाओं को हटाने और उन्हें टैरिफ ड्यूटी में परिवर्तन की भी आवश्यकता थी।
- निर्यात सब्सिडी: कृषि के इनपुट पर सब्सिडी, निर्यात को सस्ता बनाना या निर्यात के लिए अन्य प्रोत्साहन जैसे आयात शुल्क छूट आदि। निर्यात सब्सिडी के तहत शामिल हैं। इसके परिणामस्वरूप अन्य देशों में अत्यधिक सब्सिडी वाले (और सस्ते) उत्पादों की डंपिंग और अन्य देशों के घरेलू कृषि क्षेत्र को नुकसान पहुंच सकता है।

488. व्यापार उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट (Business Responsibility and Sustainability Report - BRSR)

समाचार में: वित्तीय वर्ष 2021-22 से व्यावसायिक जिम्मेदारी और स्थिरता रिपोर्ट (BRSR) अनिवार्य होगी।

- प्रकटीकरण की आवश्यकताओं ने पिछले दशक में वैश्विक स्तर पर छलांग लगाई है, जिससे कंपनियों को पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) जिम्मेदारियों और वार्षिक प्रकटीकरण में उनके पारदर्शी निगमन की पहचान के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।
- ESG मानकों पर खुलासे को बढ़ाने के निरंतर प्रयासों में इन वैश्विक विकास, प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के साथ-साथ सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा स्थायित्व रिपोर्टिंग के लिए नई आवश्यकताएं पेश की गईं।
- बिजनेस जिम्मेदारी और स्थायित्व रिपोर्ट (BRSR) नामक नए रिपोर्टिंग प्रारूप का लक्ष्य अपने ESG प्रदर्शन के साथ एक व्यापार के वित्तीय परिणामों के बीच संबंध स्थापित करना है।
- यह नियामकों और निवेशकों के लिए आसान बना सकता है, और संबद्ध हितधारकों को समग्र व्यावसायिक स्थिरता, विकास और स्थायित्व (अकेले वित्तीय प्रकटीकरण के आधार पर) का उचित अनुमान प्राप्त करने के लिए आसान हो सकता है।

- सेबी ने अनिवार्य किया है कि BRSR FY2021-22 के लिए स्वैच्छिक आधार पर और FY2022-23 से अनिवार्य आधार पर रिपोर्टिंग के लिए शीर्ष 1,000 सूचीबद्ध इकाइयों (बाजार पूंजीकरण द्वारा) पर लागू होगा।
- बीआरएसआर आवश्यकताएं जिम्मेदार व्यापार आचरण (NGRBC) के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देशों पर आधारित हैं, जो कि व्यवसायों को जरूरी है:



- हालांकि BRSR को अनुपालन आवश्यकता के रूप में माना जा सकता है, लेकिन इसमें व्यवसायों के लिए कई सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। वैश्विक स्तर पर, ESG प्रकटीकरण ने कई लाभों का प्रदर्शन किया है, जिनमें से कुछ में शामिल हैं:
 - मूल्य सृजन में वृद्धि
 - बाजारों तक पहुंच और बेहतर ग्राहक जुड़ाव
 - प्रतिभा को आकर्षित करना और बनाए रखना
 - कम वित्तीय जोखिम
 - सतत विकास लक्ष्यों के साथ गठबंधन

89. गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (Serious Fraud Investigation Office - SFIO)

- भारत सरकार ने पूर्व कैबिनेट सचिव श्री नरेश चंद्र की अध्यक्षता में 2002 में कॉर्पोरेट प्रशासन पर एक समिति की स्थापना की थी। नरेश चंद्र समिति ने अन्य बातों के साथ एक कॉर्पोरेट गंभीर धोखाधड़ी कार्यालय की स्थापना की सिफारिश की।
- गंभीर धोखाधड़ी की जांच (SFIO) शुरू में भारत सरकार द्वारा 2 जुलाई, 2003 को एक संकल्प के माध्यम से स्थापित की गई थी। उस समय SFIO को औपचारिक कानूनी स्थिति का दर्जा प्राप्त नहीं था।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 211 ने SFIO को वैधानिक स्थिति प्रदान की है।

- SFIO कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत एक बहु-अनुशासनात्मक संगठन है, जिसमें लेखा, फॉरेंसिक ऑडिटिंग, कानून, सूचना प्रौद्योगिकी, जांच, कंपनी कानून, पूंजी बाजार और कराधान के क्षेत्र में विशेषज्ञ शामिल हैं, जो सफेद कॉलर अपराधों/धोखाधड़ी का पता लगाने और मुकदमा चलाने या सिफारिश करने के लिए हैं।
- SFIO प्रमुख धोखाधड़ी जांच में शामिल है। यह धोखाधड़ी की जांच के लिए आयकर विभाग और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के साथ समन्वय करता है।
- 2 जुलाई 2003 के संकल्प के अनुसार, एसएफआईओ केवल धोखाधड़ी की जांच करने के लिए है:
 - जटिलता, अंतर-विभागीय और बहु अनुशासनात्मक प्रतिक्रियाएं।
 - मौद्रिक कदाचार के संदर्भ में या प्रभावित व्यक्तियों के संदर्भ में, आकार के आधार पर सार्वजनिक हित की महत्वपूर्ण भागीदारी।
 - सिस्टम, कानून या प्रक्रियाओं में स्पष्ट सुधार की ओर अग्रसर होने वाली जांच की संभावना।
- प्रक्रिया
 - SFIO इस संबंध में केंद्र सरकार से एक आदेश प्राप्त करने के बाद ही जांच शुरू करता है जिसका अर्थ है, यह अपनी पहल पर मामलों को नहीं उठा सकता है।
 - एक बार जब कोई मामला केंद्र सरकार द्वारा भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत जांच के लिए SFIO को सौंपा गया है, तो केंद्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार की कोई अन्य जांच एजेंसी ऐसे मामलों में जांच शुरू नहीं कर सकती है।
 - यदि ऐसी कोई जांच पहले ही शुरू हो चुकी है, तो इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, और संबंधित एजेंसी को ऐसे अपराधों के संबंध में संबंधित दस्तावेजों और रिकॉर्ड को गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय में स्थानांतरित करना होगा।
- एक कंपनी के मामलों में एक जांच केंद्र सरकार द्वारा शुरू की जा सकती है और निम्नलिखित परिस्थितियों में SFIO को सौंपा जा सकता है:
 - कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 208 (निरीक्षण पर रिपोर्ट) के तहत रजिस्ट्रार या इंस्पेक्टर की एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर।
 - एक कंपनी द्वारा पारित एक विशेष संकल्प की सूचना पर कि इसके मामलों की जांच की आवश्यकता है।
 - सार्वजनिक हित में।
 - केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी भी विभाग से अनुरोध पर।
- SFIO के पास कंपनी कानून के उल्लंघन के लिए लोगों को गिरफ्तार करने की शक्तियां हैं।

490. संयुक्त राष्ट्र कर समिति (UN TAX Committee)

समाचार में: 3 जुलाई, 2018 को, भारत कर मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र के ट्रस्ट फंड में धन का योगदान करने वाला पुनः दुनिया का एकमात्र देश बन गया।

- 'ट्रस्ट फंड' की स्थापना 2006 में हुई थी
- यह कर मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर संयुक्त राष्ट्र की विशेषज्ञों की समिति की गतिविधियों का समर्थन करता है।
- इसमें विकसित और विकासशील देशों के 25 विशेषज्ञ शामिल हैं

- और यह अंतरराष्ट्रीय कराधान के विभिन्न पहलुओं पर मानदंड सेट करता है और उनके निष्पादन में मदद करता है।
- हालांकि, समिति एक राजनीतिक निकाय नहीं है, इसमें ऐसे विशेषज्ञ शामिल हैं जो स्वयं का प्रतिनिधित्व करते हैं, न कि अपने देशों का।
- भारत और विकासशील विश्व संयुक्त राष्ट्र की कर समिति को अंतर सरकारी कर आयोग में बदलने की मांग करते रहे हैं।
- इससे डब्ल्यूटीओ जैसे वैश्विक कर प्राधिकरण का निर्माण होगा।





IASBABA'S

**RAPID REVISION (RaRe)
SERIES - UPSC 2021**

RaRe Notes Hindi

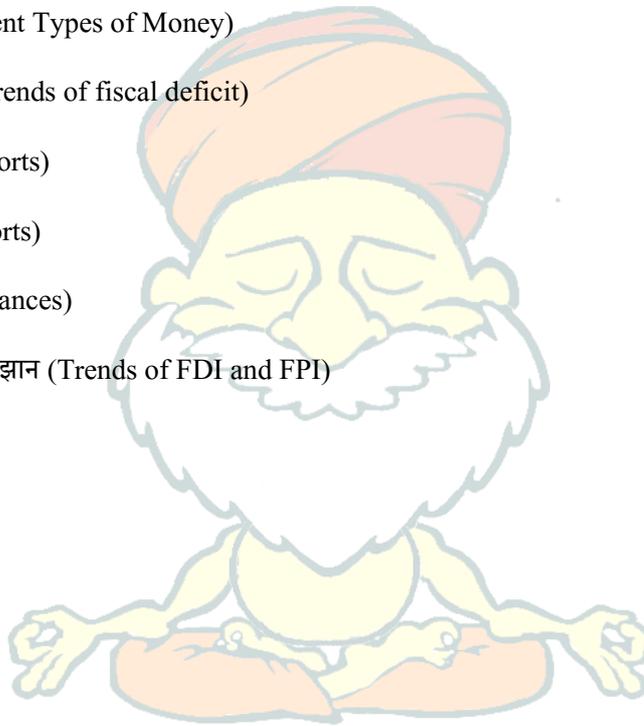
DAY 80 - ECONOMY

#RaRebaba

www.rrs.iasbaba.com

विषय

571. डब्ल्यूपीआई और सीपीआई (WPI and CPI)
572. आईआईपी में प्रमुख उद्योगों का भार (Weightage of Core Industries in IIP)
573. विभिन्न प्रकार के बैंक खाते (Different Types of Bank Accounts)
574. आरबीआई की संपत्ति और देनदारियां (Assets and Liabilities of RBI)
575. विभिन्न प्रकार की मुद्रा (Different Types of Money)
576. राजकोषीय घाटे की प्रवृत्तियां (Trends of fiscal deficit)
577. आयात पर डेटा (Data on Imports)
578. निर्यात पर डेटा (Data on Exports)
579. प्रेषण पर डेटा (Data on remittances)
580. एफडीआई और एफपीआई का रुझान (Trends of FDI and FPI)



571. डब्ल्यूपीआई और सीपीआई (WPI and CPI)**थोक मूल्य सूचकांक (WPI)**

- WPI थोक व्यवसायों द्वारा अन्य व्यवसायों को बेचे गए और थोक में व्यापार किए गए सामानों की कीमतों में बदलाव को मापता है। दूसरे शब्दों में, WPI खुदरा स्तर से पहले कारखाने के गेट पर कीमतों को ट्रैक करता है।
- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा नंबर जारी किए जाते हैं।
- आधार वर्ष **2011-12** है। नया आधार वर्ष जीडीपी और आईआईपी जैसे अन्य संकेतकों के आधार वर्ष के साथ संरेखित होता है।
- भले ही WPI का उपयोग कुछ अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति के एक प्रमुख उपाय के रूप में किया जाता है, RBI अब इसका उपयोग नीतिगत उद्देश्यों के लिए नहीं करता है, जिसमें रेपो दरें निर्धारित करना भी शामिल है।
- WPI के अनंतिम आंकड़े हर महीने (या अगले कार्य दिवस) की 14 तारीख को संदर्भ महीने के दो सप्ताह के अंतराल के साथ जारी किए जाते हैं और संस्थागत स्रोतों और पूरे भारत में चयनित विनिर्माण इकाइयों से प्राप्त आंकड़ों के साथ संकलित किए जाते हैं।

Major Group / Group	Weight		No. of items	
	2004-05	2011-12	2004-05	2011-12
All Commodities	100.00	100.00	676	697
Primary Articles	20.12	22.62	102	117
Fuel & Power	14.91	13.15	19	16
Manufactured Products	64.97	64.23	555	564

- WPI को 2017 में संशोधित किया गया था और मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं
 - WPI तीन प्रमुख समूहों का गठन जारी रखता है- प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और बिजली, और निर्मित उत्पाद।
 - मदों की संख्या **676** से बढ़ाकर **697** कर दी गई है - कुल 199 नई वस्तुओं को जोड़ा गया है और 146 पुरानी वस्तुओं को हटा दिया गया है।
 - संकलन के लिए उपयोग की जाने वाली कीमतों में राजकोषीय नीति के प्रभाव को दूर करने के लिए अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं हैं। यह अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप है और नए WPI को वैचारिक रूप से उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI) के करीब बना देगा।
 - नए WPI के लिए आइटम स्तर के समुच्चय को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम अभ्यास का पालन करते हुए जियोमेट्रिक मीन (GM) का उपयोग करके संकलित किया गया है।
 - एक नया थोक खाद्य मूल्य सूचकांक (WPIF) - खाद्य वस्तुओं (समूह प्राथमिक वस्तुओं से संबंधित) और खाद्य उत्पादों (समूह निर्मित उत्पादों से संबंधित) को मिलाकर पेश किया गया है।

इस सूचकांक के लिए प्रमुख आलोचना यह है कि आम जनता थोक मूल्य पर उत्पाद नहीं खरीदती है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) - खुदरा मुद्रास्फीति

- यह उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली अधिकांश सामान्य वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को एकत्रित करके अर्थव्यवस्था में खुदरा मुद्रास्फीति को मापने वाला एक सूचकांक है।

- यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) द्वारा जारी किया जाता है
- अप्रैल 2014 में, आरबीआई ने मुद्रास्फीति के अपने प्रमुख उपाय के रूप में **CPI** को अपनाया था।
- राष्ट्रीय स्तर पर, चार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) संख्याएँ हैं। ये:

CPI प्रकार	टोकरी	आधार वर्ष	उपयोगिता
औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई (IW)	260 आइटम (प्लस सेवाएं)	2001	<ul style="list-style-type: none"> ● केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन/वेतन को इस सूचकांक में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर संशोधित किया जाता है, महंगाई भत्ता (DA) की घोषणा वर्ष में दो बार की जाती है। ● जब वेतन आयोग वेतन संशोधन की सिफारिश करता है, तो आधार CPI (IW) होता है।
कृषि मजदूरों के लिए CPI (AL)	260 वस्तुएं एक मासिक आवृत्ति के साथ 600 गांवों में एकत्र और तीन सप्ताह का समय अंतराल है।	1986-87	<ul style="list-style-type: none"> ● इस सूचकांक का उपयोग विभिन्न राज्यों में खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी को संशोधित करने के लिए किया जाता है। ● केंद्र और राज्य इस सूचकांक में बदलाव को लेकर सतर्क रहते हैं क्योंकि यह समाज के सबसे कमजोर वर्ग पर मूल्य प्रभाव को दर्शाता है, यह खंड अपनी कुल आय का लगभग 75 प्रतिशत खाद्य वस्तुओं की खरीद पर खर्च करता है।
ग्रामीण मजदूरों के लिए सीपीआई (RL)	260 वस्तुएं मासिक आवृत्ति के साथ 600 गांवों में एकत्र किया जाता है और इसमें तीन सप्ताह का समय अंतराल होता है।	1983	<ul style="list-style-type: none"> ● भारत में कृषि और ग्रामीण मजदूर एक ओवरलैप बनाते हैं, यानी, एक बार कृषि क्षेत्र में कम या कोई रोजगार की गुंजाइश नहीं होने पर वही मजदूर ग्रामीण मजदूरों के रूप में काम करते हैं। ● शायद इसी कारण से सरकार ने 2001-02 में इस इंडेक्स को हटा दिया था। ● लेकिन केंद्र में सरकार बदलने के बाद सूचकांक को पुनः शुरू किया गया।
शहरी गैर-मैनुअल कर्मचारियों के लिए सीपीआई (UNME)	टोकरी में 146-365 वस्तुएं हैं जिसके लिए देश के 59 केंद्रों पर डेटा एकत्र किया जाता है।	1984-85	<ul style="list-style-type: none"> ● इस मूल्य सूचकांक का सीमित उपयोग है और इसका उपयोग मूल रूप से भारत में संचालित कुछ विदेशी कंपनियों (यानी, एयरलाइंस, संचार, बैंकिंग, बीमा, दूतावास और अन्य वित्तीय सेवाओं) के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) के निर्धारण के लिए किया जाता है। ● इसका उपयोग पूंजीगत लाभ निर्धारित करने के लिए आयकर अधिनियम के तहत भी किया जाता है। ● सीपीआई (U) का प्रकाशन शुरू होने के बाद से जनवरी 2011 से सूचकांक बंद कर दिया गया था।

- जबकि पहले तीन को श्रम मंत्रालय में श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित और जारी किया जाता है, चौथा (CPI-UNME) केंद्रीय सांख्यिकी संगठन(CSO) द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में जारी किया जाता है।
- 2011 में, CSO ने तीन नए CPI की शुरुआत की
 - सीपीआई - शहरी
 - सीपीआई - ग्रामीण
 - सीपीआई - संयुक्त
- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय आधार वर्ष 2012 पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) जारी कर रहा है।

- CPI माप सेवाओं पर लगभग 36% वेटेज प्रदान करता है और इसमें आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, परिवहन और संचार, व्यक्तिगत देखभाल और मनोरंजन में मूल्य परिवर्तन शामिल हैं।

Group Description	Old Series of CPI (Weights computed on the basis CES 2004-05)			Revised Series of CPI (Weights computed on the basis CES 2011-12)		
	Rural	Urban	Combnd.	Rural	Urban	Combnd.
Food and beverages	56.39	35.81	47.58	34.18	36.29	45.86
Pan, tobacco and intoxicants	2.72	1.34	2.13	3.26	1.36	2.35
Clothing and Footwear	5.36	3.91	4.73	7.36	5.57	6.53
Housing	–	22.54	9.77	–	21.67	10.07
Fuel and Light	10.42	8.40	9.49	7.94	5.50	6.84
Miscellaneous	24.91	28.00	26.31	27.26	29.53	28.32
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

WPI और CPI के बीच अंतर

- WPI, उत्पादक स्तर पर मुद्रास्फीति को ट्रैक करता है और CPI उपभोक्ता स्तर पर कीमतों के स्तर में बदलाव को पकड़ता है।
- दोनों बास्केट व्यापक अर्थव्यवस्था के भीतर मुद्रास्फीति के रुझान (मूल्य संकेतों की गति) को मापते हैं, दो सूचकांक भिन्न होते हैं जिसमें भोजन, ईंधन और निर्मित वस्तुओं को भार दिया जाता है।
- WPI सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन पर कब्जा नहीं करता है, जो CPI करता है।

हेडलाइन रिटेल महंगाई बनाम कोर महंगाई

- हेडलाइन मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के माध्यम से रिपोर्ट की गई कच्ची मुद्रास्फीति का आंकड़ा है जो CSO द्वारा जारी किया गया है। शीर्षक का आंकड़ा मौसमी या अक्सर अस्थिर तत्वों के लिए समायोजित नहीं किया जाता है।
- कोर मुद्रास्फीति CPI घटकों को हटा देती है जो महीने-दर-महीने बड़ी मात्रा में अस्थिरता का प्रदर्शन कर सकते हैं, जिससे हेडलाइन के आंकड़े में अवांछित विकृति हो सकती है। सबसे अधिक हटाए गए कारक भोजन और ऊर्जा की लागत से संबंधित हैं।

572. आईआईपी में प्रमुख उद्योगों का भार (Weightage of Core Industries in IIP)

- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) एक संकेतक है जो एक निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन को मापता है।
- आईआईपी का मौजूदा आधार वर्ष 2011-12 है।
- "सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय" के तहत केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (CSO) औद्योगिक उत्पादन (IIP) के सूचकांक को संकलित करता है।
- IIP मासिक प्रकाशित किया जाता है, संदर्भ माह समाप्त होने के छह सप्ताह बाद।
- IIP एक समग्र संकेतक है जो नीचे वर्गीकृत उद्योग समूहों की विकास दर को मापता है:
 - व्यापक क्षेत्र, अर्थात् खनन, विनिर्माण और बिजली।

- उपयोग-आधारित क्षेत्र, अर्थात् मूल सामान, पूंजीगत सामान और मध्यवर्ती सामान।
- भारत के आठ प्रमुख उद्योग आईआईपी में शामिल वस्तुओं के भार का लगभग 40% प्रतिनिधित्व करते हैं।
- आठ कोर सेक्टर और कोर सेक्टर्स में उनका भार इस प्रकार है:
 - कोयला उत्पादन (भार: 10.33 प्रतिशत)
 - कच्चे तेल का उत्पादन (भार: 8.98 प्रतिशत)
 - प्राकृतिक गैस उत्पादन (भार: 6.88 प्रतिशत)
 - पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद उत्पादन (भार: 28.04 प्रतिशत)
 - उर्वरक उत्पादन (भार 2.63 प्रतिशत)
 - इस्पात उत्पादन (भार: 17.92 प्रतिशत)
 - सीमेंट उत्पादन (भार: 5.37 प्रतिशत)
 - बिजली उत्पादन (भार: 19.85 प्रतिशत)

Sector	Base year 2011-12		New Series (base 2011-12)	Item groups	Weights (%)
	Weights (%)	Item groups			
Mining	14.373	1	Primary goods	15	34.05
Manufacturing	77.633	405	Intermediate goods	110	17.22
Electricity	7.994	1	Capital goods	67	8.22
Total	100	407	Infrastructure/ construction goods	29	12.34
			Consumer durables	86	12.84
			Consumer nondurables	100	15.33
			TOTAL	407	100

IIP का महत्व :

- IIP उत्पादन की भौतिक मात्रा पर एकमात्र उपाय है।
- इसका उपयोग नीति-निर्माण उद्देश्यों के लिए वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक आदि सहित सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाता है।
- IIP तिमाही और अग्रिम जीडीपी अनुमानों की गणना के लिए बेहद प्रासंगिक है।

573. विभिन्न प्रकार के बैंक खाते (Different Types of Bank Accounts)

बचत खाता	<ul style="list-style-type: none"> • बैंक उनके साथ इस प्रकार का खाता खोलने के लिए ब्याज का भुगतान करता है। • जमा की संख्या की कोई सीमा नहीं है लेकिन निकासी पर प्रतिबंध है। • इस प्रकार के खाते के लिए कोई न्यूनतम शेषराशि बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है। • बचत बैंक खाते को दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है: मूल बचत बैंक जमा खाता (BSBDA) और दूसरा मूल बचत बैंक जमा खाता लघु योजना (BSBDS) है।
चालू खाता	<ul style="list-style-type: none"> • ऐसे खातों से जमा या निकासी की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। • चालू बैंक खातों के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध है। • ऐसे खातों पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है।

आवर्ती जमा खाता	<ul style="list-style-type: none"> यहां खाताधारक को निश्चित परिपक्वता तिथि तक पहुंचने तक हर महीने एक निश्चित राशि जमा करने की आवश्यकता होती है। कोई भी व्यक्ति या संस्थान अलग से या संयुक्त रूप से आवर्ती जमा खाता खोल सकता है। राशि के लिए ब्याज का भुगतान किया जाता है। राशि की समयपूर्व निकासी की अनुमति है, बशर्ते राशि की राशि दंड के रूप में काटी जा सकती है।
सावधि जमा खाता	<ul style="list-style-type: none"> यह एक एक बार जमा है और एक बार निकासी खाता है। बैंक सावधि जमा खाते पर ब्याज का भुगतान करते हैं। ब्याज की दर आपके द्वारा जमा की गई राशि और एफडी की समय अवधि पर निर्भर करती है। FD की परिपक्वता तिथि से पहले राशि का पूर्ण पुनर्भुगतान उपलब्ध है।
डीमैट खाता	<ul style="list-style-type: none"> इसे केवल नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड में खोला जा सकता है। यह बांड और शेयरों के आसान व्यापार को सुविधाजनक बनाने में मदद करता है। डीमैट खाता खोलने के लिए KYC आवश्यक है। लेनदेन लागत में कटौती की जाती है।
NRI खाता	<ul style="list-style-type: none"> NRI (अनिवासी साधारण रुपये) खाता-यह एक एफडी/आरडी / चालू / बचत खाता है। NRI (अनिवासी बाहरी रुपये) खाता-यह खाता किसी भारतीय निवासी के साथ संयुक्त रूप से खोला जा सकता है। FCNR (विदेशी मुद्रा अनिवासी) खाता - यह केवल सावधि जमा के रूप में हो सकता है और केवल परिपक्वता अवधि के बाद वापस लिया जा सकता है।

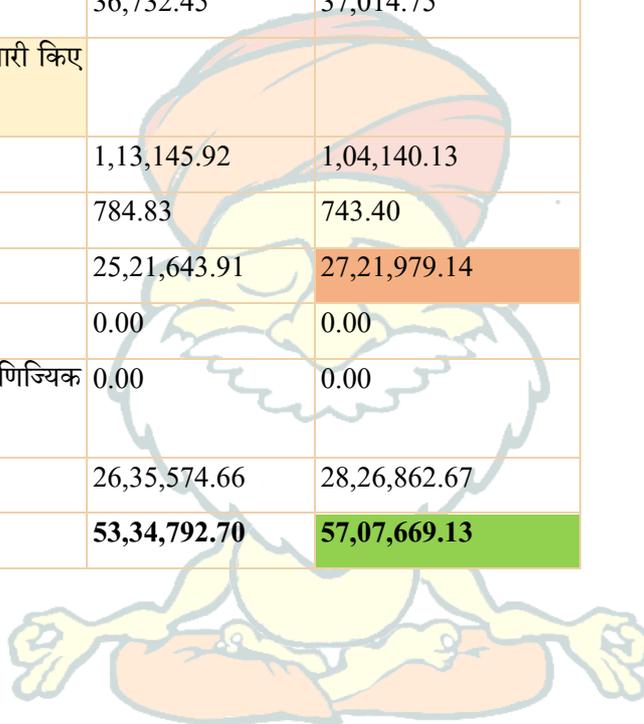
574. आरबीआई की संपत्ति और देनदारियां (Assets and Liabilities of RBI)

31 मार्च, 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट

देयताएं	2019-20	2020-21
पूंजी	5.00	5.00
सुरक्षित कोष	6,500.00	6,500.00
अन्य भंडार	232.00	234.00
जमा	11,75,859.89	14,91,537.70
जोखिम प्रावधान		
आकस्मिक निधि	2,64,033.94	2,84,542.12
एसेट डेवलपमेंट फंड	22,874.68	22,874.68
पुनर्मूल्यांकन खाते	11,24,390.72	9,24,454.99
अन्य देनदारियां	1,05,321.81	1,50,657.97
निर्गम विभाग के दायित्व		
जारी किए गए नोट	26,35,574.66	28,26,862.67
कुल देनदारियों	53,34,792.70	57,07,669.13

(राशि ₹ करोड़ में)

संपत्तियां	2019-20	2020-21
बैंकिंग विभाग की संपत्ति		
नोट, रुपया सिक्का, छोटा सिक्का	12.59	12.02
सोना - बी.डी	1,42,874.67	1,43,582.87
निवेश-विदेशी-बी.डी	10,23,399.50	12,29,940.41
निवेश-घरेलू-बी.डी	11,72,027.28	13,33,173.90
खरीदे और भुनाए गए बिल	0.00	0.00
ऋण और अग्रिम	3,22,207.95	1,35,118.91
सहायक कंपनियों में निवेश	1,963.60	1,963.60
अन्य परिसंपत्तियां	36,732.45	37,014.75
निर्गम विभाग की संपत्ति (आईडी) (जारी किए गए नोटों के लिए समर्थन के रूप में)		
गोल्ड आईडी	1,13,145.92	1,04,140.13
रुपया सिक्का	784.83	743.40
निवेश-विदेशी आईडी	25,21,643.91	27,21,979.14
निवेश-घरेलू आईडी	0.00	0.00
विनिमय के घरेलू बिल और अन्य वाणिज्यिक पत्र	0.00	0.00
	26,35,574.66	28,26,862.67
कुल संपत्ति	53,34,792.70	57,07,669.13



RESERVE BANK OF INDIA INCOME STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2021			
(Amount in ₹ crore)			
INCOME	Schedule	2019-20	2020-21
Interest	13	1,09,333.40	69,057.09
Other Income	14	40,339.06	64,215.66
Total		1,49,672.46	1,33,272.75
EXPENDITURE			
Printing of Notes		4,377.84	4,012.09
Expenditure on Remittance of Currency		87.19	54.80
Agency Charges	15	3,876.08	3,280.06
Employee Cost		8,928.06	4,788.03
Interest		1.34	1.10
Postage and Telecommunication Charges		116.74	105.46
Printing and Stationery		20.03	17.00
Rent, Taxes, Insurance, Lighting, etc.		136.39	122.24
Repairs and Maintenance		87.72	76.49
Directors' and Local Board Members' Fees and Expenses		2.02	0.36
Auditors' Fees and Expenses		6.00	4.90
Law Charges		9.22	8.57
Depreciation		206.11	200.09
Miscellaneous Expenses		1,071.19	765.44
Provisions		73,615.00	20,710.12
Total		92,540.93	34,146.75
Available Balance		57,131.53	99,126.00
Less:			
(a) Contribution to:			
i) National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund		1.00	1.00
ii) National Housing Credit (Long Term Operations) Fund		1.00	1.00
(b) Transferable to NABARD:			
i) National Rural Credit (Long Term Operations) Fund ¹		1.00	1.00
ii) National Rural Credit (Stabilisation) Fund ¹		1.00	1.00
(c) Others			
Surplus payable to the Central Government		57,127.53	99,122.00

1. These funds are maintained by the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD).

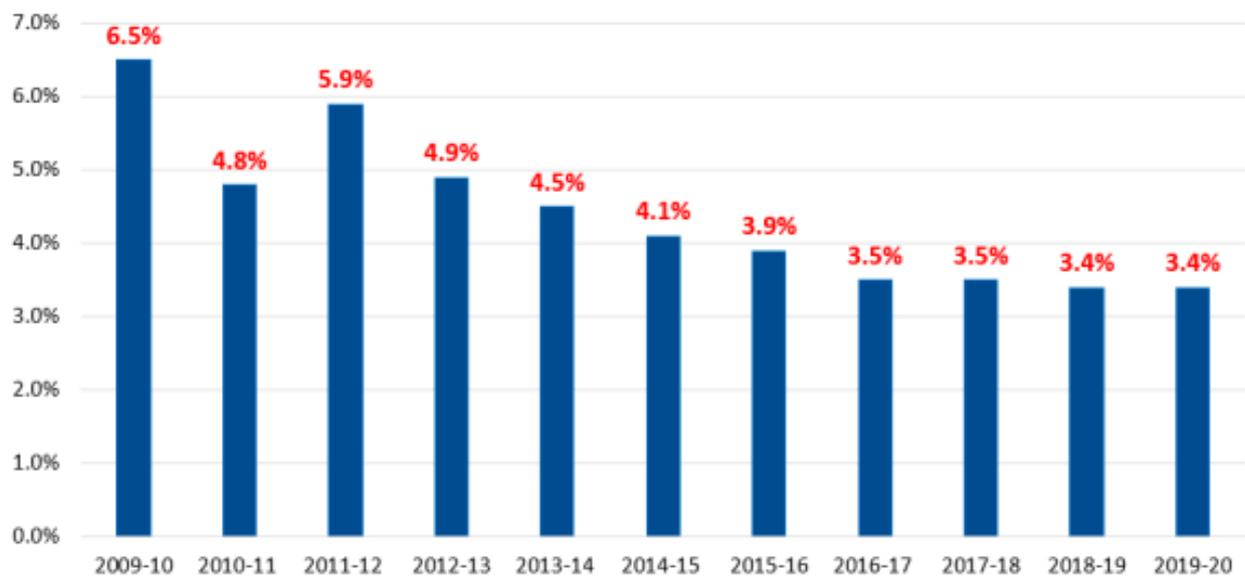
- रिज़र्व बैंक की बैलेंस शीट देश की अर्थव्यवस्था के कामकाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो मोटे तौर पर अपने मुद्रा निर्गम कार्य के साथ-साथ मौद्रिक नीति और आरक्षित प्रबंधन उद्देश्यों के अनुसरण में की गई गतिविधियों को दर्शाती है।
- बैलेंस शीट का आकार 30 जून, 2020 को ₹3,72,876.43 करोड़, यानी 6.99 प्रतिशत बढ़कर ₹53,34,792.70 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2021 तक ₹57,07,669.13 करोड़ हो गया।
- परिसंपत्ति पक्ष में वृद्धि मुख्य रूप से विदेशी और घरेलू निवेश में क्रमशः 11.48 प्रतिशत और 13.75 प्रतिशत की वृद्धि के कारण हुई थी।
- देयता पक्ष में, जमा, जारी किए गए नोट और अन्य देनदारियों में क्रमशः 26.85 प्रतिशत, 7.26 प्रतिशत और 43.05 प्रतिशत की वृद्धि के कारण वृद्धि हुई थी।
- घरेलू परिसंपत्तियों का गठन 26.42 प्रतिशत जबकि विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और सोने (भारत में रखे गए सोने और सोने सहित) का गठन कुल संपत्ति का 73.58 प्रतिशत 31 मार्च, 2021 को क्रमशः 28.75 प्रतिशत और 71.25 प्रतिशत था, जो 30 जून, 2020 तक था।
- ₹20,710.12 करोड़ का प्रावधान किया गया और आकस्मिकता निधि (CF) में स्थानांतरित कर दिया गया। परिसंपत्ति विकास निधि (ADF) के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

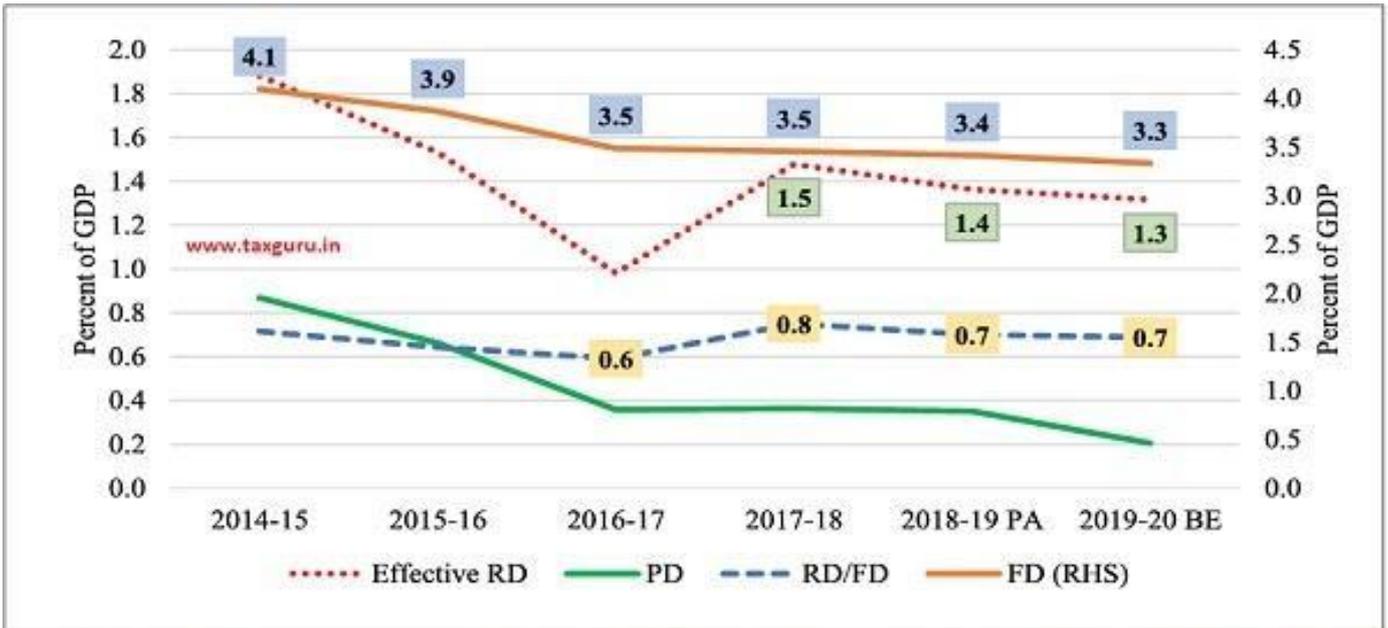
575. विभिन्न प्रकार की मुद्रा (Different Types of Money)

M1	<p>इसमें शामिल हैं</p> <ul style="list-style-type: none"> ● जनता के साथ मुद्रा ● सभी बैंकों में डिमांड डिपॉजिट (जैसे चालू खाता, बचत खाता) ● आरबीआई के पास अन्य जमा <p>इसमें शामिल नहीं है</p> <ul style="list-style-type: none"> ● आईएमएफ, विश्व बैंक, विदेशी सरकार आदि के साथ भारत की जमा राशि ● इंटरबैंक जमा
M2	<ul style="list-style-type: none"> ● $M2 = M1 + \text{डाकघर बैंक बचत}$ ● केवल डाकघर बचत खाता आवर्ती जमा खाता और सावधि जमा खाता नहीं।
M3 (ब्रॉड मनी)	<ul style="list-style-type: none"> ● इसे एग्रीगेट मनी भी कहा जाता है। ● $M3 = M1 + \text{वाणिज्यिक बैंकों के पास सावधि जमा (सावधि जमा, आवर्ती जमा)}$
M4	<ul style="list-style-type: none"> ● $M4 = M3 + \text{कुल पोस्ट ऑफिस में जमा}$. ● डाकघर "सावधि जमा" और "आवर्ती जमा" सहित।

576. राजकोषीय घाटे की प्रवृत्तियां (Trends of fiscal deficit)

India's Fiscal Deficit as % of GDP





Source: Union Budget Documents & CGA BE: Budget Estimate, PA: Provisional Actuals FD: Fiscal Deficit; RD: Revenue Deficit; PD: Primary Deficit.

Note: RD/FD has no units.

समाचार में: सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़कर ₹ 11.58 लाख करोड़ या दिसंबर 2020 के अंत में बजट अनुमान (बीई) का 145.5% (वर्ष 2020-21 के पहले नौ महीनों के लिए लेखांकन) मुख्य रूप से कम राजस्व प्राप्ति के कारण।

- राजकोषीय घाटा = सरकार का कुल व्यय (पूँजीगत और राजस्व व्यय) – सरकार की कुल आय (राजस्व प्राप्ति + ऋण की वसूली + अन्य प्राप्ति)।
 - व्यय घटक: सरकार अपने बजट में वेतन, पेंशन, आदि (राजस्व व्यय) के भुगतान और बुनियादी ढांचे, विकास, आदि (पूँजीगत व्यय) जैसी संपत्तियों के निर्माण सहित कई कार्यों के लिए धन आवंटित करती है।
 - आय घटक: आय घटक दो चरों से बना होता है, केंद्र द्वारा लगाए गए करों से उत्पन्न राजस्व और गैर-कर चर से उत्पन्न आय।
 - कर योग्य आय में निगम कर, आयकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, जीएसटी, आदि से उत्पन्न राशि शामिल है।
 - इस बीच, गैर-कर योग्य आय बाहरी अनुदान, ब्याज प्राप्ति, लाभांश और लाभ, केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्ति, आदि से आती है।
- राजकोषीय घाटा राजस्व घाटे से अलग है जो केवल सरकार के राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति से संबंधित है।
- सरकार पैसे उधार लेकर राजकोषीय घाटे की पूर्ति करती है। एक प्रकार से एक वित्तीय वर्ष में सरकार की कुल उधारी आवश्यकताएं उस वर्ष के राजकोषीय घाटे के बराबर होती हैं।
- एक उच्च राजकोषीय घाटा अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा हो सकता है यदि खर्च किया गया धन राजमार्गों, सड़कों, बंदरगाहों और हवाई अड्डों जैसी उत्पादक संपत्तियों के निर्माण में जाता है जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं और इसके परिणामस्वरूप रोजगार सृजन होता है।
- राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 में प्रावधान है कि केंद्र को 31 मार्च, 2021 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3% तक सीमित करने के लिए उचित उपाय करने चाहिए।
- एन.के.सिंह समिति (2016 में स्थापित) ने सिफारिश की थी कि सरकार को 31 मार्च, 2020 तक सकल घरेलू उत्पाद के 3% के राजकोषीय घाटे को लक्षित करना चाहिए, इसे 2020-21 में 2.8% और 2023 तक 2.5% तक कम करना चाहिए।

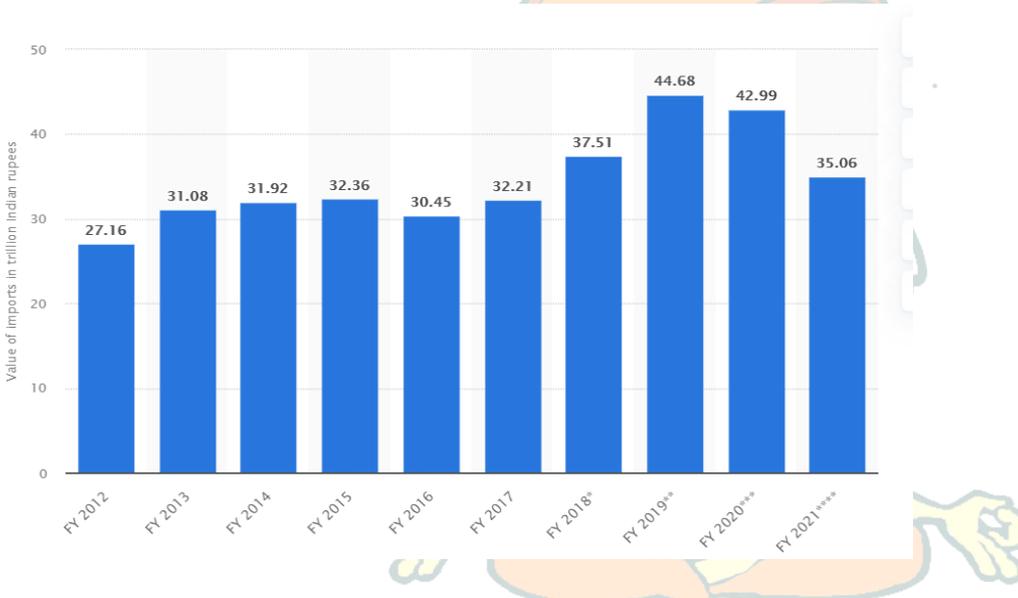
प्रमुख बिंदु

- 2020-21 के लिए तय राजकोषीय घाटा लक्ष्य: केंद्र ने राजकोषीय घाटा ₹ 7.96 लाख करोड़ या सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.5% आंका था।
- 2019-20 में राजकोषीय घाटा: लेखा महानियंत्रक (CGA) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले वित्त वर्ष में दिसंबर के अंत में राजकोषीय घाटा 2019-20 के BE का 132.4% था।

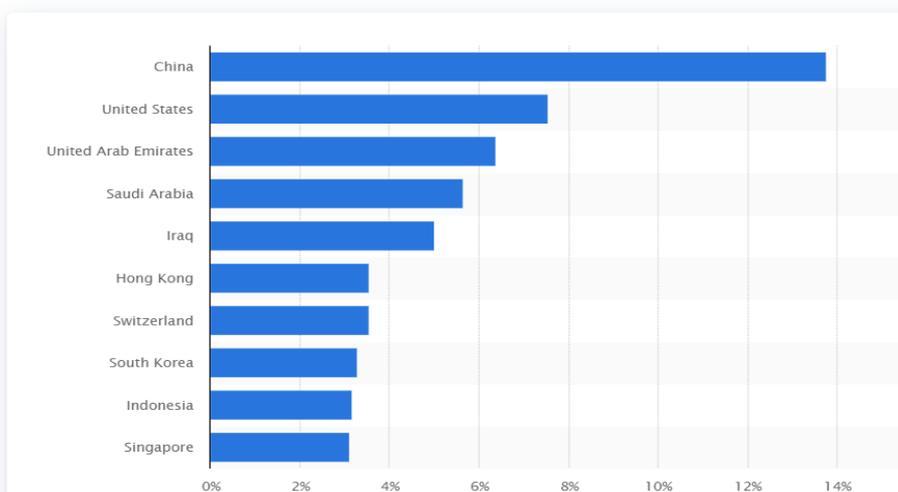
उच्च राजकोषीय घाटे के कारण:

- कम राजस्व प्राप्ति: कोरोनावायरस महामारी और लॉकडाउन के बाद सामान्य व्यावसायिक गतिविधि में व्यवधान के कारण।
- उच्च व्यय: खाद्य और सार्वजनिक वितरण और ग्रामीण विकास में राजस्व व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जिसका श्रेय सरकार के महामारी राहत कार्यक्रमों को दिया जा सकता है।

577. आयात पर डेटा (Data on Imports)



Distribution of India's imports in financial year 2020, |



2020 के दौरान भारत की आयात खरीद:

- तेल सहित खनिज ईंधन: US\$104.4 बिलियन (कुल आयात का 28.4%)
 - इलेक्ट्रिकल मशीनरी, उपकरण: \$42.9 बिलियन (11.7%)
 - रत्न, कीमती धातुएँ: \$41 बिलियन (11.2%)
 - कंप्यूटर सहित मशीनरी: \$35.2 बिलियन (9.6%)
 - कार्बनिक रसायन: \$18.2 बिलियन (4.9%)
 - प्लास्टिक, प्लास्टिक की वस्तुएँ: \$12 बिलियन (3.3%)
 - पशु/वनस्पति वसा, तेल, मोम: \$10.6 बिलियन (2.9%)
 - ऑप्टिकल, तकनीकी, चिकित्सा उपकरण: \$8.2 बिलियन (2.2%)
 - लोहा, इस्पात: \$7.6 बिलियन (2.1%)
 - उर्वरक: \$7.2 बिलियन (2%)
- भारत के शीर्ष 10 आयात अन्य देशों से अपने उत्पाद खरीद के कुल मूल्य के लगभग चार-पांचवें (78.1%) के लिए जिम्मेदार हैं
 - आयातित पशु या वनस्पति वसा, तेल और मोम ने भारत की शीर्ष 10 आयात श्रेणियों में मूल्य में एकमात्र वृद्धि दर्ज की, जो 2019 से 2020 तक 7.8% थी
 - गिरावट उत्पाद श्रेणियों अग्रणी लोहा या इस्पात (नीचे -36%), तेल (नीचे -31.6%) और जवाहरात और कीमती धातुओं (नीचे -30.3%) सहित खनिज ईंधन थे।

578. निर्यात पर डेटा (Data on Exports)

संदर्भ: भारत ने मई 2021 में 32.21 बिलियन डॉलर के माल का निर्यात किया, जो साल-दर-साल आधार पर 67% अधिक और मई 2019 के पूर्व-महामारी शिपमेंट से लगभग 8% अधिक है।

- देश का व्यापारिक व्यापार घाटा घटकर आठ महीने के निचले स्तर पर आ गया है।
- मई 2020 की तुलना में आयात 68.6% बढ़कर 38.53 बिलियन डॉलर हो गया, लेकिन 2019 में इसी महीने की तुलना में 17.5% कम था।

भारत के विदेश व्यापार के बारे में विवरण

माल व्यापार: वर्ष 2020-21 में निर्यात और आयात दोनों में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, आयात में गिरावट निर्यात में गिरावट की तुलना में अधिक थी। इस कारण 2020-21 में व्यापार घाटा (निर्यात-आयात) पिछले वित्तीय वर्षों की तुलना में कम रहा।

चालू खाता शेष: व्यापार घाटा कम होने के साथ-साथ भारत से सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में वृद्धि हुई। इन कारणों से, चालू खाता पिछले 17 वर्षों में पहली बार अधिशेष दर्ज करने के लिए निर्धारित किया गया था।

शीर्ष 3 निर्यात वस्तुएँ: पेट्रोलियम उत्पाद, दवा योगों, मोती और कीमती पत्थरों।

भारत के लिए शीर्ष 3 निर्यात गंतव्य: यूएसए, चीन, संयुक्त अरब अमीरात।

शीर्ष 3 आयात वस्तुएँ: कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद और सोना।

शीर्ष 3 आयात स्रोत: चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात।

भारत के शीर्ष व्यापारिक साझेदार

2019-20 (अप्रैल-नवंबर) की तुलना में 2020-21 (अप्रैल-नवंबर) की अवधि के लिए प्रमुख देशों के लिए भारत के व्यापारिक व्यापार संतुलन से पता चलता है कि बांग्लादेश और नेपाल के बाद भारत का संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सबसे अनुकूल व्यापार संतुलन था।

अप्रैल-नवंबर, 2020-21 और अप्रैल-नवंबर, 2019-20 के दौरान सबसे अधिक व्यापार घाटा चीन के बाद इराक और सऊदी अरब के साथ है।

579. प्रेषण पर डेटा (Data on remittances)

- समाचार में: विश्व बैंक के प्रवासन और विकास संक्षिप्त के नवीनतम संस्करण के अनुसार, कोविड -19 के बावजूद, प्रेषण प्रवाह 2020 में लचीला रहा, जिसमें पहले की तुलना में कम गिरावट दर्ज की गई।

प्रेषण

- प्रेषण वह धन है जो किसी अन्य पार्टी को भेजा जाता है, आमतौर पर एक दूसरे देश में।
- प्रेषक आमतौर पर एक अप्रवासी होता है और प्राप्तकर्ता एक देसी होता है।
- प्रेषण कम आय वाले और विकासशील देशों में लोगों के लिए आय के सबसे बड़े स्रोतों में से एक का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह अक्सर प्रत्यक्ष निवेश और आधिकारिक विकास सहायता की राशि से अधिक होता है।
- प्रेषण परिवारों को भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद करते हैं।
- भारत प्रेषण का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है। प्रेषण भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाता है और इसके चालू खाते के घाटे को पूरा करने में मदद करता है।

भारत का प्रेषण प्रवाह:

- विश्व अर्थव्यवस्था को तबाह करने वाली महामारी के बावजूद, भारत शीर्ष पर है, 2020 में प्रेषण में 83 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक प्राप्त हुआ।
 - 2019 में, भारत को प्रेषण में 83.3 बिलियन अमरीकी डालर प्राप्त हुए थे।
- पिछले वर्ष की तुलना में 2020 में भारत के प्रेषण में केवल 0.2% की गिरावट आई है, संयुक्त अरब अमीरात से प्रेषण में 17% की गिरावट के कारण बहुत अधिक गिरावट आई है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य मेजबान देशों से लचीला प्रवाह की भरपाई करता है।
- वैश्विक प्रेषण के मामले में चीन दूसरे स्थान पर है क्योंकि उसने 2020 में प्रेषण में 59.5 बिलियन अमरीकी डालर प्राप्त किए।
- भारत और चीन के बाद मेक्सिको, फिलीपींस, मिस्र, पाकिस्तान, फ्रांस और बांग्लादेश का स्थान है।

प्रेषण बहिर्वाह:

- प्रेषण बहिर्वाह संयुक्त राज्य अमेरिका (68 बिलियन अमरीकी डालर) से अधिकतम था, इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और चीन का स्थान था।

प्रेषण के सतत प्रवाह का कारण:

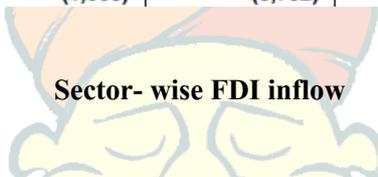
- राजकोषीय प्रोत्साहन जिसके परिणामस्वरूप मेजबान देशों में अपेक्षित आर्थिक स्थिति बेहतर हुई।
- नकदी से डिजिटल और अनौपचारिक से औपचारिक चैनलों की ओर प्रवाह में बदलाव।
- तेल की कीमतों और मुद्रा विनिमय दरों में चक्रीय उतार-चढ़ाव।

580. एफडीआई और एफपीआई का रुझान (Trends of FDI and FPI)

क्षेत्र	FDI सीमा	प्रवेश मार्ग और टिप्पणियां
कृषि और पशुपालन	100%	स्वचालित
खनन	100%	स्वचालित
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (अन्वेषण)	100%	स्वचालित
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (रिफाइनिंग)	49%	स्वचालित
रक्षा निर्माण	100%	74 तक स्वचालित%

		देश में आधुनिक प्रौद्योगिकी तक पहुंच के परिणामस्वरूप मामलों में सरकारी मार्ग के तहत 74% से अधिक।
प्रसारण	100%	स्वचालित
प्रसारण सामग्री सेवाएं	49%	सरकार
मुद्रण माध्यम	26%	सरकार
नागरिक उड्डयन - हवाई अड्डे	100%	स्वचालित
नागरिक उड्डयन - हवाई परिवहन सेवाएं	100%	49% तक स्वचालित सरकारी रूट के तहत 49% से ऊपर अनिवासी भारतीयों के लिए 100% स्वचालित
दूरसंचार सेवाएं	100%	49 % तक स्वचालित 49% से ऊपर सरकारी रूट के तहत
ई-कॉमर्स गतिविधियाँ	100%	स्वचालित
सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग	100%	49 % तक स्वचालित 49% से ऊपर सरकारी रूट के तहत
मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग	51%	सरकार
रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर	100%	स्वचालित
संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों	100%	स्वचालित
बैंकिंग- निजी क्षेत्र	74%	49 % तक स्वचालित 49% से ऊपर सरकारी रूट के तहत
बीमा	100%	स्वचालित
पेंशन क्षेत्र	49%	स्वचालित
फार्मास्यूटिकल्स (ग्रीन फील्ड)	100%	स्वचालित
फार्मास्यूटिकल्स(भूरा क्षेत्र)	100%	74 % तक स्वचालित 74% से ऊपर सरकारी मार्ग द्वारा
भारत में निर्मित या उत्पादित खाद्य उत्पाद	100%	सरकार

Rank s	Country	2018-19 (April – March)	2019-20 (April – March)	2020-21 (April – March)	Cumulative Inflows (April, 00 - March, 21)	%age to total Inflows (in terms of US \$)
1.	MAURITIUS	57,139 (8,084)	57,785 (8,241)	41,661 (5,639)	837,602 (148,350)	28%
2.	SINGAPORE	112,362 (16,228)	103,615 (14,671)	129,227 (17,419)	738,789 (115,089)	22%
3.	U.S.A.	22,335 (3,139)	29,850 (4,223)	102,499 (13,823)	278,721 (43,602)	8%
4.	NETHERLANDS	27,036 (3,870)	46,071 (6,500)	20,830 (2,789)	229,152 (36,641)	7%
5.	JAPAN	20,556 (2,965)	22,774 (3,226)	14,441 (1,950)	210,546 (35,449)	7%
6.	U.K.	9,352 (1,351)	10,041 (1,422)	15,225 (2,043)	165,637 (30,254)	6%
7.	GERMANY	6,187 (886)	3,467 (488)	4,910 (667)	73,854 (12,863)	2%
8.	UAE	6,356 (898)	2,393 (339)	31,242 (4,203)	72,944 (11,193)	2%
9.	CYPRUS	2,134 (296)	6,449 (879)	2,839 (386)	60,833 (11,134)	2%
10.	CAYMAN ISLANDS	7,147 (1,008)	26,397 (3,702)	20,779 (2,799)	70,627 (10,335)	2%

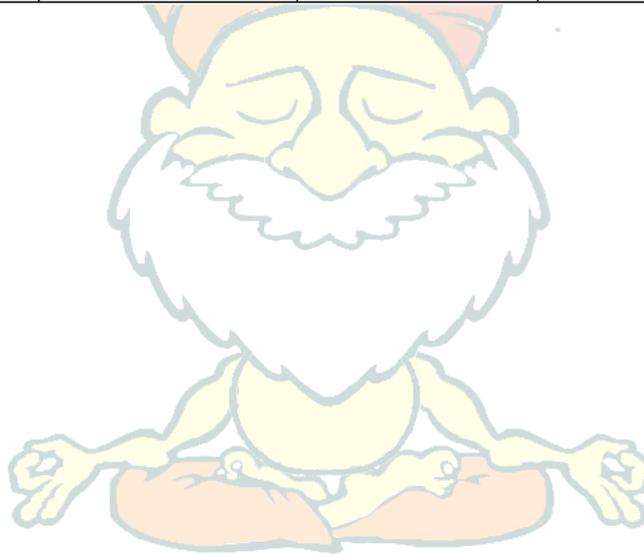


Sector- wise FDI inflow

Ranks	Sector	2018-19 (April – March)	2019-20 (April – March)	2020-21 (April – March)	Cumulative Inflows (April, 00 - March, 21)	% age to total Inflows (In terms of US\$)
1.	SERVICES SECTOR **	63,909 (9,158)	55,429 (7,854)	37,542 (5,060)	509,272 (87,063)	16%
2.	COMPUTER SOFTWARE & HARDWARE	45,297 (6,415)	54,250 (7,673)	194,291 (26,145)	470,298 (71,056)	13%
3.	TELECOMMUNICATIONS	18,337 (2,668)	30,940 (4,445)	2,884 (392)	222,073 (37,663)	7%
4.	TRADING	30,963 (4,462)	32,406 (4,574)	19,349 (2,608)	195,353 (30,203)	6%
5.	CONSTRUCTION DEVELOPMENT: Townships, housing, built-up infrastructure and construction-development projects	1,503 (213)	4,350 (617)	3,117 (422)	127,081 (26,084)	5%
6.	AUTOMOBILE INDUSTRY	18,309 (2,623)	19,753 (2,824)	12,115 (1,637)	155,857 (25,848)	5%
7.	CONSTRUCTION (INFRASTRUCTURE) ACTIVITIES	15,927 (2,258)	14,510 (2,042)	58,240 (7,875)	166,622 (24,721)	5%
8.	CHEMICALS (OTHER THAN FERTILIZERS)	13,685 (1,981)	7,492 (1,058)	6,300 (847)	104,855 (18,487)	3%
9.	DRUGS & PHARMACEUTICALS	1,842 (266)	3,650 (518)	11,015 (1,490)	98,830 (17,991)	3%
10.	HOTEL & TOURISM	7,590 (1,076)	21,060 (2,938)	2,761 (369)	94,540 (15,658)	3%

State- wise FDI inflow

S. No.	STATE	2019-20 (October – March)	2020-21 (April – March)	Cumulative Inflows (October, 19 - March, 21)	%age to total Inflows (in terms of US\$)
1	GUJARAT	18,964 (2,591)	1,62,830 (21,890)	1,81,794 (24,481)	30%
2	MAHARASHTRA	52,073 (7,263)	1,19,734 (16,170)	1,71,807 (23,432)	28%
3	KARNATAKA	30,746 (4,289)	56,884 (7,670)	87,631 (11,959)	14%
4	DELHI	28,487 (3,973)	40,464 (5,471)	68,951 (9,444)	11%
5	TAMIL NADU	7,230 (1,006)	17,208 (2,323)	24,439 (3,329)	4%
6	JHARKHAND	13,208 (1,852)	5,993 (792)	19,200 (2,644)	3%
7	HARYANA	5,198 (726)	12,559 (1,697)	17,757 (2,423)	3%
8	TELANGANA	4,865 (680)	8,618 (1,155)	13,483 (1,835)	2%
9	PUNJAB	698 (97)	4,719 (644)	5,417 (741)	1%
10	UTTAR PRADESH	1,738 (243)	3,123 (422)	4,861 (665)	1%





IASBABA'S

**RAPID REVISION (RaRe)
SERIES - UPSC 2021**

RaRe Notes Hindi

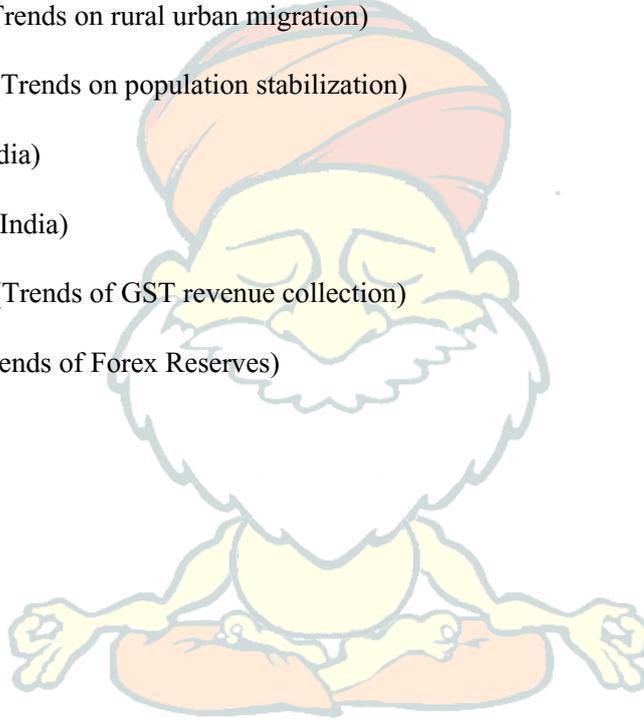
DAY 81 - ECONOMY

#RaRebaba

www.rrs.iasbaba.com

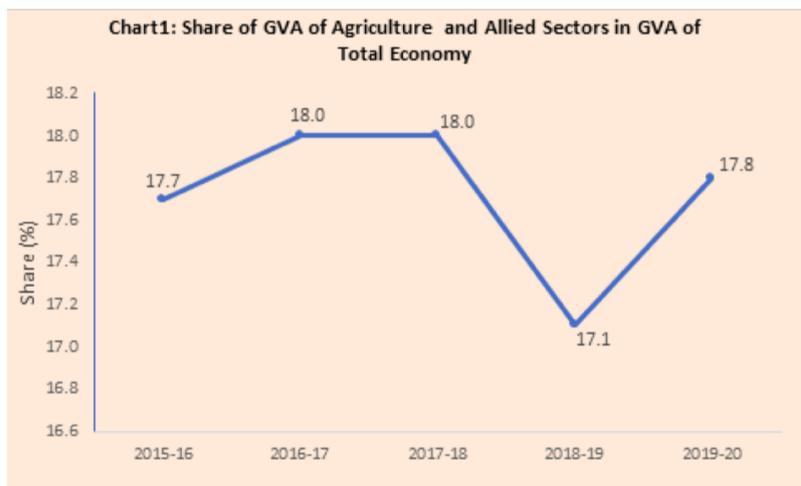
विषय

581. कृषि उत्पादन की प्रवृत्तियां (Trends of Agricultural Production)
582. भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का रुझान (Trends of MSP in India)
583. कृषि आयात और निर्यात (Agricultural Imports and Exports)
584. आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labor force survey)
585. ग्रामीण शहरी प्रवास पर रुझान (Trends on rural urban migration)
586. जनसंख्या स्थिरीकरण पर रुझान (Trends on population stabilization)
587. भारत में गरीबी (Poverty in India)
588. भारत में साक्षरता (Literacy in India)
589. जीएसटी राजस्व संग्रह के रुझान (Trends of GST revenue collection)
590. विदेशी मुद्रा भंडार का रुझान (Trends of Forex Reserves)



581. कृषि उत्पादन की प्रवृत्तियां (Trends of Agricultural Production)

- भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कुल कार्यबल का 54.6% कृषि और संबद्ध क्षेत्र की गतिविधियों में लगा हुआ है (जनगणना 2011)
- साथ ही, वर्ष 2019-20 (मौजूदा कीमतों पर) के लिए देश के सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) में कृषि का योगदान 17.8 फीसदी था, जो 2015-16 में 17.7 फीसदी से थोड़ा अधिक है।
- भूमि उपयोग सांख्यिकी 2016-17 के अनुसार, देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र 328.7 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें से 139.4 मिलियन हेक्टेयर शुद्ध बोया गया क्षेत्र है और 200.2 मिलियन हेक्टेयर सकल फसल क्षेत्र है, जिसमें 143.6% की फसल तीव्रता है।
 - कुल बोया गया क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का 42.4% है।
 - शुद्ध सिंचित क्षेत्र 68.6 मिलियन हेक्टेयर है।



	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
GVA of Agriculture and Allied Sectors (Rs. In Crore)	22,27,533	25,18,662	27,96,908	29,22,846	32,57,443
Per cent to total GVA	17.7	18.0	18.0	17.1	17.8

Year	Total Economy	Agriculture & Allied Sector	Crops	Livestock	Forestry & Logging	Fishing
2015-16	8.0	0.6	-2.9	7.5	1.7	9.7
2016-17	8.0	6.8	5.3	10.0	5.5	10.4
2017-18	6.6	5.9	4.4	7.4	6.2	14.7
2018-19	6.0	2.4	-1.0	8.1	0.4	12.0
2019-20	3.9	4.0	To be released			

क्षेत्र, उत्पादन और प्रमुख फसलों की उपज

Crops	Area (Lakh hectare)			Production (Million Tonnes)			Yield (kg/hectare)		
	2017-18	2018-19	2019-20*	2017-18	2018-19	2019-20*	2017-18	2018-19	2019-20*
Rice	437.7	441.6	437.8	112.8	116.5	118.4	2576	2638	2705
Wheat	296.5	293.2	314.5	99.9	103.6	107.6	3368	3533	3421
Nutri / Coarse cereals	242.9	221.5	240.2	47.0	43.1	47.5	1934	1944	1976

Pulses	298.1	291.6	283.4	25.4	22.1	23.2	853	757	817
Foodgrains	1275.2	1247.8	1275.9	285.0	285.2	296.6	2235	2286	2325
Oilseeds	245.1	247.9	270.4	31.5	31.5	33.4	1284	1271	1236
Sugarcane	47.4	50.6	45.7	379.9	405.4	355.7	80198	80105	77893
Cotton	125.9	126.1	133.7	32.8	28.0	35.5	443	378	451
Jute & Mesta	7.4	7.0	6.8	10.0	9.8	9.9	2435	2508	2641

खरीफ 2020-21 और औसत (2014-15 से 2018-19) में उत्पादन (मिलियन टन में)

Crop	2020-21 (Advance Estimates)	Average (2014- 15 to 2018-19)	Absolute Difference (2020-21 over average)	Percentage Increase/ decrease (+)/(-) in 2021 over average
Foodgrains	144.52	134.69	9.83	7.30
Oilseeds	25.73	19.83	5.90	29.75
Sugarcane	399.83	360.43	39.40	10.93
Cotton@	37.12	31.65	5.47	17.28
Jute& Mesta	9.66	10.49	-0.83	-7.91

582. भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का रुझान (Trends of MSP in India)

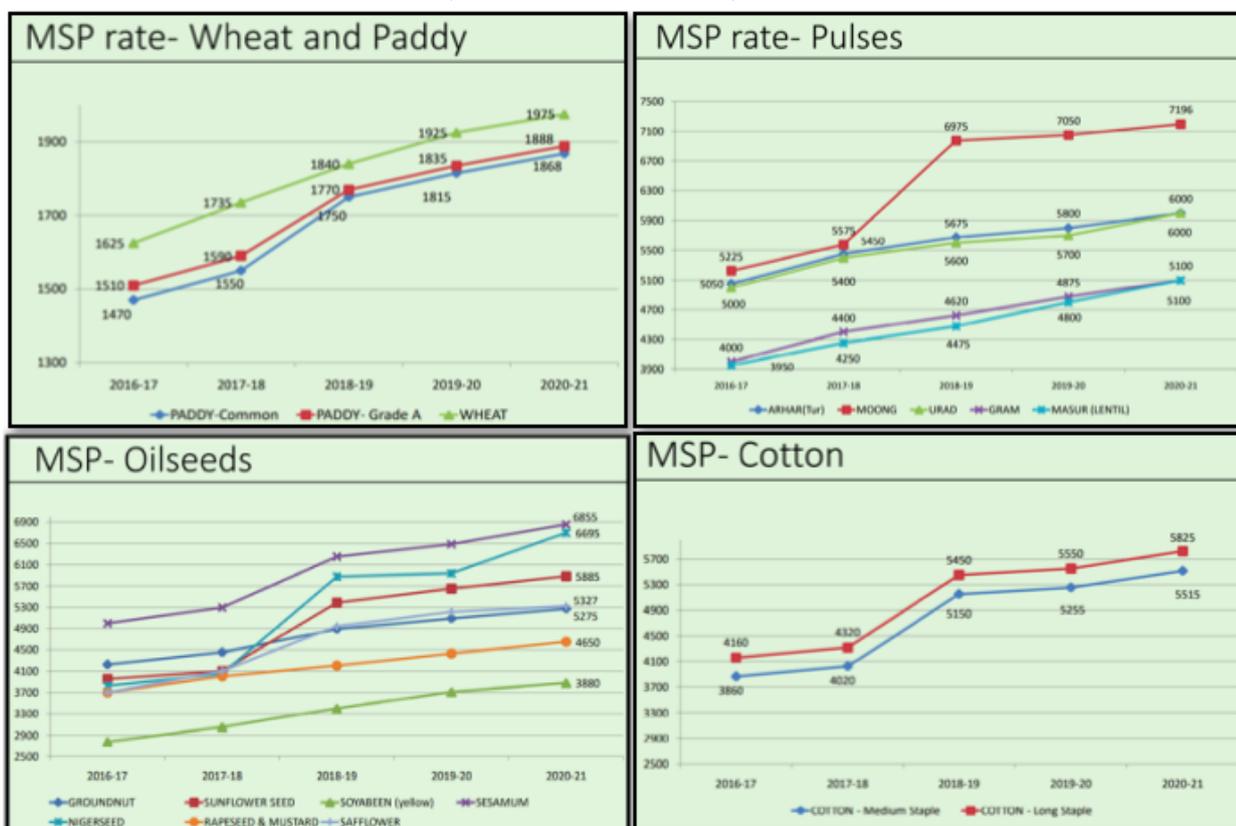
- MSP सरकार द्वारा किसानों से फसल खरीदने के लिए निर्धारित मूल्य है, चाहे फसलों का बाजार मूल्य कुछ भी हो।
- कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों के आधार पर बुवाई के समय से पहले आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा MSP की घोषणा की जाती है।
- समर्थन मूल्य आम तौर पर किसानों के निर्णयों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, जैसे फसलों के लिए भूमि आवंटन, उत्पादित होने वाली फसलों की मात्रा आदि।
- MSP बाजार को स्पष्ट मूल्य संकेत प्रदान करने के अलावा किसानों की कृषि आय का आश्वासन देता है।
- इसका प्रमुख उद्देश्य किसानों को संकटग्रस्त बिक्री से बचाना और सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्न की खरीद करना है।

क्या MSP के लिए कोई कानूनी समर्थन है?

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA), सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के लिए एक कानूनी आधार प्रदान करती है जो पहले केवल एक नियमित सरकारी योजना के रूप में संचालित होता था।
- NFSA ने PDS तक पहुंच को एक अधिकार बना दिया, जिससे "प्राथमिकता वाले घर" से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को सस्ती दरों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार मिल गया।
- MSP, इसके विपरीत, किसी भी कानूनी समर्थन से रहित है। MSP तक पहुंच, PDS के माध्यम से सब्सिडी वाले अनाज के विपरीत, किसानों के लिए एक अधिकार नहीं है। वे इसे अधिकार के रूप में मांग नहीं सकते।
- सरकार चाहे तो MSP पर खरीद सकती है। कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। न ही यह दूसरों (निजी व्यापारियों, संगठित खुदरा विक्रेताओं, प्रोसेसर या निर्यातकों) को भुगतान करने के लिए मजबूर कर सकता है।

फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य का आधार क्या है?

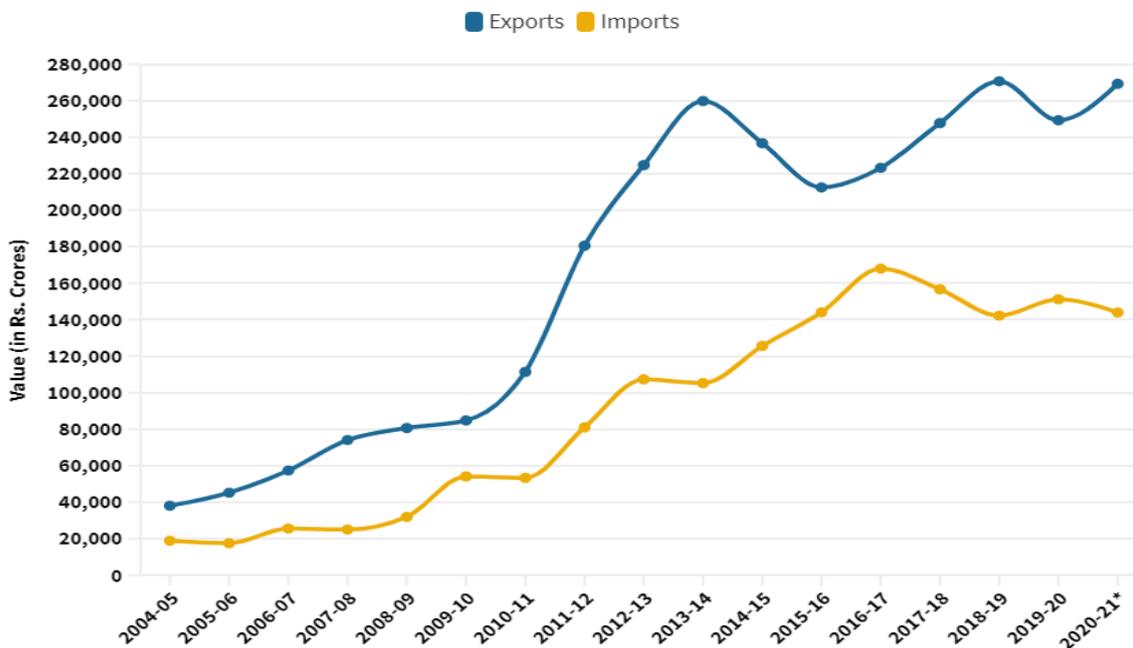
- यह केवल एक सरकारी नीति है जो प्रशासनिक निर्णय लेने का हिस्सा है।
- सरकार फसलों के लिए MSP की घोषणा करती है, लेकिन उनके कार्यान्वयन को अनिवार्य करने वाला कोई कानून नहीं है।
- केंद्र वर्तमान में CACP की सिफारिशों के आधार पर 23 कृषि वस्तुओं के लिए MSP तय करता है —
 - 7 अनाज-धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ
 - 5 दालें-चना, अरहर, उड़द, मूंग और मसूर
 - 7 तिलहन-रेपसीड-सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूजमुखी, तिलसम, कुसुम और नाइजरसीड
 - 4 व्यावसायिक फसलें-कपास, गन्ना, खोपरा और कच्चा जूट
- CACP स्वयं कोई वैधानिक निकाय नहीं है बल्कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। यह MSP की सिफारिश कर सकता है, लेकिन फिक्सिंग (या यहां तक कि फिक्सिंग नहीं) और प्रवर्तन पर निर्णय अंततः सरकार के पास है।



583. कृषि आयात और निर्यात (Agricultural Imports and Exports)

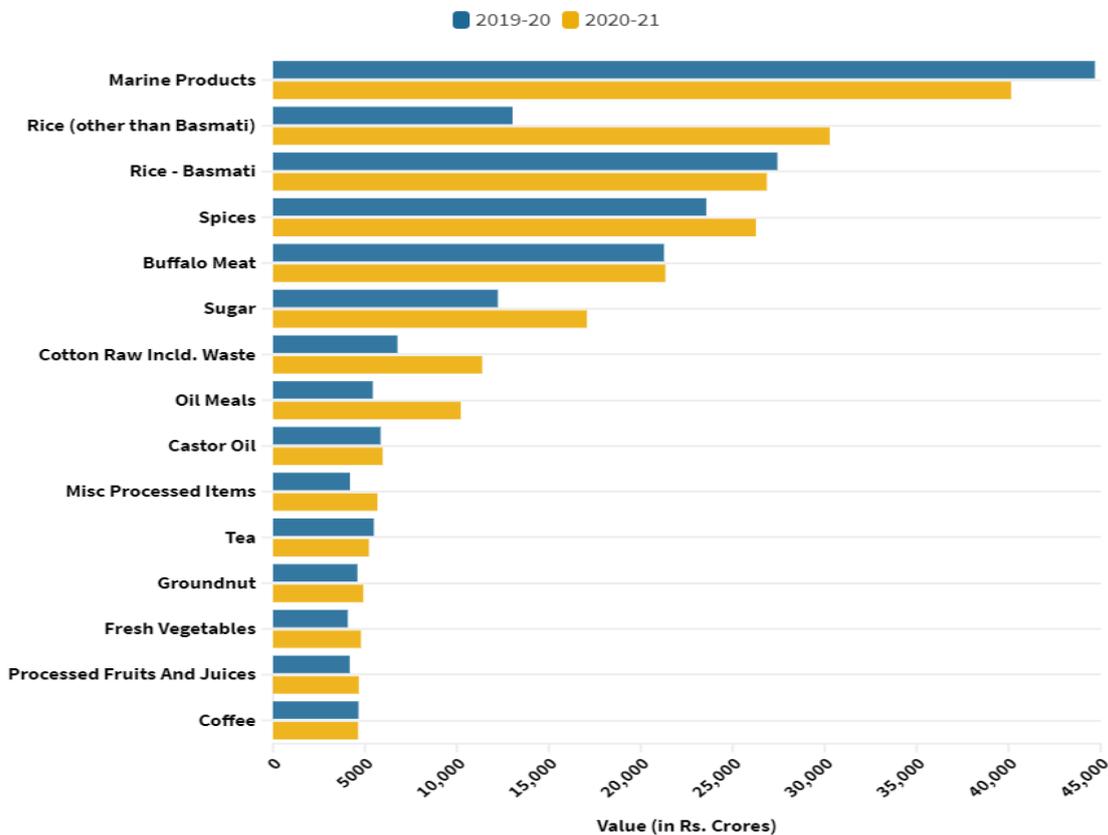
Trend in Imports & Exports of Agricultural commodities

(2004-05 to 2020-21*)



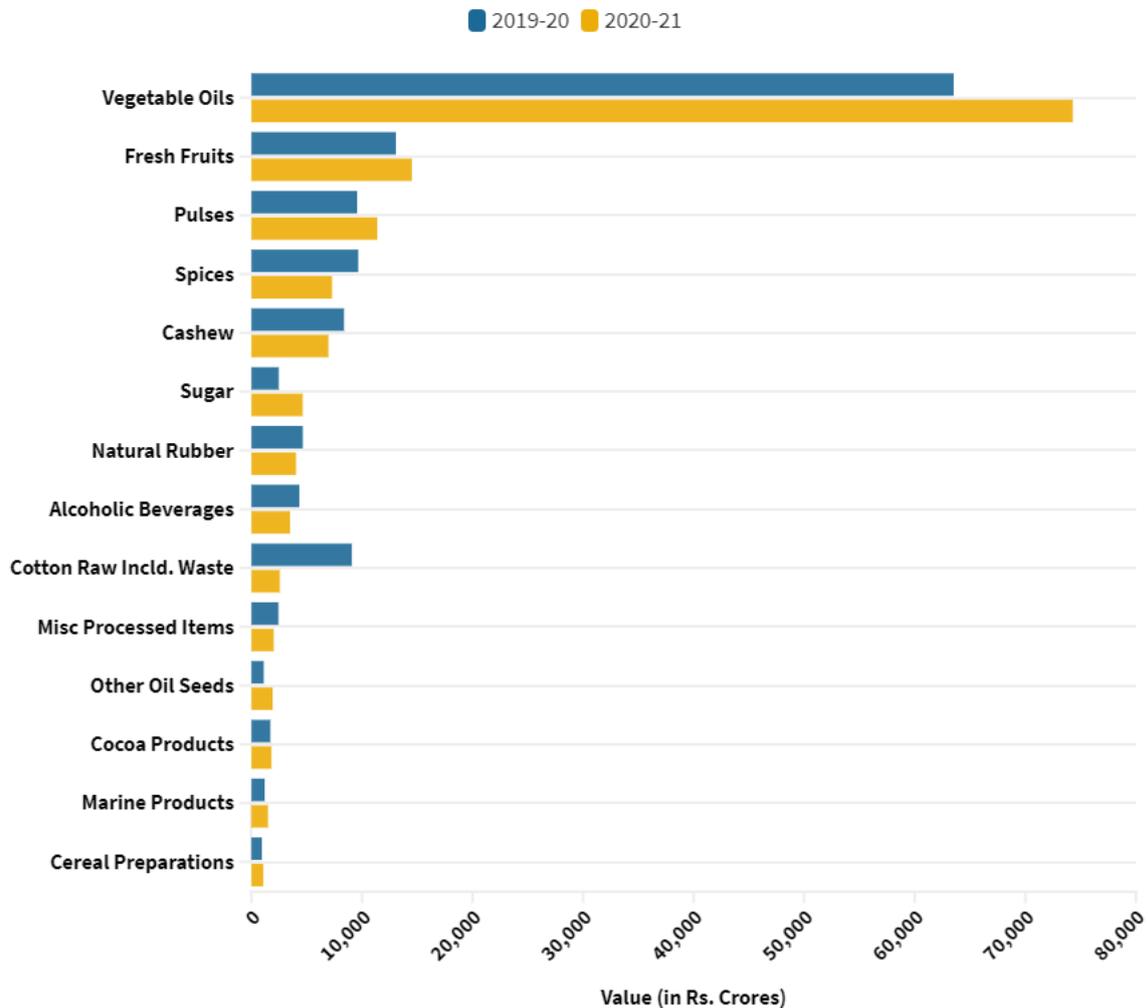
Exports of Major Commodities in 2019-20* and 2020-21*

by Value in Rs. Crores



Imports of major commodities in 2019-20* & 2020-21*

by Value in Rs. Crores



584. आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labor force survey)

- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने अप्रैल 2017 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) शुरू किया था।
- यह शहरी परिवारों के लिए सालाना और तिमाही आधार पर ग्रामीण परिवारों में श्रम शक्ति भागीदारी दर, श्रमिक जनसंख्या अनुपात, बेरोजगार अनुपात और बेरोजगारी दर जैसे प्रमुख संकेतकों का अनुमान देता है।
- PLFS का गठन अमिताभ कुंडू की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिश के आधार पर किया जाता है।
- PLFS से पहले, NSSO अपने पंचवर्षीय (हर 5 साल) घरेलू सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण कार्यक्रम के आधार पर रोजगार और बेरोजगारी से संबंधित डेटा लाता था।
- सर्वेक्षण के आयाम:
 - श्रम शक्ति की भागीदारी दर (LFPR)
 - श्रमिक जनसंख्या अनुपात
 - बेरोजगार
 - बेरोजगारी दर

बेरोजगारी दर (UR): इसे श्रम बल में व्यक्तियों के बीच बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।

श्रम बल भागीदारी दर (LFPR): इसे जनसंख्या में श्रम बल (अर्थात् काम करने वाले या तलाश करने वाले या काम के लिए उपलब्ध) में व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।

श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR): इसे जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।

गतिविधि की स्थिति:

- किसी व्यक्ति की गतिविधि की स्थिति उस व्यक्ति द्वारा निर्दिष्ट संदर्भ अवधि के दौरान की गई गतिविधियों के आधार पर निर्धारित की जाती है।
- सामान्य स्थिति: सर्वेक्षण की तारीख से पहले पिछले 365 दिनों की संदर्भ अवधि के आधार पर निर्धारित गतिविधि की स्थिति को व्यक्ति की सामान्य गतिविधि स्थिति के रूप में जाना जाता है।
- वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS): सर्वेक्षण की तारीख से पहले पिछले 7 दिनों की संदर्भ अवधि के आधार पर निर्धारित गतिविधि की स्थिति को व्यक्ति की वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS) के रूप में जाना जाता है।

Rates	Rural			Urban			Rural+Urban		
	male	female	person	male	female	person	male	female	person
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
all-India									
PLFS 2019-20									
LFPR	56.3	24.7	40.8	57.8	18.5	38.6	56.8	22.8	40.1
WPR	53.8	24.0	39.2	54.1	16.8	35.9	53.9	21.8	38.2
UR	4.5	2.6	4.0	6.4	8.9	7.0	5.1	4.2	4.8

585. ग्रामीण शहरी प्रवास पर रुझान (Trends on rural urban migration)

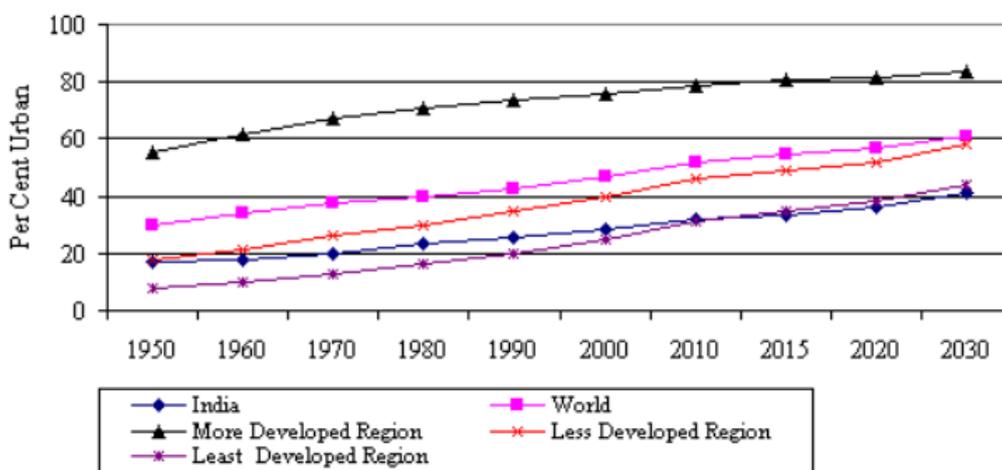
- मानव प्रवास दुनिया में लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है।
 - लोग या तो स्थानांतरित करना चुन सकते हैं (स्वैच्छिक प्रवास) या स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया जा सकता है (अनैच्छिक प्रवास)।
- प्रकार: भारत में आंतरिक प्रवास मुख्यतः दो प्रकार का होता है:
 - दीर्घकालिक प्रवासन, जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति या परिवार का स्थानांतरण होता है।
 - लघु अवधि के प्रवास, जिसमें स्रोत और गंतव्य के बीच आगे और पीछे की आवाजाही शामिल है।
- प्रमुख स्रोत राज्य: उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़।
- प्रमुख गंतव्य राज्य: दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और कर्नाटक।

- भारत में अनुमानित 600 मिलियन प्रवासी हैं। दूसरे शब्दों में, भारत का लगभग आधा हिस्सा ऐसी जगह पर रह रहा है जहाँ उसका जन्म नहीं हुआ था।
- अनुमानित 400 मिलियन भारतीय उस जिले के भीतर "प्रवास" करते हैं जिसमें वे रहते हैं। अगले 140 मिलियन एक जिले से दूसरे जिले में लेकिन उसी राज्य के भीतर पलायन करते हैं।
- और केवल लगभग 60 मिलियन-यानी, सभी आंतरिक प्रवासियों का सिर्फ 10% — एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं।
- प्रवासन का सबसे प्रमुख रूप ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्रों में है। कुल प्रवास का केवल 20% (600 मिलियन) ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में है।
- कुल प्रवासन का 20% एक शहरी क्षेत्र से दूसरे शहरी क्षेत्र में है। जैसे, शहरी प्रवास (ग्रामीण से शहरी और शहरी से शहरी) कुल प्रवास का 40% है।

Table 3: Distribution of Migration in different Streams, 1999-2000 and 2007-2008

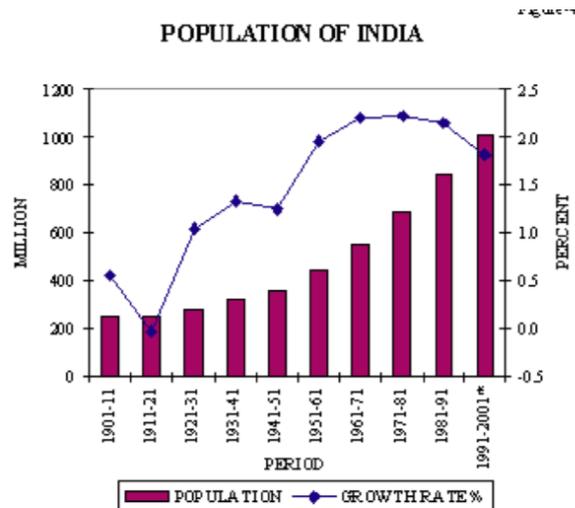
Stream	Male		Female	
	1999-2000	2007-2008	1999-2000	2007-2008
Rural to Rural	32.3	27.1	70.3	70.0
Rural to Urban	34.3	39.0	14.4	14.8
Urban to Rural	10.7	8.9	5.2	4.9
Urban to Urban	22.6	24.8	10.1	10.3
Total	100.0	100.0	100.0	100.0

World Urbanisation Trends, 1950-2030



586. जनसंख्या स्थिरीकरण पर रुझान (Trends on population stabilization)

- 2100 में भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश होगा।
- भारत में 20-64 आयु वर्ग के कामकाजी उम्र के वयस्कों की संख्या 2017 में लगभग 762 मिलियन से गिरकर 2100 में लगभग 578 मिलियन होने का अनुमान है।
- हालांकि, 2100 तक भारत में दुनिया की सबसे बड़ी कामकाजी उम्र की आबादी होने का अनुमान लगाया गया है।



Source:- Registrar General India

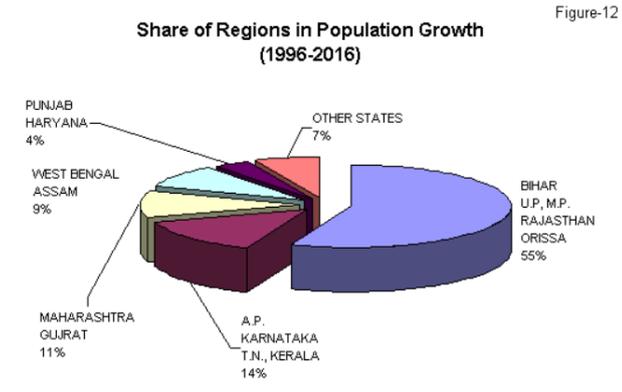


Figure-12

Population Indicators for India: 1990 to 2020

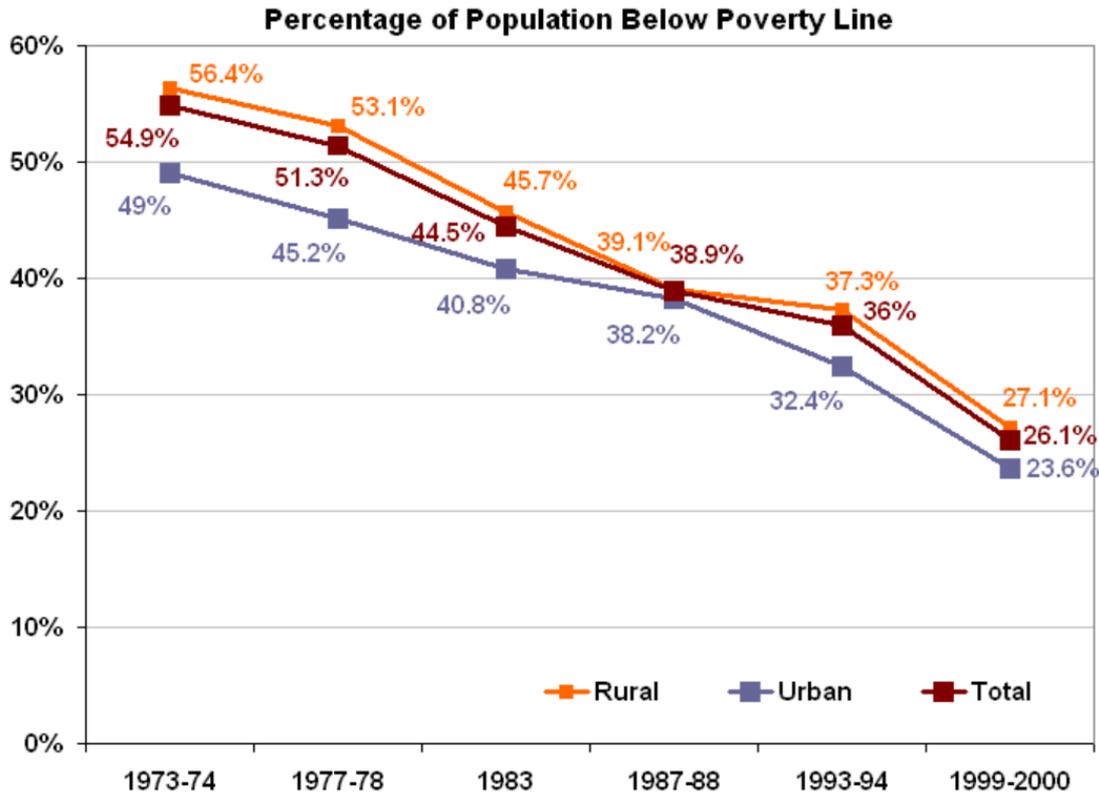
Indicator	1995	1997	2000	2020
POPULATION (thousands)				
Total country	933,252	966,783	1,016,118	1,334,914
Urban	250,111	266,832	290,610	551,319
Rural	683,140	699,951	725,508	783,594
Male, total country				
All ages	483,197	500,005	524,635	681,114
0 to 14	171,370	173,421	175,443	178,643
6 to 12	78,583	80,092	81,281	83,141
13 to 18	61,960	63,449	65,544	69,779
15 to 44	224,906	234,848	249,411	327,395
15 to 49	246,921	258,173	274,907	368,964
15 to 64	290,327	304,049	325,089	456,859
65 and over	21,500	22,536	24,103	45,613
Female, total country				
All ages	450,055	466,778	491,483	653,799
0 to 14	160,657	163,434	165,764	170,595
6 to 12	73,858	75,308	76,399	79,385
13 to 18	54,908	57,404	61,213	66,516
15 to 44	209,847	218,870	232,802	308,519
15 to 49	229,472	239,917	256,331	345,034
15 to 64	268,824	281,625	302,300	435,262
65 and over	20,573	21,719	23,419	47,942

587. भारत में गरीबी (Poverty in India)

- निर्वाह स्तर के संदर्भ में गरीबी की परिभाषा गरीबी को जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए आवश्यक आय की कमी के रूप में वर्णित करती है।

- गरीबी एक अत्यंत जटिल घटना है, जो खुद को अतिव्यापी और आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अभावों की एक श्रृंखला में प्रकट करती है।
- इनमें संपत्ति की कमी, निम्न आय स्तर, भूख, खराब स्वास्थ्य, असुरक्षा, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कठिनाई, सामाजिक बहिष्कार, गिरावट और भेदभाव, और राजनीतिक शक्तिहीनता और अलगाव शामिल हैं।

हाल की रिपोर्टों के अनुसार, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली एक चौथाई से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। भारत के ग्रामीण भागों में रहने वाली कुल जनसंख्या में से 25.7% गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली 13.7% आबादी के साथ स्थिति थोड़ी बेहतर है।

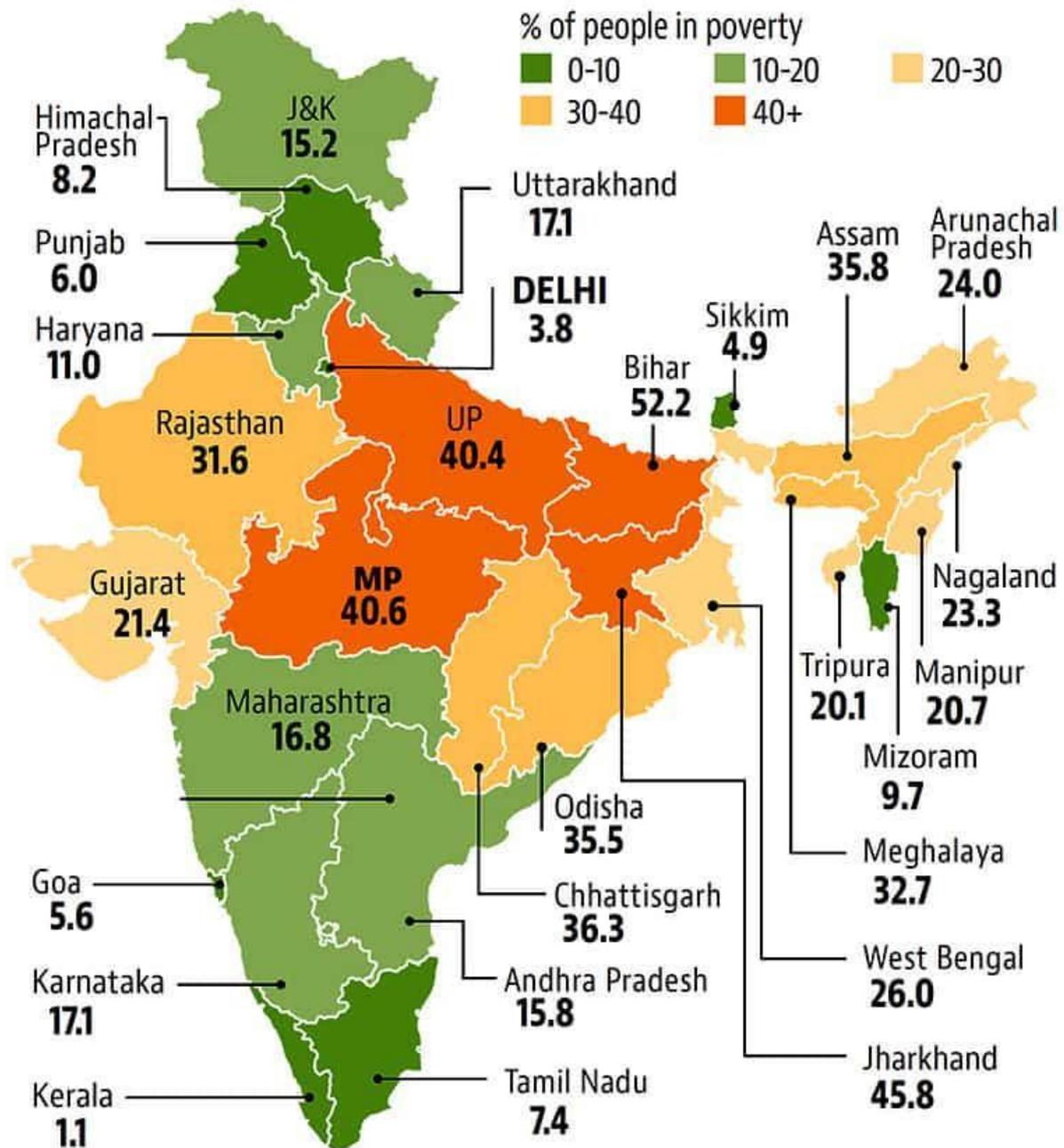


- पूर्ण गरीबी: इसे बुनियादी मानवीय जरूरतों के गंभीर अभाव की विशेषता वाली स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है।
- सापेक्ष गरीबी: इसे उस स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें लोगों को उस समाज में रहने के औसत मानक को बनाए रखने के लिए आवश्यक आय की न्यूनतम राशि की कमी होती है जिसमें वे रहते हैं।
- गरीबी रेखा: यह किसी व्यक्ति को अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक धन की राशि है। इसे किसी व्यक्ति को बुनियादी कल्याण प्रदान करने के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के धन मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है।
- गरीबी रेखा एक देश से दूसरे देश में भिन्न होती है, जो गरीबी के विचार पर निर्भर करती है।
- कर्मचारियों की संख्या का अनुपात: गरीबी रेखा से नीचे की कुल जनसंख्या का प्रतिशत।
- गरीबी का अंतर: यह गरीबों की औसत आय और गरीबी रेखा के बीच का अंतर है। दूसरे शब्दों में, यह गरीबी रेखा से कुल जनसंख्या की औसत कमी है। इस माप का उपयोग गरीबी की तीव्रता को दर्शाने के लिए किया जाता है। गरीबी अंतराल की अवधारणा को विश्व बैंक द्वारा विकसित किया गया था और विभिन्न देशों में गरीबी की घटनाओं को मापने के लिए इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

समितियां	गरीबी आकलन की पद्धति
वाई.के. अलघ	कैलोरी सेवन के आधार पर एक आधिकारिक गरीबी रेखा के साथ आने वाले पहले व्यक्ति। शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी, ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी।
तेंडुलकर	<ul style="list-style-type: none"> ● भारत वर्तमान में इस पद्धति का अनुसरण करता है। ● कैलोरी आधारित अनुमान को व्यय आधारित में बदला। ● एक नया शब्द गरीबी रेखा टोकरी (PLB) पेश किया जो गरीबी को निर्धारित करने के लिए चुने गए सभी सामानों की टोकरी है। ● खपत मात्रा ग्रामीण और शहरी दोनों लोगों के लिए समान है लेकिन कीमत अलग है। ग्रामीण के लिए दैनिक प्रति व्यक्ति व्यय- रु. 27, शहरी के लिए दैनिक प्रति व्यक्ति व्यय- रु. 33. ● अनुमान है कि भारतीय आबादी का 21.5% गरीब है।
रंगराजन	<ul style="list-style-type: none"> ● कैलोरी-आधारित दृष्टिकोण अपनाया जो अतीत में इस्तेमाल किया गया था। ● साधन के रूप में प्रति व्यक्ति या प्रति परिवार मासिक उपभोग व्यय, ग्रामीण के लिए दैनिक प्रति व्यक्ति व्यय- रु. 33 और शहरी के लिए दैनिक प्रति व्यक्ति व्यय- रु. 47 ● कुल गरीबी- 29.5 प्रतिशत (वर्ष 2011-12 में) ● ग्रामीण- 30.9 प्रतिशत (वर्ष 2011-12 में) ● शहरी- 26.4 प्रतिशत (वर्ष 2011-12 में)
SECC (सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना)	<ul style="list-style-type: none"> ● BPL आबादी का अनुमान लगाने के लिए, SECC ने तीन चरणों वाली प्रक्रिया का पालन किया: <ul style="list-style-type: none"> ● स्वचालित बहिष्करण। ● स्वचालित समावेश। ● न तो स्वचालित रूप से शामिल है और न ही स्वचालित रूप से बाहर रखा गया। ● उपरोक्त पद्धति को लागू करने के बाद यह पाया गया कि 2011-12 में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में 30.95 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 26.4 प्रतिशत था। ● अवयव: <ol style="list-style-type: none"> 1. खाद्य घटक 2. गैर-खाद्य घटक जैसे, शिक्षा वस्त्र, वाहन, किराया, व्यवहार संबंधी व्यय।

WHERE STATES STAND

Map shows % of poor people in Indian states in 2015-16



588. भारत में साक्षरता (Literacy in India)

समाचार में: हाल ही में, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वें दौर के हिस्से के रूप में 'घरेलू सामाजिक उपभोग: भारत में शिक्षा - जुलाई 2017 से जून 2018 तक' पर रिपोर्ट जारी की गई है।

- यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) सर्वेक्षण पर आधारित है और सात वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच साक्षरता दर का राज्यवार विवरण प्रदान करता है।
- यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस से पहले आती है जो हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है।

डेटा विश्लेषण: भारत की समग्र साक्षरता दर 77.7% है।

- शहरी क्षेत्र: 87.7%
- ग्रामीण क्षेत्र: 73.5%
- पुरुष साक्षरता दर: 84.7%
- महिला साक्षरता दर: 70.3%
- सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में पुरुष साक्षरता दर महिला साक्षरता दर से अधिक है।
- सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन: केरल > दिल्ली > उत्तराखंड > हिमाचल प्रदेश > असम।
- सबसे खराब प्रदर्शन: आंध्र प्रदेश < राजस्थान < बिहार < तेलंगाना < उत्तर प्रदेश।
- डिजिटल साक्षरता:
 - शहरी परिवारों के 23% और ग्रामीण परिवारों के 4% के पास कंप्यूटर हैं।
 - 15-29 वर्ष की आयु के व्यक्तियों में, शहरी क्षेत्रों में लगभग 56% और ग्रामीण क्षेत्रों में 24% कंप्यूटर संचालित करने में सक्षम थे।
 - इसी आयु वर्ग में, ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 25% और शहरी क्षेत्रों में 58% ने इंटरनेट के उपयोग की सूचना दी।

क्या आप जानते हैं?

- अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के साथ 2030 पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और इसका लक्ष्य SDG 4 के अपने लक्ष्यों के भीतर "सभी के लिए समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और आजीवन सीखने को बढ़ावा देना" है।
- यूनेस्को के अनुसार, भारत 2060 तक सार्वभौमिक साक्षरता हासिल कर लेगा।

589. जीएसटी राजस्व संग्रह के रुझान (Trends of GST revenue collection)

- समाचार में: अप्रैल 2021 के महीने में एकत्र किया गया सकल जीएसटी राजस्व 1,41,384 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर रहा। जिसमें से
 - CGST रु. 27,837 करोड़
 - SGST रु. 35,621 करोड़
 - IGST 68,481 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर एकत्रित 29,599 करोड़ रुपये सहित)
 - उपकर रु. 9,445 करोड़ (वस्तुओं के आयात पर एकत्रित 981 करोड़ रुपये सहित)।
- देश के कई हिस्सों को प्रभावित करने वाली COVID-19 महामारी की दूसरी लहर के बावजूद, भारतीय व्यवसायों ने एक बार फिर से न केवल रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकताओं का पालन करके, बल्कि महीने के दौरान समय पर अपने GST बकाया का भुगतान करके उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया है।
- अप्रैल 2021 के दौरान GST राजस्व पिछले महीने (मार्च 2021) में संग्रह को पार करने के बाद से सबसे अधिक है।

- नकली बिलिंग के खिलाफ कड़ी निगरानी, जीएसटी, आयकर और सीमा शुल्क आईटी सिस्टम और प्रभावी कर प्रशासन सहित कई स्रोतों से डेटा का उपयोग करते हुए गहन डेटा विश्लेषण ने भी कर राजस्व में लगातार वृद्धि में योगदान दिया है।

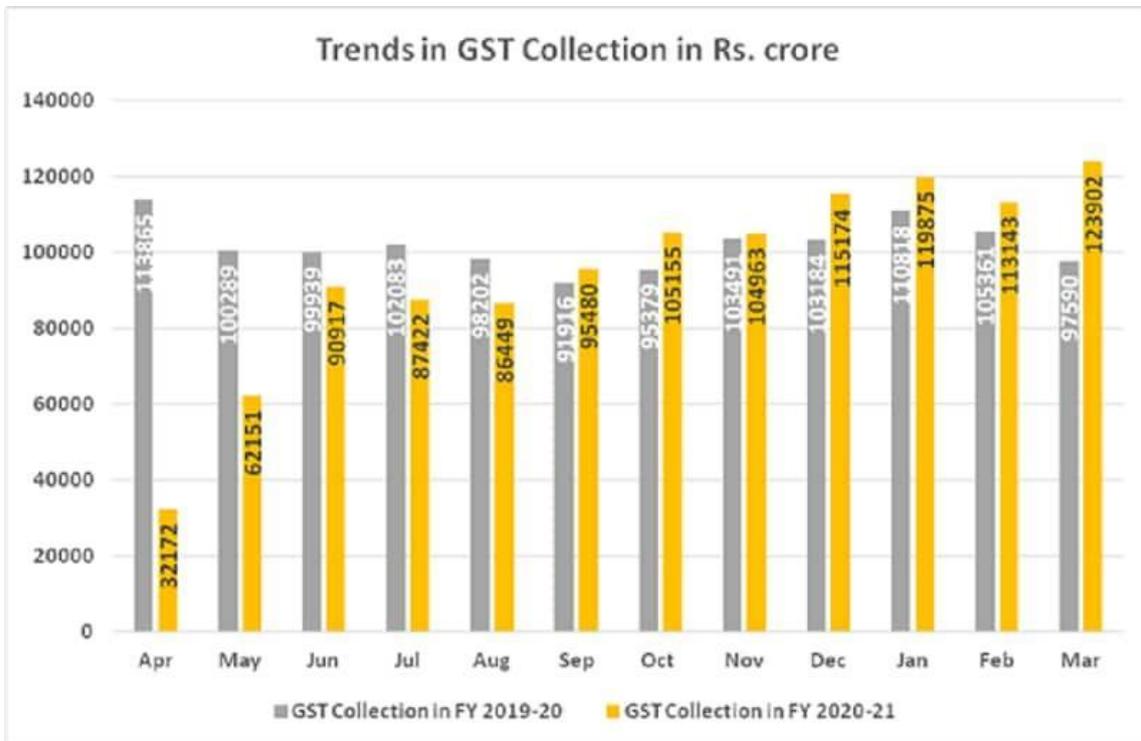


Figure 1: Composition of Central Taxes

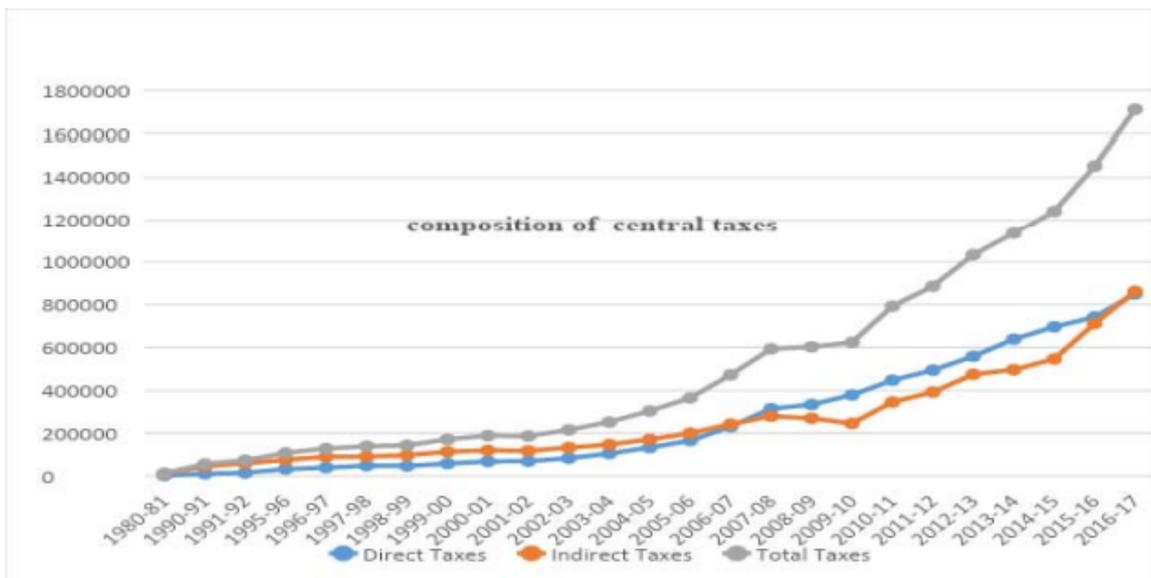
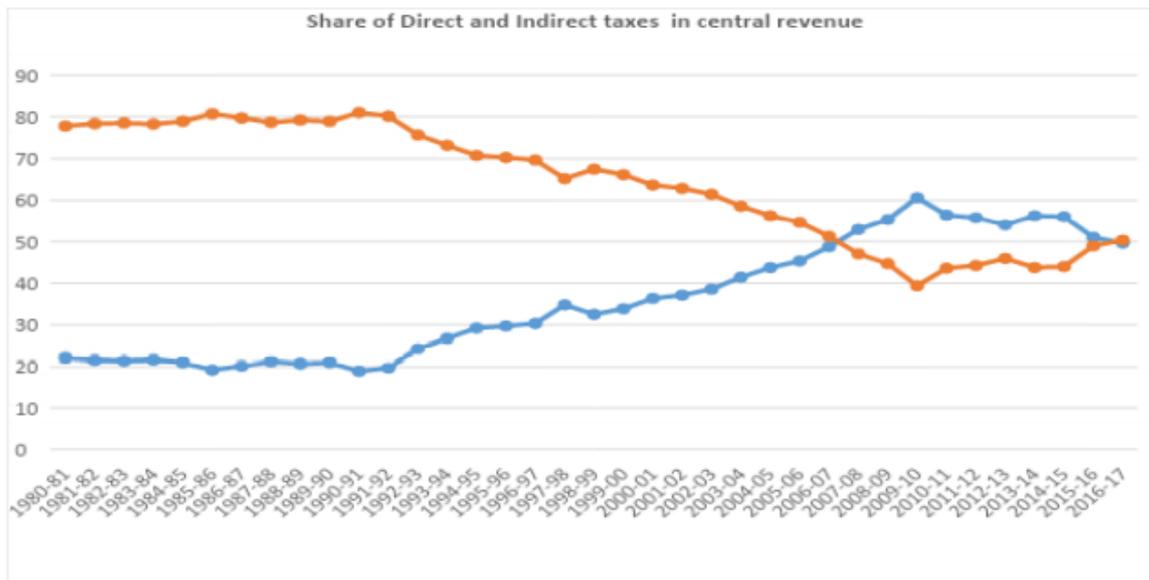


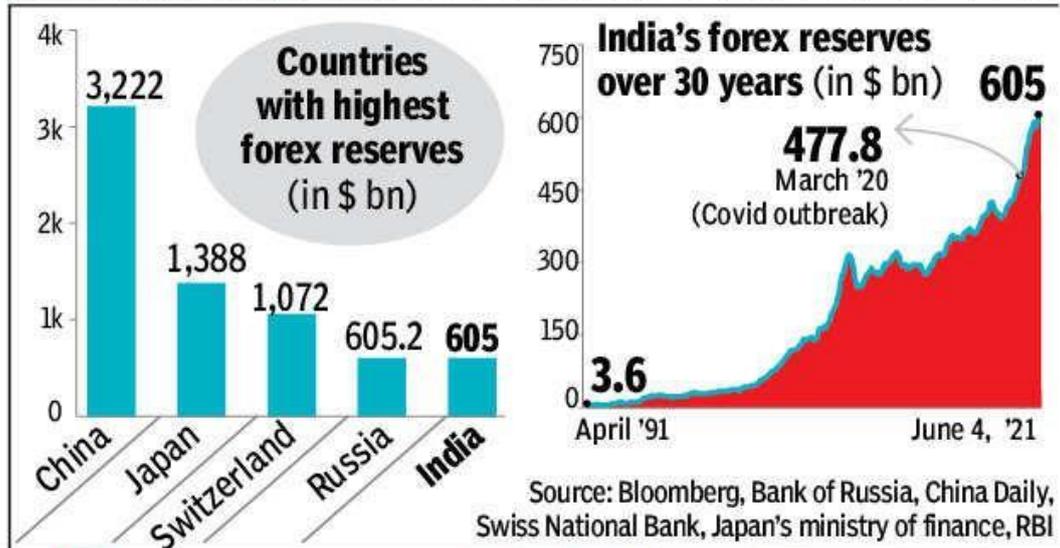
Figure 2: Trends of Direct and Indirect Taxes



590. विदेशी मुद्रा भंडार का रुझान (Trends of Forex Reserves)

- भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, 25 जून, 2021 को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा (विदेशी मुद्रा) भंडार \$ 5 बिलियन बढ़कर \$ 609 बिलियन हो गया।

AMONG THE TOP 30 YRS AFTER ECO CRISIS



विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में

- विदेशी मुद्रा भंडार एक केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्राओं में आरक्षित संपत्ति है, जिसमें बांड, ट्रेजरी बिल और अन्य सरकारी प्रतिभूतियां शामिल हो सकती हैं।
- भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल हैं:
 - विदेशी मुद्रा संपत्ति
 - सोने का भंडार
 - विशेष आहरण अधिकार
 - अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के साथ रिजर्व स्थिति

- इन भंडार का उपयोग देनदारियों को वापस करने, आरबीआई बाजार के हस्तक्षेप के माध्यम से विनिमय दर को प्रभावित करने और मौद्रिक नीति को प्रभावित करने के लिए किया जाता है।

Foreign Exchange Reserves				
Item	As on July 30, 2021		Week	
	₹ Cr.	US\$ Mn.	₹ Cr.	US\$ Mn.
	1	2	3	4
1 Total Reserves	4617303	620576	67930	9427
1.1 Foreign Currency Assets	4287317	576224	61905	8596
1.2 Gold	280086	37644	5522	760
1.3 SDRs	11545	1552	39	6
1.4 Reserve Position in the IMF	38355	5156	464	65

* Difference, if any, is due to rounding off





IASBABA'S

**RAPID REVISION (RaRe)
SERIES - UPSC 2021**

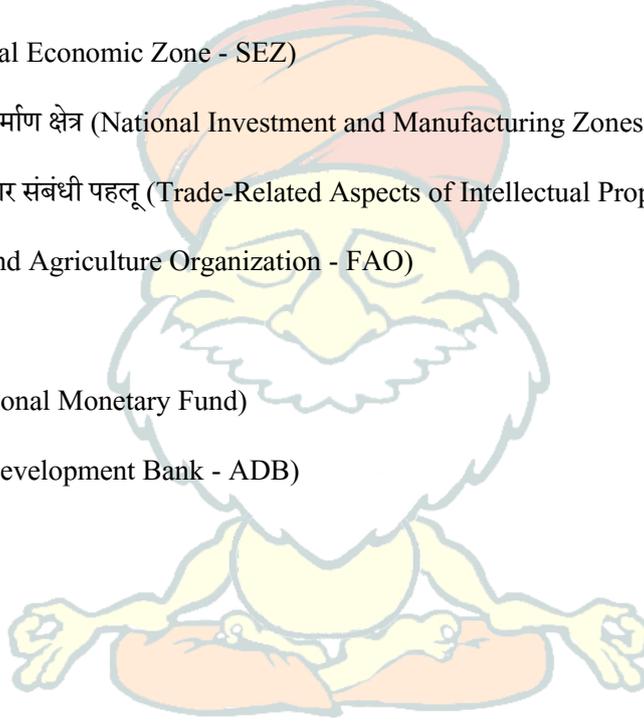
RaRe Notes Hindi

DAY 94 - ECONOMY

#RaRebaba
www.rrs.iasbaba.com

विषय

671. बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs)
672. बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs)
673. ई-रूपी (E-RUPI)
674. स्पेशल इकॉनामिक जोन (Special Economic Zone - SEZ)
675. भारत में राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र (National Investment and Manufacturing Zones - NIMZ)
676. बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलू (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)
677. खाद्य एवं कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization - FAO)
678. विश्व बैंक (World Bank)
679. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund)
680. एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank - ADB)



671. और 672. बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs)

Q.1) बजट के साथ-साथ वित्त मंत्री अन्य दस्तावेज भी संसद के समक्ष रखते हैं जिनमें "द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट" शामिल है।

उपरोक्त दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है क्योंकि यह किसके द्वारा अनिवार्य है

- लंबे समय से चली आ रही संसदीय परंपरा
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 और अनुच्छेद 110 (1)
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 113
- राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 के प्रावधान

Answer: (d)

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) 2003 में एक अधिनियम बन गया। अधिनियम का उद्देश्य राजकोषीय प्रबंधन में अंतर-पीढ़ीगत इक्विटी, दीर्घकालिक व्यापक आर्थिक स्थिरता, राजकोषीय और मौद्रिक नीति के बीच बेहतर समन्वय और सरकार के वित्तीय संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

इसके लिए संसद के समक्ष निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रस्तुति की आवश्यकता होती है - मध्यम अवधि के व्यय रूपरेखा विवरण (MTEF), मध्यम अवधि के वित्तीय नीति वक्तव्य, राजकोषीय नीति रणनीति वक्तव्य और व्यापक आर्थिक ढांचा वक्तव्य।

Q.2) परिभाषा के अनुसार एक संवैधानिक सरकार है

- विधायिका द्वारा सरकार
- लोकप्रिय सरकार
- बहुदलीय सरकार
- सीमित सरकार

Answer: (d)

संवैधानिक सरकार को एक संविधान के अस्तित्व से परिभाषित किया जाता है—जो एक कानूनी साधन हो सकता है या केवल निश्चित मानदंडों या सिद्धांतों का एक सेट हो सकता है जिसे आम तौर पर राजनीति के मौलिक कानून के रूप में स्वीकार किया जाता है - जो प्रभावी रूप से राजनीतिक शक्ति के प्रयोग को नियंत्रित करता है।

संवैधानिकता का सार कई राज्य अंगों या कार्यालयों के बीच इसके वितरण द्वारा सत्ता का नियंत्रण इस तरह से है कि वे प्रत्येक पारस्परिक नियंत्रण के अधीन हैं और राज्य की इच्छा तैयार करने में सहयोग करने के लिए मजबूर हैं।

संक्षेप में संवैधानिक सरकार संवैधानिकता के बारे में है जो सीमित सरकार के बारे में है। कई मामलों में, संवैधानिक सरकार का उपयोग "संवैधानिक रूप से सीमित सरकार" या "सीमित सरकार" के साथ किया जाता है।

Q.3) मौलिक अधिकारों के अलावा, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (1948) के सिद्धांतों और प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है?

- प्रस्तावना
- राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत
- मौलिक कर्तव्य

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिये:

- केवल 1 और 2

- b) केवल 2
- c) केवल 1 और 3
- d) 1, 2 और 3

प्रस्तावना और DPSP स्पष्ट रूप से UDHR के समानता सिद्धांत को दर्शाते हैं।
इसके अतिरिक्त, मौलिक कर्तव्य भी यूडीएचआर सिद्धांतों को दर्शाते हैं।

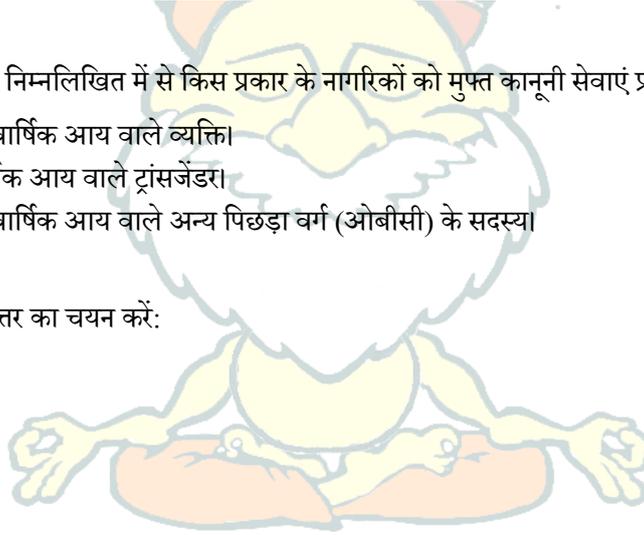
Also, though they were added later by way of amendment, the fundamental duties enshrined in the Constitution of India, contained in Part IV A, are in consonance with Article 29 (1) of the Universal Declaration of Human Rights, which says, "everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible". 'We must reaffirm faith in recognition of the inherent dignity and inalienable rights of all citizens as the foundation of freedom, justice and peace in the world, which implies obligations and responsibilities.' Human rights, thus, go hand in hand with responsibilities. It is very necessary that all citizens should be made aware of the potential of Article 51A relating to fundamental duties as a means to ensure the protection of human rights.¹⁰

Q.4) भारत में, कानूनी सेवा प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करते हैं?

1. 1,00,000 रुपये से कम की वार्षिक आय वाले व्यक्ति।
2. 2,00,000 रुपये से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर।
3. 3,00,000 रुपये से कम की वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के सदस्य।
4. सभी वरिष्ठ नागरिक

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें:

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 3 और 4
- c) केवल 2 और 3
- d) केवल 1 और 4



Answer: (a)

मुफ्त कानूनी सेवाएं प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्तियों में शामिल हैं:

- ✓ महिलाएं और बच्चे
- ✓ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य
- ✓ औद्योगिक कामगार
- ✓ सामूहिक आपदा, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप औद्योगिक आपदा के शिकार
- ✓ विकलांग व्यक्ति
- ✓ हिरासत में व्यक्ति
- ✓ ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक नहीं है



मानव तस्करी के शिकार या बेगार।

अतः कथन 1 सही है।

मुफ्त कानूनी सहायता के लिए वरिष्ठ नागरिकों की पात्रता इस संबंध में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, दिल्ली में वरिष्ठ नागरिक वार्षिक आय की निर्धारित सीमा के अधीन मुफ्त कानूनी सहायता के लिए पात्र हैं। इसलिए, सभी वरिष्ठ नागरिक मुफ्त सहायता के लिए पात्र नहीं हैं। अतः कथन 4 सही नहीं है।

एससी और एसटी समुदाय के सदस्यों को मुफ्त सहायता है लेकिन ओबीसी के लिए नहीं। अतः कथन 3 सही नहीं है।

दिल्ली में ट्रांसजेंडर्स को 2 लाख तक की मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान है। (लेकिन इसे अभी अखिल भारतीय स्तर पर लागू किया जाना बाकी है)

इसलिए, (a) दी गई सूची में सबसे उपयुक्त विकल्प प्रतीत होता है।

Q.5) निम्नलिखित जोड़ियों, अंतर्राष्ट्रीय समझौता/सेट-अप विषय पर विचार करें:

1. अल्मा-अता घोषणा - लोगों की स्वास्थ्य देखभाल
2. हेग कन्वेंशन - जैविक और रासायनिक हथियार
3. तलानोआ संवाद - वैश्विक जलवायु परिवर्तन
4. अंडर2 गठबंधन - बाल अधिकार

ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन-सा सही ढंग से सुमेलित है?

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 4
- c) केवल 1 और 3
- d) केवल 2, 3 और 4



Answer: (c)

1978 में "सभी के लिए स्वास्थ्य" पर अल्मा अता घोषणा ने प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (पीएचसी) दृष्टिकोण नामक सिद्धांतों का एक व्यापक सेट निर्धारित किया। इसने बहु-आयामी, अंतर-क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित किया, जिसे "घर के सबसे करीब" उपलब्ध कराया जाना था। यह प्रभावी और सुरक्षित होने के साथ-साथ सरल और कम लागत वाली तकनीक की आवश्यकता थी। प्राथमिक देखभाल, माध्यमिक और तृतीयक स्तरों के साथ भी पीएचसी सिद्धांतों को अपनाते हुए, इस प्रणाली के केंद्र के रूप में कल्पना की गई थी। अतः युग्म 1 सुमेलित है।

2016 में, तत्कालीन महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा था कि भारत खराब शादी से भाग रही महिलाओं के हित में अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं पर हेग कन्वेंशन की पुष्टि नहीं करेगा और पंजाब और हरियाणा की अध्यक्षता में पैनल का गठन किया था। विस्तृत रिपोर्ट के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजेश बिंदल और पैनल ने अपनी 2018 की रिपोर्ट में संधि पर हस्ताक्षर करने की सिफारिश नहीं की है। अतः युग्म 2 सही नहीं है।

जनवरी 2018 से शुरू होने वाले जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का तलानोआ डायलॉग, पार्टियों को पेरिस के बाद की प्रगति का जायजा लेने में सुविधा प्रदान करेगा। अतः युग्म 3 सही है।

अंडर 2 गठबंधन, उप-सरकारों द्वारा 2050 तक शुद्ध-शून्य की ओर अपने ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन को कम करने के लिए एक समझौता ज्ञापन, बोल्ट जलवायु नेतृत्व के लिए एक अनूठी मिसाल पैदा कर रहा है, इसके सदस्य राज्यों और क्षेत्रों की संख्या 200 से अधिक है। वर्तमान में, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ अन्य शीर्ष उत्सर्जकों के प्रतिनिधित्व की तुलना में भारत से इस समझौते के लिए हस्ताक्षरकर्ता हैं: चीन में 26 उप-राष्ट्रीय सरकारों और यू.एस. में 24 अतः जोड़ी 4 सही नहीं है।

673. ई-रूपी (E-RUPI)

खबरों में क्यों: प्रधान मंत्री ने हाल ही में अगस्त में E-RUPI लॉन्च किया।

E-RUPI के बारे में:

- E-RUPI डिजिटल भुगतान के लिए एक कैशलेस और संपर्क रहित साधन है।
- यह एक क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग-आधारित ई-वाउचर है, जो लाभार्थियों को दिया जाता है।
- इस निर्बाध वन-टाइम भुगतान तंत्र के उपयोगकर्ता सेवा प्रदाता पर कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस के बिना वाउचर को भुनाने में सक्षम होंगे।
- इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा अपने यूपीआई मंच पर वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया गया है।

e-RUPI कैसे काम करेगा?

- e-RUPI मूल रूप से एक डिजिटल वाउचर है जो एक लाभार्थी को उसके फोन पर एसएमएस या क्यूआर कोड के रूप में मिलता है। यह एक प्रीपेड वाउचर है, जिसे वह स्वीकार करने वाले किसी भी केंद्र पर जाकर रिडीम कर सकता/सकती है।
- उदाहरण के लिए, यदि सरकार किसी निर्दिष्ट अस्पताल में किसी कर्मचारी के विशेष उपचार को कवर करना चाहती है, तो वह एक भागीदार बैंक के माध्यम से निर्धारित राशि के लिए e-RUPI वाउचर जारी कर सकती है। कर्मचारी को उसके फीचर फोन/स्मार्टफोन पर एक एसएमएस या एक क्यूआर कोड प्राप्त होगा। वह निर्दिष्ट अस्पताल में जा सकता है, सेवाओं का लाभ उठा सकता है और अपने फोन पर प्राप्त e-RUPI वाउचर के माध्यम से भुगतान कर सकता है।
- e-RUPI सेवाओं के प्रायोजकों (सरकार) को लाभार्थियों (बीपीएल कार्ड धारक) और सेवा प्रदाताओं (अस्पतालों) के साथ बिना किसी भौतिक इंटरफेस के डिजिटल तरीके से जोड़ेगा।
- इस प्रकार e-RUPI एक बार का संपर्क रहित, कैशलेस वाउचर-आधारित भुगतान का तरीका है जो उपयोगकर्ताओं को कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस के बिना वाउचर को भुनाने में मदद करता है।

टीकाकरण में **e-RUPI** का अनुप्रयोग

- इसका तात्कालिक और पहला उपयोग पेड कोविड टीकाकरण केंद्रों (CVCs) में कैशलेस सेवा की सुविधा के लिए हो सकता है।
- उदाहरण के लिए, कॉरपोरेट और परोपकारी कर्मचारी और जरूरतमंद लोगों को टीका लगाने के लिए थोक में सेवाएं खरीद सकते हैं।
- इच्छुक लाभार्थियों को उनके सुविधा/स्मार्टफोन पर एक एसएमएस या क्यूआर कोड प्राप्त होगा, जिसे भाग लेने वाले केंद्रों पर कैशलेस टीकाकरण के लिए भुनाया जा सकता है।

पीडीएस आवेदन में **e-RUPI**

- कार्यक्रम की अक्षमता उच्च ओवरहेड लागत, रिसाव, बहिष्करण और अक्षमताओं में निहित है।
- खाद्य-विशिष्ट e-RUPI वाउचर से लाभार्थियों को अपनी पसंद के आउटलेट से राशन खरीदने की सुविधा मिलेगी।
- e-RUPI पीडीएस कार्यक्रम को और अधिक कुशल बना सकता है।
- वन नेशन, वन राशन कार्ड में पीडीएस नेटवर्क के भीतर और बाहर व्यापारियों द्वारा वाउचर को बाजार मूल्य पर भुनाने की क्षमता है।

674. स्पेशल इकॉनामिक जोन (Special Economic Zone - SEZ)

खबरों में क्यों: हाल ही में, विशेष आर्थिक क्षेत्रों ने निर्यात, निवेश और रोजगार में प्रदर्शन के मामले में नई ऊंचाइयों को छुआ है।

प्रमुख विशेषताएं:

- यह एक विशेष रूप से चित्रित शुल्क-मुक्त एन्क्लेव है, जिसे व्यापार संचालन और कर्तव्यों और शुल्कों के प्रयोजनों के लिए विदेशी क्षेत्र माना जाता है।
- घरेलू टैरिफ क्षेत्र (SEZ को छोड़कर पूरे भारत) से SEZ क्षेत्र में जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं को निर्यात माना जाएगा और SEZ क्षेत्र से DTA में आने वाली वस्तुओं को आयात माना जाएगा।
- इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी निवेश बढ़ाना और निर्यात के लिए परेशानी मुक्त वातावरण प्रदान करना था।
- SEZ के पास विनिर्माण इनपुट के शुल्क मुक्त आयात तक पहुंच है।
- आयात के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।
- विनिर्माण या सेवा गतिविधियों की अनुमति है।
- घरेलू बिक्री पूर्ण सीमा शुल्क और आयात नीति के अधीन है।
- SEZ इकाइयों को उप-ठेकेदारी की स्वतंत्रता होगी।
- निर्यात/आयात कार्गो के सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा कोई नियमित जांच नहीं।
- एसईजेड डेवलपर्स/सह-डेवलपर्स और इकाइयां एसईजेड अधिनियम, 2005 में निर्धारित कर लाभों का आनंद लेती हैं।

SEZ का प्रशासनिक ढांचा

- SEZ का कामकाज त्रिस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा शासित होता है।
- अनुमोदन बोर्ड सर्वोच्च निकाय है और इसके अध्यक्ष वाणिज्य विभाग के सचिव हैं।
- जोन स्तर पर अनुमोदन समिति SEZ में इकाइयों के अनुमोदन और अन्य संबंधित मुद्दों से संबंधित है।
- प्रत्येक जोन का नेतृत्व विकास आयुक्त करता है, जो अनुमोदन समिति का पदेन अध्यक्ष होता है।

SEZ का प्रदर्शन

- निर्यात में वर्ष 2005-06 में 22,840 करोड़ रुपये से वर्ष 2020-21 में 7,59,524 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।
- रुपये का निवेश 2005-06 में 4,035.51 करोड़ रूपए से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 6,17,499 करोड़ (संचयी आधार) तक और 2005-06 में 1,34,704 व्यक्तियों को प्रदान किया गया रोजगार वर्ष 2020-21 में 23,58,136 व्यक्तियों (संचयी आधार) तक बढ़ गया है।

675. भारत में राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र (National Investment and Manufacturing Zones - NIMZ)

- राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र (NIMZ) राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, 2011 के महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक हैं।
- विश्व स्तर की विनिर्माण गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र के साथ विकसित भूमि के बड़े क्षेत्रों के रूप में एनआईएमजेड की परिकल्पना की गई है।

- NIMZ को विश्व स्तरीय विनिर्माण गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए अपेक्षित पारिस्थितिकी प्रणाली के साथ विकसित भूमि के बड़े क्षेत्रों के रूप में परिकल्पित किया गया है।
- विशेष आर्थिक क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना है, जबकि NIMZ राज्यों के साथ साझेदारी में औद्योगिक विकास के सिद्धांत पर आधारित है और विनिर्माण विकास और रोजगार सृजन पर केंद्रित है।
 - NIMZ आकार, बुनियादी ढांचे की योजना के स्तर, नियामक प्रक्रियाओं से संबंधित शासन संरचनाओं और निकास नीतियों के मामले में SEZ से अलग हैं।
- NIMZ को एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप के रूप में परिकल्पित किया गया है:
 - अत्याधुनिक बुनियादी ढाँचा।
 - जोनिंग के आधार पर भूमि का उपयोग।
 - स्वच्छ और ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकी।
 - आवश्यक सामाजिक आधारभूत संरचना।
 - कौशल विकास सुविधाएं आदि।
- NIMZ के बारे में तथ्य:
 - NIMZ को कम से कम 5000 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र के साथ प्रस्तावित किया जा सकता है।
 - यदि आवश्यक हो तो भूमि अधिग्रहण सहित NIMZ के विकास के लिए उपयुक्त भूमि के चयन के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। भूमि का गठन हो सकता है:
- सरकारी स्वामित्व वाली भूमि;
 - राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित की जाने वाली प्रस्तावित NIMZ के भीतर पड़ने वाली निजी भूमि;
 - सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों/संपदाओं/बीमार और निष्क्रिय इकाइयों के अंतर्गत भूमि।
- NIMZ का प्रबंधन एक विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ, पर्यावरण के उन लोगों सहित करेंगे।
- भूमि की पहचान के बाद यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वह संभावित NIMZ के लिए पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन करवाए। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के परामर्श से DIPP अध्ययन करने के लिए नामित एजेंसियों को सूचित करेगा।
- NIMZ के लिए प्रस्तावित कुल भूमि क्षेत्र का कम से कम 30% विनिर्माण इकाइयों के स्थान के लिए उपयोग किया जाएगा। राज्य MSME के लिए एक क्षेत्र में उपयुक्त भूमि का एक निश्चित प्रतिशत आरक्षित कर सकते हैं।
- राज्य सरकार अधिग्रहित भूमि के मालिकों के लिए पुनर्वास और पुनर्मुधार पैकेज की लागत वहन करेगी, यदि कोई हो। SPV के सहयोग से लागत वसूली की व्यवस्था की जा सकती है।
- NIMZ को स्वशासी स्वायत्त निकायों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए, उन्हें राज्य सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243Q(c) के तहत औद्योगिक टाउनशिप के रूप में घोषित किया जाएगा।

केंद्र सरकार की भूमिका

- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग NIMZ से संबंधित मामलों में केंद्र सरकार के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।
- प्रत्येक NIMZ को DIPP द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

- NIMZ के लिए मास्टर प्लानिंग का खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी;
- केंद्र सरकार समयबद्ध तरीके से रेल, सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग), बंदरगाहों, हवाई अड्डों और दूरसंचार सहित NIMZ को बाहरी भौतिक बुनियादी ढांचे के संपर्क में सुधार/प्रदान करेगी।
- केंद्र सरकार अपने संस्थानों और योजनाओं के माध्यम से NIMZ के भीतर नवाचार और कौशल विकास को प्रोत्साहित करते हुए उत्पादकता, गुणवत्ता (परीक्षण सुविधाएं आदि) और डिजाइन क्षमताओं के लिए संस्थागत बुनियादी ढांचा प्रदान करेगी;
- केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार के साथ, NIMZ में घरेलू और साथ ही वैश्विक निवेश को बढ़ावा देगी;

केंद्र सरकार ने 4 NIMZ की स्थापना के लिए अंतिम मंजूरी दे दी है:

- ✓ प्रकाशम जिला (आंध्र प्रदेश)
- ✓ संगारेड्डी जिला (तेलंगाना)
- ✓ कलिंगनगर, जाजपुर जिला (ओडिशा)
- ✓ रंगारेड्डी जिले (तेलंगाना) में हैदराबाद फार्मा सिटी NIMZ
- ✓ इसके अलावा, दिल्ली के साथ आठ निवेश क्षेत्र
- ✓ मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (DMIC) परियोजना को NIMZ घोषित किया गया था।

राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के बारे में:

- राष्ट्रीय विनिर्माण नीति एनएमपी विशेष रूप से राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्रों (NIMZ) के निर्माण के माध्यम से समूहों और एकीकरण को बढ़ावा देने का प्रावधान करती है।
- राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (NMP) का उद्देश्य सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी को 25% तक बढ़ाना और एक दशक में 100 मिलियन रोजगार सृजित करना है।

676. बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलू (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - TRIPS)

समाचार में क्यों: बिडेन प्रशासन ने घोषणा की कि वह COVID टीकों से संबंधित बौद्धिक संपदा सुरक्षा के "TRIPS छूट" का समर्थन करेगा।

- बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पहलू विश्व व्यापार संगठन के तहत एक समझौता है।
- यह पेटेंट से लेकर कॉपीराइट तक बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित है।
- इस पर बातचीत होने से पहले, 50 से अधिक देशों ने फार्मास्युटिकल उत्पादों पर पेटेंट संरक्षण को मान्यता नहीं दी थी।

TRIPS में शामिल हैं

- 20 वर्ष की न्यूनतम पेटेंट अवधि;
- उत्पाद पेटेंट के लिए प्रावधान;

TRIPS PLUS में शामिल हैं

- पेटेंट की अवधि को न्यूनतम बीस वर्ष से अधिक बढ़ाना।
- प्रक्रिया पेटेंट - सदाबहार के लिए उदार प्रावधान।
- अनिवार्य लाइसेंस के उपयोग को सीमित करने वाले प्रावधान प्रस्तुत करना।

- डेटा विशिष्टता - 'अनुचित व्यावसायिक उपयोग' से फार्मास्युटिकल परीक्षण डेटा की सुरक्षा।

COVID टीकों के लिए TRIPS छूट:

- TRIPS छूट विश्व व्यापार संगठन के एक प्रस्ताव को संदर्भित करती है जिसमें COVID-19 को रोकने, नियंत्रित करने या उसका इलाज करने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियों के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण को माफ करने का प्रस्ताव है।
- यह तब तक किया जाना चाहिए जब तक कि विश्व स्तर पर व्यापक टीकाकरण न हो जाए।
- और जब तक दुनिया की अधिकांश आबादी ने प्रतिरक्षा विकसित नहीं कर ली है।

छूट पर संयुक्त राज्य अमेरिका रुख:

- संयुक्त राज्य अमेरिका इस प्रस्ताव के लिए एक प्रमुख पकड़ रहा था।
- मई 2021 में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने पहले के रुख को उलट दिया और छूट के लिए समर्थन की घोषणा की।

भारत और दक्षिण अफ्रीका का रुख:

- देशों ने ट्रिप्स काउंसिल से "जितनी जल्दी हो सके" समझौते के दूसरे भाग में चार वर्गों के कार्यान्वयन, आवेदन और प्रवर्तन पर छूट की सिफारिश करने के लिए कहा था।
- ये खंड - 1, 4, 5, और 7 - कॉपीराइट, औद्योगिक डिजाइन, पेटेंट और अघोषित जानकारी के संरक्षण से संबंधित हैं।

677. खाद्य एवं कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization - FAO)

खाद्य और कृषि संगठन (FAO) संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भूख को हराने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है।

FAO के बारे में अधिक जानकारी

- कनाडा के क्यूबेक शहर में, संयुक्त राष्ट्र के पहले सत्र ने संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी के रूप में खाद्य और कृषि संगठन (FAO) की स्थापना की।
- इसका मुख्यालय रोम में है।
- 1961 का भूख से मुक्ति अभियान FAO के लिए एक मील का पत्थर है।
- उसके बाद इसने संगठन को एक तकनीकी एजेंसी से एक विकास संगठन में बदलने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
- 1963 में, एफएओ और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने समानांतर प्रस्तावों को अपनाया जिसने प्रभावित क्षेत्रों को वास्तविक समय में तत्काल खाद्य सहायता पहुंचाने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना की।
- 1979 में, FAO सम्मेलन के 20वें सत्र ने FAO की स्थापना के सम्मान में प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाने का सर्वसम्मत निर्णय लिया।

FAO का दृष्टिकोण

- समझौतों, आचार संहिता और तकनीकी मानकों को विकसित करने और लागू करने के लिए देशों के साथ काम करना।
- नीतिगत निर्णयों का समर्थन करने के लिए कृषि डेटा और जानकारी एकत्र करना, विश्लेषण करना और निगरानी करना।

- वैश्विक, क्षेत्रीय और देश के स्तर पर नीतिगत संवाद को सक्षम करना।
- अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों, विश्वविद्यालयों, सरकारों, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र सहित संस्थानों की एक विस्तृत शृंखला के साथ साझेदारी में काम करना।
- अपने कृषि विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए देशों की क्षमता का निर्माण करना।
- आंतरिक रूप से और भागीदारों के साथ ज्ञान प्राप्त करना और साझा करना।
- काम के बारे में संवाद।

की गई पहल:

- एफएओ खाद्य मूल्य सूचकांक (FFPI) खाद्य वस्तुओं की एक टोकरी की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में मासिक परिवर्तन का एक उपाय है।
 - यह अनाज, तिलहन, डेयरी उत्पाद, मांस और चीनी की एक टोकरी के लिए परिवर्तनों को मापता है। आधार अवधि: 2014-16
- विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली (GIAHS)
- दुनिया भर में डेजर्ट टिड्डी की स्थिति पर नज़र रखता है।
- कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन या CAC संयुक्त एफएओ/डब्ल्यूएचओ खाद्य मानक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में सभी मामलों के लिए जिम्मेदार निकाय है।
- खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतरराष्ट्रीय संधि को 2001 में खाद्य और कृषि संगठन के सम्मेलन के इकतीसवें सत्र द्वारा अपनाया गया था।

प्रमुख प्रकाशन:

- विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि राज्य (SOFIA)
- विश्व के वनों का राज्य (SOFO)
- विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण राज्य (SOFI)
- खाद्य और कृषि राज्य (SOFA)
- स्टेट ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटी मार्केट्स (SOCO)

678. विश्व बैंक (World Bank)

- 1944 में पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक के रूप में स्थापित।
- मूल रूप से, इसके ऋणों ने द्वितीय विश्व युद्ध से तबाह हुए देशों के पुनर्निर्माण में मदद की।
- विश्व बैंक एक सहकारिता की तरह है, जो 189 सदस्य देशों से बना है।
- इन सदस्य देशों, या शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा किया जाता है, जो विश्व बैंक में अंतिम नीति निर्माता हैं।
- आम तौर पर, राज्यपाल सदस्य देशों के वित्त मंत्री या विकास मंत्री होते हैं।
- विश्व बैंक समूह एक अद्वितीय वैश्विक साझेदारी है जिसमें पांच विकास संस्थान शामिल हैं।

मिशन:

- अत्यधिक गरीबी को समाप्त करने के लिए: 2030 तक अत्यधिक गरीबी में रहने वाली वैश्विक आबादी की हिस्सेदारी को 3 प्रतिशत तक कम करके।
- साझा समृद्धि को बढ़ावा देना: हर देश में सबसे गरीब 40 प्रतिशत लोगों की आय में वृद्धि करके।

विश्व बैंक समूह

- पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक (IBRD) ऋण, क्रेडिट और अनुदान प्रदान करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA) कम आय वाले देशों को कम या बिना ब्याज वाले ऋण प्रदान करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) कंपनियों और सरकारों को निवेश, सलाह और परिसंपत्ति प्रबंधन प्रदान करता है।
- बहुपक्षीय गारंटी एजेंसी (MIGA) युद्ध जैसे राजनीतिक जोखिम के खिलाफ उधारदाताओं और निवेशकों का बीमा करती है।
- निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (ICSID) निवेशकों और देशों के बीच निवेश-विवादों का निपटारा करता है। भारत ICSID का सदस्य नहीं है।

679. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund)

समाचार में क्यों: IMF ने 2021 के लिए भारत की विकास दर 11.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया और इस वित्तीय वर्ष में भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने का अनुमान लगाया।

IMF का इतिहास

- IMF, जिसे फंड के रूप में भी जाना जाता है, की कल्पना जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में की गई थी।
- उस सम्मेलन में 44 देशों ने प्रतिस्पर्धी अवमूल्यन की पुनरावृत्ति से बचने के लिए आर्थिक सहयोग के लिए एक रूपरेखा बनाने की मांग की, जिसने 1930 के महामंदी में योगदान दिया था।
- अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD) में सदस्यता के लिए देश तब तक पात्र नहीं थे जब तक कि वे IMF के सदस्य न हों।
- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए ब्रेटन वुड्स समझौते के अनुसार, आईएमएफ ने निश्चित विनिमय दरों पर परिवर्तनीय मुद्राओं की एक प्रणाली शुरू की, और आधिकारिक रिजर्व के लिए अमेरिकी डॉलर (सोना \$35 प्रति औंस पर) के साथ सोने को बदल दिया।
- 1971 में ब्रेटन वुड्स प्रणाली (स्थिर विनिमय दरों की प्रणाली) के ध्वस्त होने के बाद, IMF ने अस्थायी विनिमय दरों की प्रणाली को बढ़ावा दिया है। देश अपनी विनिमय व्यवस्था चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, जिसका अर्थ है कि बाजार की ताकतें एक दूसरे के सापेक्ष मुद्राओं का मूल्य निर्धारित करती हैं। यह व्यवस्था आज भी कायम है।
- IMF अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के प्रमुख संगठनों में से एक था; इसके डिजाइन ने प्रणाली को राष्ट्रीय आर्थिक संप्रभुता और मानव कल्याण के अधिकतमकरण के साथ अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवाद के पुनर्निर्माण को संतुलित करने की अनुमति दी, जिसे एम्बेडेड उदारवाद भी कहा जाता है।
- IMF ने पूर्व सोवियत ब्लॉक के देशों को केंद्रीय योजना से बाजार संचालित अर्थव्यवस्थाओं में संक्रमण में मदद करने में एक केंद्रीय भूमिका निभाई।
- 1997 में, थाईलैंड से लेकर इंडोनेशिया से लेकर कोरिया और उससे आगे पूर्वी एशिया में वित्तीय संकटों की लहर दौड़ गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने सबसे अधिक प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं के लिए बेलआउट (बचाव पैकेज) की एक श्रृंखला बनाई ताकि वे डिफॉल्ट से बचने में सक्षम हो सकें, पैकेजों को मुद्रा, बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली सुधारों से जोड़ सकें।

- वैश्विक आर्थिक संकट (2008): अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अधिक वैश्वीकृत और परस्पर विश्व के प्रति प्रतिक्रिया के लिए निगरानी को मजबूत करने के लिए प्रमुख पहल की। इन पहलों में शामिल थे
 - फैल-ओवर को कवर करने के लिए निगरानी के लिए कानूनी ढांचे में सुधार करना (जब एक देश में आर्थिक नीतियां दूसरों को प्रभावित कर सकती हैं),
 - जोखिम और वित्तीय प्रणालियों का गहन विश्लेषण,
 - सदस्यों की बाहरी स्थिति के आकलन में तेजी लाना,
 - सदस्यों की चिंताओं का अधिक तत्परता से जवाब देना।

शासन

- बोर्ड ऑफ गवर्नर्स: इसमें प्रत्येक सदस्य देश के लिए एक गवर्नर और एक वैकल्पिक गवर्नर होता है। प्रत्येक सदस्य देश अपने दो राज्यपालों की नियुक्ति करता है।
 - यह कार्यकारी बोर्ड के कार्यकारी निदेशकों को चुनने या नियुक्त करने के लिए जिम्मेदार है।
 - कोटा बढ़ाने की स्वीकृति, विशेष आहरण अधिकार आवंटन,
 - नए सदस्यों का प्रवेश, सदस्य की अनिवार्य वापसी,
 - समझौते और उप-कानूनों के लेखों में संशोधन।
 - बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को दो मंत्रिस्तरीय समितियों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति (IMFC) और विकास समिति द्वारा सलाह दी जाती है।
 - IMF और विश्व बैंक समूह के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आम तौर पर साल में एक बार, IMF-विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों के दौरान, अपने संबंधित संस्थानों के काम पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं।
- कार्यकारी बोर्ड: यह 24 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड है जिसे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा चुना जाता है।
 - यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दैनिक व्यवसाय का संचालन करता है और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा इसे सौंपी गई शक्तियों और समझौते के लेखों द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करता है।
 - यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए प्रासंगिक नीतिगत मुद्दों के लिए सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं की आईएमएफ कर्मचारियों की वार्षिक स्वास्थ्य जांच से फंड के काम के सभी पहलुओं पर चर्चा करता है।
- IMF सदस्य: कोई भी अन्य राज्य, चाहे संयुक्त राष्ट्र का सदस्य हो या न हो, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा निर्धारित समझौते और शर्तों के IMF लेखों के अनुसार IMF का सदस्य बन सकता है।
 - कोटा सदस्यता का भुगतान करें: IMF में शामिल होने पर, प्रत्येक सदस्य देश एक निश्चित राशि का योगदान देता है, जिसे कोटा सदस्यता कहा जाता है, जो देश के धन और आर्थिक प्रदर्शन (कोटा फॉर्मूला) पर आधारित होता है।
 - यह सकल घरेलू उत्पाद का भारित औसत है (50 प्रतिशत का भार)
 - खुलापन (30 प्रतिशत),
 - आर्थिक परिवर्तनशीलता (15 प्रतिशत),
 - अंतर्राष्ट्रीय भंडार (5 प्रतिशत)।
 - सदस्य देश के सकल घरेलू उत्पाद को बाजार विनिमय दरों (60 प्रतिशत का भार) और पीपीपी विनिमय दरों (40 प्रतिशत) के आधार पर जीडीपी के मिश्रण के माध्यम से मापा जाता है।

IMF के कार्य:

- नियामक कार्य: IMF एक नियामक निकाय के रूप में कार्य करता है और यह विनिमय दर नीतियों के लिए आचार संहिता और चालू खाता लेनदेन के लिए भुगतान पर प्रतिबंध लगाने पर भी ध्यान केंद्रित करता है।

- वित्तीय कार्य: IMF सदस्य देशों को अल्पकालिक और मध्यम अवधि के भुगतान संतुलन (BoP) को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता और संसाधन प्रदान करता है।
- परामर्शी कार्य: IMF सदस्य देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का केंद्र है। यह वकील और तकनीकी सहायता के स्रोत के रूप में भी कार्य करता है।

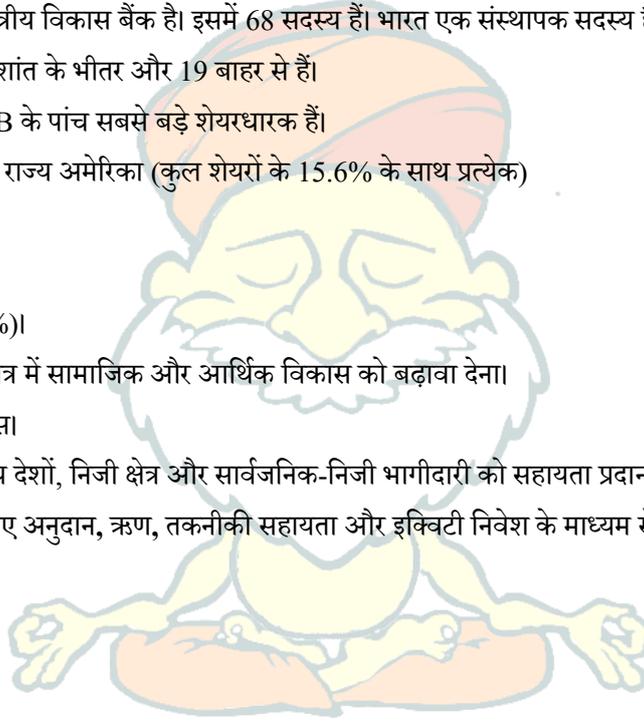
680. एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank - ADB)

समाचार में क्यों: रिपोर्ट एशियन डेवलपमेंट आउटलुक (ADO) 2021 के अनुसार, कोविड -19 की दूसरी लहर भारत की आर्थिक सुधार को "जोखिम" में डाल सकती है।

- ADO एशियाई विकास बैंक (ADB) के विकासशील सदस्य देशों (DMC) पर वार्षिक आर्थिक रिपोर्टों की एक श्रृंखला है।

ADB के बारे में

- यह 1966 में स्थापित एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसमें 68 सदस्य हैं। भारत एक संस्थापक सदस्य है।
 - 49 एशिया और प्रशांत के भीतर और 19 बाहर से हैं।
- 31 दिसंबर 2019 तक, ADB के पांच सबसे बड़े शेयरधारक हैं।
 - जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका (कुल शेयरों के 15.6% के साथ प्रत्येक)
 - चीन (6.4%)
 - भारत (6.3%)
 - ऑस्ट्रेलिया (5.8%)।
- उद्देश्य: एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
- मुख्यालय: मनीला, फिलीपींस।
- यह अपने विकासशील सदस्य देशों, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक-निजी भागीदारी को सहायता प्रदान करता है।
- विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुदान, ऋण, तकनीकी सहायता और इक्विटी निवेश के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है।





IASBABA'S

**RAPID REVISION (RaRe)
SERIES - UPSC 2021**

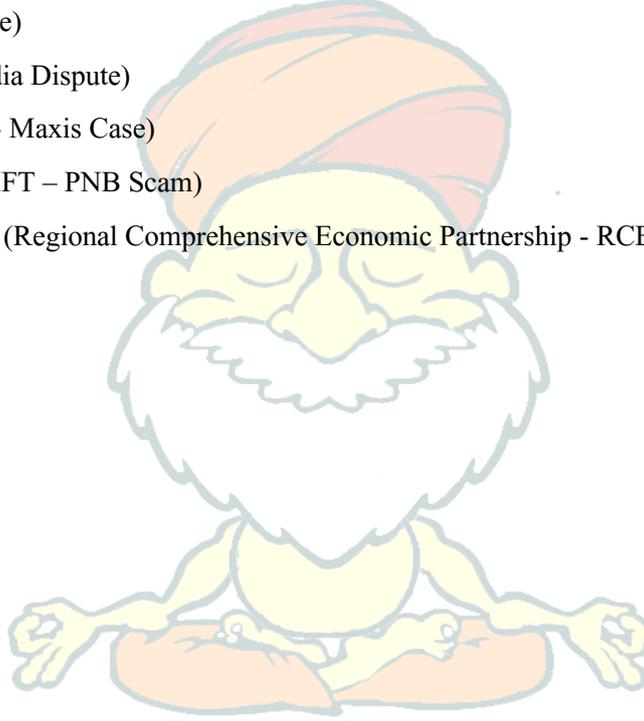
RaRe Notes Hindi

DAY 95 - ECONOMY

#RaRebaba
www.rrs.iasbaba.com

विषय

681. बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs)
682. बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs)
683. न्यू डेवलपमेंट बैंक (New Development Bank- NDB)
684. एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB)
685. वोडाफोन केस (Vodafone case)
686. केयर्न इंडिया विवाद (Cairn India Dispute)
687. एयरसेल- मैक्सिस केस (Aircel- Maxis Case)
688. स्विफ्ट - पीएनबी घोटाला (SWIFT – PNB Scam)
689. क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (Regional Comprehensive Economic Partnership - RCEP)
690. बेसल मानदंड (Basel Norms)



681. और 682. बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs)

Q.1) भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

1. औरंग-प्रदेश के कोषागार प्रभारी
2. बनियन (Banian) - ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट
3. मिरासीदार - राज्य को नामित राजस्व दाता

ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन-सा सही सुमेलित है?

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2 और 3
- c) केवल 3
- d) 1, 2 और 3

Answer: (b)

कथन 1 - औरंग एक गोदाम के लिए एक फारसी शब्द है - एक ऐसा स्थान जहाँ माल बेचने से पहले एकत्र किया जाता है। यह शब्द तैयार माल के लिए एक कार्यशाला को भी संदर्भित करता है।

कथन 2 - बनियन (Banian) ने व्यक्तिगत ईआईसी प्रबंधकों के लिए एक एजेंट के रूप में काम किया, और बहीखाता पद्धति, व्याख्या और दलाली सहित कई कार्यों का प्रदर्शन किया, साथ ही साथ अपने घरेलू और व्यक्तिगत व्यावसायिक गतिविधियों का प्रबंधन भी किया।

कथन 3 - थलकारी या मिरासदार ने भू-राजस्व का भुगतान किया, लेकिन अधिकारी नहीं थे और ग्राम समुदाय का एक बड़ा हिस्सा थे, और भूमि के वंशानुगत मालिक थे। मिरासदार थलकारी के लिए एक अरबी शब्द (मिरास = विरासत) है।

Q.2) भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. स्थविरवाद (Sthaviravadins) महायान बौद्ध धर्म से संबंधित हैं।
2. लोकोत्तरवाद (Lokottaravāda) संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंधिका संप्रदाय की एक शाखा थी।
3. महासंधिकों द्वारा बुद्ध की मूर्तिपूजा ने महायान बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा सही है?

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2 और 3
- c) केवल 3
- d) 1, 2 और 3

Solution (b)

कथन 1 गलत है - स्थविरवाद (Sthaviravadins) थेरवाद से संबंधित हैं। यह बौद्ध धर्म का एक प्रारंभिक विद्यालय है। बौद्ध धर्म प्रमुख रूप से महायान और हीनयान संप्रदायों में विभाजित है। हीनयान, जिसे थेरवादिन भी कहा जाता है, प्राचीन भारतीय बौद्ध धर्म के पाली सिद्धांत को आधिकारिक के रूप में स्वीकार करते हैं और अपने सांप्रदायिक वंश को वापस बड़ों (संस्कृत: स्थविरस; पाली: थेरस) में खोजते हैं, जिन्होंने पहले बौद्ध संघ, या समुदाय के वरिष्ठ भिक्षुओं की परंपरा का पालन किया था। इस प्रकार थेरवाद को स्थविरवाद (Sthaviravad) भी कहा जाता है।

कथन 2 सही है-महापुरुषों ने बुद्ध की बहुलता में विश्वास किया, जो सुपरमुंडेन (लोकोत्तरा) हैं और मानते हैं कि गौतम बुद्ध के लिए उनके सांसारिक अस्तित्व में जो पारित हुआ वह केवल एक स्पष्टता थी। स्कूल पहले वैशाली के क्षेत्र में स्थित था और दक्षिण भारत में भी फैला हुआ था, जिसमें

अमरावती और नागार्जुनकोंडा के केंद्र थे।

इसके ग्रंथ प्राकृत में लिखे गए थे। यह आगे कई उपखंडों में विभाजित हो गया, जिनमें से सबसे अच्छा ज्ञात लोकोत्तरवाद था (तथाकथित लोकोट्टारा पर इसके विचारों के कारण)।

कथन 3 सही है - महासंघिका, (संस्कृत महासंघ से, "भिक्षुओं का महान आदेश"), भारत में प्रारंभिक बौद्ध स्कूल, जो बुद्ध की प्रकृति के अपने विचारों में, महायान परंपरा का अग्रदूत था। (<https://www.britannica.com/topic/Mahasanghika>)

Q.3) निम्नलिखित में से कौन सा कथन उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध के दौरान भारत पर औद्योगिक क्रांति के प्रभाव की सही व्याख्या करता है?

- भारतीय हस्तशिल्प बर्बाद हो गए।
- भारतीय वस्त्र उद्योग में बड़ी संख्या में मशीनों की शुरुआत की गई।
- देश के कई हिस्सों में रेलवे लाइनें बिछाई गईं।
- ब्रिटिश विनिर्माण के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया था।

Answer: (a)

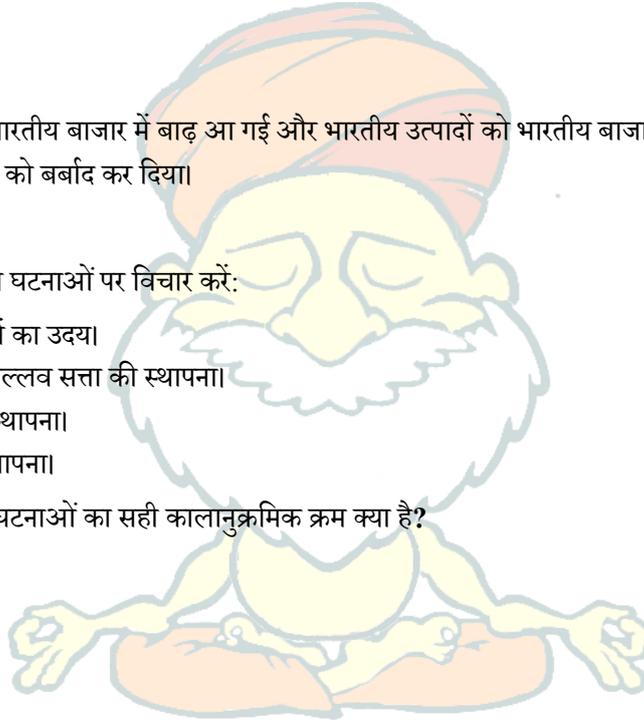
सस्ते और मशीन-निर्मित आयातों की भारतीय बाजार में बाढ़ आ गई और भारतीय उत्पादों को भारतीय बाजार में प्रवेश करना मुश्किल हो गया। इस औद्योगिक क्रांति ने भारतीय हस्तशिल्प को बर्बाद कर दिया।

Q.4) भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें:

- राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय।
- महेन्द्रवर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना।
- पुरंतक द्वारा चोल शक्ति की स्थापना।
- गोपाल द्वारा पाल वंश की स्थापना।

प्राचीन काल से आरम्भ करके उपरोक्त घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है?

- 2-1-4-3
- 3-1-4-2
- 2-4-1-3
- 3-4-1-2



Solution (c)

व्याख्या:

- राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय – 830 ई
- महेन्द्रवर्मन के तहत पल्लव शक्ति की स्थापना – 600 ई
- चोल परान्तक की स्थापना – I – 910 ई
- पाल वंश गोपाल द्वारा स्थापित - 750 ई

Q.5) निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश हुंडी की प्रकृति को परिभाषित करता है जिसे आमतौर पर वर्ष काल के बाद के स्रोतों में संदर्भित किया जाता है?

- राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को जारी एक सलाह
- दैनिक खातों के लिए रखी जाने वाली एक डायरी
- विनिमय बिल
- सामंती स्वामी से अपने अधीनस्थों के लिए एक आदेश

Solution (c)

व्याख्या:

हुंडी साधन या विनिमय बिल का एक अनौपचारिक तरीका है; इस प्रकार कानूनी प्रणाली में इसका कोई स्थान नहीं है और परक्राम्य लिखत अधिनियम उन्हें विनियमित या कवर नहीं करता है। वे विनिमय के बिल हैं और उनका उपयोग इस तरह से किया जाता था कि आज आम बोलचाल में चेक का उपयोग किया जाता है।

संदर्भ:

https://www.rbi.org.in/scripts/ms_hundies.aspx

683. न्यू डेवलपमेंट बैंक (New Development Bank- NDB)

- इसकी स्थापना ब्रिक्स देशों ने की थी।
- NDB का उद्देश्य ब्रिक्स देशों और अन्य विकासशील देशों और उभरते बाजारों में सतत विकास परियोजनाओं को वित्तपोषित करना है।
- NDB को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूरक के रूप में पेश किया जाता है, न कि उनके लिए एक चुनौती के रूप में।
- NDB के पीछे का विचार भारत द्वारा 2012 में नई दिल्ली में चौथे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रखा गया था।
- गठन संधि पर 2014 में ब्राजील के फोर्टालेजा में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए थे।
- 2018 में, NDB ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में 'पर्यवेक्षक' का दर्जा हासिल किया।
- इसका मुख्यालय शंघाई, चीन में है। भारत को छोड़कर अन्य सभी सदस्य देशों में क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

NDB शासन

- NDB का संचालन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा किया जाता है।
- बोर्ड में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्री शामिल हैं।
- मतदान शक्ति NDB में प्रत्येक सदस्य की हिस्सेदारी पर आधारित है।
- वर्तमान में, सभी सदस्यों को समान मतदान अधिकार है।
- बैंक की सदस्यता संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों के लिए खुली है लेकिन ब्रिक्स देशों की हिस्सेदारी कभी भी मतदान शक्ति के 55% से कम नहीं हो सकती है।
- NDB के अध्यक्ष सदस्य देशों में से चुने जाते हैं।
- बाकी सदस्यों में से चार उपाध्यक्ष हैं।
- NDB के पहले अध्यक्ष भारत के केवी कामथ थे। दूसरे और वर्तमान राष्ट्रपति ब्राजील के मार्कोस प्राडो ट्रायजो (2020 से) हैं।
- भारत 2021 के लिए ब्रिक्स समूह का अध्यक्ष है।

684. एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (Asian Infrastructure Investment Bank - AIIB)

- AIIB ने एआईआईबी आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट की शर्तों के तहत 2016 में परिचालन शुरू किया था।
- इसका मुख्यालय बीजिंग में है।
- यह एक विकास बैंक है जिसका मिशन एशिया में आर्थिक और सामाजिक परिणामों में सुधार करना है।
- यह स्थायी बुनियादी ढांचे और विकासात्मक परियोजनाओं में निवेश पर केंद्रित है।

एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का गवर्नेंस

- AIIB में सदस्यता विश्व बैंक या एशियाई विकास बैंक के सभी सदस्यों के लिए खुली है और इसे क्षेत्रीय और गैर-क्षेत्रीय सदस्यों में विभाजित किया गया है।
 - क्षेत्रीय सदस्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा एशिया और ओशिनिया के रूप में वर्गीकृत क्षेत्रों के भीतर स्थित हैं।
- अन्य MDB (बहुपक्षीय विकास बैंक) के विपरीत, AIIB गैर-संप्रभु संस्थाओं को AIIB सदस्यता के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है, यह मानते हुए कि उनका देश एक सदस्य है।
 - इस प्रकार, संप्रभु धन निधि (जैसे चीन निवेश निगम) या सदस्य देशों के राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम संभावित रूप से बैंक में शामिल हो सकते हैं।
- बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में प्रत्येक सदस्य देश का एक गवर्नर और एक वैकल्पिक गवर्नर होता है।
- ये गवर्नर और वैकल्पिक गवर्नर निदेशक मंडल को शक्तियां और जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं।

AIIB का वित्त

- AIIB की प्रारंभिक कुल पूंजी 100 बिलियन डॉलर है।
- बैंक में चीन का सबसे बड़ा योगदानकर्ता है, जो 50 बिलियन अमरीकी डालर का योगदान देता है, जो प्रारंभिक अभिदान पूंजी का आधा है।
- भारत दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है, जिसने 8.4 बिलियन अमरीकी डालर का योगदान दिया है।

मतदान का अधिकार

- बैंक में 26.61% वोटिंग शेयरों के साथ चीन सबसे बड़ा शेयरधारक है, इसके बाद भारत (7.6%), रूस (6.01%) और जर्मनी (4.2%) हैं।
- क्षेत्रीय सदस्य बैंक में कुल मतदान शक्ति का 75% रखते हैं।
- AIIB के पास अन्य MDB (बहुपक्षीय विकास बैंक) के समान शासन संरचना है, जिसमें दो प्रमुख अंतर हैं:
 - इसमें कार्यकारी निदेशकों का एक निवासी बोर्ड नहीं है जो दिन-प्रतिदिन के आधार पर सदस्य देशों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है; तथा
 - AIIB क्षेत्रीय देशों और सबसे बड़े शेयरधारक, चीन को अधिक निर्णय लेने का अधिकार देता है।
- AIIB वित्तपोषण के प्राप्तकर्ताओं में सदस्य देश (या एजेंसियां और संस्थाएं या सदस्य क्षेत्रों में उद्यम), साथ ही एशिया-प्रशांत क्षेत्र के आर्थिक विकास से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय या क्षेत्रीय एजेंसियां शामिल हो सकती हैं।
- बैंक एशिया के बाहर उधार दे सकता है बशर्ते कि यह एशिया के साथ कनेक्टिविटी का समर्थन करता हो या यह वैश्विक सार्वजनिक भलाई के लिए हो और यह ऋण एशिया को महत्वपूर्ण रूप से लाभान्वित करता हो।
 - गैर-क्षेत्रीय ऋणों की अधिकतम सीमा 25% है।

AIIB और भारत

- भारत के पास बैंक के 7.6% शेयर हैं।
- भारत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए AIIB वित्तपोषण का सबसे बड़ा लाभार्थी है।
- भारत में परियोजनाएं बैंगलोर मेट्रो रेल सहित ऊर्जा, जल, परिवहन आदि जैसे कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं।
- बैंक ने COVID-19 इमरजेंसी रिस्पांस फंड और हेल्थ सिस्टम प्रिपेयरनेस प्रोजेक्ट के लिए \$500 मिलियन की मंजूरी भी दी है।

न्यू डेवलपमेंट बैंक	एशियाई बुनियादी ढांचे के निवेश बैंक
सदस्य: 5	सदस्य: 103
मुख्यालय: शंघाई, चीन	मुख्यालय: बीजिंग, चीन
गठित: 2014	गठित: 2006
प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है। वोट सदस्यों की हिस्सेदारी पर आधारित होते हैं।	वोट प्रत्येक सदस्य देश की अर्थव्यवस्था (पीपीपी संदर्भ में जीडीपी) के आकार पर आधारित होते हैं।
सदस्यता संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों के लिए खुली है।	सदस्यता एशियाई विकास बैंक या विश्व बैंक के सभी सदस्यों के लिए खुली है।

685. वोडाफोन केस (Vodafone case)

- ब्रिटेन स्थित वोडाफोन ने कंपनी हचिसन एस्सार का अधिग्रहण किया, जो 11 बिलियन डॉलर के विचार के लिए भारत में दूरसंचार सेवाएं प्रदान कर रही थी।
- हालांकि यह डील भारत में नहीं हुई, लेकिन वोडाफोन पर इनकम टैक्स की भारी राशि आरोपित हुई। भारत सरकार ने पहली बार वोडाफोन से पूंजीगत लाभ में 7,990 करोड़ रुपए की मांग की।
- वोडाफोन ने बॉम्बे हाईकोर्ट में डिमांड नोटिस को चुनौती दी, जिसने आयकर विभाग के पक्ष में फैसला सुनाया।
- एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद, वोडाफोन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राहत दी गई, जिसने फैसला सुनाया कि भारतीय अधिकारी कैमैन द्वीप में निष्पादित एक सौदे पर कर नहीं लगा सकते।
- यह वह फैसला था जिसके कारण 2012 में भारत के आयकर अधिनियम में बदलाव आया, जिसने इस तरह के अप्रत्यक्ष कॉर्पोरेट लेनदेन को देश के कर दायरे में ला दिया।
 - यदि एक भारतीय संपत्ति एक विदेशी कंपनी के पास थी और एक अधिग्रहणकर्ता ने इस होल्डिंग कंपनी को खरीदा था, तो इस तरह के लेनदेन को भारत में कर योग्य माना जाता है क्योंकि अंतर्निहित संपत्ति भारत में स्थित थी।
 - इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस परिवर्तन को 1962 से पूर्वव्यापी रूप से लागू किया गया था, एक ऐसा निर्णय जो स्पष्ट रूप से ऐसे अन्य सौदों के अलावा वोडाफोन लेनदेन को कर योग्य बनाने की मांग करता था।
 - इस प्रावधान की पूर्वव्यापी प्रयोज्यता को तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा। ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधान मंत्री गॉर्डन ब्राउन ने भी भारत के सामने अपने देश की चिंताओं को उठाया था।

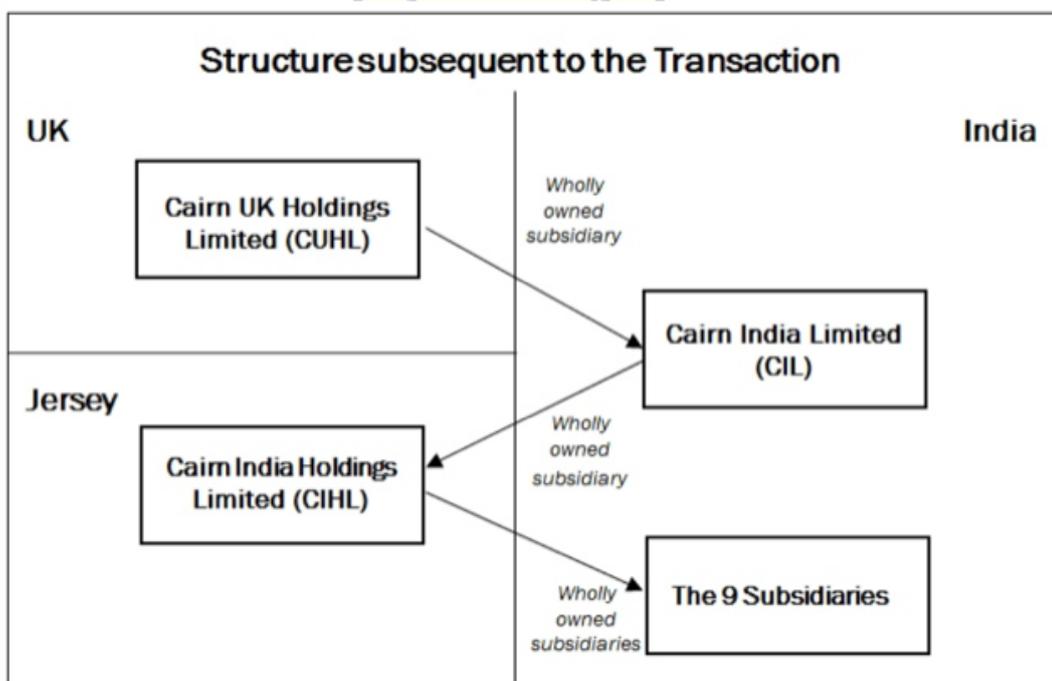
- वोडाफोन समूह ने 1995 में भारत और नीदरलैंड के बीच हस्ताक्षरित द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) के खंड 9 को लागू किया और हेग, नीदरलैंड में स्थायी मध्यस्थता अदालत (PCA) में भारत के खिलाफ मामला दायर किया।
- PCA ने वोडाफोन के पक्ष में फैसला सुनाया और भारत सरकार को वोडाफोन को 4 मिलियन पाउंड से अधिक का भुगतान करने का निर्देश दिया, जो कि कानूनी प्रतिनिधित्व और सहायता के लिए कंपनी की लागत का 60% है।
- 5 अगस्त, 2021 को इस पूर्वव्यापी कर के भूत को शांत कर दिया गया। सरकार ने 2012 के वित्त विधेयक से कपटपूर्ण प्रावधान को पूर्ववत करने के लिए कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 पेश किया।
 - 28 मई 2012 से पहले लेन-देन होने पर सरकार ऐसे किसी भी मामले में कर मांग नहीं उठाएगी। पहले से उठाई गई किसी भी मांग को वापस ले लिया जाएगा और एकत्र किए गए किसी भी कर की मूल राशि का भुगतान किया जाएगा।

686. केयर्न इंडिया विवाद (Cairn India Dispute)

समाचार में: दिसंबर 2020 में, स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (PCA) ने भारत सरकार और केयर्न एनर्जी PLC के बीच पूर्वव्यापी कर विवाद में भारत के खिलाफ फैसला सुनाया।

भारत पृष्ठभूमि के साथ केयर्न टैक्स विवाद

- 2006 (BSE में लिस्टिंग) से पहले, केयर्न एनर्जी के भारत संचालन का स्वामित्व जर्सी, यूके में शामिल केयर्न इंडिया होल्डिंग्स लिमिटेड (CIHL) नामक कंपनी के पास था।
- प्रारंभ में, भारत में केयर्न एनर्जी की संपत्ति केयर्न इंडिया होल्डिंग्स लिमिटेड के स्वामित्व में थी, जो केयर्न यूके होल्डिंग्स (CUHL) की पूरी तरह से स्वामित्व वाली सहायक कंपनी थी, जो बदले में, पूरी तरह से केयर्न एनर्जी PLC के स्वामित्व में थी।
 - केयर्न इंडिया होल्डिंग्स लिमिटेड ब्रिटेन में स्थित थी।
 - केयर्न एनर्जी PLC एक तेल और गैस कंपनी है जिसका मुख्यालय यूके में है और लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है।



- 2006 में, केयर्न इंडिया लिमिटेड (CIL) ने केयर्न यूके होल्डिंग्स (CUHL) से केयर्न इंडिया होल्डिंग्स (CIHL) की संपूर्ण शेयर पूंजी का अधिग्रहण किया। बदले में, CIL में 69 प्रतिशत शेयर केयर्न यूके होल्डिंग्स (CUHL) को जारी किए गए थे।
 - इसलिए, केयर्न एनर्जी (CPLC), केयर्न यूके होल्डिंग्स (CUHL) के माध्यम से केयर्न इंडिया लिमिटेड में 69 प्रतिशत हिस्सेदारी रखती है।
- भारतीय कर अधिकारियों के अनुसार, इस लेनदेन से केयर्न एनर्जी PLC को 24,500 करोड़ रुपये का पूंजीगत लाभ हुआ। यही वह आधार था जिस पर भारत द्वारा कर की मांग की गई थी।
- बाद में, 2011 में, केयर्न एनर्जी ने 9.8 प्रतिशत की मामूली हिस्सेदारी को छोड़कर, केयर्न इंडिया को खनन अरबपति अनिल अग्रवाल के वेदांत समूह को बेच दिया। वह बची हुई हिस्सेदारी को भी बेचना चाहती थी लेकिन आयकर विभाग ने उसे ऐसा करने से रोक दिया था। सरकार ने केयर्न इंडिया द्वारा केयर्न एनर्जी को लाभांश का भुगतान भी रोक दिया।
- 2012 में, सरकार ने वित्त विधेयक में पूर्वव्यापी कर संशोधन पेश किया और 2014 में आईटी अधिकारियों ने IPO से पहले किए गए लेनदेन में पूर्वव्यापी कर जांच शुरू की।

पूर्वव्यापी कराधान

- 2012 में, भारत ने अपने आयकर अधिनियम, 1961 में संशोधन किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत के बाहर होने वाले शेयरों के हस्तांतरण पर भी कर लगाया जा सकता है यदि शेयरों का मूल्य भारत में संपत्ति पर आधारित है। और, यह पूर्वव्यापी रूप से लागू किया गया था।

कंपनी द्वारा अपील

- ITAT ने कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाया जबकि मामला अभी भी हाईकोर्ट में लंबित है।
- फिर, कंपनी ने ब्रिटेन-भारत द्विपक्षीय निवेश संधि के तहत मध्यस्थता के स्थायी न्यायालय में मध्यस्थता की कार्यवाही शुरू की।

केयर्न की दलीलें

- जब तक पूर्वव्यापी रूप से कर में संशोधन नहीं किया गया था, तब तक अप्रत्यक्ष हस्तांतरण पर कोई कर नहीं लगाया गया था, अर्थात्, गैर-भारतीय कंपनियों में एक अनिवासी द्वारा शेयरों का हस्तांतरण, जो अप्रत्यक्ष रूप से भारत में संपत्ति का स्वामित्व रखते थे।
- उन्होंने कहा कि इस कराधान ने यूके-भारत द्विपक्षीय निवेश संधि का उल्लंघन किया है।

भारतीय पक्ष

- भारत ने तर्क दिया कि "भारतीय कानून ने लंबे समय से कराधान की अनुमति दी है जहां लेनदेन का भारत के साथ एक मजबूत आर्थिक गठजोड़ है"।

PCA का फैसला

- भारत ने ब्रिटेन-भारत द्विपक्षीय निवेश संधि का उल्लंघन किया था।
- इसके तहत भारत सरकार को केयर्न को लगभग 1.2 बिलियन डॉलर (लगभग 10000 करोड़ रुपये) का मुआवजा देने का आदेश दिया गया।

687. एयरसेल- मैक्सिस केस (Aircel- Maxis Case)

- एयरसेल एक भारतीय नेटवर्क ऑपरेटर है, जबकि मैक्सिस बरहाद मलेशियाई संचार सेवा प्रदाता है।
- 2006 में मैक्सिस ने 74 फीसदी हिस्सेदारी खरीदकर एयरसेल का अधिग्रहण कर लिया था।

- साल 2011 में जब एयरसेल के मालिक सी शिवसंकरन ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन पर मैक्सिस को अपनी हिस्सेदारी बेचने का दबाव बनाया गया था।
- शिव संकरन ने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री दयानिधि मारन और उनके उद्योगपति भाई कलानिधि को सन टीवी नेटवर्क में मैक्सिस समूह के निवेश (एस्ट्रो नेटवर्क के माध्यम से) के रूप में रिश्वत मिली, जिसका स्वामित्व दयानिधि मारन परिवार के पास है।
- 10 अक्टूबर को सीबीआई ने केस दर्ज किया। अगले साल, प्रवर्तन निदेशालय ने मारन भाइयों के खिलाफ कथित तौर पर एयरसेल-मैक्सिस सौदे में लगभग 5.5 अरब रुपये का अवैध मुआवजा प्राप्त करने के लिए मनी-लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया।

चिदंबरम की भूमिका:

- बीजेपी नेता और एडवोकेट सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया था कि पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम द्वारा नियंत्रित एक कंपनी को 2006 में एयरसेल में 5 फीसदी हिस्सेदारी मिली थी, जिसके बदले मैक्सिस को 40 अरब रुपये में एयरसेल के 74 फीसदी शेयर देने थे।
- स्वामी के अनुसार, चिदंबरम ने सौदे की विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) की मंजूरी को तब तक रोक दिया जब तक कि उनके बेटे को शिवसंकरन की कंपनी में पांच प्रतिशत हिस्सा नहीं मिल गया।

688. सोसायटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - SWIFT)

संदर्भ: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) स्विफ्ट के संभावित दुरुपयोग पर उधारदाताओं को चेतावनी देता रहा है; इसने लापरवाही के लिए 36 बैंकों पर जुर्माना लगाया है।

SWIFT:

- स्विफ्ट वैश्विक संदेश सेवा सॉफ्टवेयर है और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है।
- यह वित्तीय संस्थाओं को एक सुरक्षित, मानकीकृत और विश्वसनीय वातावरण में वित्तीय लेनदेन के बारे में संदेश भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देता है।
- इसकी मुख्य भूमिका एक सुरक्षित ट्रांसमिशन चैनल प्रदान करना है ताकि बैंक A को पता चले कि बैंक B को उसका संदेश बैंक B को जाता है किसी और को नहीं। बैंक B, बदले में, जानता है कि बैंक A, और बैंक A के अलावा किसी ने भी संदेश को रास्ते में भेजा, पढ़ा या बदला नहीं है। वास्तव में संदेश भेजने से पहले बैंकों को निश्चित रूप से जांच करने की आवश्यकता होती है।
- यह एक वैश्विक सदस्य-स्वामित्व वाली सहकारी संस्था है।
- इसकी स्थापना 1973 में सीमा पार से भुगतान की सुविधा के लिए एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक संदेश सेवा और सामान्य मानकों को विकसित करने के लिए की गई थी।
 - स्विफ्ट से पहले, अंतरराष्ट्रीय फंड ट्रांसफर के लिए संदेश पुष्टिकरण का एकमात्र विश्वसनीय साधन टेलेक्स था। कम गति, सुरक्षा चिंताओं और एक मुफ्त संदेश प्रारूप जैसे कई मुद्दों के कारण इसे बंद कर दिया गया था।
- गोपनीयता की रक्षा के लिए संदेशों को एन्क्रिप्ट किया गया है।

- स्विफ्ट फंड ट्रांसफर की सुविधा नहीं देता है: बल्कि, यह भुगतान आदेश भेजता है, जिसे उन संवाददाता खातों द्वारा तय किया जाना चाहिए जो संस्थानों के पास एक दूसरे के पास हैं।
- स्विफ्ट न तो अपने आप में धन रखता है और न ही बाहरी ग्राहक खातों का प्रबंधन करता है।

क्या आप जानते हैं?

- पीएनबी मामले में इसकी सबसे बड़ी विफलताओं में से एक स्विफ्ट और बैंक के बैकएंड सॉफ्टवेयर के बीच की कड़ी थी।
- इसने धोखेबाजों को फंड ट्रांसफर करने के लिए स्विफ्ट नेटवर्क के माध्यम से किसी अन्य बैंक को लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग या ऋण अनुरोध का उपयोग करने की अनुमति दी।

689. क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (Regional Comprehensive Economic Partnership - RCEP)

संदर्भ: 15 देशों ने एक साथ आकर 15 नवंबर 2020 को वियतनाम द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन आसियान शिखर सम्मेलन के मौके पर क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) पर हस्ताक्षर किए।

- भले ही भारत ने चर्चा से बाहर रहने का विकल्प चुना, आरसीईपी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत के लिए वार्ता की मेज पर लौटने के लिए दरवाजा खुला रहेगा।

RCEP क्या है?

- RCEP मूल रूप से 16 देशों — आसियान के सदस्यों और उन देशों के बीच जिनके साथ बातचीत हुई उनके मुक्त व्यापार समझौते (FTA) हैं, अर्थात् ऑस्ट्रेलिया, चीन, कोरिया, जापान, न्यूजीलैंड और भारत।
- उद्देश्य: सौदे का उद्देश्य सभी 16 देशों में फैले एक "एकीकृत बाजार" का निर्माण करना है। यह इन देशों में से प्रत्येक के उत्पादों और सेवाओं के लिए इस क्षेत्र में उपलब्ध होना आसान बना देगा।
- मेगा ट्रेड डील: इसे "सबसे बड़े" क्षेत्रीय व्यापार समझौते के रूप में वर्णित किया गया था क्योंकि इसमें शामिल देश दुनिया की लगभग आधी आबादी के लिए जिम्मेदार हैं, विश्व निर्यात के एक चौथाई से अधिक का योगदान करते हैं, और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 30% बनाते हैं।
- इस सौदे को चार्ट करने के लिए बातचीत 2013 से चल रही थी, और भारत को नवंबर 2019 में सौदे से बाहर रहने के अपने फैसले तक एक हस्ताक्षरकर्ता होने की उम्मीद थी।

INDIA'S TRADE BALANCE WITH RCEP MEMBERS		
RCEP Member	2018-19	2019-20
ASEAN	-21.85	-23.82
China	-53.58	-48.65
South Korea	-12.05	-10.81
Japan	-7.91	-7.91
New Zealand	-0.25	-0.14
Australia	-9.61	-6.93

All figures in \$ billion
Source: Ministry of Commerce and Industry

भारत ने वॉकआउट क्यों किया?

- व्यापार का प्रतिकूल संतुलन: 15 RCEP देशों में से 11 के साथ भारत का व्यापार घाटा है, और कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत निर्यात बढ़ाने के लिए कई RCEP सदस्यों के साथ अपने मौजूदा द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौतों का लाभ उठाने में असमर्थ रहा है।
- चीनी सामानों की डंपिंग का डर: भारत पहले ही चीन को छोड़कर RCEP के सभी देशों के साथ FTA पर हस्ताक्षर कर चुका है। यह भारत के लिए प्रमुख चिंता का विषय है, क्योंकि RCEP पर हस्ताक्षर करने के बाद चीन से सस्ते उत्पादों की भारतीय बाजार में बाढ़ आ जाती।
- ऑटो-ट्रिगर तंत्र की गैर-स्वीकृति: आयात में आसन्न वृद्धि से निपटने के लिए, भारत एक ऑटो-ट्रिगर तंत्र की मांग कर रहा था जो भारत को ऐसे मामलों में उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाने की अनुमति देता जहां आयात एक निश्चित सीमा को पार कर जाता है। हालांकि RCEP में शामिल अन्य देश इस प्रस्ताव के खिलाफ थे।
- मूल के नियमों पर आम सहमति का अभाव: मूल के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंड हैं। भारत मूल के नियमों के "संभावित परिधि" के बारे में चिंतित था। इस सौदे में उत्पादों के मार्ग को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं थे।
- घरेलू उद्योगों की रक्षा: वार्ता के दौरान, डेयरी उद्योग ने सुरक्षा की मांग की क्योंकि इस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने पर उद्योग को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह स्टील और टेक्सटाइल सेक्टर ने भी सुरक्षा की मांग की है।
- MFN की स्थिति: भारत चाहता था कि RCEP निवेश अध्याय से मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) दायित्वों को बाहर करे, क्योंकि वह विशेष रूप से उन देशों को सौंपना नहीं चाहता था जिनके साथ सीमा विवाद हैं, जो लाभ अपने रणनीतिक सहयोगियों को दे रहे थे।
- बाजार पहुंच का मुद्दा: RCEP में चीन जैसे देशों में बाजार पहुंच के मुद्दों और भारतीय कंपनियों पर गैर-टैरिफ बाधाओं पर भी स्पष्ट आश्वासन का अभाव है।
- उपरोक्त मुद्दों को हल करने के लिए प्रतिबद्धता का अभाव: भारत वार्ता के दौरान "मौलिक मुद्दों" और चिंताओं को "लगातार" उठा रहा था और इस स्टैंड को लेने के लिए प्रेरित किया गया था क्योंकि उन्हें समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रतिबद्ध करने की समय सीमा तक हल नहीं किया गया था।
- खराब समझौते से बेहतर है कोई सौदा न होना: भारत का रुख एक नई व्यवस्था में प्रवेश करने के लाभ और लागत की "स्पष्ट आंखों की गणना" पर आधारित था, और यह कि कोई भी समझौता "बुरे समझौते" से बेहतर नहीं था।

690. बेसल मानदंड (Basel Norms)

- बेसल मानदंड या बेसल समझौते बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति द्वारा जारी किए गए अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग नियम हैं।
- बेसल मानदंड अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली को मजबूत बनाने के लक्ष्य के साथ, दुनिया भर में बैंकिंग नियमों का समन्वय करने का एक प्रयास है।
- यह बेसल कमेटी ऑफ बैंकिंग पर्यवेक्षण (BCBS) द्वारा समझौते का सेट है जो बैंकों और वित्तीय प्रणाली के लिए जोखिमों पर केंद्रित है।
 - BCBS की स्थापना 1974 में दस देशों के समूह के सेंट्रल बैंक गवर्नर्स द्वारा की गई थी।
 - समिति ने 2009 में और फिर 2014 में अपनी सदस्यता का विस्तार किया।
 - BCBS में अब 28 क्षेत्राधिकारों से 45 सदस्य हैं, जिसमें बैंकिंग विनियमन की जिम्मेदारी वाले केंद्रीय बैंक और प्राधिकरण शामिल हैं।
 - यह बैंकिंग पर्यवेक्षी मामलों पर नियमित सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करता है।

- इसका उद्देश्य प्रमुख पर्यवेक्षी मुद्दों की समझ को बढ़ाना और दुनिया भर में बैंकिंग पर्यवेक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना है।

बेसल -I

- इसकी शुरुआत 1988 में हुई थी।
- इसने लगभग पूरी तरह से क्रेडिट जोखिम पर ध्यान केंद्रित किया।
 - ऋण जोखिम एक ऋण चुकाने या संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में उधारकर्ता की विफलता के परिणामस्वरूप होने वाली हानि की संभावना है। परंपरागत रूप से, यह उस जोखिम को संदर्भित करता है जो एक ऋणदाता को बकाया मूलधन और ब्याज प्राप्त नहीं हो सकता है।
- न्यूनतम पूंजी आवश्यकता जोखिम भारत परिसंपत्तियों (RWA) के 8% पर तय की गई थी।
 - RWA का अर्थ है विभिन्न जोखिम प्रोफाइल वाली संपत्ति।
- भारत ने 1999 में बेसल-I दिशानिर्देशों को अपनाया।

बेसल-II

- 2004 में, बासेल द्वितीय दिशानिर्देश BCBS द्वारा प्रकाशित किए गए थे।
- यह गाइडलाइन तीन पैरामीटर्स पर आधारित थी, जिसे कमेटी इसे आधार मानती है।
 - पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताएं: बैंकों को जोखिम परिसंपत्तियों के 8% की न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता आवश्यकता को बनाए रखना चाहिए।
 - पर्यवेक्षी समीक्षा: इसके अनुसार, बैंकों को उन सभी तीन प्रकार के जोखिमों की निगरानी और प्रबंधन में बेहतर जोखिम प्रबंधन तकनीकों का विकास और उपयोग करने की आवश्यकता थी, जिनका सामना बैंक करता है, अर्थात् ऋण, बाजार और परिचालन जोखिम।
 - बाजार अनुशासन: यह प्रकटीकरण आवश्यकताओं में वृद्धि की जरूरत है। बैंकों को अनिवार्य रूप से केंद्रीय बैंक को अपनी कार, जोखिम जोखिम, आदि का खुलासा करने की आवश्यकता है।
- भारत और विदेशों में बेसल II मानदंडों को अभी पूरी तरह से लागू किया जाना बाकी है, हालांकि भारत इन मानदंडों का पालन करता है।

बेसल III

- 2010 में, बेसल III दिशानिर्देश जारी किए गए थे।
- ये दिशानिर्देश 2008 के वित्तीय संकट के जवाब में पेश किए गए थे।
- प्रणाली को और मजबूत करने की आवश्यकता महसूस की गई क्योंकि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बैंक कम पूंजीकृत, अधिक लीवरेज्ड थे और अल्पकालिक वित्त पोषण पर अधिक निर्भरता रखते थे।
- यह भी महसूस किया गया कि बासेल II के तहत पूंजी की मात्रा और गुणवत्ता को किसी और जोखिम को नियंत्रित करने के लिए अपर्याप्त माना गया था।
- मानदंड चार महत्वपूर्ण बैंकिंग मापदंडों पर केंद्रित हैं। पूंजी, उत्तोलन, वित्त पोषण और तरलता।
- पूंजी पर्याप्तता अनुपात 12.5% पर बनाए रखा जाना है।
 - आम इक्विटी टियर 1 जोखिम भारत परिसंपत्तियों का कम से कम 4.5% होना चाहिए (RWA)
 - टियर 1 पूंजी कम से कम 6% होनी चाहिए।
 - पूंजी संरक्षण बफर सहित दोनों स्तरों की कुल न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात 10.5% है।
 - इसके अलावा, बैंकों को 2.5% की पूंजी संरक्षण बफर बनाए रखना होगा।
 - काउंटर-चक्रीय बफर को भी 0-2.5% पर बनाए रखा जाना है।

- उत्तोलन: उत्तोलन दर कम से कम 3% होनी चाहिए। उत्तोलन दर बैंक की टियर -1 पूंजी का औसत कुल समेकित संपत्ति का अनुपात है।
 - तरलता कवरेज अनुपात (LCR) के लिए बैंकों को नकदी के बहिर्वाह से निपटने के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति का बफर रखने की आवश्यकता होगी।
- और 4: धन और तरलता
 - बेसल-III ने दो तरलता अनुपात बनाए: LCR और NSFR
 - तरलता कवरेज अनुपात (LCR) के लिए बैंकों को उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्तियों का एक बफर रखने की आवश्यकता होगी जो पर्यवेक्षकों द्वारा निर्दिष्ट एक तीव्र अल्पकालिक तनाव परिदृश्य में आने वाले नकदी बहिर्वाह से निपटने के लिए पर्याप्त हो।
 - यह "बैंक रन" जैसी स्थितियों को रोकने के लिए है। लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंकों के पास 30 दिनों के तनाव परिदृश्य के लिए पर्याप्त तरलता है यदि ऐसा होना था।
 - नेट स्टेबल फंड्स रेट (NSFR) के लिए बैंकों को अपनी बैलेंस-शीट परिसंपत्तियों और गतिविधियों के संबंध में एक स्थिर फंडिंग प्रोफाइल बनाए रखने की आवश्यकता होती है। NSFR को बैंकों को वित्त के स्थिर स्रोतों (एक वर्ष के क्षितिज पर विश्वसनीय) के साथ अपनी गतिविधियों को निधि देने की आवश्यकता है।
 - न्यूनतम NSFR आवश्यकता 100% है। इसलिए, LCR अल्पकालिक (30 दिन) लचीलापन मापता है, और NSFR मध्यम अवधि (1 वर्ष) लचीलापन मापता है।
- भारत में बेसल-III के कार्यान्वयन की समय सीमा मार्च 2019 थी। इसे मार्च 2020 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। कोरोनावायरस महामारी के आलोक में, RBI ने बेसल मानदंडों के कार्यान्वयन को और 6 महीने के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया।

क्या आप जानते हैं?

- बैंक रन तब होता है जब बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान के बड़ी संख्या में ग्राहक बैंक की सॉल्वेंसी की चिंताओं पर एक साथ अपनी जमा राशि निकालते हैं। जैसे-जैसे अधिक लोग अपने धन को वापस लेते हैं, डिफॉल्ट की संभावना बढ़ जाती है, और अधिक लोगों को अपनी जमा राशि वापस लेने के लिए प्रेरित करते हैं।



IASBABA'S

**RAPID REVISION (RaRe)
SERIES - UPSC 2021**

RaRe Notes Hindi

DAY 108 - ECONOMY

#RaRebaba

www.rrs.iasbaba.com

विषय

771. बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs)

772. बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs)

773. आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में (About economic survey)

774. अर्थव्यवस्था और कोविड-19 (Economy and Covid 19)

775. जीडीपी अनुमान (GDP estimation)

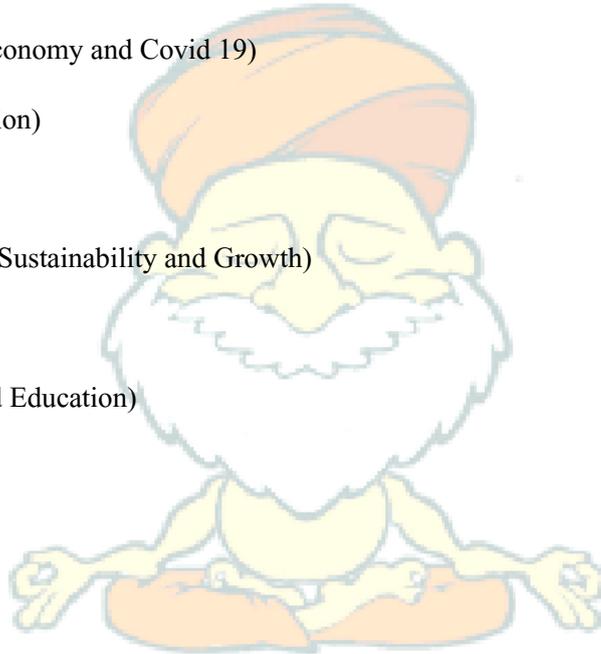
776. बाहरी क्षेत्र (External Sector)

777. ऋण स्थिरता और विकास (Debt Sustainability and Growth)

778. सेवा क्षेत्र (Service sector)

779. स्वास्थ्य और शिक्षा (Health and Education)

780. कृषि (Agriculture)



771. और 772. बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs)

Q.1) व्यापार से संबंधित निवेश उपायों (TRIMS) के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

1. विदेशी निवेशकों द्वारा आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध निषिद्ध हैं।
2. वे वस्तुओं और सेवाओं दोनों में व्यापार से संबंधित निवेश उपायों पर लागू होते हैं।
3. उनका विदेशी निवेश के नियमन से कोई सरोकार नहीं है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2
- c) केवल 1 और 3
- d) 1, 2 और 3

Solution (c)

व्याख्या:

उरुवे दौर के दौरान बातचीत की गई यह समझौता केवल उन उपायों पर लागू होता है जो माल के व्यापार को प्रभावित करते हैं। यह स्वीकार करते हुए कि कुछ निवेश उपायों में व्यापार-प्रतिबंधात्मक और विकृत प्रभाव के हो सकते हैं, इसके अनुसार कोई भी सदस्य ऐसे उपाय को लागू नहीं करेगा जो GATT अनुच्छेद III (राष्ट्रीय उपचार) या अनुच्छेद XI (मात्रात्मक प्रतिबंध) के प्रावधानों द्वारा निषिद्ध है।

Q.2) यदि आरबीआई एक विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाने का फैसला करता है, तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा?

1. वैधानिक तरलता अनुपात में कटौती और अनुकूलन
2. सीमांत स्थायी सुविधा दर में वृद्धि
3. बैंक रेट और रेपो रेट में कटौती।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2
- c) केवल 1 और 3
- d) 1, 2 और 3

Solution (b)

व्याख्या:

जब विस्तारवादी मौद्रिक नीति को लागू करना होता है, तो सरल शब्दों में इसका मतलब है कि बाजार में धन का प्रवाह बढ़ाया जाना चाहिए, इसके लिए आरबीआई कई गुणात्मक और मात्रात्मक उपाय करता है जैसे कि रेपो रेट, एस्पएलआर आदि में कमी।

संदर्भ:

<https://www.economicdiscussion.net/reserve-bank/monetary-policy-of-rbi-policy-of-credit-expansion-control-with-evaluation/31364>

<https://iasbaba.com/2020/05/rbi-new-announcement-to-boost-economy-all-india-radio-air-ias-upsc/>

Q.3) 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. शहरी क्षेत्रों में श्रमिक उत्पादकता (2004 - 05 की कीमतों पर प्रति कार्यकर्ता) में वृद्धि हुई जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी कमी हुई।
2. कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी में लगातार वृद्धि हुई।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में, गैर-कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि में वृद्धि हुई।
4. ग्रामीण रोजगार में वृद्धि दर में कमी आई है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा सही है?

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 3 और 4
- c) केवल 3
- d) 1, 2 और 4

Solution (b)

व्याख्या::

कथन 1: शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में श्रमिकों की उत्पादकता में वृद्धि हुई है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी में वृद्धि की दर अधिक थी।

कथन 2: कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिशत हिस्सा पुरुष के लिए बढ़ा लेकिन महिलाओं के लिए कम हो गया।

कथन 3: ग्रामीण क्षेत्रों में, गैर-कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई।

कथन 4: विकास दर सकारात्मक थी लेकिन 1992 के उदारीकरण के बाद विकास दर में वृद्धि हुई।

Plans	Annual GDP Growth Rate (at constant price)	Growth of Employment
I Plan (1951-56)	3.7	0.39
II Plan (1956-61)	4.2	0.85
III Plan (1961-66)	2.8	2.03
IV Plan (1969-74)	3.4	1.99
V Plan (1974-79)	5.0	1.84
VI Plan (1979-84)	5.4	1.89
VII Plan (1987-92)	5.5	1.38
VIII Plan (1992-97)	6.6	1.13
IX Plan (1997-02)	5.5	1.14
X Plan (2002-07)	7.9	0.96

Q.4) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. कृषि क्षेत्र को अल्पकालिक ऋण वितरण के संदर्भ में, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCB) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में अधिक ऋण प्रदान करते हैं।
2. DCCB के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को धन प्रदान करना है।

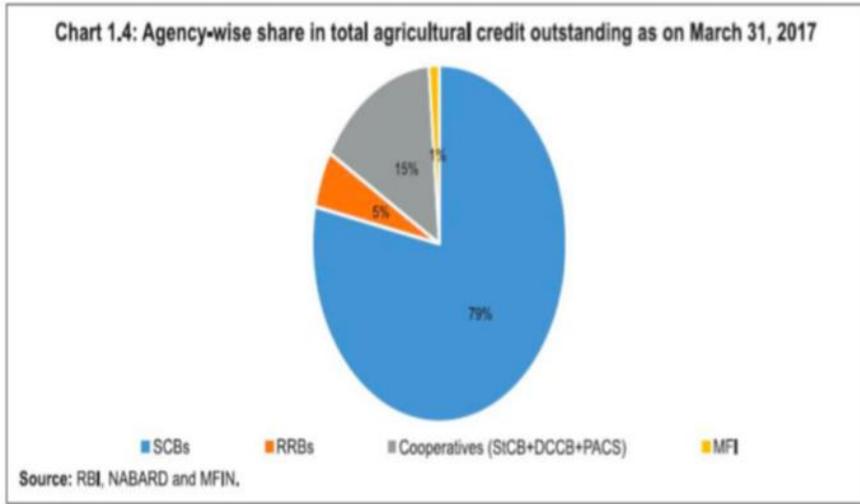
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा सही है?

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2

Solution (b)

व्याख्या:

संस्थागत स्रोतों में, कृषि ऋण के लिए, इसमें वाणिज्यिक बैंक, सहकारी ऋण संस्थान, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं। संस्थागत स्रोतों के तहत, वाणिज्यिक बैंक ने हाल ही में इस क्षेत्र में प्रवेश किया। सहकारी संस्थाएं कृषि क्षेत्र को ऋण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।



जिला केंद्रीय सहकारी बैंक सहकारी ऋण संरचना में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCB) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में मात्रात्मक रूप से अधिक ऋण प्रदान नहीं करते हैं। अतः कथन 1 सही नहीं है।

यद्यपि कथन 1 सही नहीं है, उपरोक्त पाई-चार्ट कुल कृषि ऋण का हिस्सा दर्शाता है न कि अल्पकालिक ऋण। अल्पकालिक ऋण में, अनुसूचित सहकारी बैंकों की हिस्सेदारी लगभग 60% और सहकारी बैंकों की लगभग 30% है।

जिला केंद्रीय सहकारी बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्राथमिक सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो जिले में इससे संबद्ध हैं। ये समितियाँ अत्यधिक विविध श्रेणियों जैसे प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, उत्पादकों की सहकारी समितियों, हथकरघा और हस्तशिल्प सहकारी समितियों, वेतनभोगी सहकारी समितियों, उपभोक्ता सहकारी समितियों, प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों आदि से संबंधित हैं। हालाँकि जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का समर्थन और विकास करना है। अतः कथन 2 सही है।

Q.5) भारत में, व्यक्तियों के लिए साइबर बीमा के तहत, धन की हानि और अन्य लाभों के भुगतान के अलावा, आम तौर पर निम्नलिखित में से कौन से लाभ कवर किए जाते हैं?

- किसी के कंप्यूटर तक पहुंच को बाधित करने वाले मैलवेयर के मामले में कंप्यूटर सिस्टम की बहाली की लागत।
- एक नए कंप्यूटर की कीमत अगर कुछ बदमाश जानबूझकर इसे नुकसान पहुंचाते हैं, अगर ऐसा साबित होता है।
- साइबर जबरन वसूली के मामले में नुकसान को कम करने के लिए एक विशेष सलाहकार को काम पर रखने की लागत।
- यदि कोई तीसरा पक्ष मुकदमा दायर करता है तो न्यायालय में बचाव की लागत।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा सही है?

- केवल 1, 2 और 4

- b) केवल 1, 3 और 4
- c) केवल 2 और 3
- d) 1, 2, 3 और 4

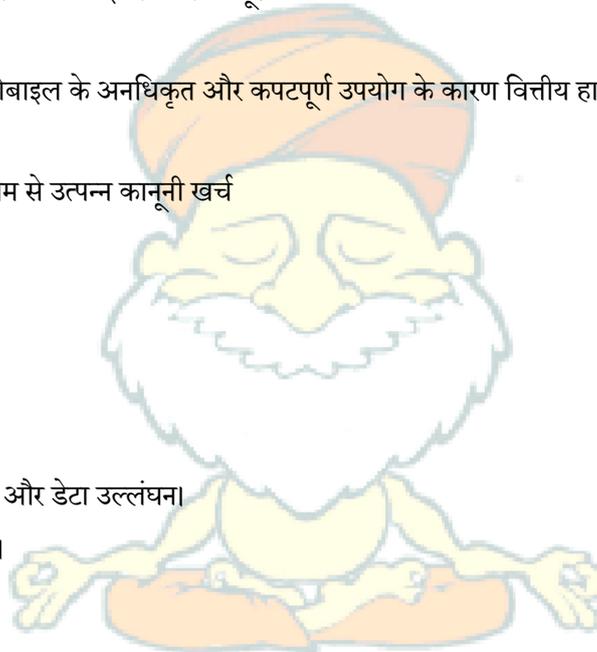
Solution (b)

व्याख्या:

साइबर बीमा को साइबर हमलों के संभावित प्रभावों से व्यवसायों की रक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है। साइबर हमले/उल्लंघन होने के बाद, यह एक संगठन को लागत को कम करके जोखिम को कम करने में मदद करता है। सरल बनाने के लिए, साइबर बीमा को साइबर उल्लंघनों से जुड़ी फीस, खर्च और कानूनी लागतों को कवर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो किसी संगठन के हैक होने के बाद या ग्राहक/कर्मचारी की जानकारी की चोरी या हानि से होते हैं। भारत में, साइबर इन्शुरन्स (आमतौर पर) निम्नलिखित को कवर करता है:

- पहचान की चोरी
- साइबर-बदमाशी और साइबर-स्टॉकिंग साइबर जबरन वसूली
- मालवेयर घुसपैठ
- बैंक खाते, क्रेडिट कार्ड और मोबाइल के अनधिकृत और कपटपूर्ण उपयोग के कारण वित्तीय हानि
- पर्स
- किसी भी कवर किए गए जोखिम से उत्पन्न कानूनी खर्च
- सोशल मीडिया कवर
- फ़िशिंग कवर
- ई-मेल स्पूफिंग
- मीडिया देयता दावा कवर
- साइबर जबरन वसूली कवर
- तीसरे पक्ष द्वारा भंग गोपनीयता और डेटा उल्लंघन।

अतः केवल विकल्प 1, 3 और 4 सही हैं।

**773. आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में (About economic survey)**

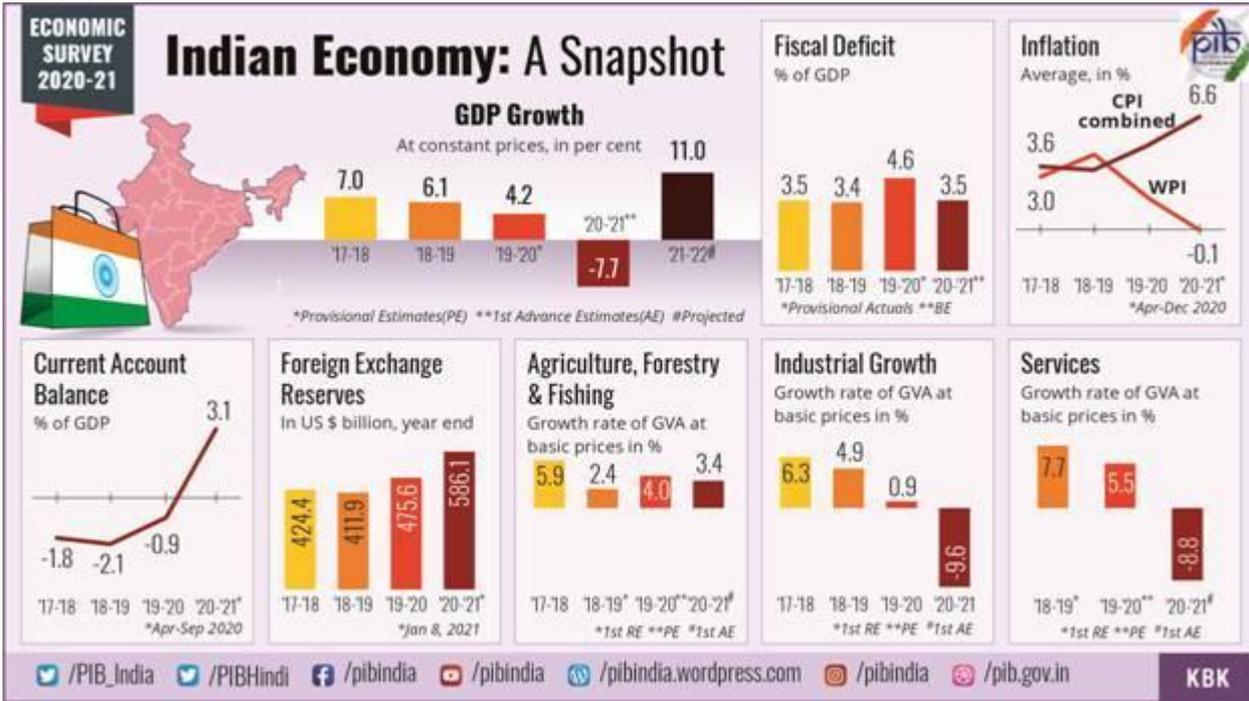
- यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक वार्षिक दस्तावेज है।
- यह सरकार में पिछले एक वर्ष में अर्थव्यवस्था की स्थिति को प्रस्तुत करता है, जो प्रमुख चुनौतियों का अनुमान लगाता है।
- आर्थिक सर्वेक्षण दस्तावेज मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) के अर्थशास्त्र विभाग द्वारा तैयार किया जाता है।
 - भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था।
 - 1964 तक, इसे केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किया गया था।
 - सर्वेक्षण को वर्ष 1964 में बजट से अलग कर दिया गया था और अग्रिम रूप से परिचालित किया गया था ताकि बजट का एक संदर्भ प्रदान किया जा सके।
 - आर्थिक सर्वेक्षण आम तौर पर वित्त मंत्री द्वारा संसद में केंद्रीय बजट पेश करने से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है।

- आर्थिक सर्वेक्षण एक सरकारी दस्तावेज और मुख्य आर्थिक सलाहकार के लिए एक उदासीन, आर्थिक उद्देश्य विश्लेषण प्रदान करने का अवसर भी है।
- आर्थिक सर्वेक्षण पेश करना सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। संविधान में इसका कहीं उल्लेख नहीं है। हालांकि, अब हर साल बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश करना सरकार के अभ्यास का हिस्सा है।
- दुनिया के अधिकांश विकसित और उभरते देश आर्थिक सर्वेक्षण निकालने की परंपरा का पालन करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्कैंडिनेवियाई राष्ट्र और यूरोपीय संघ आदि अपने स्वयं के आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित करते हैं।
- महत्व:
 - एक सुबोध तरीके से डेटा और विश्लेषण प्रदान करके नागरिकों को आर्थिक नीति बनाने के करीब लाना आर्थिक सर्वेक्षण की सेवाओं और चुनौतियों में से एक है।
 - नीतियों और आर्थिक निर्णय लेने के लोकतंत्रीकरण के लिए नागरिक जागरूकता और भागीदारी महत्वपूर्ण है। इस कारण से, मुख्य आर्थिक सलाहकार और आर्थिक प्रभाग सर्वेक्षण के प्रसार के लिए व्यापक आउटरीच का संचालन करते हैं।

774. अर्थव्यवस्था और कोविड-19 (Economy and Covid 19)

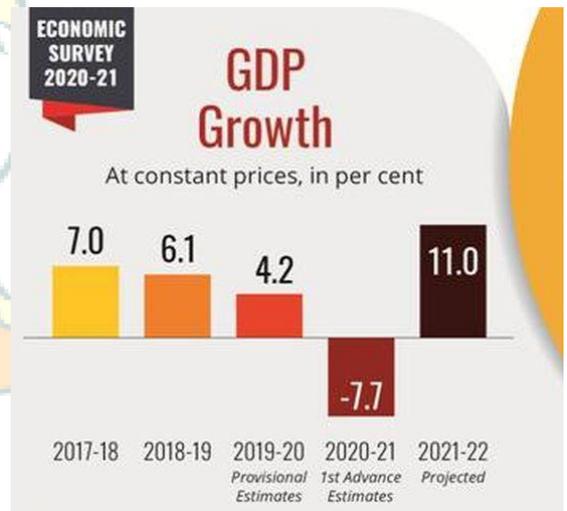
महामारी का सामना करने की रणनीति:

- प्रमुख अंतर्दृष्टि में से एक यह था कि महामारी अधिक और घनी आबादी में तेजी से फैलती है और महामारी की शुरुआत में लॉकडाउन की तीव्रता सबसे अधिक मायने रखती है।
- भारत ने रोकथाम, राजकोषीय, वित्तीय और दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधारों की एक अनूठी चार-स्तंभ रणनीति अपनाई।
 - एक अनुकूल मौद्रिक नीति ने प्रचुर मात्रा में तरलता सुनिश्चित की।
 - लॉकडाउन में कमजोर लोगों को सहायता देना और अनलॉक करते समय खपत और निवेश को बढ़ावा देना।
 - रु. 1.46 लाख करोड़ की प्रोडक्शन लिंकड इंसेंटिव (PLI) योजना से भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक अभिन्न अंग बनाने की उम्मीद है।
 - राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन मांग बल और आगे रिकवरी में तेजी लाने के लिए शुरू की।
- जुलाई 2020 से, एक लचीला वी-आकार की रिकवरी चल रही है।



775. जीडीपी अनुमान (GDP estimation)

- भारत की वास्तविक जीडीपी में 2021-22 में 11% की वृद्धि दर्ज की जाएगी और नॉमिनल जीडीपी में 15.4% की वृद्धि दर्ज की जाएगी - जो स्वतंत्रता के बाद से सबसे अधिक है
 - ये अनुमान अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों के अनुरूप हैं।
- वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष) 2020-21 में भारत की जीडीपी के 7.7% घटने का अनुमान है।
- क्षेत्रवार कृषि उम्मीद की किरण बनी हुई है।
- जबकि संपर्क-आधारित सेवाएं, विनिर्माण, निर्माण सबसे कठिन प्रभावित हुए, और अब तेजी से ठीक हो रहे हैं।
- बाहरी क्षेत्र ने भारत के साथ विकास के लिए एक प्रभावी सहयोग प्रदान किया, जो वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में जीडीपी के 3.1% का चालू खाता अधिशेष दर्ज कर रहा है।



776. बाहरी क्षेत्र (External Sector)

- 08 जनवरी, 2021 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 586.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर है।
- पूंजी खाते में शेष राशि मजबूत FDI और FPI अंतर्वाह से पुष्ट होती है:
 - अप्रैल-अक्टूबर 2020 में 27.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का शुद्ध FDI प्रवाह: वित्त वर्ष 2019-20 के पहले सात महीनों की तुलना में 14.8% अधिक है।

- अप्रैल-दिसंबर 2020 में शुद्ध FPI अंतर्वाह 28.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 12.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- सितंबर 2020 के अंत में विदेशी ऋण 556.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो मार्च 2020 के अंत की तुलना में 2.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर (0.4%) कम है।

777. ऋण स्थिरता और विकास (Debt Sustainability and Growth)

- विकास भारतीय संदर्भ में ऋण स्थिरता की ओर ले जाता है लेकिन इसके विपरीत भी जरूरी नहीं।
- ऋण स्थिरता 'ब्याज दर वृद्धि दर अंतर' (IRGD) पर निर्भर करती है, अर्थात्, ब्याज दर और विकास दर के बीच का अंतर।
- भारत में नकारात्मक IRGD - कम ब्याज दरों के कारण नहीं बल्कि बहुत अधिक विकास दर के कारण।
- राजकोषीय नीति जो विकास को गति प्रदान करती है, वह ऋण-से-जीडीपी अनुपात को कम करेगी।
- भारत की विकास क्षमता को देखते हुए, सबसे खराब स्थितियों में भी ऋण स्थिरता एक समस्या होने की संभावना नहीं है।
- आर्थिक मंदी के दौरान विकास को सक्षम करने के लिए प्रति-चक्रिय राजकोषीय नीति का उपयोग करना वांछनीय है।

778. सेवा क्षेत्र (Service sector)

- भारत के सकल मूल्य वर्धित (GVA) में सेवा क्षेत्र का 54% से अधिक और भारत में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का लगभग चार-पांचवां हिस्सा है।
- हाल के वर्षों में कुल निर्यात में सेवा क्षेत्र का योगदान 48% है, जो माल निर्यात से बेहतर है।
- सर्विस परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, रेल फ्रेट ट्रेफिक और पोर्ट ट्रेफिक जैसे प्रमुख संकेतक लॉकडाउन के दौरान तेज गिरावट के बाद वी-आकार की रिकवरी प्रदर्शित कर रहे हैं।
- स्टार्ट अप: कोविड-19 महामारी के बीच भारतीय स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र अच्छी तरह से प्रगति कर रहा है,
- भारत 38 यूनिकॉर्न का घर है - पिछले साल यूनिकॉर्न सूची में 12 स्टार्ट-अप की रिकॉर्ड संख्या जोड़ी गयी।
- अंतरिक्ष क्षेत्र: भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र पिछले छह दशकों में तेजी से बढ़ा है।

779. स्वास्थ्य और शिक्षा (Health and Education)

स्वास्थ्य देखभाल:

- **PM-JAY** ने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को लागू करने वाले राज्यों में कई स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करने में योगदान दिया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM):

- **NHM** ने असमानता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई क्योंकि सबसे गरीब लोगों की प्रसव पूर्व/प्रसवोत्तर देखभाल और संस्थागत प्रसव तक पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
- आयुष्मान भारत के तहत इस योजना को प्रमुखता दी जानी चाहिए।

सरकारी खर्च:

- स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र पर सरकारी खर्च में वृद्धि - जीडीपी के वर्तमान 1% से 2.5-3% तक - जैसा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में परिकल्पित है, जब खर्च को कम कर सकता है।

शिक्षा

- भारत ने प्राथमिक विद्यालय स्तर पर लगभग **96%** साक्षरता स्तर प्राप्त किया है।
- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) के अनुसार, अखिल भारतीय स्तर पर 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की साक्षरता दर **77.7%** रही।
- हिंदू और इस्लाम के धार्मिक समूहों सहित एससी, एसटी, ओबीसी के सामाजिक समूहों में महिला साक्षरता राष्ट्रीय औसत से नीचे रही।
- स्मार्टफोन रखने वाले सरकारी और निजी स्कूलों के नामांकित बच्चों का प्रतिशत **2018** में **36.5%** से बढ़कर ग्रामीण भारत में **2020** में **61.8%** हो गया।
- **PM eVIDYA** डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित एक व्यापक पहल है।
- करीब 92 पाठ्यक्रम शुरू हो चुके हैं और 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स स्वयंपाठी ओपन ऑनलाइन कोर्स (MOOC) के तहत दाखिला ले रहे हैं।
- डिजिटल शिक्षा पर **PRAGYATA** दिशानिर्देश विकसित किए गए हैं।
- आत्मनिर्भर भारत अभियान में मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए **MANODARPAN** पहल को शामिल किया गया है।

व्यावसायिक पाठ्यक्रम और कौशल विकास:

- 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों में वोकेशनल कोर्स चरणबद्ध तरीके से शुरू किए जाएंगे।
- केंद्र की प्रमुख कौशल योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना **3.0** के हिस्से के रूप में
 - **15-59** वर्ष के आयु वर्ग में भारत के केवल **2.4%** कार्यबल ने औपचारिक व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

Healthcare under spotlight

ECONOMIC SURVEY 2020-21

- To respond to pandemics, health infrastructure must be agile
- Emphasis on National Health Mission should continue
- Increase in public healthcare spend from **1% to 2.5-3%** of GDP can decrease Out of Pocket Expenditure from **65% to 35%** of overall healthcare spend
- Regulation of health sector required given information asymmetry in healthcare
- Mitigating information asymmetry can lower insurance premiums, enable the offering of better products and increase insurance penetration
- Telemedicine needs to be harnessed to the fullest

- जबकि अन्य 8.9% ने अनौपचारिक स्रोतों से प्रशिक्षण प्राप्त किया।
- गैर-औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 8.9% कार्यबल में से, सबसे बड़ा हिस्सा ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण (3.3%) का है, इसके बाद स्व-शिक्षण (2.5%) और वंशानुगत स्रोतों (2.1%) और अन्य स्रोतों का (1%) योगदान है।
- औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों में, पुरुषों और महिलाओं दोनों के बीच सबसे अधिक चुना गया प्रशिक्षण पाठ्यक्रम IT-ITES है।
- एकीकृत कौशल नियामक-राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (NCVET) का संचालन हाल ही में किया गया था।

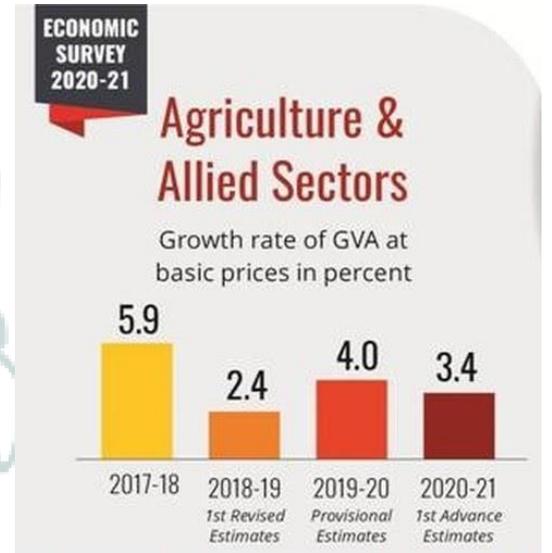
780. कृषि (Agriculture)

विकास:

- कृषि और संबद्ध गतिविधियों में 3.4% की वृद्धि दर्ज की गई।
- केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी राष्ट्रीय आय के अंतिम अनुमानों के अनुसार, वर्तमान कीमतों पर देश के सकल मूल्य वर्धित (GVA) में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की हिस्सेदारी वर्ष 2019-20 के लिए 17.8% है।

निर्यात:

- 2019-20 में, प्रमुख कृषि और संबद्ध निर्यात गंतव्य संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, ईरान, नेपाल और बांग्लादेश थे।
- भारत से निर्यात किए जाने वाले शीर्ष कृषि और संबंधित उत्पाद समुद्री उत्पाद, बासमती चावल, भैंस का मांस, मसाले, गैर-बासमती चावल, कच्चे कपास, तेल भोजन, चीनी, अरंडी का तेल और चाय थे।





IASBABA'S

**RAPID REVISION (RaRe)
SERIES - UPSC 2021**

RaRe Notes Hindi

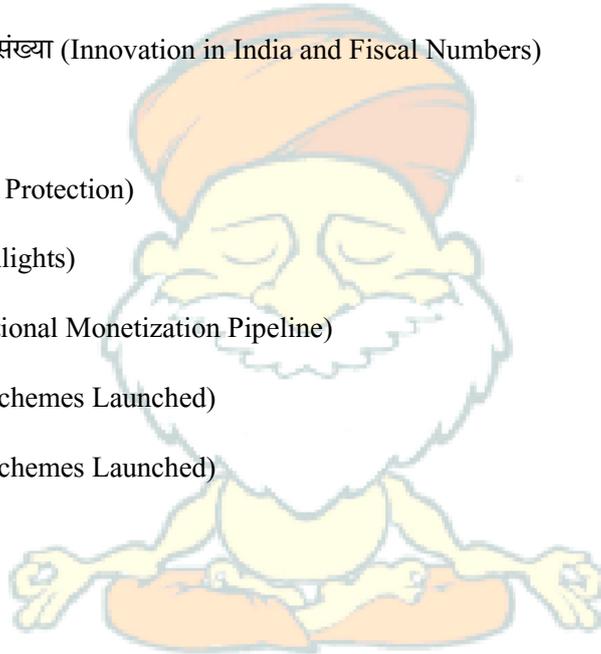
DAY 109 - ECONOMY

#RaRebaba

www.rrs.iasbaba.com

विषय

781. बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs)
782. बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs)
783. भारत में विनियमन (Regulation in India)
784. भारत में नवाचार और राजकोषीय संख्या (Innovation in India and Fiscal Numbers)
785. सामाजिक क्षेत्र (Social Sector)
786. पर्यावरण संरक्षण (Environment Protection)
787. बजट हाइलाइट्स (Budget Highlights)
788. राष्ट्रीय मुद्राकरण पाइपलाइन (National Monetization Pipeline)
789. नई शुरू की गई योजनाएं (New Schemes Launched)
790. नई शुरू की गई योजनाएं (New Schemes Launched)



781. और 782. बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs)

Q.1) भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

1. परिव्राजक :: त्यागी और पथिक
2. श्रमण :: उच्च पद वाला पुजारी
3. उपासक :: बौद्ध धर्म का अनुयायी

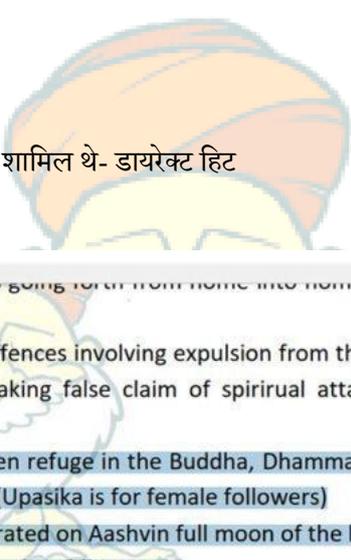
ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन-सा सही सुमेलित है?

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 1 और 3
- c) केवल 2 और 3
- d) 1,2 और 3

Solution (b)

संदर्भ:

आईएलपी वैल्यू एड नोट्स-प्राचीन भारत: तीनों वैन में शामिल थे- डायरेक्ट हिट



ILP 2020-ANCIENT IND... x

Parajika: Ceremony to mark a person's going forth from home into homelessness (in Buddhism)

- **Parajika:** It includes four most serious offences involving expulsion from the Sangha i.e Sexual intercourse, killing someone, making false claim of spirirual attainment and taking what is not given. (in Buddhism)
- **Upasakas:** Male followers who have taken refuge in the Buddha, Dhamma and Sangha but who have not taken monastic vows. (Upasika is for female followers)
- **Pavarana:** It is a Buddhist holy day celebrated on Aashvin full moon of the lunar month. It marks the end of rainy season, also called Buddhist Lent.
- **Uposatha/Upavasatha:** Ceremony held on full moon and new moon for act of confession (Buddhism)
- **Paribbajaka/Parivarajaka:** Wandered
- **Samana/Shramana:** One who strives to realize the truth.

Q.2) भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. एक हाथी समूह की नेता मादा होती है।
2. मादा हाथी की गर्भधारण की अधिकतम अवधि 22 महीने हो सकती है।
3. एक मादा हाथी सामान्य रूप से केवल 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे को जन्म दे सकती है।
4. भारत के राज्यों में, हाथी की सबसे अधिक आबादी केरल में है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा सही है?

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2 और 4
- c) केवल 3
- d) 1,3 और 4 केवल

Solution (a)

व्याख्या:

कथन 1: हाथी परिवारों का मुखिया मातृसत्तात्मक होता है, जिसका अर्थ है कि एक वृद्ध, अनुभवी महिला हाथी झुंड की अगुवाई करती है। एक परिवार में आमतौर पर एक माँ, उसकी बहनें, बेटियाँ उनके बच्चे (बछड़े) होते हैं। कभी-कभी, गैर-संबंधित हाथी परिवार बनाने के लिए जुड़ जाते हैं। महिला परिवार इकाइयाँ तीन से पच्चीस हाथियों तक होती हैं।

कथन 2: अफ्रीकी हाथी की गर्भधारण अवधि 22 महीने है और एशियाई हाथियों के लिए यह 18-22 महीने के बीच है।

कथन 3: हाथी 45-60 वर्ष की आयु तक प्रजनन कर सकते हैं।

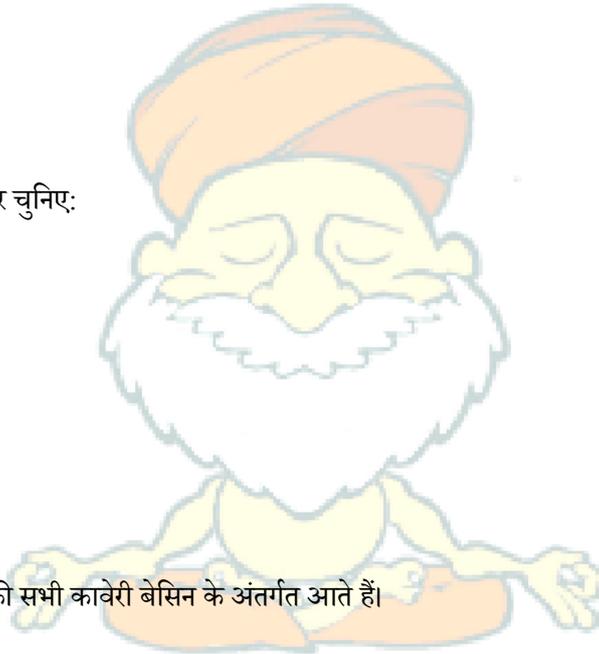
कथन 4: कर्नाटक में भारत में सबसे अधिक हाथी आबादी है।

Q.3) निम्नलिखित में से कौन से संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित हैं?

1. नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान
2. पपिकोंदा राष्ट्रीय उद्यान
3. सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व
4. वायनाड वन्यजीव अभयारण्य

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 3 और 4
- c) 1,3 और 4 केवल
- d) 1,2,3 और 4

**Solution (c)**

व्याख्या :

पपिकोंदा गोदावरी बेसिन में आता है बाकी सभी कावेरी बेसिन के अंतर्गत आते हैं।

Q.4) भारत की जैव विविधता के संदर्भ में, सीलोन फ्रॉगमाउथ, कॉपरस्मिथ बारबेट, ग्रे-चिन्ड मिनिवेट और व्हाइट-श्रोटेड रेडस्टार्ट हैं

- a) पक्षियों
- b) नरवानर गण
- c) सरीसृप
- d) उभयचर

Solution (a)

व्याख्या:

सीलोन फ्रॉगमाउथ, कॉपरस्मिथ बारबेट, ग्रे-चिन्ड मिनिवेट और व्हाइट-श्रोटेड रेडस्टार्ट भारत में पाए जाने वाले पक्षी हैं।

संदर्भ: बाबापीडिया और करेंट अफेयर्स सत्रों में भी शामिल।

Brown-headed barbet

- It is an Asian barbet species native to the Indian subcontinent, where it inhabits tropical and subtropical moist broadleaf forests.
- It is widespread from the Terai in both Nepal and India to Sri Lanka, and listed as Least Concern on the IUCN Red List.
- It is an arboreal species of gardens and wooded country which eats fruit and insects. It is fairly tolerant of humans and often seen in city parks.
- The species is purely arboreal, living high from the ground in heavy foliage, making it hard to spot. Thus, like several other birds in India, this Barbet is exceedingly well known to many people only by sound and not by sight.

19th November – Sri Lankan Frogmouth

IASBaba | Posted on November 19, 2018

News: It was spotted in Chinnar Wildlife Sanctuary. Its presence was noticed on the eastern side of the Western Ghats for the first time**About**

- It is found in the Western Ghats of south India and Sri Lanka.
- It is usually confined to its habitation in the western side of the Western Ghats forests

Q.5) निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्रों में से कौन सा भारतीय दलदली हिरण (बारासिंगा) की उप-प्रजाति के संरक्षण के लिए जाना जाता है जो कठोर भूमि में अच्छी तरह से पनपता है और विशेष रूप से ग्रामीण है?

- कान्हा राष्ट्रीय उद्यान
- मानस राष्ट्रीय उद्यान
- मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य
- तालछापर वन्यजीव अभयारण्य

Solution (a)

व्याख्या:

कठोर भूमि दलदली हिरण, जिसे भारत में बारासिंगा के नाम से जाना जाता है, जो कभी मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में विलुप्त होने के करीब था, को एक सफल प्रजनन कार्यक्रम और संरक्षण प्रथाओं के माध्यम से बचाया गया है। पांच दशकों के समर्पित और कुशल संरक्षण कार्य के बाद, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में दलदली हिरणों की आबादी 800 है।

संदर्भ: बाबापीडिया:

News: Kanha has become the first tiger reserve in India to officially introduce a mascot — Bhoorsingh the Barasingha — to present the hard ground swamp deer as the spirit of the reserve and spread awareness to save it from possible extinction.

Highlights

- Barasingha, or swamp deer, is the state animal of Madhya Pradesh.
- The Kanha tiger reserve, spread over Mandla and Balaghat districts, is the only place in the world where the species exists.

783. भारत में विनियमन (Regulation in India)

- सर्वेक्षण में देश में अत्यधिक विनियमन पर प्रकाश डाला गया।
- भारत अर्थव्यवस्था को अति-विनियमित करता है जिसके परिणामस्वरूप विनियम अप्रभावी होते हैं।
- अत्यधिक विनियमन की समस्या का मूल कारण एक ऐसा दृष्टिकोण है जो हर संभव परिणाम का हिसाब देने का प्रयास करता है।
- इसका समाधान विनियमों को सरल बनाना और अधिक पर्यवेक्षण में निवेश करना है, जो परिभाषा के अनुसार, अधिक विवेक का अर्थ है।

- वैश्विक वित्तीय संकट के बाद बैंकों के लिए नियामक प्रतिबंध में पुनर्गठन परिसंपत्तियों के मानदंडों में ढील देना शामिल था, जहां पुनर्गठित परिसंपत्तियों को अब गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता नहीं थी।

सुझाव:

- वर्षों तक नियामक प्रतिबंध जारी रखने के बजाय, नीति निर्माताओं को आर्थिक सुधार की सीमा निर्धारित करनी चाहिए, जिस पर इस तरह के उपायों को वापस ले लिया जाएगा।

784. भारत में नवाचार और राजकोषीय संख्या (Innovation in India and Fiscal Numbers)

भारत और नवाचार:

- 2007 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की स्थापना के बाद से भारत ने 2020 में पहली बार शीर्ष -50 नवोन्मेषी देशों में प्रवेश किया,
- मध्य और दक्षिण एशिया में पहले स्थान पर, और निम्न मध्यम आय वर्ग की अर्थव्यवस्थाओं में तीसरे स्थान पर।
- अनुसंधान और विकास पर भारत का सकल घरेलू व्यय (GERD) शीर्ष दस अर्थव्यवस्थाओं में सबसे कम है।
- भारत की आकांक्षा शीर्ष दस अर्थव्यवस्थाओं के साथ नवाचार पर प्रतिस्पर्धा करने की होनी चाहिए।

भारत और सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग:

- भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांतों को प्रतिबिंबित नहीं करती है और वैश्विक एजेंसियों को अपनी रेटिंग में अधिक पारदर्शी और कम व्यक्तिपरक होना चाहिए।

राजकोषीय संख्या

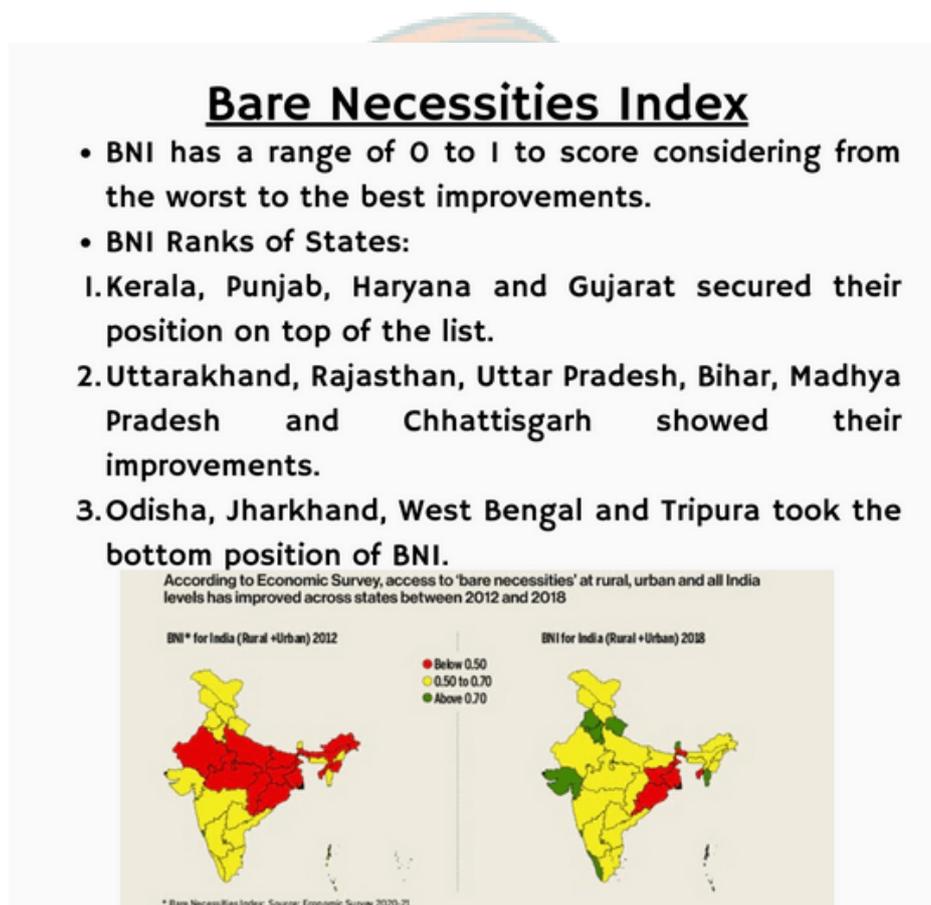
- सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, चालू वित्त वर्ष में सरकारी व्यय घटकर 15.6 प्रतिशत रह जाएगा, जो पिछले वित्त वर्ष में 17.7 प्रतिशत था।
- वित्त वर्ष 2021 के लिए राजकोषीय घाटा 9.5 % था और वित्त वर्ष 2022 में इसे घटाकर 6.8 % करने का अनुमान है।
- एक अवधि में लगातार गिरावट के साथ, सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को 2025-26 तक पूरा किया जाएगा।
 - 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2026 तक एफडी को घटाकर 4% करने की सिफारिश की है।
 - FRBM ने वित्त वर्ष 2021 तक (2018 में संशोधन के अनुसार) सकल घरेलू उत्पाद के 3% का लक्ष्य निर्धारित किया था।
- राजस्व घाटा वित्त वर्ष 2021 के लिए 7.5% और वित्त वर्ष 2022 के लिए 5.1% संशोधित किया गया है।
- 1991 में उदारीकरण सुधार शुरू होने के बाद से चालू वित्त वर्ष के लिए FD सबसे अधिक होगी।



- सरकार ने वित्त वर्ष 2021 के लिए 3.5% के एफडी लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन महामारी ने बैलेंस शीट को दोहरे झटके दिए हैं।
 - नाममात्र जीडीपी में संकुचन, कर राजस्व में कमी
 - अधिक खर्च

785. सामाजिक क्षेत्र (Social Sector)

- सभी/लक्षित जिलों के लिए बुनियादी आवश्यकता सूचकांक (**Bare Necessities Index - BNI**) का निर्माण किया जा सकता है ताकि बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच की प्रगति का आकलन किया जा सके।
 - BNI पांच आयामों पर 26 संकेतकों को सारांशित करता है, जैसे पानी, स्वच्छता, आवास, सूक्ष्म पर्यावरण, और अन्य सुविधाएं।
- 2012 की तुलना में 2018 में देश के सभी राज्यों में बुनियादी आवश्यकताओं में सुधार हुआ है।



असमानता और विकास:

- आर्थिक विकास का असमानता की तुलना में गरीबी उन्मूलन पर अधिक प्रभाव पड़ता है।
- भारत को गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए आर्थिक विकास पर ध्यान देना चाहिए।
- विकासशील अर्थव्यवस्था में पुनर्वितरण तभी संभव है जब आर्थिक पाई का आकार बढ़ता है।

सामाजिक अवसंरचना, रोजगार और मानव विकास:

- सकल घरेलू उत्पाद के% के रूप में संयुक्त (केंद्र और राज्य) सामाजिक क्षेत्र व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 में वृद्धि हुई है।
- मानव विकास सूचकांक (HDI) 2019 में भारत का रैंक 131 दर्ज किया गया, जो कुल 189 देशों में से था।
- आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के माध्यम से रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार का प्रोत्साहन परिणाम दे रहा है।

भारत में महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर (एलएफपीआर) का निम्न स्तर:

- महिलाएं अवैतनिक घरेलू और देखभाल करने वाली सेवाओं पर अधिक समय व्यतीत करती हैं (समय उपयोग सर्वेक्षण, 2019)।
- कार्यस्थल पर गैर-भेदभावपूर्ण प्रथाओं को बढ़ावा देने की आवश्यकता है जैसे वेतन और कैरियर की प्रगति।
- महिला श्रमिकों के लिए चिकित्सा और सामाजिक सुरक्षा लाभ सहित कार्य प्रोत्साहनों में सुधार करना।

786. पर्यावरण संरक्षण (Environment Protection)

सतत विकास और जलवायु परिवर्तन:

- सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच (HLPF) को स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (VNR) प्रस्तुत की गई।
- लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी भी रणनीति के लिए SDG का स्थानीयकरण महत्वपूर्ण है।
- जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) के तहत आठ राष्ट्रीय मिशनों ने जलवायु जोखिमों पर अनुकूलन, शमन और तैयारियों के उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित किया।
- राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) कहता है कि वित्त जलवायु परिवर्तन कार्रवाई का एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक है।
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) ने दो नई पहल शुरू की -
 - 'वर्ल्ड सोलर बैंक' और 'वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव' - वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा क्रांति लाने की ओर अग्रसर है।

787. बजट हाइलाइट्स (Budget Highlights)

- राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 9.5% है जो चालू वित्त वर्ष में 6.8% रहने का अनुमान है।
- राज्य उधारी को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GDSP) के 4% तक बढ़ा दिया गया है।
- स्वचालित मार्ग के तहत बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी कर दी गई है।
- सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों में विनिवेश से 1 लाख करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद है।
 - रक्षा के लिए आवंटित पूंजी बजट 2016-17 के बाद से पूरी तरह से उपयोग किया गया है, जो धन के समर्पण के पिछले रुझानों को उलट देता है।
- MSME के लिए बजट पिछले वर्ष से दोगुना कर 15,700 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
- लाभांश आय को अब प्राप्तकर्ता के हाथों कर योग्य बना दिया गया है। इससे पहले, कंपनियां अपने द्वारा शेयरधारकों को वितरित किए गए लाभांश पर 15% कर का भुगतान कर रही थीं।
- 2,23,846 करोड़ रुपये का बजट स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र को आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष में 94,452 करोड़ रु की तुलना में 137% अधिक है।

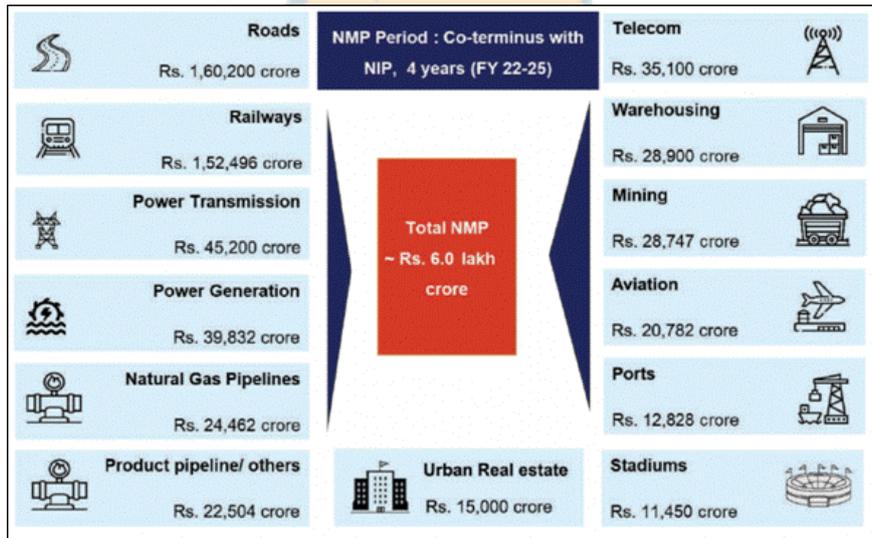
- लाभांश आय अब प्राप्तकर्ता के हाथों में कर योग्य बना दिया गया है। इससे पहले, कंपनियां शेयरधारकों को इसके द्वारा वितरित लाभांश पर 15% का कर दे रही थीं।
- पुराने और अनुपयुक्त वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए वाहन स्क्रेपिंग नीति की घोषणा की गई है।
- इसके अलावा, सभी वाहनों को एक फिटनेस परीक्षण से गुजरना पड़ता है।

788. राष्ट्रीय मुद्राकरण पाइपलाइन (National Monetization Pipeline)

समाचार में केंद्रीय वित्त मंत्री ने हाल ही में राष्ट्रीय मुद्राकरण पाइपलाइन (NMP) लॉन्च किया, जिसके माध्यम से सरकार का लक्ष्य अगले चार वर्षों में (वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2025 तक) राज्य के स्वामित्व वाली बुनियादी ढांचे की संपत्ति को पट्टे पर देकर \$81 बिलियन डॉलर जुटाना है।

संपत्ति मुद्राकरण क्या है?

- संपत्ति मुद्राकरण में मौजूदा अप्रयुक्त या कम सार्वजनिक परिसंपत्तियों के मूल्य को अनलॉक करके राजस्व के नए स्रोतों का निर्माण शामिल है।
- कई सार्वजनिक क्षेत्र की परिसंपत्तियों का उप-उपयोग किया जाता है और परिसंपत्तियों से बेहतर मूल्य बनाने के लिए निजी क्षेत्र (पट्टे या बिक्री) को शामिल करके उचित रूप से मुद्राकृत किया जा सकता है।



राष्ट्रीय मुद्राकरण योजना की मुख्य विशेषताएं

- NMP का रोडमैप नीति आयोग ने केंद्रीय बजट 2021-22 के 'एसेट मोनेटाइजेशन' जनादेश के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर लाइन मंत्रालयों के परामर्श से तैयार किया है।
 - नीति आयोग के पास एक सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रकोष्ठ है और इसने किसी भी मंत्रालय को मुद्राकरण रोडमैप को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी सहायता के लिए लेनदेन सलाहकारों को नियुक्त किया है।
- जिन क्षेत्रों में संपत्ति का मुद्राकरण करने के लिए पहचान की जा रही है, उनमें सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डे, रेलवे, बिजली उत्पादन और संचरण, दूरसंचार, भंडारण, गैस और उत्पाद पाइपलाइन, खनन, स्टेडियम, आतिथ्य और आवास शामिल हैं।
- अभी के लिए, सरकार ने केवल बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में काम करने वाले बुनियादी ढांचे के मंत्रालयों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) की संपत्ति को शामिल किया है।
- विनिवेश के माध्यम से मुद्राकरण और गैर-प्रमुख संपत्तियों के मुद्राकरण को NMP में शामिल नहीं किया गया है।

- मूल परिसंपत्ति मुद्रिकरण के मुद्रिकरण की रूपरेखा में तीन प्रमुख अनिवार्यताएं हैं:
 - अधिकारों का मुद्रिकरण स्वामित्व नहीं जिसका अर्थ है कि संपत्ति का लेनदेन जीवन के अंत में वापस सौंपना होगा। समग्र लेनदेन राजस्व अधिकारों के आसपास संरचित किया जाएगा।
 - ब्राउनफील्ड डी-रिस्क वाली संपत्ति: यहां कोई जमीन नहीं है, यह संपूर्ण (NMP) ब्राउनफील्ड परियोजनाओं के बारे में है जहां निवेश पहले ही किया जा चुका है और एक पूर्ण संपत्ति है जो या तो सुस्त है या यह पूरी तरह से मुद्रिकृत नहीं है या इसका उपयोग नहीं किया गया है।
 - परिभाषित संविदात्मक ढांचे और पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली के तहत संरचित भागीदारी, जहां संविदात्मक भागीदारों को प्रमुख प्रदर्शन संकेतक और प्रदर्शन मानकों का पालन करना होगा।
- NMP के तहत पहचान की गई संपत्ति और लेनदेन को कई प्रकार के उपकरणों के माध्यम से शुरू किए जाने की उम्मीद है।
 - इनमें सार्वजनिक निजी भागीदारी रियायतें और पूंजी बाजार के साधन जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (InvITs) जैसे प्रत्यक्ष संविदात्मक उपकरण शामिल हैं।
 - उदाहरण के लिए: योजना के तहत, निजी फर्म इनविट रूट का उपयोग करके एक निश्चित रिटर्न के लिए परियोजनाओं में निवेश कर सकती हैं और साथ ही उन्हें सरकारी एजेंसी को वापस स्थानांतरित करने से पहले एक निश्चित अवधि के लिए संपत्ति का संचालन और विकास कर सकती हैं।
 - साधन का चुनाव क्षेत्र, संपत्ति की प्रकृति आदि द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
- NMP का उद्देश्य सार्वजनिक संपत्ति के मालिकों के लिए कार्यक्रम का एक मध्यम अवधि का रोडमैप प्रदान करना है; निजी क्षेत्र के लिए संभावित संपत्तियों पर दृश्यता के साथ।
- NMP दिसंबर 2019 में घोषित 100 लाख करोड़ रुपये की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के साथ सह-टर्मिनस चलाएगा।
- संपत्ति मुद्रिकरण कार्यक्रम को लागू करने और निगरानी करने के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है। संपत्ति मुद्रिकरण (CGAM) पर सचिवों के कोर ग्रुप की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे।
- परिसंपत्ति मुद्रिकरण डैशबोर्ड के माध्यम से वास्तविक समय की निगरानी की जाएगी। सरकार वार्षिक लक्ष्यों और एक अधिकार प्राप्त समिति द्वारा मासिक समीक्षा के साथ NMP की प्रगति की बारीकी से निगरानी करेगी।
- शीर्ष 5 क्षेत्र (अनुमानित मूल्य के अनुसार) कुल पाइपलाइन मूल्य का ~ 83% शामिल करते हैं। इनमें: सड़कें (27%) इसके बाद रेलवे (25%), बिजली (15%), तेल और गैस पाइपलाइन (8%) और दूरसंचार (6%) शामिल हैं।

NMP के गुण

- संसाधन दक्षता: इससे सरकारी संपत्तियों का इष्टतम उपयोग होता है।
- राजकोषीय विवेक: इन परिसंपत्तियों को निजी क्षेत्र को पट्टे पर देने से अर्जित राजस्व सरकारी वित्त पर दबाव डाले बिना नए पूंजीगत व्यय को निधि देने में मदद करेगा।

- प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना: परिसंपत्तियों का मुद्रिकरण कोई नई बात नहीं है, लेकिन सरकार ने अंततः इसे लक्ष्य निर्धारित करने, बाधाओं की पहचान करने और एक रूपरेखा तैयार करने में लगा दिया है।
- निजी पूंजी जुटाना: चूंकि परिसंपत्तियां जोखिम रहित होती हैं क्योंकि यह ब्राउनफील्ड परियोजनाएं हैं, इससे निजी पूंजी (घरेलू और विदेशी दोनों) जुटाने में मदद मिलेगी। वैश्विक निवेशकों ने खुलासा किया है कि वे पारदर्शी/प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से मुद्रिकृत होने वाली परियोजनाओं में भाग लेने के इच्छुक हैं।
- कम प्रतिरोध: योजना में स्वामित्व को स्थानांतरित किए बिना या संपत्ति की आग बिक्री का सहारा लिए बिना निजी क्षेत्र को पट्टे पर देना शामिल है। इसलिए इसे विपक्ष के कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा।
- सहकारी संघवाद: विमुद्रिकरण को आगे बढ़ाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार पहले ही प्रोत्साहन के रूप में 5,000 करोड़ रुपये निर्धारित कर चुकी है।
 - यदि कोई राज्य सरकार किसी सार्वजनिक उपक्रम में अपनी हिस्सेदारी बेचती है, तो केंद्र राज्य को विनिवेश का 100 प्रतिशत मिलान मूल्य प्रदान करेगा।
 - यदि कोई राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को शेयर बाजारों में सूचीबद्ध करता है, तो केंद्र सरकार उसे लिस्टिंग के माध्यम से जुटाई गई राशि का 50 प्रतिशत देगी।
 - यदि कोई राज्य किसी संपत्ति का मुद्रिकरण करता है, तो उसे केंद्र से मुद्रिकरण से जुटाई गई राशि का 33 प्राप्त होगा।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना: NMP का अंतिम उद्देश्य 'मुद्रिकरण के माध्यम से बुनियादी ढांचे के निर्माण' को सक्षम करना है, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र सहयोग करते हैं, प्रत्येक अपने क्षमता के मुख्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट है, ताकि देश के नागरिकों को सामाजिक-आर्थिक विकास और जीवन की गुणवत्ता प्रदान की जा सके।

789. नई शुरू की गई योजनाएं (New Schemes Launched)

एक स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय संस्थान

- 17,788 ग्रामीण और 11,024 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र
- वायरोलॉजी के लिए 4 क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थान
- 15 स्वास्थ्य आपातकालीन संचालन केंद्र और 2 मोबाइल अस्पताल
- सभी जिलों में एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला

मिशन पोषण 2.0 लॉन्च किया जाएगा:

- पोषण सामग्री, वितरण, आउटरीच और परिणाम को मजबूत करने के लिए।
- पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का विलय।

एक व्यापक राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन 2021-22

- इसका उद्देश्य हरित ऊर्जा संसाधनों से हाइड्रोजन का उत्पादन करना है।

जल जीवन मिशन (शहरी) - प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया जाएगा:

- 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शन
- सभी 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में यूनियर्सल वाटर सप्लाई

स्क्रेपिंग नीति

- पुराने और अनुपयुक्त वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए स्वैच्छिक वाहन स्कैपिंग नीति
- स्वचालित फिटनेस केंद्रों में फिटनेस परीक्षण:
- निजी वाहनों के मामले में 20 साल बाद
- वाणिज्यिक वाहनों के मामले में 15 साल बाद

उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLI)

- 5 सेक्टरों में पीएलआई स्कीमों के लिए 13 साल
- विनिर्माण कंपनियों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का एक अभिन्न अंग बनने में मदद करने के लिए, मुख्य क्षमता और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के अधिकारी हैं।

790. नई शुरू की गई योजनाएं (New Schemes Launched)

मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क (MITRA) योजना:

- 3 वर्षों में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए
- कपड़ा उद्योग विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनेगा, बड़े निवेश आकर्षित करेगा और रोजगार सृजन और निर्यात को बढ़ावा देगा।

राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) का विस्तार 7,400 परियोजनाओं तक किया गया:

- लगभग 217 परियोजनाएं रु. 1.10 लाख करोड़।
- NIP के लिए वित्त पोषण बढ़ाने के लिए तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उपाय:
- संस्थागत संरचनाओं का निर्माण
- संपत्ति के मुद्राकरण पर बड़ा जोर
- पूंजीगत व्यय के हिस्से में वृद्धि

विकास वित्तीय संस्थान (DFI) की स्थापना और पूंजीकरण के लिए 20,000 करोड़ रु. - बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए प्रदाता, प्रवर्तक और उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए।

3 वर्षों में प्रस्तावित DFI के तहत 5 लाख करोड़ रु. का उधार पोर्टफोलियो बनाया जाएगा।

अन्य पहल

- टीयर -2 शहरों और टीयर -1 शहरों के परिधीय क्षेत्रों में समान अनुभव के साथ बहुत कम लागत पर मेट्रो रेल प्रणाली प्रदान करने के लिए 'मेट्रोलाइट 'और' मेट्रोनियो ' प्रौद्योगिकियां।
- एक एकल प्रतिभूति बाजार कोड विकसित किया जाना है।
- GIFT - IFSC में विश्व स्तरीय फिन-टेक हब के विकास के लिए समर्थन
- प्रमुख भारतीय भाषाओं में शासन और नीति संबंधी ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन (NTLM).